वार्षिक रिपोर्ट

1980-81

वार्षिक रिपोर्ट

1980-81

विद्ययाऽमृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
National Council of Educational Research and Training

दिसंबर 1981
पौष 1903

P.D. IT-PD

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 1981

प्रकाशन विभाग में, श्री विनोदकुमार पंडित, सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली-110016 द्वारा प्रकाशित तथा सरस्वती प्रिंटिंग प्रेस, मौजपुर, दिल्ली-110053 में मुद्रित।

कृतज्ञता-ज्ञापन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, केन्द्रीय शिक्षा तथा संस्कृति के मंत्री और शिक्षा के राज्य मंत्री द्वारा परिषद् के कार्यों में गहरी रुचि लेने के लिए उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ है। परिषद् उन सभी विशेषज्ञों के प्रति आभारी है जो इसकी विभिन्न समितियों में रहकर अपना बहुमूल्य समय इसके कार्यों के लिए देते रहे हैं और अन्य कई प्रकार से परिषद् की सहायता करते रहे हैं। परिषद् उन सभी संगठनों और संस्थाओं, विशेष रूप से राज्य-शिक्षा-विभागों के प्रति भी कृतज्ञ है, जिन्होंने इसके कार्यकलापों को चलाए रखने में सहयोग दिया है। परिषद् यूनेस्को, यूनीसेफ़, यू० एन० डी० पी० और ब्रिटिश काउंसिल का भी सधन्यवाद आभार स्वीकार करती है, जिन्होंने इसे सहायता प्रदान की है।

विषय-सूची

	कृतज्ञता-ज्ञापन	V
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् : भूमिका एवं संरचना	1
2.	वर्ष के महत्त्वपूर्ण कार्य	8
3.	प्रारंभिक शैशवकाल की शिक्षा	15
4.	पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का निर्माण	23
5.	प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण	44
6.	लाभ-वंचित वर्गों की शिक्षा	60
7.	अध्यापकों और अन्य कर्मियों की शिक्षा	66
8.	शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण-साधन	96
9.	जनसंख्या-शिक्षा	109
10.	मापन और मूल्यांकन	115
11.	सर्वेक्षण, आधार-सामग्री प्रक्रिया और प्रलेखन	122
12.	अनुसंधान और नव परिवर्तन	129
13.	विस्तार कार्यक्रम और राज्यों के साथ कार्य करना	157
14.	प्रतिभा की खोज	165
15.	अंतर्राष्ट्रीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय संबंध	171
16.	प्रकाशन	182
17.	हिन्दी प्रयोग की दिशा में	197
18.	आय और भुगतान	200

परिशिष्ट

(क)	व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सहायता देने की योजना	205
(ख)	राज्यों में परिषद् के क्षेत्र-सलाहकारों के पते	212
(ग)	समितियों की संरचना	215
(घ)	सन् 1980-81 के दौरान समितियों द्वारा किए गए प्रमुख निर्णय	252

1

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् : भूमिका एवं संरचना

भूमिका और कार्य-व्यापार

स्कूल स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के निमित्त, शैक्षणिक आवश्यकताओं की आपूर्ति कराने के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो (1954), राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान (1956), राष्ट्रीय दृश्य-श्रव्य शिक्षा संस्थान (1959), माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यक्रम निदेशालय (1959) आदि जैसे जो अनेक विशेषीकृत संस्थान बना रखे थे, उनको इकट्ठा मिला करके मन्त्रालय द्वारा सितम्बर 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (एन० सी० ई० आर० टी०) की स्थापना की गई थी।

संस्था की विवरणिका के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का उद्देश्य है—शिक्षा, विशेषकर स्कूल स्तर की शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय को अपनी नीतियों और प्रमुख कार्यक्रमों को लागू करने की दिशा में सलाह तथा सहायता प्रदान करना। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, परिषद् निम्नलिखित कार्यक्रम और गतिविधियाँ चलाती है :

(क) स्कूल स्तर की शिक्षा के सभी क्षेत्रों में **अनुसंधान** करती है, अथवा करवाने के लिए सहायता देती है, उसे बढ़ावा देती है और उनमें समन्वय करती है।

(ख) सेवा-पूर्व और सेवाकालीन **प्रशिक्षण,** विशेषकर उच्च स्तर के प्रशिक्षण आयोजित करती है।

(ग) शैक्षिक पुनर्रचना में लगे हुए संस्थानों, संगठनों, और माध्यमों के लिए **विस्तार सेवाओं** का आयोजन करती है।

(घ) सुधरी हुई शैक्षिक विधियों, अभ्यासों और अभिनव परिवर्तनों को विकसित करती है और उन पर प्रयोग करती है।

(ङ) शैक्षिक जानकारी को एकत्र करती है, उन्हें सम्पादित करती है और फिर उन्हें **प्रचारित-प्रसारित** करती है।

(च) स्कूल-शिक्षा के **गुणात्मक सुधार** के लिए बने कार्यक्रमों को विकसित करने अथवा लागू करने में राज्यों एवं राज्य-स्तर के संस्थानों, संगठनों और माध्यमों की सहायता करती है।

(छ) यूनेस्को, यूनिसेफ़ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य देशों के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संस्थानों को सहयोग प्रदान करती है।

(ज) अन्य देशों के शैक्षिक कर्मियों को प्रशिक्षण एवं अध्ययन की सुविधाएँ प्रदान करती है।

(झ) अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के शैक्षणिक सचिवालय के रूप में कार्य करती है।

अनुसंधान करना और अनुसंधान के लिए सहायता या बढ़ावा देना परिषद् की महत्त्वपूर्ण गतिविधियाँ हैं। बाहर की संस्थाओं को वित्तीय सहायता देकर यह शैक्षिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। फ़ेलोशिप प्रदान कर भी यह अनुसंधान को बढ़ावा देती है। इसके पीछे यह उद्देश्य रहता है कि शैक्षिक समस्याएँ ढूँढ़ी जा सकें और निपुण अनुसंधान कर्मियों का दल बनाया जा सके। दूसरों के अनुसंधान-कार्यों को बढ़ावा देने के साथ-साथ, परिषद् शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अपने आप उल्लेखनीय अनुसंधान कार्य करवाती है। यह शैक्षिक सर्वेक्षण भी कराती है जिससे शैक्षिक नियोजन में सहायता मिलती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् प्रशिक्षण और विस्तार के जो कार्यक्रम चलाती है, उनसे राज्यों को अभिनव परिवर्तन के लिए नए-नए प्रयोगों को अपनाने में सहायता मिलती है। ये कार्यकलाप परिषद् के प्रमुख कार्यों में आते हैं। इस प्रशिक्षण का कई गुना प्रभाव लाने के लिए, परिषद् राज्य-स्तर पर प्रमुख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करती है। आगे चल कर ये प्रशिक्षित लोग अध्यापकों और अन्य स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित करते हैं। राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बनाए रखने के लिए परिषद् ने 16 क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित कर रखे हैं।

शैक्षिक जानकारी के विकीर्णन की अपनी गतिविधि के एक अंग के रूप में परिषद् चार पत्रिकाएँ प्रकाशित करती है। ये पत्रिकाएँ अलग-अलग विषयों की हैं और विभिन्न वर्ग के पाठकों के लिए हैं। 'प्राइमरी शिक्षक' प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए सार्थक और प्रासंगिक सामग्री प्रकाशित करती है। इस सामग्री को सीधे कक्षा में इस्तेमाल किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के वास्ते 'स्कूल साइंस' खुले मंच के रूप में सामने आती है। 'जर्नल ऑफ इंडियन एजुकेशन' एक ऐसा मंच प्रदान करती है जिस पर सामयिक रूप से प्रचलित शैक्षिक समस्याओं पर विचार-विमर्श करके शिक्षा में मौलिक विवेचना को बढ़ावा दिया जा सके। 'इंडियन एजुकेशनल रिव्यू' चौथी पत्रिका है जिसे परिषद् प्रकाशित करती है। इसके माध्यम से एक ऐसे मंच का निर्माण किया गया है जहाँ शैक्षिक अनुसंधान और नव परिवर्तन के क्षेत्र में किए जाने वाले अनुभवों का आदान-प्रदान होता है।

परिषद् देश की ऐसी पेशेवर शैक्षिक संस्थाओं की सहायता भी करती है, जो स्कूल शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए अभिनव परिवर्तन वाले कार्यक्रम चलाती हैं।

विकासात्मक गतिविधियाँ परिषद् के कार्य का प्रमुख भाग हैं। परिषद् नई स्कूल-शिक्षा-पद्धति की ज़रूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों के संशोधन और विकास तथा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण का कार्य हाथ में लेती है। यह कार्य सदा चलता रहता है। यह शिक्षक-दर्शिकाओं, अभ्यास-पुस्तिकाओं, सहायक पठन-सामग्री और शोध-प्रबन्धों का निर्माण भी करती है। इसने अनौपचारिक शिक्षा के प्रयोगात्मक कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के निमित्त वैकल्पिक मार्गकौशल के रूप में अनौपचारिक शिक्षा को अपनाने के लिए पर्याप्त अनुभव उपलब्ध हो जाए। स्कूल-शिक्षा के व्यावसायी-करण वाले कार्यक्रम के निमित्त पाठ्यक्रमों और अनुदेशीय सामग्री के विकास के लिए किए जाने वाले सर्वेक्षणों को आयोजित करने में यह राज्यों की सहायता करती है। राष्ट्रीय परिषद् उत्तम पाठ्यपुस्तकें लिखवा कर प्रकाशित करती है। यह प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं के लिए सस्ते विज्ञान किटों, प्रयोगशाला-उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों एवं शिक्षण सामग्रियों का उत्पादन करती है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों के मध्य द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य करने वाले माध्यमों में एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार यह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक समस्याओं के विशेष अध्ययन के निमित्त शिष्ट-मंडलों को विदेश भेज कर और विदेशों के प्रतिनिधियों के लिए यहाँ प्रशिक्षण और अध्ययन की व्यवस्था करके, शैक्षिक विचारों का द्विपक्षी आदान-प्रदान बनाए रखती है। परिषद् विविध अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों/सभाओं में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को वहाँ भेजती है और विदेशी अतिथियों को अपने यहाँ समय समय पर बुलाती है। बैंङ्कॉक स्थित एशिया और ओसनिया के यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय के तत्वावधान में हो रहे 'विकास के लिए शैक्षिक नवाचार का एशियाई कार्यक्रम' के अंतर्गत परिषद् सहयोगी केन्द्रों में से एक है।

संरचना और प्रशासन

परिषद् में निम्नलिखित शामिल हैं : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री (अध्यक्ष), शिक्षा के राज्य मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के सचिव, चार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति (हर क्षेत्र से एक एक), हर राज्य सरकार या संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि, कार्यकारी समिति के सभी सदस्य (जो ऊपर नहीं गिनाए गए हैं), और भारत सरकार द्वारा समय समय पर नामजद अन्य व्यक्ति जिनकी संख्या बारह से अधिक नहीं होगी और जिनमें से कम से कम चार को स्कूल शिक्षक होना चाहिए। परिषद् नीति निर्धारण की निकाय है।

परिषद् की **कार्यकारी समिति** को परिषद् की निधियों के इस्तेमाल और प्रशासन के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। कार्यकारी समिति में निम्नलिखित आते हैं—परिषद् के अध्यक्ष (पदेन अध्यक्ष), शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (पदेन उप-अध्यक्ष), शिक्षा मंत्रालय के उप मंत्री, परिषद् के निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, स्कूल-शिक्षा में गहरी रुचि लेने के लिए विख्यात चार शिक्षाशास्त्री (जिनमें से दो को स्कूल शिक्षक होना चाहिए), परिषद् के सह निदेशक, परिषद् की संकाय के तीन सदस्य (जिनमें से कम से कम दो प्रोफ़ेसर और विभागाध्यक्ष के स्तर के होने चाहिए), शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (जो परिषद् का वित्तीय सलाहकार होगा)। कार्यकारी समिति निम्नलिखित स्थायी समितियों की सहायता से अपने कार्य करती है—

—कार्यक्रम सलाहकार समिति

—वित्त समिति

—स्थापना समिति

—भवन और निर्माण समिति

—क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियाँ

—शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति

सामान्य रूप से परिषद् के तीन प्रमुख एकक हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिसके अंतर्गत अनेक विभाग या एकक हैं जो अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और विकीर्णन के विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक-शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करते हैं और क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में अनुसंधान करवाते हैं। ये अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्यों के उद्देश्य के लिए रा० शै० अ० और प्र० परिषद् के एक रूप में ही कार्य करते हैं। सोलह राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय इसलिए स्थापित किए गए हैं कि राज्य शिक्षा प्राधिकरणों और राज्य स्तर के शैक्षिक संस्थानों के साथ अधिक प्रभावी जन सम्पर्क बनाया जा सके।

परिषद् का सचिवालय गृह व्यवस्था के कार्यों का प्रबन्ध करता है और अन्य सुविधाएँ जुटाता है। सचिवालय सचिव के अधीन कार्य करता है। सचिव सहनिदेशक और निदेशक के मार्गदर्शन और निर्देशन में काम करते हैं। विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों को निभाने में सचिव की सहायता करने के लिए दो उप सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। सचिवालय को सशक्त करने के लिए अवर सचिवों तथा पर्यवेक्षी कार्मिकों की कुछ और जगहें भी बनाई गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् भारत सरकार और अन्य देशों की सरकारों के मध्य द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए कार्य करने वाले माध्यमों में एक प्रमुख माध्यम के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार यह अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक समस्याओं के विशेष अध्ययन के निमित्त शिष्ट-मंडलों को विदेश भेज कर और विदेशों के प्रतिनिधियों के लिए यहाँ प्रशिक्षण और अध्ययन की व्यवस्था करके, शैक्षिक विचारों का द्विपक्षी आदान-प्रदान बनाए रखती है। परिषद् विविध अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों/सभाओं में भाग लेने के लिए अपने अधिकारियों को वहाँ भेजती है और विदेशी अतिथियों को अपने यहाँ समय समय पर बुलाती है। बैंङ्कॉक स्थित एशिया और ओसनिया के यूनेस्को क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालय के तत्वावधान में हो रहे 'विकास के लिए शैक्षिक नवाचार का एशियाई कार्यक्रम' के अंतर्गत परिषद् सहयोगी केन्द्रों में से एक है।

संरचना और प्रशासन

परिषद् में निम्नलिखित शामिल हैं : केन्द्रीय शिक्षा मंत्री (अध्यक्ष), शिक्षा के राज्य मंत्री, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय के सचिव, चार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति (हर क्षेत्र से एक एक), हर राज्य सरकार या संघ क्षेत्र के प्रतिनिधि, कार्यकारी समिति के सभी सदस्य (जो ऊपर नहीं गिनाए गए हैं), और भारत सरकार द्वारा समय समय पर नामजद अन्य व्यक्ति जिनकी संख्या बारह से अधिक नहीं होगी और जिनमें से कम से कम चार को स्कूल शिक्षक होना चाहिए। परिषद् नीति निर्धारण की निकाय है।

परिषद् की **कार्यकारी समिति** को परिषद् की निधियों के इस्तेमाल और प्रशासन के समस्त अधिकार प्राप्त हैं। कार्यकारी समिति में निम्नलिखित आते हैं— परिषद् के अध्यक्ष (पदेन अध्यक्ष), शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री (पदेन उप-अध्यक्ष), शिक्षा मंत्रालय के उप मंत्री, परिषद् के निदेशक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, स्कूल-शिक्षा में गहरी रुचि लेने के लिए विख्यात चार शिक्षाशास्त्री (जिनमें से दो को स्कूल शिक्षक होना चाहिए), परिषद् के सह निदेशक, परिषद् की संकाय के तीन सदस्य (जिनमें से कम से कम दो प्रोफ़ेसर और विभागाध्यक्ष के स्तर के होने चाहिए), शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, और वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि (जो परिषद् का वित्तीय सलाहकार होगा)। कार्यकारी समिति निम्नलिखित स्थायी समितियों की सहायता से अपने कार्य करती है—

—कार्यक्रम सलाहकार समिति

—वित्त समिति

—स्थापना समिति

—भवन और निर्माण समिति

—क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की प्रबन्ध समितियाँ

—शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति

सामान्य रूप से परिषद् के तीन प्रमुख एकक हैं। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, जिसके अंतर्गत अनेक विभाग या एकक हैं जो अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, मूल्यांकन और विकीर्णन के विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध हैं। अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, जो स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर अध्यापक-शिक्षा की सुविधाएँ प्रदान करते हैं और क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में अनुसंधान करवाते हैं। ये अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्यों के उद्देश्य के लिए रा० शै० अ० और प्र० परिषद् के एक रूप में ही कार्य करते हैं। सोलह राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालय इसलिए स्थापित किए गए हैं कि राज्य शिक्षा प्राधिकरणों और राज्य स्तर के शैक्षिक संस्थानों के साथ अधिक प्रभावी जन सम्पर्क बनाया जा सके।

परिषद् का सचिवालय गृह व्यवस्था के कार्यों का प्रबन्ध करता है और अन्य सुविधाएँ जुटाता है। सचिवालय सचिव के अधीन कार्य करता है। सचिव सहनिदेशक और निदेशक के मार्गदर्शन और निर्देशन में काम करते हैं। विविध प्रकार के उत्तरदायित्वों को निभाने में सचिव की सहायता करने के लिए दो उप सचिव भी नियुक्त किए गए हैं। सचिवालय को सशक्त करने के लिए अवर सचिवों तथा पर्यवेक्षी कार्मिकों की कुछ और जगहें भी बनाई गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के संघटक

रा० शै० अ० और प्र० परिषद् के विविध संघटक एकक इस प्रकार हैं—

परिषद् मुख्यालय

(क) परिषद् सचिवालय

(ख) लेखा शाखा

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान

1. नियोजन, समन्वय और मूल्यांकन एकक
2. अध्यापक-शिक्षा विभाग
3. विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
4. सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
5. मापन एवं मूल्यांकन विभाग
6. शिक्षण साधन विभाग
7. विस्तार एकक
8. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज एकक
9. जनसंख्या-शिक्षा एकक
10. शिक्षा का व्यावसायीकरण एकक
11. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एकक
12. सर्वेक्षण और आधार-सामग्री प्रक्रिया एकक
13. शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक
14. शैक्षिक मनोविज्ञान एकक

15. शिशु-अध्ययन एकक
16. स्त्री-शिक्षा एकक
17. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक
18. अनौपचारिक शिक्षा वर्ग
19. पाठ्यक्रम वर्ग
20. प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
21. प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम प्रकोष्ठ
22. समुदाय शिक्षा और प्रतिभागिता में विकासात्मक गतिविधियाँ
23. शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति
24. पत्रिका प्रकोष्ठ
25. प्रकाशन विभाग
26. विज्ञान वर्कशॉप विभाग
27. पुस्तकालय तथा प्रलेखन एकक
28. केन्द्रीय समन्वय एकक

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

1. अजमेर
2. भुवनेश्वर
3. भोपाल
4. मैसूर

क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय

1. अहमदाबाद
2. इलाहाबाद
3. कलकत्ता
4. गौहाटी
5. चंडीगढ़
6. जयपुर
7. त्रिवेंद्रम
8. पटना
9. पुणे
10. बंगलोर
11. भुवनेश्वर
12. भोपाल
13. मद्रास
14. शिलङ
15. श्रीनगर
16. हैदराबाद

2

वर्ष के महत्त्वपूर्ण कार्य

वर्ष 1980-81 छठी पंचवर्षीय योजना का पहला साल था। समग्र रूप से आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए और विशेष तौर पर शैक्षिक विकास के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के प्रकाश में, परिषद् ने 1980-85 की योजना के प्रतिपादन का कार्य हाथ में लिया। पिछले वर्षों की भाँति, इस बार भी स्कूल-स्तर की शिक्षा को सुधारने (जो कि परिषद् की ही जिम्मेवारी है) के उद्देश्यों ने परिषद् के वे कार्यक्रम निर्धारित किए जिन्हें छठी पंचवर्षीय योजना के पाँच वर्षों में परिषद् द्वारा लागू किया जाना है। स्कूल-

शिक्षा के क्षेत्र में, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण को, विशेषकर उन राज्यों में जहाँ इस की कसर रह गई है, और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण को मुख्य प्राथमिकता देने की बात दुहराई गई।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रतिपादन के संदर्भ में विविध दिशाओं में किए गए पिछले प्रयासों का एक मूल्यांकन किया गया। ऐसा इस दृष्टि से किया गया कि जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका पुनर्अनुकूलन किया जा सके या नए कार्यक्रमों के प्रतिपादन के लिए दिशाएँ खोजी जा सकें ताकि शैक्षिक ज़रूरतों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा करने में परिषद् सहायक हो सके। कई कार्यक्रमों के मामले में, उनकी मार्गदर्शी स्थिति को लागू करने में जो उपलब्धियाँ पाई गईं, उनसे इतना आत्मविश्वास मिला है कि उनके क्षेत्र को और बढ़ाया जाए—अर्थात् नए राज्यों और संघ क्षेत्रों में उनको शुरू किया जाए और उन राज्यों तथा संघ क्षेत्रों में उनको बढ़ाया जाए जहाँ प्रयोगात्मक अवस्था को लागू किया जा चुका है। इस तरह के कामों में ये शामिल हैं—प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम-नवीकरण की यूनीसेफ़-सहायता-प्राप्त परियोजनाएँ, समुदाय शिक्षा और प्रतिभागिता में विकासात्मक गतिविधियाँ, प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा तथा परिवेशीय स्वच्छता, और शिशु माध्यम प्रयोगशाला। इन परियोजनाओं को करने और सारगर्भित रूप से बढ़ाने के लिए संचालन की अगली वृहद योजना में गुंजाइश रखी गई है।

परिषद् द्वारा प्रयोगात्मक परियोजनाओं को लागू करने के पीछे बुनियादी उद्देश्य यह है कि उन अनुभवों को प्रदान किया जाए जो शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यावहारिक मार्गों की तलाश में भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की सहायता करते हैं। इस दृष्टिकोण से, चल रही गतिविधियों का मियादी मूल्यांकन आवश्यक हो जाता है। क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालयों द्वारा लागू किए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम तथा यूनिसेफ़-सहायता-प्राप्त परियोजनाओं के, जिनको काम करते हुए चार पाँच वर्ष हो चुके हैं, प्रभाव के मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक कदम 1980-81 के दौरान उठाए गए।

इस वर्ष के दौरान एक बड़ी बात यह हुई कि सार्वजनिक लेखा समिति ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कुछ कार्यक्रमों की, विशेष कर 1974 से 79 की अवधि के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० पर केंद्रीय राजस्व के महालेखापाल द्वारा लेखा परीक्षा की समीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के संदर्भ में, आलोचनात्मक समीक्षा करने का निर्णय लिया। इससे परिषद् के संघटक एककों को यह अवसर मिला है कि वे अपने कार्यक्रमों और उपागमों की जाँच पड़ताल कर सकें।

जहाँ तक पंचवर्षीय योजना (1980-85) के शैक्षिक कार्यों का संबंध है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और शिक्षा के व्यावसायीकरण को परिषद् सर्वोच्च प्राथमिकता देती

रहेगी । जनसंख्या शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा और परिवेशीय स्वच्छता, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि के लिए परिषद् व्यवस्थित कार्यक्रमों का विकास करेगी । अन्य बातों के अलावा इन कार्यकलापों में ये बातें होंगी —

—पाठ्क्रमों, विशेष कर विज्ञान और गणित के पाठ्यक्रमों को अधुनातन और अभिनव गुणों वाला बनाना

—श्रेष्ठ पाठ्यपुस्तकों का निर्माण

—पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

—छात्रों की उपलब्धियों के मूल्यांकन के तरीकों में सुधार

—अध्यापक-शिक्षा का सुधार

—अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण

—राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

—शिल्प विज्ञानों और तकनीकों का बढ़ता हुआ इस्तेमाल

—शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार पर बल

राष्ट्रीय परिषद् ने छठी पंचवर्षीय योजना के लिए 17 करोड़ रुपयों का प्रस्ताव दिया था जिसमें भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (आइएनएसएटी) 1982 के संदर्भ में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के कार्यक्रमों के लिए 4·02 करोड़ रुपयों का प्रावधान भी था । इस प्रस्ताव के बदले 12 करोड़ रुपयों के खर्च की अनुमति मिली है ।

इस वर्ष के दौरान लागू किए गए कार्यक्रमों में से कुछ उल्लेख्य कार्यक्रमों की चर्चा नीचे की जा रही है—

विज्ञान-शिक्षा-कार्यक्रम के अंतर्गत, देश के स्कूल स्तर के विज्ञान-शिक्षण को सुधारने की दृष्टि से, स्कूलों और प्रशिक्षण संस्थानों को प्रयोगशाला उपकरण, कारखाने (वर्कशॉप) के औजार, पुस्तकें एवं दृश्य-श्रव्य साधनों की आपूर्ति तथा स्कूल स्तर पर नई पाठ्यक्रमीय सामग्री के परिचय (प्रवेश) पर विशेष बल दिया जाता रहा है । अभी तक 972 केंद्रों को अपग्रेड किया जा चुका है । वर्ष 1980-81 के दौरान 299 केंद्रों को सामग्री दी गई ।

विज्ञान-वर्कशॉप ने माध्यमिक स्कूलों में इस्तेमाल के लिए इलेक्ट्रोनिक किट का एक आदर्श रूप विकसित किया और इस तरह के लगभग 5000 किटों के सामानों के निर्माण को परिष्कृत किया ।

शैक्षिक सर्वेक्षणों ने 31 दिसंबर 1980 को चौथे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण का काम पूरा करके और प्रारंभिक रिपोर्ट का प्रकाशन करके एक अन्य कीर्ति स्तम्भ स्थापित

किया। इसके बाद नमूने के तौर पर आधार-सामग्री का गौण विश्लेषण, चुने हुए आठ राज्यों में लड़कियों के पढ़ाई में पिछड़ेपन के नमूने के सर्वेक्षण के लिए एक परिरूप का प्रतिपादन, और चौथे सर्वेक्षण द्वारा उपलब्ध की गई आधार-सामग्री पर आधारित शिक्षा के लिए जिला-विकास-योजनाओं के प्रतिपादन में राज्य स्तर के कर्मियों का प्रशिक्षण किया गया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने "प्रारंभिक वर्षों में वंचनाओं के अध्ययन के प्रभाव" पर भारत-अमरीकी परिसंवाद का आयोजन किया। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सात और भारत के दस प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अपने अपने प्रबंध पढ़ने और विचार-विमर्श करने के अलावा प्रतिनिधियों ने कुछ प्रायोगिक परियोजनाएँ भी देखीं। विचार-विमर्श के लिए मुख्य विषय थे—वंचनाओं के विविध पहलू, अधिगम (पढ़ाई) पर उनके प्रभाव, विकास की कठिन अवधियाँ, प्रभावित होने वाली पढ़ाई की किस्में, अनुसंधान परिरूपों की समस्याएँ और अंतर-विषयी शोध क्षेत्र।

"विकलांगों की शिक्षा" विषय पर वर्ष के दौरान तृतीय अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान सभा आयोजित की गई। विकलांगता के विशिष्ट क्षेत्रों के बारे में शोध-प्रबंध और विचार प्रबंध पढ़े गए। अंतिम सत्र में विकलांगों की शिक्षा में अनुसंधान के विषय और समस्याओं की पहचान पर ध्यान दिया गया। सभा के साथ-साथ एक फोटो प्रदर्शनी भी की गई जिसके फोटो **यूनिसेफ़** और ब्रिटिश काउंसिल से प्राप्त किए गए थे।

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के लिए, 'प्राथमिक शिक्षा की कायापलट' विषय पर, एक **अनुकूलन कोर्स** किया गया जिसके उद्देश्य थे—संघ के कार्यकारी सदस्यों को क्षेत्र की नई प्रवृत्तियों से परिचित कराना, और इस प्रकार नए विचारों और प्रवृत्तियों को फैलाने में मदद करना ताकि उत्पादिता में सुधार हो, और धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद एवं राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों का विकास हो सके।

भूटान के यूनेस्को शिक्षावृत्ति भोगियों के लिए प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा में एक **प्रशिक्षण कोर्स** आयोजित किया गया। इस कोर्स में अध्यापक-शिक्षा के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल और मैसूर स्थित **क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों** में सेवा-पूर्व और सेवाकालीन कोर्सों के अनेक कार्यक्रम किए गए जिनका उद्देश्य था—अपने-अपने प्रदेशों की शैक्षिक ज़रूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार स्कूल स्तर की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाना।

मापन और मूल्यांकन के अंतर्गत रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली योग्यता छात्रवृत्ति पाने वालों का एक गहन अध्ययन शुरू किया। इस परियोजना का प्रारंभिक कार्य पूरा हो चुका है। छात्रवृत्ति पाने वालों के बारे में जानकारी

पाने के लिए एक प्रश्नावली उन आवासीय स्कूलों में भेजी गई जहाँ वे छात्र पढ़ रहे हैं। कुछ जानकारी आ चुकी है और उसका विश्लेषण हो रहा है।

शैक्षिक मनोविज्ञान में, विशेषज्ञों द्वारा मेधा, रुचि, अभिवृत्ति, प्रवृत्ति और व्यक्तित्व के परीक्षणों की समीक्षा की गई।

समीक्षाधीन अवधि में स्कूल-पाठ्यक्रम से संबद्ध निम्नलिखित **फिल्में** बनाई गई हैं : (1) शिक्षण के ग्रैफ़िक साधन, और (2) लचीलापन।

प्रकाशनों में शामिल हैं— शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम, जनसंख्या-शिक्षा के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण, अभिनव परिवर्तन वाली शैक्षिक परियोजनाएं, राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी, परिवेश अध्ययनों का मूल्यांकन, चौथा शैक्षिक सर्वेक्षण, लघु शिक्षण की प्रभावान्विता आदि पर शोध प्रबंध।

स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में परिषद् ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण और व्यावसायीकरण के परिप्रेक्ष्य में, लड़कियों के लिए कार्यक्रमों के प्रतिपादन पर एक उच्चस्तरीय परामर्श सभा आयोजित की।

स्कूल शिक्षा के सुधार की दिशा में, विज्ञान-शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा व्यापक उपागम, प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम-नवीकरण, समुदाय शिक्षा और प्रतिभागिता की विकासात्मक गतिविधियाँ, पोषण, स्वास्थ्य विज्ञान और परिवेशीय स्वच्छता की यूनिसेफ़-सहायताप्राप्त **परियोजनाओं** ने महत्वपूर्ण प्रगति की। प्राप्त अनुभव के प्रारंभिक मूल्यांकन से इन परियोजनाओं को बढ़ाने में मदद मिली है।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज की तीन विभिन्न स्तरों अर्थात् कक्षा X, XI और XII की परीक्षाएं पूरे देश के 430 केन्द्रों में हुईं। इस परीक्षा में कुल 80 हज़ार प्रत्याशी बैठे। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के 379 छात्रों के लिए 27 विभिन्न जगहों पर ग्रीष्म स्कूल और ग्रीष्म कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम मूल्यांकन में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने चार कार्य-दल आयोजित किए ताकि प्राथमिक शिक्षा-सार्वजनीकरण-कार्यक्रम के अनुश्रवण और मूल्यांकन के उपकरणों के बारे में, प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले राज्य स्तर के पदाधिकारियों की प्रतिक्रियाओं को जाना जा सके। योजना आयोग, शिक्षा मंत्रालय, शैक्षिक नियोजन व प्रशासन के राष्ट्रीय संस्थान, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रतिनिधियों के एक कार्य-दल ने कर्मयोजना पर पर्यालोचन किया।

शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के नौ-महीने वाले स्नातकोत्तर डिप्लोमा का इस बार इक्कीसवाँ कोर्स था। इसमें 25 प्रशिक्षार्थी आए।

अध्यापक-शिक्षा में सेमिनार रीडिंग्स की सातवीं अखिल भारतीय प्रतियोगिता हुई। 500 रुपए का नगद पुरस्कार और योग्यता सनद मध्यप्रदेश, राजस्थान (2), उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र (2) के छह प्राथमिक स्कूल अध्यापक-शिक्षकों को तथा मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और महाराष्ट्र के चार माध्यमिक स्तर के अध्यापक-शिक्षकों को प्रदान किए गए। विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक-शिक्षा परिषद् के पाठ्यक्रम को लागू किए जाने का काम चलता रहा।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की "किशन और जादू का रथ" नामक फिल्म को प्रतिष्ठित "रेड रिबन अवार्ड" मिला। यह पुरस्कार न्यूयार्क के एजुकेशनल फिल्म लायब्रेरी एसोसिएशन द्वारा 1980 में आयोजित अमेरिकन फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट फ़िल्म के अवसर पर मिला।

शिक्षण साधनों में, परिवेश, लैम्पों और सूर्यग्रहण पर फिल्मों का परीक्षण/मूल्यांकन हुआ। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने जनसंख्या-शिक्षा पर टेप-स्लाइडें, अंधे बच्चों के लिए श्रव्य टेपें, शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर टेप-स्लाइड्स सिस्टम और ग्रैफिक्स तथा लचीलेपन पर फिल्में भी बनाईं।

शिशु अध्ययन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने लगभग सभी राज्यों व संघ क्षेत्रों में खिलौना बनाने की राज्य-स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं जिन में प्रथम, द्वितीय और अनेक सांत्वना पुरस्कार दिए गए। राज्य-स्तर की प्रतियोगिताएँ आगे चलकर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हुईं जहाँ तीन सर्वश्रेष्ठ प्रथम पुरस्कारों के अलावा तीन सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। इस प्रतियोगिता में रद्दी माल से शिक्षाप्रद खिलौने बनाने वालों को पुरस्कृत किया गया।

राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी इक्कीसवीं बार, सदा की तरह जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिन समारोह के अवसर पर नवम्बर 1980 में तीन मूर्ति भवन में की गई। इसमें 500 से अधिक छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया और लगभग 200 प्रदर्श दिखाए गए।

पाठ्यक्रम-विकास में, विशेषज्ञ दलों की अनेक बैठकें, उन क्षेत्रों की पहचान के लिए जहाँ परिषद् को अनुसंधान और विकास करने चाहिए, की गईं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के **क्षेत्र-एककों** ने, 6 से 14 वर्ष के स्कूल न जाने वाले या जाना छोड़ चुके बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए बने अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने में अपना विनम्र योग दिया। इसके अलावा नवाचार और प्रयोगधर्मिता के लिए माध्यमिक स्कूलों में प्रायोगिक परियोजनाओं को स्वीकृत कराने में भी उनका हाथ रहा था।

रा० शै० अ० और प्र० परिषद् के **विस्तार कार्यक्रमों** में संयुक्त राष्ट्र दिवस और मानव अधिकार दिवस को मनाना था। "यूनाइटेड नेशंस : ह्वाट इट डज़" नामक अंग्रेज़ी पुस्तिका भी प्रकाशित की गई।

भविष्य की दिशाएँ

परिषद् को जो उपलब्धियाँ हुई हैं उन्हें बचाए रखने की हर कोशिश होनी चाहिए। पर साथ ही यह भी ज़रूरी है कि परिषद् यह भी समझे कि उसे अभी कहाँ-कहाँ पहल करनी है। इस दृष्टि से अनेक ऐसे क्षेत्रों की पहचान हो गई है जहाँ परिषद् को अभिनव परिवर्तन वाले बड़े काम करने हैं। ऐसे काम हैं—

—यूनिसेफ़ की सहायता से प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा के प्रायोगिक कार्यक्रमों को इस दृष्टि से हाथ में लेने का निर्णय कि ऐसी शिक्षा शिशुओं को स्कूल जाने के लिए तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

—विशेष शिक्षा के लिए अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का काम, विशेष कर इस दृष्टि से कि विभिन्न विकलांगताओं से पीड़ित बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतों को सामान्य स्कूल परिवेश में कैसे पूरा किया जाए।

—सन् 1982 के प्रारंभ में जिस भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाना है, उसके द्वारा प्रदत्त संचार-सुविधाओं का शैक्षिक उद्देश्यों से इस्तेमाल करने के लिए अपेक्षित संस्थानिक तंत्र।

—लड़कियों में शिक्षा प्रचार की गति को रोकने वाले कारकों की पहचान करने के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े आठ राज्यों का वृहद सर्वेक्षण करने का निर्णय।

—शिशुओं की शिक्षा पर वंचनाओं के प्रभावों को पहचानने के लिए, विशेषज्ञों के परिसंवादों का आयोजन ताकि यह पता चल सके कि विकलांगों की शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ पहले अनुसंधान करना है, और अधिगम विकलांगता की प्रकृति, कारण और परिमाण-आकार की पहचान।

—क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षा-कोर्सों का आलोचनात्मक मूल्यांकन ताकि अभिनव परिवर्तन लाने वाले, कुशल और निष्ठावान अध्यापकों के निर्माण के लिए ऐसे कोर्सों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके।

3

प्रारंभिक शैशवकाल की शिक्षा

किसी भी बच्चे के विकास में उसके शैशवकाल का कितना महत्व होता है, इस तथ्य को ध्यान में रख-कर परिषद् प्रारंभिक शैशवकाल की शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यकलाप करती है। इन कार्यों का मुख्य केन्द्र बिंदु यह होता है कि भारतीय शिशु के विकास की प्रक्रिया को समझने-सराहने को सुकर बनाया जाए, प्रारंभिक शैशवकाल की शिक्षा और शैक्षिक सामग्री के रूप में देसी उपा-गमों का विकास किया जाए, स्कूल-पूर्व की शिक्षा के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए, जो कार्यकलाप हो रहे हैं उनका मूल्यांकन किया जाए और खिलौनों, चित्रों, पुस्तकों, श्रव्य टेपों आदि जैसी शिशुओं की सामग्री

का विकास किया जाए। वर्ष के दौरान जो कार्यक्रम किए गए, उनकी चर्चा नीचे के अनुच्छेदों में की जा रही है।

प्रशिक्षण

अफ़गानिस्तान, भूटान और मालदीव द्वीपसमूह के शिक्षकों को शैशवकालीन शिक्षा में प्रशिक्षण की सुविधाएँ प्रदान की गईं। प्रशिक्षण 21 जनवरी 1981 को शुरू हुआ। प्रशिक्षण में प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा का एक थियरी कोर्स था, कम खर्च वाली खेल सामग्री का निर्माण था और था पढ़ाने का अभ्यास। कार्यक्रम में इनके अलावा दिल्ली, बड़ोदा, अहमदाबाद, कोसवड, बम्बई, मद्रास और बंगलोर की यात्राएं भी शामिल थीं।

बिहार, उड़ीसा और सिक्किम में, आदिवासी और सुदूर एकांत के स्थलों से आने वाले प्रारंभिक प्राथमिक शिक्षकों और स्कूल पूर्व के शिक्षकों के लिए कम खर्च वाली शिक्षण सामग्री के विकास के निमित्त राज्य-स्तर के तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए। उड़ीसा के 21 (मार्गदर्शक और अधीक्षक) प्रतिभागियों ने सितंबर 1980 में हुई एक कार्यगोष्ठी में भाग लिया। यह कार्यगोष्ठी कोरापुत के आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले स्कूल-पूर्व शिक्षकों के लिए थी। प्रतिभागियों को स्कूल पूर्व शिक्षा की पद्धतियों और कम खर्च वाली सीधी-सादी खेल सामग्री के निर्माण और इस्तेमाल में अनुकूलित किया गया।

गंगटोक में स्कूल-पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए एक छह-दिवसीय कार्यगोष्ठी 18 से 23 सितंबर 1980 तक आयोजित की गई जिसमें इकतीस प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों में अप्रशिक्षित प्राथमिक-पूर्व स्तर के शिक्षक, आइ० सी० डी० एस० स्टाफ़ और क्रेश कार्मिक थे जिन्हें स्कूल-पूर्व शिक्षा की पद्धतियों और अभ्यासों में, तथा कम खर्च वाली खेल सामग्री के निर्माण और इस्तेमाल में अनुकूलित किया गया। यह कार्यगोष्ठी सिक्किम सरकार के शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण विभाग के सहयोग से आयोजित की गई थी।

राँची के होली शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र में, 12 से 17 नवंबर 1980 तक एक कार्यगोष्ठी आयोजित की गई जो बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाली बाल सेविकाओं के लिए थी। 35 महिलाओं ने बच्चों के लिए कम खर्च वाले सीधे-सादे खेलों और खेल सामग्री पर हुई इस छह दिवसीय कार्यगोष्ठी में भाग लिया।

अध्यापक-शिक्षकों के लिए राज्य स्तर के दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक उत्तरप्रदेश के लिए, दूसरा आंध्रप्रदेश के लिए आयोजित किए गए। आंध्रप्रदेश के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम हैदराबाद की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में 4 से 18 दिसंबर 1980 तक हुआ जिसमें शिक्षा महाविद्यालयों और प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के 17 लोगों ने और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के 7 लोगों ने—कुल 24 प्रतिभागियों ने—भाग लिया। इसी तरह इलाहाबाद

के राज्य शिक्षा संस्थान में, 15 दिनों के लिए; प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा पर राज्य स्तर का प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। इन कोर्सों का उद्देश्य प्रतिभागियों को शिशु विकास की आधुनिक प्रवृत्तियों और प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा में उनके इस्तेमाल से परिचित कराना था। कोर्स की विषय वस्तु का मुख्य केन्द्र बिंदु था—प्रारंभिक शैशव-कालीन शिक्षा का महत्व, कार्यक्रम नियोजन और शिशु विकास के विविध पक्ष। अन्य गति-विधियों के साथ कोर्स में भ्रमण, फिल्म शो, विचार-विमर्श और विशेष भाषणों का भी प्रबंध किया गया था। कार्यक्रम का एक उल्लेखनीय पहलू यह था कि इसमें सृजनात्मक नाटक, सृजनात्मक कलाएँ, संगीत, खेल, कठपुतली नाटक और शिशुओं के भाषा-विकास के लिए व्यावहारिक कार्यकलाप भी थे।

'स्कूल की तैयारी' विषय में एक अनुकूलन कार्यक्रम, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों या राज्य शिक्षा संस्थानों के कर्मचारियों को अनुकूलित करने के लिए, 28 से 30 अक्तूबर 1980 तक रा० शै० अ० और प्र० परिषद् में किया गया। यह स्कूल की तैयारी के उस किट से सम्बद्ध था जो उन शिशुओं के लिए बनाया गया है जो बिना किसी स्कूल-पूर्व-शिक्षा के कक्षा I में चले जाते हैं। पन्द्रह राज्यों/संघ क्षेत्रों के सोलह प्रति-भागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। हर प्रतिभागी को स्कूल की तैयारी का एक एक किट दिया गया। इस किट में सीखने के कार्यकलाप से सम्बद्ध शिशुओं के लिए गाने, खेल, कहानियाँ आदि हैं जिन्हें शिशुओं के लिए स्कूल के शुरू के छह सप्ताहों में आयोजित करना है।

जम्मू और कश्मीर राज्य के सामाजिक कल्याण निदेशालय के सहयोग से अछाबल में 6 से 12 अगस्त 1980 तक एक सात-दिवसीय कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया जो आँगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए था। कार्यगोष्ठी का विषय था--शिशु-विकास और शिशुओं के लिए कम खर्च वाली सीधी-सादी खेल सामग्री। कार्यगोष्ठी में 58 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

दिल्ली के राज्य शिक्षा संस्थान की प्रार्थना पर, दिल्ली के नर्सरी प्रशिक्षण संस्थानों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए, तीन-दिवसीय अनुकूलन कोर्स का आयोजन, 28 से 30 अगस्त 1980 तक रा० शै० अ० और प्र० प० में किया गया। इस कोर्स का उद्देश्य था—कक्षा II तक हिन्दी, अंग्रेज़ी, गणित, और परिवेश अध्ययन (विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन) पढ़ाने की विधि में अध्यापक-शिक्षकों को अनुकूलित करना।

महाराष्ट्र के कर्मा के चिल्ड्रेन्स एजुकेशन सेंटर के दो कर्मचारियों को प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा में 23 से 29 जुलाई 1980 तक प्रशिक्षित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उन्हें विविध प्रकार की स्कूल-गतिविधियाँ और खेल सामग्रियाँ दिखाई गईं। उन्हें आई० आई० टी० नर्सरी स्कूल में प्रशिक्षुता-प्रशिक्षण दिया गया।

अरविंद स्कूलों के अध्यापकों के लिए भाषा-विकास पर, 10 अक्तूबर 1980 को एक कार्यगोष्ठी दिल्ली के मदर्स स्कूल के नए अहाते में हुई। इस कार्यक्रम में 27 प्रतिभागी आए। कार्यक्रम में शामिल था—शिशु के भाषा-विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों पर एक संक्षिप्त भाषण, विभिन्न पद्धतियों का निदर्शन, किस्सा गोई, खेल, कठपुतली नाटक आदि; और कहानी सुनाने का चार्ट, बातचीत का चार्ट, फ्लैनेलग्राफ़, चित्रमय कहानी, और कठपुतलियों जैसी सामग्री का निर्माण।

अनुसंधान

कक्षा I और II में दाखिल हुए, हानि में रहने वाले बच्चों के लिए घरेलू हस्तक्षेप की सम्भाव्यता का अध्ययन इस दृष्टि से शुरू किया गया कि स्कूल और घर का कार्मिक सम्बन्ध स्थापित किया जा सके। आशा की जाती है कि यह अध्ययन शिशु-केन्द्रित उपागम का अनुसरण करने में शिक्षकों की मदद करेगा और घरों में मिलने वाली खेल तथा भाषा-विकास की सुविधाओं की महत्ता समझने में माता-पिता की सहायता करेगा क्योंकि स्कूल में बच्चों को मिलने वाली उपलब्धि पर इसका प्रभाव पड़ता है। परिणामों को विश्लेषित किया जा रहा है और आशा की जाती है कि यह अध्ययन कुछ ही महीनों में पूरा हो जाएगा।

प्रारंभिक शैशवकाल की शिक्षा की देश में चल रही परियोजनाओं का अध्ययन करने के लिए अध्यापकों, अध्यापक-शिक्षकों और अन्य कर्मियों को यात्रा-अनुदान के रूप में सदैव की भाँति सहायता प्रदान की गई। छह अध्ययन पूरे हो चुके हैं और उनकी परियोजना-रिपोर्ट दे दी गई है। ये हैं—

—अधो-सुविधा-प्राप्त बच्चों के लिए प्रारंभिक शैशवकालीन शिक्षा-कार्यक्रमों का अध्ययन।

—उड़ीसा और मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में बालवाड़ी।

—विभिन्न प्रकार की पूर्व-प्राथमिक शिक्षा-प्रणालियों की अनुदेशीय सामग्री में अभिनव परिवर्तन और पाठ्यक्रम।

—बंगाल का शिशु-साहित्य।

—पूर्वी भारत के 'मिशनरीज़ ऑफ़ चैरिटी' का अध्ययन।

—4 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्वी भारत में संग्रहालयों की शैक्षिक सम्भाव्यता का मूल्यांकन।

विकासात्मक कार्य

परिषद् के शिशु अध्ययन एकक की एक महत्वपूर्ण परियोजना है—देसी खिलौनों की पहचान और स्कूल-पूर्व के शिशुओं की शिक्षा के लिए उनका इस्तेमाल। परियोजना का

उद्देश्य है—स्थानीय स्तर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध रद्दी के सामान से शिक्षाप्रद खिलौने बनाने की कला को बढ़ावा देना ताकि इस कला के प्रति शिक्षकों में रुचि बढ़े और शिशुओं को ऐसे अनुभव मिलें जिनसे वे कुछ सीख सकें।

इस परियोजना के पहले कदम के रूप में राज्य-स्तर की प्रतियोगिताएँ हुईं जिन्हें परिषद् के विभिन्न क्षेत्र सलाहकारों ने अपने-अपने राज्य में आयोजित किया। प्रतियोगिता में आई प्रविष्टियों को तीन निर्णायकों की एक समिति ने जाँचा-परखा और विजेताओं को नगद पुरस्कार के साथ-साथ योग्यता की सनद भी दी गई। पुरस्कार वितरण के अवसर पर हर राज्य या संघ क्षेत्र ने एक एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया।

परियोजना का दूसरा कदम राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित करने का होता है। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के दिल्ली स्थित मुख्यालय में 19 से 21 फरवरी 1981 तक हुई। इसमें राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने वाले 13 प्रतियोगी सम्मिलित हुए। प्रतियोगियों ने तुरन्त खिलौने बनाकर दिखाए। तीन निर्णायकों की एक समिति ने अपनी कसौटी पर कस कर निर्विवाद रूप से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार घोषित किए। तीन सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए। अंतिम दिन एक खिलौना प्रदर्शनी भी हुई जिसमें पुरस्कृत खिलौनों को रखा गया। इसी दिन पुरस्कार-वितरण समारोह भी हुआ।

शिशु-विकास पर एक राष्ट्रीय परिसंवाद 11 से 13 मार्च 1981 तक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के दिल्ली स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। परिसंवाद का उद्देश्य था—शिशु-विकास के क्षेत्र में होने वाले शोध-अनुसंधान की जानकारी एकत्र करना और फिर उसे फैलाना। परिसंवाद में लगभग 25 पर्चे पढ़े गए जिनके विषय थे—स्वास्थ्य और पोषण, सामाजिक-संवेगात्मक विकास, प्रारंभिक शैशवकाल की शिक्षा और भविष्य के अनुसंधान के लिए निर्देशन की आवश्यकता आदि। परिसंवाद में इस पर भी विचार-विमर्श हुआ कि पोषण और स्वास्थ्य, बाल-चिकित्सा, मनोविज्ञान, शिशु-विकास और शिक्षा जैसे विषयों पर अंतर-विषयी अनुसंधान की कितनी सम्भावना है। भारत के विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के शिशु-विकास, मनोविज्ञान, बाल-चिकित्सा, पोषण एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा विषयों के लगभग पचीस विद्वान इस तीन-दिवसीय परिसंवाद में सम्मिलित हुए।

प्रस्तावित नई पुस्तक "शिशु विकास पर विचार-गोष्ठी" पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय परिषद् के मुख्यालय में 24 और 25 अक्तूबर 1980 को एक कार्यगोष्ठी आयोजित की गई। विभागीय शैक्षणिक सदस्यों के अलावा सात विशेषज्ञों ने इस कार्यगोष्ठी में भाग लिया। चूँकि भारतीय आधार सामग्री पर आधारित शिशु-मनोविज्ञान की पुस्तकों की कमी है, इसलिए विशेषज्ञों ने इस प्रकार की पुस्तक की आवश्यकता को समझा और उसकी रूप-

रेखा, संरचना तथा विषय-सामग्री का पर्यालोचन किया। विशेषज्ञों ने इस प्रस्तावित पुस्तक के लिए लेखकों के नाम भी सुझाए और उस तरीके के बारे में सलाह दी जिसमें इसके अध्यायों को लिखा जाना है।

सामग्री का विकास

शिशुओं के लिए समुचित क्रम वाली मनोरंजक सामग्री के अभाव को देखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने यूनिसेफ़ के वित्त-पोषण पर एक शिशु माध्यम प्रयोगशाला बनाई थी। इस प्रयोगशाला का विशिष्ट उद्देश्य 3 से 8 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के लिए सस्ती, अनौपचारिक, प्रभावी, शैक्षिक और मनोरंजक सामग्री को ढूंढ़ना या बनाना है ताकि ऐसी जानकारी, निपुणता और अभिवृत्ति को पुरअसर तरीके से संप्रेषित किया जा सके जो उनकी संभावनाओं को बढ़ा देगी। शिशु माध्यम प्रयोगशाला की उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि शिशुओं के लिए अधिगम (सीखना) को अधिक रोचक-आनन्दप्रद तथा सार्थक बनाने में माध्यम के इस्तेमाल के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा हो गई है। किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा से यह बात और भी साबित हो जाती है।

जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उनमें से एक खेल-सामग्री के विकास का है। इस परियोजना का लक्ष्य यह दिखाना है कि स्थानीय रूप से उपलब्ध सस्ते सामान और पारम्परिक खिलौनों से किस प्रकार से प्रभावी तरीके से शिशु सीख सकता है। परियोजना में राज्य में उपलब्ध खेल-सामग्री और खेलों का व्यवस्थित सर्वेक्षण करना, इन खिलौनों की शैक्षिक सम्भावनाओं का पता लगाना और शिक्षकों के लिए पुस्तकें तैयार करना, खिलौनों में क्या सुधार किए जा सकते हैं यह सुझाना, और स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से नए खिलौने बनाना शामिल है।

सन् 1980 में यह परियोजना मध्यप्रदेश, जम्मू व कश्मीर, आंध्रप्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उड़ीसा और केरल में चल रही थी। सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, सूचनाओं को संकलित किया गया और अध्यापकों के लिए पुस्तकें तैयार की गईं। उड़ीसा और केरल में सर्वेक्षण हो रहा है और शीघ्र ही पूरा किया जाएगा। जो पुस्तकें तैयार हो गई हैं उन्हें प्रकाशन के लिए भेजा जा रहा है। मध्यप्रदेश की खेल-सामग्री पुस्तक हिन्दी में तैयार की गई है।

पढ़ने में बच्चों की रुचि जगाने के लिए और अच्छी तरह पढ़ना सीखने के लिए, नौ चित्र-पुस्तकें तैयार की गई हैं। इनको अच्छी तरह से चित्रित किया गया है और ये उन बच्चों के लिए बोल कर पढ़ने वाली हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते, साथ ही प्रारंभिक प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए ये शुरुआत की रीडरों का काम करेंगी। इन पुस्तकों में अभि-

भावकों और शिक्षकों के लिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं जिनकी सहायता से वे पुस्तकों का इस्तेमाल कर सकेंगे। उन्हें ऐसे सम्बद्ध कार्यकलाप के सुझाव भी दिए गए हैं जिन्हें आयोजित करके बच्चों में भाषा-विकास को बढ़ाया जा सकता है। अभी तक दो पुस्तकें छपी हैं। बाकी छप रही हैं। चित्र-पुस्तकों की माला में हिन्दी में दस और पुस्तकें भी तैयार हो रही हैं जिनमें आकृति की परिकल्पना को समझाया गया है। इनका लक्ष्य यह है कि बच्चे को उसके परिवेश के उदाहरणों द्वारा इन परिकल्पनाओं से परिचित कराया जाए। रंगों की सभी पुस्तिकाएँ और आकार की दो पुस्तिकाएँ छप चुकी हैं।

शिशुओं के खेलों का एक संग्रह तैयार किया गया है। इन खेलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है—माँ और शिशु के खेल, स्कूल-पूर्व के शिशुओं के खेल, और प्राथमिक स्कूल के बच्चों के खेल। इनको फोटोग्राफ़ों से सुसज्जित करके छपने के लिए भेजा गया है। यह प्रकाशन पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के उन शिक्षकों और अभिभावकों के लिए है जिन्हें काम चलाऊ अंग्रेज़ी की पर्याप्त जानकारी है।

ताशों के ऐसे आदर्श रूप भी बनाए गए हैं जिनमें पशु, पक्षी, कीड़े, फल और सब्जियाँ दिखाई गई हैं। कई प्रकार के ऐसे खेल इन ताशों से खेले जा सकते हैं जिनमें वर्गीकरण, संख्या कौशल आदि सिखाना होता है। इनको छापा जा रहा है ताकि इन्हें बच्चों में जाँचा-परखा जा सके।

बच्चों के लिए बोर्ड पर खेले जाने वाले चार ऐसे खेल तैयार किए गए हैं जिनके द्वारा स्वच्छता, पोषण, गिनती और भाषा-कुशलता की धारणाओं को बच्चों में पैदा किया जा सकेगा। 'सफ़ाई की सीढ़ी' और 'गणित खेल' छप चुके हैं। 'सफ़ाई की सीढ़ी' में बोर्ड पर ऐसे चौकोर खाने बने हुए हैं जिनमें से कुछ पर सफ़ाई के सिद्धांत लिखे हुए हैं जैसे—'क्या तुम रोज़ दाँत साफ़ करते हो?', 'क्या तुम नाक में अँगुली डालते हो?' आदि। 'साँप और सीढ़ी' के खेल की तरह बच्चे इसमें सही या गलत आदत के अनुसार सीढ़ी के ऊपर या नीचे उतरते चढ़ते हैं। 'गणित खेल' में चौकोर खाने के रंग से मिलने वाला कार्ड उठाना होता है जिस पर गणित का कोई आसान सवाल लिखा होता है जिसे हल करना होता है।

विभिन्न रुचियों के विषयों पर स्लाइड-सह-टेप प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। इनमें हैं—

—रद्दी सामग्री और कम खर्च वाली सामग्री से खिलौने बनाने की कला में अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के मूल उद्देश्य से सस्ती खेल-सामग्री का निर्माण। नेपाल में हुई 'एपीड' क्षेत्रीय सभा के कार्यक्रम के अनुवर्ती कार्य के रूप में इसे विकसित किया गया था।

—नर्सरी स्कूलों के विभिन्न कार्यकलापों पर शिक्षकों के लिए स्कूल-पूर्व गतिविधियों पर स्लाइड-टेप प्रोग्राम।

—"सागर तट पर बच्चे" मद्रास के मछुआरों के बच्चों की रोज़ की गतिविधियाँ दिखाता है।

निम्नलिखित स्लाइड-टेप प्रोग्रामों पर काम हो रहा है—वृक्ष, पानी के खेल, सामाजिक जागरूकता।

शिशु माध्यम प्रयोगशाला का श्रव्य-टेप कार्यक्रम दो उद्देश्यों से काम करता है—(i) स्थिति जैसी भी है, उसका सर्वेक्षण और शिशुओं के लिए प्रसारणों की उपयुक्तता का मूल्यांकन; तथा (ii) 3 से 8 वर्ष के शिशुओं के लिए रेडियो-कार्यक्रमों के आदर्श रूपों का निर्माण।

सन् 1980 में पुणे, राजकोट, बँगलोर और जलंधर में रेडियो-अनुश्रवण-समितियाँ बनी थीं। आकाशवाणी के इन केन्द्रों से नन्हें-मुन्नों (3 से 8 वर्ष के) लिए प्रसारित होने वाले प्रोग्रामों को तीन महीनों तक अनुश्रवित किया गया है। इन प्रोग्रामों पर बच्चों की प्रतिक्रियाओं को एक प्रपत्र पर रेकार्ड किया गया। यह पाया गया कि अपेक्षित श्रोताओं के लिए ये प्रोग्राम ठीक नहीं हैं।

इस वर्ष रेडियो कार्यक्रमों के तेरह आदर्श रूप तैयार किए गए हैं। ये पन्द्रह मिनट की कैपसूलों के रूप में हैं। हरेक में एक कहानी, एक गीत, एक खेल और कुछ बातचीत है जो बच्चों की रुचि के विषयों पर हैं। विभिन्न पशु और उनकी आवाज़ें, रंग, रसोई के औज़ार और सामान, तथा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ जैसे विषयों पर टेपों के कार्यक्रम तैयार किए जा चुके हैं। इनका मूल्यांकन भी हो चुका है।

4

पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक का निर्माण

पाठ्यक्रम का विकास करना और अनुदेशीय सामग्री का निर्माण करना ऐसे कार्य हैं जिनके प्रति परिषद् को काफ़ी चिंता रहती है। पाठ्यक्रम के रूप में परिषद् एक ऐसी वृहद् रूपरेखा विकसित करती है जो राज्य सरकारों और स्कूल/माध्यमिक शिक्षा बोर्डों को अपने पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं के निर्माण में सहायता पहुँचाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और केंद्रीय विद्यालय संगठन से संबद्ध स्कूलों के लिए भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने पाठ्यपुस्तकें बनाई हैं।

पाठ्यक्रम का विकास

पाठ्यक्रम के नियोजन, विकास, कार्यान्वयन, समीक्षा और नवीनीकरण से संबद्ध रियोजनाओं को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् हाथ में लेती है। इस त्र में लागू किए गए कुछ कार्यक्रमों की चर्चा नीचे लिखे अनुच्छेदों में की जा रही है।

कूल पाठ्यक्रम का प्रभावी इस्तेमाल

परियोजना का लक्ष्य है किसी शिशु के विकास की अवस्थाओं पर आधारित और ाठ्यक्रम के पारंपरिक और विकास-आधृत माडल के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित ाठ्यक्रम के प्रतिरूपों का निर्माण करना। परियोजना अब प्रायोगिक अवस्था में पहुँच ुकी है। सन् 1980-81 के दौरान नीचे लिखी पुस्तिकाएँ प्रकाशित की गईं—

—प्राथमिक स्तर पर अध्यापन और अधिगम के लिए परिवेश के इस्तेमाल की विधियाँ (हिंदी में)

—छात्र-विकास का मूल्यांकन।

—छात्र-विकास-मूल्यांकन का मानदंड।

—प्राथमिक स्कूल का पाठ्यक्रम और कलाएँ।

शिक्षा के विकासात्मक उद्देश्यों, शिशु के मनोविज्ञान और अध्यापन-अधिगम-विधियों के संदर्भ में पाठ्यक्रम-विश्लेषण को भी पूरा किया जा चुका है। आगामी प्रायोगिक अवस्था में इस्तेमाल के लिए संसाधन-सामग्री के निर्माण का कार्य भी इसके साथ अव तैयार है।

पाठ्यक्रमों को पुरअसर तरीके से लागू करने के लिए सार्थक कार्यकलाप

इस संदर्भ में, स्कूली कार्यकलापों की संभावनाओं और उस कार्यकलाप को करने की विधियों के पहचान का कार्य हो चुका है। इस प्रकार 'सह-पाठ्यक्रमीय कार्यकलाप' की अप्रासंगिक नित्यचर्या के रूप में जो कुछ यों ही हो जाता है, उसे स्कूली पाठ्यक्रम का अविभाज्य अंग बनाया जा सकेगा और पाठ्यक्रम को प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करने के उपकरण के रूप में उसको प्रयुक्त किया जा सकेगा। प्रातःकालीन सभा, सामान्य बैठकें, विशेष दिवसों के समारोह आदि जैसे कार्यकलापों को उनकी शैक्षिक संभावनाओं और सामाजिक प्रासंगिकता के संदर्भ में विश्लेषित और समय-सारणी में शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार उनके द्वारा बच्चों की शिक्षा को पूरा करने वाले स्वस्थ स्कूली परिवेश का सृजन हो सकेगा। "गतिविधियों का कैलेंडर" और "पाठ्यक्रम को पुरअसर तरीके से लागू

करने के लिए सार्थक कार्यकलाप" पर अध्यापकों के लिए पुस्तक बनाने के उद्देश्य से कार्य-कलापों की जाँच प्रक्रिया हो रही है।

विभिन्न राज्यों में माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम-भार की तुलना

यह परियोजना एक ऐसी समस्या से संबंधित है, जिसने अभी हाल में अभिभावकों, छात्रों व शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया है और बड़ी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम-भार के अंगों की पहचान और उनके मूल्यांकन के लिए समुचित उपकरणों का निर्माण 1980-81 के दौरान पूरा किया जा चुका है। हरियाणा, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा के राज्यों तथा दिल्ली के संघ क्षेत्र में आधार-सामग्री के संकलन का कार्य राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् शुरू करने वाली है।

शारीरिक शिक्षा में पाठ्यक्रम का निर्माण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्मित 'दस वर्षीय स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम : एक रूपरेखा' में तथा 'दसवर्षीय स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम' पर श्री ईश्वरभाई जे० पटेल की समीक्षा समिति में की गई सिफ़ारिश के बाद, अगस्त 1978 में परियोजना ने काम करना शुरू किया। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य 10+2 की शिक्षा-प्रणाली के साथ शारीरिक शिक्षा को जोड़ने के विचार से शारीरिक शिक्षा के पाठ्य-क्रम को पुन: नया करना रहा है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को सुधारने के पीछे यह सिद्धांत रहा है कि कार्यक्रम को सभी छात्रों के लिए होना चाहिए न कि केवल कुछ चुने छात्रों के ही लिए।

समीक्षाधीन वर्ष में नीचे लिखा काम हुआ—

—'शारीरिक शिक्षा : कक्षा I से X तक के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप' नामक प्रलेख को छाप कर सभी राज्य शिक्षा विभागों और विभिन्न शारीरिक शिक्षा विशेषज्ञों को भेजा गया कि उनकी टिप्पणी मिल सके और वे राज्यों में उसे लगाने के लिए उचित कदम उठा सकें।

—कक्षा V से X तक के छात्रों को योगासन सिखाने वाली एक निर्देशिका को छपने के लिए भेजा गया। आशा है वह शीघ्र छप जाएगी।

—कक्षा I से V तक के लिए शारीरिक शिक्षा पर एक अध्यापक पुस्तिका को मिमियोग्राफ़ कराके विशेषज्ञों की सेवा में भेजा गया।

—कक्षा VI से X तक के लिए शारीरिक शिक्षा पर एक अध्यापक निर्देशिका का प्रारूप तैयार किया गया है।

—उच्चतर माध्यमिक (+2) स्तर के सभी छात्रों के लिए वैकल्पिक विषय और अनिवार्य कार्यकलाप दोनों के रूप में शारीरिक शिक्षा का प्रारूपपाठ्यक्रम विकसित किया गया है।

औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा में कलाओं की भूमिका को बढ़ाना

यह एक अनुसंधान-सह-विकास की परियोजना है जिसका लक्ष्य है—कक्षा में कलाओं के अध्यापन-अधिगम की विधि को व्यवस्थित रूप से विकसित करना। परियोजना का एक विशिष्ट उद्देश्य कलाओं को अन्य विषयों के साथ प्रभावशाली अधिगम प्रक्रिया के लिए एकीकृत करना है। पारंपरिक तरीके की तुलना में प्रक्रिया के तरीके से कलाओं के शिक्षण पर बल दिया गया है।

अभी तक मुख्यत: चार क्षेत्रों में काम किया गया है—

—सृजनात्मक कलाओं के अनुभव को प्राथमिक स्कूल के पाठ्यक्रम से संबद्ध करना।

—स्कूल-पाठ्यक्रम में कलाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए माध्यम और सामग्री।

—विभिन्न कलाओं को 'प्रक्रिया अनुभव तरीके' से पढ़ाने के लिए अध्यापक-अनुकूलन-कार्यक्रम।

—कलाओं के मूल्यांकन की विधि।

परियोजना को एक सैद्धांतिक रूपरेखा और मार्गदर्शी रेखाएँ उपलब्ध कराने के लिए, एक पुस्तिका भी प्रकाशित की गई है जिसका नाम है, "कलाएँ और प्राथमिक-स्कूल-पाठ्यक्रम"।

शिक्षा के विभिन्न सोपानों पर कलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारूप-पाठ्यक्रम का विकास

इस परियोजना के अंतर्गत, कक्षा I से X तक के लिए सन् 1978 में बने, कलाओं के पाठ्यक्रम के प्रारूप की समीक्षा की गई और उसे अंतिम रूप दिया गया। सारे संसार में कला-शिक्षा की अधुनातन प्रवृत्तियों पर आधृत एक सैद्धांतिक रूप रेखा का निर्माण किया गया है। इस सिद्धांत की विशिष्ट विशेषता यह है कि विविध कलाओं के लिए प्रक्रिया-अनुभव विधि को अपनाया गया है जिसे छह वर्षों में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विकसित किया है। कक्षा I से V तक के लिए यह संश्लिष्ट कला-कार्यक्रम बच्चों के सृजनात्मक अनुभवों पर आधारित है जो दृश्य और निष्पादित की जाने वाली कलाओं से संबद्ध है। कक्षा VI से X तक के लिए दृश्य कलाओं और निष्पादित की

जाने वाली कलाओं के कार्यक्रम अलग से उपलब्ध कराए गए हैं, साथ ही अध्यापन-अधिगम और प्रेरणार्थक अनुभवों तथा कलाओं में मूल्यांकन की विधि के बारे में अध्यापकों के लिए संकेत भी हैं।

विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कला के कार्यक्रम को जोड़ना

कला-शिक्षा के लिए नई समस्याओं और विषयों को जन्म देने वाली व्यावसायिक धारा विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता और उच्च श्रेणी के तकनीकी प्रशिक्षण को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए, +2 स्तर की स्कूली शिक्षा के बारे में प्रासंगिक विशेष समस्याओं और विषयों को पहचान लिया गया है। अब तक व्यावसायिक कला कोर्सों के लिए तरीके को बना लिया गया है और शैक्षणिक धारा के लिए दृश्य कला के कोर्सों के प्रथम प्रारूप का निर्माण कर लिया गया है। कला के कार्यक्रमों को लागू करने की गहन विधि के बारे में भी सोच लिया गया है। कला-अभिमुखी व्यावसायिक कोर्सों और केंद्रिक सौन्दर्य बोध वाले कार्यक्रमों को विकसित करने के बारे में महत्वपूर्ण सिफ़ारिशें की गई हैं, विशेष कर "विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से कला के कार्यक्रम को जोड़ने" वाले संदर्भ में।

शिक्षकों और छात्रों के लिए कलाओं में अनुदेशीय सामग्री तैयार करना

इस परियोजना के अंतर्गत 'कलाओं में दस-वर्षीय स्कूल-पाठ्यक्रम' को लागू करने से संबद्ध नीचे लिखी पुस्तिकाएँ तैयार की गई हैं, उनकी समीक्षा की गई है और उन्हें अंतिम रूप दिया गया है।

—सृजनात्मक कला के कार्यकलापों के लिए सामग्री/माध्यम, और तकनीकें/विधियाँ।

—प्राथमिक स्तर पर सृजनात्मक नाटक।

—प्राथमिक और मिडिल स्तरों पर कठपुतलियों एवं शिशु-नाटकों का निर्माण।

—चित्रकला की कहानी।

विभिन्न पुस्तिकाओं के लिए अपेक्षित कला-कृतियों के मुद्रण और समुचित सचित्र सामग्री के उत्पादन और निरीक्षण के बारे में सुझाव दिए गए हैं।

कलाओं के शिक्षण के लिए शिक्षक-संदर्शिका का निर्माण

कला के पाठ्यक्रम को लागू करने में अध्यापकों की सहायता की दृष्टि से, कलाओं के शिक्षण लिए एक शिक्षक-संदर्शिका बनाने का काम शुरू किया गया है। दृश्य-कलाओं के शिक्षण के लिए शिक्षक-संदर्शिका का एक फारम अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है और आगे के काम को लिखने के लिए अधिकारी लेखकों को कहा जाना है।

पाठ्यक्रम-विकास-कार्यान्वयन के विविध पहलुओं से संबंधित समस्याएँ और विषय

ऐसी समस्याओं और विषयों को संक्षेप में "हमारे पाठ्यक्रम का वास्ता" नामक प्रबंध में चार वर्गों में लिख लिया गया है।

(i) पाठ्यक्रम और छात्रों का विकास।

(ii) पाठ्यक्रम और राष्ट्रीय विकास।

(iii) पाठ्यक्रम और शिक्षा का सार्वजनीकरण।

(iv) पाठ्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन में शिक्षकों की प्रतिभागिता।

ऊपर गिनाए गए पहलुओं पर जो विचार-विमर्श हुए उनकी पुष्टि में दस पर्चे तैयार किए गए जिन्हें इस प्रबंध में दिया गया है।

पाठ्यक्रम-संसाधन केन्द्र

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा बनाए गए केन्द्र ने देश के और विदेशों के पाठ्यक्रम-माध्यमों से महत्वपूर्ण सूचनाएँ और सामग्री एकत्र की है। उनको इस तरह से व्यवस्थित किया गया है कि संदर्भ सामग्री के रूप में ज़रूरत पड़ने पर उन्हें देखा जा सके। बीच-बीच में विशेष पुस्तिकाएँ भी निकाली जाती रही हैं। सन् 1980-81 के दौरान "स्कूल पाठ्यक्रम की संदर्भ सामग्री" और "स्कूल पाठ्यक्रम की चुनी हुई सटीक संदर्भ सूची" नामक दो पुस्तिकाएँ केंद्र ने प्रकाशित कीं।

पाठ्यक्रम-समाचार

"करीक्यूलम बुलेटिन—पाठ्यक्रम दल का चतुर्मासिक प्रकाशन" के तीन अंक सन् 1980-81 के दौरान प्रकाशित किए गए। इसका अधुनातन अंक एक विशेषांक है जो "छठी पंचवर्षीय योजना और स्कूली पाठ्यक्रम" से संबंधित है। इसमें छठी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में गिनाए गए योजना अवधि के शैक्षिक विकास के उद्देश्यों को संदर्भित किया गया है।

स्कूली-पाठ्यक्रम का प्रभावशाली उपयोग

पाठ्यक्रम-विकास और कार्यान्वयन के संदर्भ में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा राज्यों के सहयोग को भी पाठ्यक्रम दल ने अपना योग दिया है। स्कूली शिक्षा के कई बोर्डों की पाठ्यक्रम-समितियों में इसने रा० शै० अ० और प्र० प० का प्रतिनिधित्व किया है। नागालैंड के शिक्षा निदेशालय के संपर्क में भी पाठ्यक्रम दल रहा है जिससे कि स्कूल-पाठ्यक्रम को सुधारने में उनकी मदद की जा सके। स्कूल-पाठ्यक्रम के प्रभावशाली उपयोग के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा बनाई गई मार्गदर्शी रेखाओं पर काम शुरू करने के लिए कई राज्यों ने अपनी दिलचस्पी प्रकट की है।

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी

सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी के क्षेत्र में, रा० शै० अ० और प्र० परिषद् मुख्य रूप से पाठ्यक्रम के विकास और पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य अनुदेशीय सामग्री के निर्माण के कार्य करती है। यह राज्यों में प्रमुख व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण एवं अनुकूलन के कार्यक्रम आयोजित करती है। ऐसी अनुसंधान परियोजनाएँ भी हाथ में ली जाती हैं जिनका सीधा प्रभाव कक्षा-शिक्षण के सुधार पर पड़ता है। इसके कार्यकलाप कक्षा I से XII तक के सम्पूर्ण स्कूल स्तर को समाहित करते हैं।

सामाजिक विज्ञानों में काम करने के इसके मुख्य क्षेत्र हैं—परिवेश-अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और नागरिकता-शिक्षा, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान। मानविकी में रा० शै० अ० और प्र० परिषद् मातृभाषा और द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेज़ी और संस्कृत के लिए काम करती है। कला-शिक्षा, नैतिकता की शिक्षा, योग, जनसंख्या-शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय परिषद् काम करती है।

पाठ्यक्रम का विकास

—स्कूल स्तर के वर्तमान विषयों में शामिल किए जाने के लिए, उत्पादकता-शिक्षा के पाठ्यक्रम को रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने अंतिम रूप दिया। इसका उद्देश्य यह है कि स्कूली बच्चों में काम के प्रति उचित प्रवृत्ति पैदा हो सके।

—कक्षा IX-X के लिए मातृभाषा के रूप में हिंदी के पाठ्यक्रम के संशोधन का कार्य विभाग ने एक सतत चलने वाली गतिविधि के रूप में हाथ में लिया।

—माध्यमिक स्कूल स्तर के शिक्षकों का निर्माण करने वाले शिक्षा महाविद्यालयों में इस्तेमाल कराने के उद्देश्य से अर्थशास्त्र पढ़ाने की विधियों की एक पाठ्यचर्या विकसित की गई।

भाषाओं के पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने स्कूल पाठ्यक्रम के लिए भाषाओं की एक सलाहकार समिति नियुक्त की है जिसके निम्नलिखित दायित्व हैं—भाषा कोर्सों में पाठ्यक्रम के विकास और कार्यान्वयन के लिए किए गए काम की समीक्षा करना, स्कूल स्तर पर समुचित पाठ्यक्रमों के विकास के लिए सामान्य नीति निर्धारित करना, अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र बताना, समुचित अनुदेशीय सामग्री बनाने के तरीकों पर विचार करना और स्कूलों में भाषा-शिक्षण की विधियों को सुधारने के उपाय ढूँढ़ना ।

एक उपसमिति भी गठित की गई है । इस उपसमिति ने निम्नलिखित तीन कार्य-दलों के माध्यम से कार्य करना शुरू कर दिया है—

—प्राथमिक भाषाओं में पाठ्यक्रमों की समीक्षा और विकास ।

—द्वितीय और तृतीय भाषा में पाठ्यक्रम की समीक्षा और विकास ।

—विधियाँ और सामग्रियाँ ।

पाठ्यपुस्तकों का निर्माण

—मातृभाषा के रूप में हिंदी के क्षेत्र में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने 'बाल-भारती भाग पाँच' नामक कक्षा V की पाठ्यपुस्तक की पाण्डु-लिपि को अंतिम रूप प्रदान किया । इस पुस्तक के निर्माण के साथ रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने कक्षा I से V तक की अपनी बाल भारती पुस्तक माला की कड़ी पूरी कर ली । द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी क्षेत्रों में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् अरुणाचल प्रदेश के साथ काम करती रही है । वहाँ के प्राथमिक स्कूलों के लिए अरुण भारती पाठ्य पुस्तक माला के विकास का कार्य चलता रहा है । इस वर्ष परिषद् ने कक्षा II के लिए अरुण भारती भाग II की पाण्डुलिपि को अंतिम रूप दिया है ।

—अंग्रेज़ी के क्षेत्र में, अपनी पाठ्यपुस्तक माला 'स्टेप्स टु इंग्लिश' पर परिषद् काम करती रही । कक्षा IX के लिए 'स्टेप IV' की पाण्डुलिपि को अंतिम रूप दिया गया ।

—संस्कृत के क्षेत्र में, परिषद् ने 'काव्य तरंगिणी' को संशोधित किया, जो अब कक्षा XI की पाठ्यपुस्तक है । पहले यह कक्षा XII के लिए थी ।

पाठ्यपुस्तकों से इतर अनुदेशीय सामग्री का विकास

विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में निम्नलिखित शैक्षणिक और अन्य प्रकार की सामग्री विकसित की गई है—

—'बाल भारती भाग पाँच की अभ्यास पुस्तिका' नाम की **हिंदी** अभ्यास पुस्तक; अरुणाचल प्रदेश में प्रयुक्त की जाने वाली 'अरुण भारती की अभ्यास पुस्तिका भाग II' कक्षा दो के लिए।

—हैदराबाद के केन्द्रीय अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा संस्थान के सहयोग से निर्मित कक्षा नौ की **अंग्रेज़ी** सप्लीमेंटरी रीडर और एक अभ्यास पुस्तक।

—'रीड फ़ॉर प्लेज़र' पुस्तक माला के अंतर्गत कक्षा VII और VIII के लिए बुक IV और बुक V बनाई गई हैं।

—केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्कूलों के लिए कक्षा V और VI की **संस्कृत** अभ्यास पुस्तकें तथा नीचे लिखी पाँच सहायक पुस्तकों की पाण्डुलिपियाँ—

—हितोपदेश (कक्षा IX और X)

—पंचतंत्र (कक्षा IX और X)

—भवभूति और उनके नाटक (कक्षा XI और XII)

—भास और उनके नाटक (कक्षा XI और XII)

—दण्डी और उनका दशकुमार चरित (कक्षा XI और XII)

—**इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र**—रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने पटियाला में, राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए निकष एवं उपकरणों के विकासार्थ एक कार्यगोष्ठी आयोजित की। पाठ्यपुस्तकों के गहन मूल्यांकन के लिए अपेक्षित उपकरणों के विकास की दिशा में भी कार्यगोष्ठी ने सोचा।

—एक कार्यगोष्ठी की गई जिसमें सन् 1857 से 15 अगस्त 1947 तक के हमारे स्वाधीनता-संग्राम के विविध कीर्ति स्तंभों पर 75 नामिकाएँ बनाई गईं।

—सहायक पुस्तक 'परिवेशीय बचाव और संसाधनों की रक्षा' बनाई गई।

—स्कूली पाठ्यक्रमों में संयुक्त राष्ट्र और उसकी गतिविधियों का परिचय देने के लिए, यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद-कार्यगोष्ठी के सिलसिले में एक पुस्तक बनाई गई—'संयुक्त राष्ट्र और वह क्या करता है'। अंग्रेज़ी पुस्तक भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल द्वारा विमोचित की गई।

—हिंदी लेखक प्रेमचंद की जन्म शताब्दी के अवसर पर नीचे लिखी तीन पुस्तकों की पाण्डुलिपियां अंतिम रूप से बनाई गईं—

(i) प्रेमचंद (हिंदी)

(ii) प्रेमचंद (उर्दू)

(iii) प्रेमचंद : ग्रामीण भारत की आवाज़ (अंग्रेज़ी)

सहायक पठन सामग्री बनाने की कई परियोजनाएँ, जिन्हें पहले शुरू किया गया था, इस वर्ष भी चलती रहीं। इनमें से मुख्य हैं—

—कक्षा XI और XII के लिए भूगोल में प्रयोगात्मक कार्यों की अध्यापक पुस्तक।

—बच्चों में चित्र-पठन-कुशलताएँ विकसित करने के लिए भूगोल में चित्र पुस्तक।

—कक्षा शिक्षण में सहायक भूगोल के चार्ट।

—दिल्ली प्रशासन के कुछ स्कूलों के सहयोग से "नागरिक शास्त्र में प्रयोगात्मक कार्यकलापों की रूपरेखा" पर अध्यापक-पुस्तक।

प्रशिक्षण और अनुकूलन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण कार्य किए, उनमें से एक है—अंग्रेज़ी के संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण। हैदराबाद के केंद्रीय अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा संस्थान के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कक्षा IX के कोर्स बी की पाठ्य सामग्री बनाई है। ये किताबें जुलाई 1981 से दिल्ली प्रशासन के हाई स्कूलों में और उन स्कूलों में पढ़ाई जानी हैं जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन से संबद्ध हैं। पैंसठ स्नातकोत्तर शिक्षकों को दो दलों में छः छः दिनों के लिए 16 फरवरी से 28 फरवरी 1981 तक अनुकूलित किया गया। ये शिक्षक संसाधन व्यक्तियों के रूप में काम करेंगे। इनसे अपेक्षा है कि ये दिल्ली के 3000 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों को अनुकूलित कर सकेंगे।

यह कार्यक्रम ब्रिटिश काउंसिल, दिल्ली प्रशासन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हैदराबाद के केंद्रीय अंग्रेज़ी और विदेशी भाषा संस्थान के सहयोग से आयोजित किया गया। शिक्षकों को अनुकूलित करने में जिस विधि का प्रयोग किया गया उसमें प्रवाचन, ट्यूटोरियल्स, परिसंवाद और प्रदर्श-पाठ शामिल हैं। ब्रिटिश काउंसिल के दो विशेषज्ञों—एक यू० के० से आए हुए और दूसरे उसके दिल्ली कार्यालय के—ने इन कार्यक्रमों में परामर्शदाताओं के रूप में कार्य किया। हर प्रतिभागी को ब्रिटिश काउंसिल ने उपयुक्त संदर्भ साहित्य भेंट किया।

हिंदी और सामाजिक अध्ययन के शिक्षकों को अनुकूलित करने में अरुणाचल प्रदेश की सहायता की गई। महाराष्ट्र राज्य और गोआ, दमन तथा दीव के संघ शासित क्षेत्र के 45 अध्यापक-शिक्षकों के लिए, पुणे के भारतीय शिक्षा संस्थान में, पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से भूगोल में एक अनुकूलन कार्यक्रम चलाया गया।

उदयपुर के विद्या भवन टीचर्स कालेज में अध्यापक-शिक्षकों के लिए, भाषा प्रयोगशाला के उपयोग और साफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में एक आठ-दिवसीय अनुकूलन कोर्स आयोजित किया गया। इसमें सोलह टेप-स्क्रिप्ट बनाई गईं।

अनुसंधान परियोजनाएँ

दिल्ली के ऐसे स्कूलों में जहाँ अंग्रेज़ी माध्यम नहीं है, कक्षा VI के अंग्रेज़ी-शिक्षण में प्रयुक्त की जाने वाली विधियों व तकनीकों का सर्वेक्षण-कार्य हाथ में लिया गया। इस सर्वेक्षण से यह पता चल सकेगा कि वास्तव में शिक्षक किस विधि से पढ़ा रहे हैं और उस विधि को इस्तेमाल करने के क्या कारण हैं। इससे यह भी मालूम हो सकेगा कि पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाली अलग-अलग विधियों का छात्रों की उपलब्धियों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

संस्कृत पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होने वाली विधियों का पता लगाने के लिए, दिल्ली के यों ही चुन लिए गए 32 स्कूलों में एक सर्वेक्षण किया गया। इसके लिए प्रश्नावली और साक्षात्कार विधि का प्रयोग किया गया।

विशेष परियोजनाएँ

राष्ट्रीय परिषद् ने प्रौढ़ शिक्षा और नैतिकता की शिक्षा के क्षेत्रों में भी कार्य ले रखा है। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, हरियाणा के शहरी इलाकों में काम करने वाले अपढ़ प्रौढ़ों के लिए, साक्षरता और अन्य संबद्ध निपुणताओं में क्रमिक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग के सहयोग से जो अनुदेशीय सामग्री बनाई गई है उसमें ये चीज़ें हैं—एक प्राइमर, एक शिक्षक-संदर्शिका, एक अभ्यास-पुस्तिका और एक कहानी-संग्रह। मध्य प्रदेश के लिए भी, राज्य शिक्षा विभाग के सहयोग से नव-साक्षरों के लिए पाठ्यक्रम बनाया गया गया है। इस राज्य के लिए जो सामग्री बनी है, वह है—एक पाठ्यपुस्तक, एक अध्यापक-संदर्शिका और एक अभ्यास पुस्तिका।

मध्यप्रदेश के पंचायत कल्याण-विभाग के सहयोग से, जबलपुर में अधीक्षकों के लिए, दो सप्ताहों वाला एक अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जेल में रहने वालों को साक्षर बनाने के लिए दिल्ली के तिहाड़ जेल में, प्रौढ़ शिक्षा के शिक्षकों के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम किया गया। लंबी सज़ा काट रहे कैदियों में से ही इन शिक्षकों का चुनाव किया गया था।

नैतिकता की शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में मूल्य बदलते जा रहे हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय परिषद् ने कई कार्यक्रम शुरू कर रखे हैं। भारतीय राज्यों और संघ क्षेत्रों में नैतिकता की शिक्षा की वर्तमान स्थिति के अध्ययन को पूरा किया जा चुका है। शिक्षा में सामाजिक,

नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर 28 से 30 मार्च 1981 तक एक परिसंवाद आयोजित करने के लिए रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने नई दिल्ली के श्री अरविंद केंद्र को वित्तीय सहायता दी।

राज्यों और अन्य माध्यमों को सहयोग

भाषाओं और सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्रों में खुले स्कूलों की योजना के लिए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने सहायता प्रदान की।

विभिन्न सामाजिक विज्ञानों और भाषाओं में शिक्षण की विधियों पर भाषणों का प्रबंध करके परिषद् ने नई दिल्ली के ब्लाइंड रिलीफ़ असोसिएशन के प्रशिक्षण महाविद्यालय को सहायता देने का काम जारी रखा।

विज्ञान-शिक्षा

देश के स्कूल स्तर पर विज्ञान और गणित शिक्षा की गति को तेज़ करने की प्रमुख भूमिका निभाने का काम रा० शै० अ० और प्र० परिषद् करती रही। परिवेश की संरक्षा और विज्ञान-शिक्षण के लिए उसका संसाधन के रूप में इस्तेमाल लोगों के ध्यान का केंद्र बना। इस प्रयास में स्वास्थ्य एवं पोषण-शिक्षा को भी उनका प्राप्य उचित भाग मिला। इस क्षेत्र की प्रमुख गतिविधियाँ थीं—नई पाठ्यक्रमीय सामग्री का निर्माण, शिक्षक संदर्शिका का निर्माण, प्रायोगिक कार्य के लिए सामग्री, परीक्षण विषयों का निर्माण, और राज्यों के प्रमुख कार्मिकों का प्रशिक्षण।

परिवेश-अध्ययन

परिवेश-अध्ययन के क्षेत्र में मुख्य कार्य था—प्रमुख कार्मिकों का प्रशिक्षण ताकि वे इस बात को समझ सकें कि स्थानीय परिवेश को किस प्रकार खोज की मूल निपुणताओं के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। परियोजना के अंतर्गत विकसित की गई स्लाइडों और कैसेट टेपों के एक सेट को हर उस राज्य/संघ क्षेत्र को उपलब्ध कराया गया जो इस परियोजना में भाग ले रहे थे।

स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा

स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा के क्षेत्र में, "अच्छी सेहत कैसे बनाएँ" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई जो प्रारंभिक शिक्षकों के लिए है। इस पुस्तिका में प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को वह जानकारी और मार्गदर्शी रेखाएँ दी गई हैं जिनसे स्कूली बच्चों में अपेक्षित आदतों का विकास किया जा सकता है और उनमें बेहतर आदतों, बेहतर निपुणताओं, बेहतर वातावरण और बेहतर भोजन की समझ पैदा की जा सकती है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शिक्षकों की सहायक पुस्तक का विकास

सेवा में लगे शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक सहायक-पुस्तक बनाई गई जिसमें सन् 1979 में हुई परिवेशीय शिक्षा की आठ कार्यगोष्ठियों की मुख्य सिफ़ारिशों को शामिल किया गया है।

पाठ्य-सामग्री और शिक्षक-संदर्शिकाओं का विकास

नीचे लिखी पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण-संदर्शिकाएँ विकास अथवा मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में थीं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है—

विषय	शीर्षक	कक्षा	विकास की अवस्था
सामान्य विज्ञान	माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान भाग I और भाग II	IX—X	पुनर्मुद्रण के लिए संशोधित
,,	शिक्षक-संदर्शिका भाग I	IX	छप रही है
,,	शिक्षक-संदर्शिका भाग II	X	संपादित हो रही है
भौतिकी	टेक्स्टबुक ऑफ़ फ़िज़िक्स फॉर हायर सेकंडरी क्लासेज़	XI—XII	नए संयुक्त संस्करण के लिए संशोधित
,,	टीचर्स गाइड फॉर टेक्स्टबुक ऑफ़ फ़िज़िक्स फॉर हायर सेकंडरी क्लासेज़—पार्ट I	XI	प्रकाशित
,,	उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए भौतिकी की पाठ्य-पुस्तक भाग I और भाग II	XI—XII	पुनर्मुद्रण के लिए संशोधित
रसायन शास्त्र	टेक्स्टबुक ऑफ़ केमिस्ट्री पार्ट I और पार्ट II	XI—XII	पुनर्मुद्रण के लिए संशोधित
,,	रसायनशास्त्र की पाठ्यपुस्तक भाग I और भाग II	XI—XII	पुनर्मुद्रण के लिए संशोधित
,,	प्रोजेक्ट ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स इन केमिस्ट्री	XI—XII	प्रथम प्रारूप तैयार
,,	कन्सेप्ट सेंटर्ड एक्सपेरीमेंट्स इन केमिस्ट्री	XI—XII	प्रयोग जाँच-परख के लिए तैयार
,,	टेक्स्टबुक ऑफ़ केमिस्ट्री पार्ट I और पार्ट II	XI—XII	कार्यगोष्ठी में मूल्यांकित

विषय	शीर्षक	कक्षा	विकास की अवस्था
जीवविज्ञान	टेक्स्टबुक ऑफ़ बायोलोजी	XI—XII	समीक्षित,
,,	जीवविज्ञान की पाठ्यपुस्तक	XI—XII	संशोधित और परिवर्द्धित
,,	उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तक के लिए शिक्षक-संदर्शिका	XI—XII	संपादित हो रही है
गणित	टेक्स्टबुक ऑफ़ मैथेमैटिक्स पार्ट V	XII	प्रकाशित
,,	गणित की पाठ्यपुस्तक भाग 5	XII	प्रकाशित
,,	गणित की पाठ्यपुस्तक	IV	छपाई के लिए
,,	गणित की पाठ्यपुस्तक की शिक्षक-संदर्शिका	IX	तैयार बन रही है
,,	गणित की पाठ्यपुस्तकें	I—X	पुनर्मुद्रण के लिए संशोधित

राज्यों के प्रमुख कार्मिकों का प्रशिक्षण

10 + 2 प्रणाली की शिक्षा के लिए तैयार की गई नई सामग्री से शिक्षकों/अध्यापक-शिक्षकों/प्रमुख कार्मिकों को सुपरिचित कराने के लिए, विभिन्न विषयों में कई अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनमें प्रमुख हैं—

—राज्यों के प्रमुख कार्मिकों के लिए, एकीकृत विज्ञान का अनुकूलन कार्यक्रम।

—माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए तैयार की गई सामग्री से प्रमुख कार्मिकों और अध्यापक-शिक्षकों को परिचित कराने के लिए जीवविज्ञान पर दो सम्पन्नीकरण कार्यक्रम। रसायन विज्ञान में +2 स्तर पर, रसायन विज्ञान में प्रायोगिक कार्य के लिए, नई कोर्स-सामग्री से राज्यों/संघ क्षेत्रों के प्रमुख कार्मिकों को सुपरिचित कराने के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम।

अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से समन्वय

पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा पर क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा, परियोजना के जन्म से अब तक किए गए कार्य की समीक्षा करने के लिए, यूनेस्को की सहायता से, मई 1980 में एक समीक्षा-कार्यगोष्ठी आयोजित की गई।

ग्रामीण परिवेशों से विज्ञान को जोड़ने वाली अध्यापन-अध्ययन की सामग्री के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी जिसे यूनेस्को ने प्रवर्तित किया, जुलाई 1980 में

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित की गई। अब इस कार्य-गोष्ठी की रिपोर्ट छप चुकी है। इस कार्यगोष्ठी की प्रमुख सिफ़ारिशें हैं—आज उपलब्ध विविध प्रकार की विज्ञान की अनुदेशीय सामग्री की जाँच-परख और कार्यान्वयन पर अधिक बल दिया जाना चाहिए; सभी दृष्टियों से पूर्ण विज्ञान के एक नए पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वर्तमान विज्ञान पाठ्यक्रमों को बदला जा सके न कि संपूर्ण विज्ञान शिक्षा में पैबंद की तरह इक्की दुक्की इकाइयों को ही अदल बदल कर संतोष कर लिया जाए; कार्यक्रमों को इस तरह से बनाया जाना चाहिए कि उन्हें शिक्षक, समाज और प्रयोक्ता पूरे मन से अपना लें, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परियोजनाओं को इस तरह से बनाना चाहिए कि वे अध्यापकों/अधीक्षकों/पाठ्यक्रम निर्माताओं को उचित तरह से प्रेरित करें, अनुकूलित करें और प्रशिक्षित करें।

यूनेस्को के तत्वावधान में, विभाग ने स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में पाठ्यक्रम-विकास पर एक कार्य दल की बैठक भी बुलाई, जिसमें 12 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक के प्रमुख उद्देश्य थे—

—स्वास्थ्य और पोषण की बेहतर शिक्षा के विकास के लिए, पाठ्यक्रमों का विश्लेषण करना।

—बैठक के प्रतिभागियों द्वारा लाई गई आदर्श सामग्री की जाँच करना।

—प्राथमिक स्तर पर पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के परिचय के विशेष संदर्भ में, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार का अध्ययन करना।

—स्वास्थ्य और पोषण से संबद्ध पाठ्यक्रमीय एवं अनुदेशीय सामग्री के लिए मार्ग-दर्शी रेखाएँ सुझाना।

—स्वास्थ्य और पोषण की शिक्षा के कार्यक्रमों के विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में विभिन्न माध्यमों और व्यक्तियों—प्रशासकों, अधीक्षकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और समाज की भूमिका तय करना।

हाथ में ली गई परियोजनाएँ

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) द्वारा स्वीकृत परियोजनाएँ और परिषद् के कर्मचारियों द्वारा हाथ में ली गईं, अभी चल रही अन्य परियोजनाएँ हैं—

—भौतिकी के ओपेन एंडेड प्रयोग।

—परिवेशीय और स्थानीय साधनों का प्रयोग करने वाले प्लांट बेस्ड प्रयोग।

—जीवविज्ञान में आवश्यकता-आधृत और समाजोन्मुखी, स्वयं सीखने वाली सामग्री विकसित करना।

—भौतिकी में शिक्षा की व्यक्तिपरक प्रणाली ।

—भौतिकी में परिकल्पना का ग्रेड प्लेसमेंट ।

—एकीकृत विज्ञान पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन का अध्ययन ।

—दैनिक जीवन की परिस्थितियों के साथ सार्थक जीवन जीने के लिए परिवेश में व्यवस्था की पहचान ।

—+2 स्तर के रसायन शास्त्र के प्रायोगिक कोर्स में छात्रों के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी रेखाएँ विकसित करना ।

प्रकाशित हुए अनुसंधान प्रबंधों में ये शामिल हैं—भौतिकी में ओपेन एंडेड प्रयोग । जीवविज्ञान में प्रयोगशाला-कार्यविधि और प्रयोगशाला उपकरणों का रख-रखाव ।

प्रायोगिक कार्य के लिए परीक्षण-इकाइयों और सामग्री का विकास

'उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए 'भौतिकी' भाग I की परीक्षण-इकाइयाँ छप चुकी हैं और भाग II की बन चुकी हैं । 'उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए जीव-विज्ञान' भाग I और II की परीक्षण-इकाइयाँ बनाई जा चुकी हैं । भाग I की छापी जा चुकी हैं और भाग II की छप रही हैं । कक्षा IX की गणित के लिए प्रश्नों का विकास किया जा चुका है । इन प्रश्नों को प्रश्न बैंक में जाना है । ये छप रहे हैं । कक्षा X के लिए प्रश्न बन रहे हैं ।

राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रदर्शनियाँ

नई दिल्ली के तीन मूर्ति भवन में बच्चों के लिए दसवीं राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी 14 से 21 नवंबर 1980 तक की गई । इस प्रदर्शनी का विषय था, "हमारे परिवेश में विज्ञान" । 25 राज्यों, संघ क्षेत्रों और केन्द्रीय विद्यालय संगठन से आई लगभग 200 पुरस्कृत वस्तुएँ प्रदर्शित की गईं । इस अवसर पर तीन पुस्तिकाएँ भी प्रकाशित की गईं—'राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का एक दशक', 'विज्ञान मॉडल की संरचना और कार्यविधि' तथा 'प्रदर्शों की सूची' ।

राज्य स्तर की प्रदर्शनियाँ आयोजित करने के लिए राज्यों को सहायता प्रदान की गईं । राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियाँ आयोजित करने में होने वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए दो दिनों की एक परिचर्चा की गई । इसमें क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और राज्य स्तर की प्रदर्शनियों के प्रभारी अधिकारियों ने भाग लिया ।

विज्ञान से संबद्ध सूचनाओं और सामग्री का विकीर्णन

विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों के अनेक स्कूलों और संस्थानों ने सामग्री की निरंतर माँग की । माँगने पर निम्नलिखित प्रकाशन भेजे गए—

—कक्षा XI की भौतिकी भाग I की परीक्षण इकाइयाँ।

—कक्षा XI की जीव विज्ञान भाग I की परीक्षण इकाइयाँ।

—कक्षा XI की भौतिकी भाग I की शिक्षक-संदर्शिका।

—ओपेन-एंडेड एक्सपेरीमेंट्स इन फ़िज़िक्स।

—विज्ञान मॉडलों की संरचना और कार्यविधि—1976, 1978, 1979 और 1980 के चारों अंक।

—बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का एक दशक (सन् 1970 से 1980)।

—1980 की राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी की विवरणिका।

—विज्ञान क्लबों का आयोजन—एक परिचय पुस्तिका।

—स्वास्थ्य और पोषण की पाठ्यक्रम-दर्शिका।

—कक्षा IX और X के उपकरणों की सूची।

पाठ्यक्रम-सामग्री का मूल्यांकन

एक और प्रमुख कार्यकलाप उत्पादित पाठ्यक्रम-सामग्री के मूल्यांकन के लिए प्रारंभिक प्रयास करना था। मूल्यांकन प्रविधि पर एक गहन दस्तावेज़ विकसित किया गया। दस्तावेज़ में बताई गई राह पर मूल्यांकन करने का काम आगामी वर्ष हाथ में लिया जाएगा।

व्यावसायिक शिक्षा

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम/परियोजनाएँ/कार्यकलाप इन क्षेत्रों में आते हैं—अनुसंधान, प्रशिक्षण, विकास, विस्तार और परामर्श। व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का क्षेत्र-क्रम से ब्यौरा और उनके स्कूली शिक्षा के गुणात्मक सुधार पर प्रभाव को नीचे संक्षेप में दिया जा रहा है—

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर संसाधन पुस्तक

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के विविध पहलुओं पर चार भागों में एक संसाधन पुस्तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने बनाई है। इस पुस्तक में वे कार्यकलाप गिनाए गए हैं जिन्हें स्कूल कर सकते हैं। साथ ही वे मार्गदर्शी रेखाएँ भी दी गई हैं जिन पर चल कर व्यावहारिक रूप से इन कार्यकलापों को सामान्य स्कूल स्थितियों में किया जा सकता है। इन कार्यकलापों को वे सभी स्कूल शुरू कर सकते हैं जहाँ स० उ० का० की व्यवस्था है। यह पुस्तक हिन्दी में भी तैयार की गई है। छप जाने के बाद पुस्तक के चारों भागों को विभिन्न राज्यों के प्रमुख व्यक्तियों और स० उ० का० के शिक्षकों को बाँटा जाएगा ताकि स० उ० का० के कार्यक्रमों को समुचित रूप से कार्यान्वित किया जा सके। विभिन्न

कार्यकलापों को चलाने के लिए अपेक्षित तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करने में यह पुस्तक स० उ० का० के शिक्षकों की मदद करेगी। पुस्तक सहज सरल भाषा में लिखी गई है और बहुत अच्छी तरह से चित्रित की गई है। पुस्तक स्कूलों के लिए बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी जहाँ लगभग सभी शिक्षक स० उ० का० के कार्यक्रमों को सफलता से लागू करने की जिम्मेदारी सँभालना चाहेंगे।

प्रमुख व्यक्तियों के लिए स० उ० का० का अनुकूलन

हालाँकि समाजोपयोगी उत्पादक कार्य को प्राथमिक स्तर से ही स्कूल-पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग माना जाता रहा है, और बहुत से राज्यों ने अपने स्कूलों में इस कार्यक्रम को शुरू भी करवा दिया है, फिर भी एक प्रकार का वैचारिक भ्रम अभी भी चल रहा है। इसके दार्शनिक और वैचारिक पक्षों को स्पष्ट करने के लिए, रा० शै० अ० और प्र० प० ने मैसूर, भुवनेश्वर, सोलन और कोचीन में, प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए स० उ० का० पर अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए। प्रतिभागी राज्य शिक्षा विभाग और स्कूलों से लिए गए। कार्यक्रम के विविध अंगभूतों से परिचित कराने के साथ-साथ, प्रतिभागियों को स० उ० का० के कुछ कार्यकलाप आयोजित करने को प्रोत्साहित किया गया जिससे कि उनका आत्मविश्वास बढ़ सके और वे विपरीत स्थितियों वाले स्कूलों में भी समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के कार्यकलाप आयोजित कर सकें।

स० उ० का० में परामर्श और सहयोग

राज्य शिक्षा संस्थानों, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न एककों और बहुत से स्कूलों जैसे विभिन्न संस्थानों/माध्यमों को रा० शै० अ० और प्र० प० ने अपनी विशेषज्ञता और सहयोग दिया। इसके लिए परिषद् ने अपने शैक्षणिक कर्मचारियों को विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिनियुक्त किया।

शिक्षा के व्यावसायीकरण का आलोचनात्मक अध्ययन

महाराष्ट्र में शिक्षा के व्यावसायीकरण को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिस रूप में लागू किया गया है, उसका आलोचनात्मक अध्ययन नवम्बर-दिसम्बर 1980 में, राज्य के लगभग बीस संस्थानों में किया गया। इस अध्ययन की रिपोर्ट से यह पता चल जाएगा कि योजना को लागू करने में क्या कमियाँ रह गई हैं, और उनके प्रकाश में भविष्य के लिए योजना को सुधारा जाएगा।

"व्यावसायिक कोर्स (1977-79) लेने वाले विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि का अध्ययन"

नामक एक लेख के रूप में, एक अनुसंधान रिपोर्ट विकसित की गई है।

व्यावसायिक शिक्षा में अल्पकालिक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम

व्यावसायिक शिक्षकों के ज्ञान को अधुनातन बनाने के लिए और उनकी कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से, रा० शै० अ० और प्र० प० ने मई-जून 1980 के दौरान महाराष्ट्र में पाँच और तमिलनाडु में दो अल्प-कालिक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जिनमें कृषि और प्रौद्योगिकी के व्यावसायिक क्षेत्रों को लिया गया था। ये कार्यक्रम उच्च और विशेष विद्यार्जन के संस्थानों में किए गए थे। प्रशिक्षुओं को उनके व्यावसायिक कोर्सों के व्यावहारिक पक्षों में निष्णात करने के लिए अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त की गई थीं। प्रशिक्षण के ये कार्यक्रम लगभग एक महीने तक चले थे। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षक अब स्वयं विशेषज्ञ होकर आत्मविश्वासपूर्वक अपने छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर सकेंगे।

व्यावसायिक शिक्षा में पाठ्यचर्या का संशोधन

किसी भी व्यावसायिक कोर्स की पाठ्यचर्या को उस क्षेत्र की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के प्रति निश्चय ही प्रासंगिक होना चाहिए। व्यवसाय के विभिन्न कामों को कर पाने के लिए जिन अनिवार्य पेशेवर निपुणताओं की आवश्यकता होती है उनका विकास करने में इस पाठ्यचर्या को सक्षम होना ही चाहिए। इस संदर्भ में, व्यावसायिक विषयों की पाठ्यचर्याओं का संशोधन-परिवर्धन बीच-बीच में होते रहना चाहिए। यह संशोधन-परिवर्धन समाज की बदलती ज़रूरतों के अनुरूप होना चाहिए। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, गुजरात के शिक्षा विभाग के सहयोग से रा० शै० अ० और प्र० प० ने अहमदाबाद में एक पाठ्यचर्या-सुधार-कार्यगोष्ठी की। वाणिज्य विषयक चार व्यावसायिक कोर्सों की पाठ्यचर्याओं को संशोधित किया गया। इन संशोधित पाठ्यचर्याओं से अपेक्षा की जाती है कि ये व्यावसायिक प्रशिक्षण का स्तर ऊँचा उठाएँगी और उसे सार्थकता प्रदान करेंगी।

शिक्षा के व्यावसायीकरण का कार्यान्वयन

रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने 'भारत में शिक्षा का व्यावसायीकरण और उसका कार्यान्वयन' नामक एक पुस्तिका तैयार की है। यह पुस्तिका इस योजना की वस्तुस्थिति को उसकी दार्शनिक और वैचारिक पृष्ठभूमि में बताती है। पुस्तिका छप रही है।

व्यावसायिक शिक्षा के अनुकूलन-कार्यक्रम

चूँकि व्यावसायिक शिक्षा के अध्यापक और शैक्षिक संस्थाओं के प्रिंसिपल ही इस योजना को सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि उन्हें शिक्षा के

व्यावसायीकरण की धारणा और उद्देश्य से सुपरिचित करा दिया जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर रा० शै० अ० और प्र० प० ने गुजरात (जनवरी 1981), आंध्रप्रदेश और बिहार (फरवरी 1981) राज्यों में अनुकूलन के कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों के हितकारी परिणामों का असर सम्बद्ध राज्यों में शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के बेहतर आयोजन और कार्यान्वयन पर पड़ेगा, खास कर बिहार में, जहाँ उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अगले शैक्षणिक सत्र से व्यावसायिक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं।

व्यावसायिक शिक्षा में परामर्श और सहयोग

राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, विभिन्न स्कूल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न एकक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् जैसे माध्यमों को विभिन्न अनुकूलन कार्यक्रमों के संचालन में विशेषज्ञता की सहायता देकर शिक्षा के व्यावसायीकरण के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने विविध संगठनों, माध्यमों को सक्रिय सहयोग दिया।

पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभाग और एकक पाठ्यपुस्तकों का निरंतर मूल्यांकन कई दृष्टियों से किया करते हैं। 1980 के दौरान इन दृष्टियों में एक और दृष्टि भी जुड़ गई अर्थात् राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तकों का मूल्यांकन।

राष्ट्रीय परिषद् पाठ्यपुस्तक-मूल्यांकन के विविध कार्यक्रमों में लगी हुई है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जो काम हुआ है उनके बारे में संक्षेप में चर्चा की जा रही है। कार्यकारी समिति के निर्णय के अनुसार, रा० शै० अ० और प्र० प० ने राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से स्कूली पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन की परियोजना हाथ में ली है। सबसे पहले इतिहास और भाषा की स्कूली पाठ्यपुस्तकों की परख की जाएगी। असली मूल्यांकन तो राज्य करेंगे, रा० शै० अ० और प्र० परिषद् पूरे कार्यक्रम को समन्वित करेगी। इतिहास और भाषा की पाठ्यपुस्तकों को मूल्यांकित करने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० ने कामचलाऊ अस्थायी उपकरण और निकष बना लिए हैं। ये कामचलाऊ निकष राज्यों को भेजे गए हैं और स्वीकार करने के पूर्व इनको विद्वज्जन ठीक करेंगे।

परिषद् की पाठ्यपुस्तकों की जाँच-परख

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित कक्षा I, II और VI की हिन्दी पाठ्यपुस्तकों की जाँच-परख के लिए 15 स्कूल (अधिकांश केन्द्रीय विद्यालय) चुने गये थे। अध्यापकों के लिए बने हर पाठ के वास्ते शिक्षण-पूर्व और शिक्षणोत्तर उपकरणों द्वारा आधार-सामग्री संकलित की गई। तीसरा उपकरण बच्चों के लिए था जिसे

कक्षा में पाठ को पढ़ा लेने के बाद प्रयुक्त किया जाना था। कक्षा VI और II की पाठ्यपुस्तकों पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और कक्षा I की पाठ्यपुस्तक की रिपोर्ट अभी बन रही है।

औपचारिक शिक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का अध्ययन करने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। सामाजिक परिवर्तन और शैक्षिक विकासों के संदर्भ में, पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन को यह जाँचती है।

विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त हुई भाषा की बोधगम्यता का अध्ययन भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शुरू किया है। प्रारम्भ में केवल प्राथमिक स्तर तक के लिए ही यह कार्य होगा। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं - किसी विशेष कक्षा के बच्चों द्वारा बोली या लिखी जाने वाली भाषा की तुलना में पाठ्यपुस्तकों की भाषाई विषयवस्तु का मूल्यांकन, पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की बोधगम्यता नापने के लिए उपकरणों का विकास, तथा पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषिक सामर्थ्य के मानकों की स्थापना।

सबसे पहले इस अध्ययन को एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में राजस्थान के कक्षा III के बच्चों और पाठ्यपुस्तकों के लिए शुरू किया गया है। सामाजिक विज्ञानों और मातृभाषा की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की बोधगम्यता शहरी और देहाती बच्चों में काफ़ी अलग-अलग पाई गई। साथ ही यह भी पाया गया कि पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की बोधगम्यता लड़कों और लड़कियों में अलग-अलग नहीं थी। किसी बड़े पैमाने पर परियोजना को शुरू करने के पहले, यह सोचा गया है कि कुछ केस स्टडी की जाए। तीन प्रबंधों को लिख लिया गया है जिनके शीर्षक हैं—(i) पाठ्यपुस्तक-बोधगम्यता का आदर्श; (ii) पाठ्यपुस्तकों की बोधगम्यता पर सटीक संदर्भ-सूची; और (iii) बोधगम्यता के मापन की धारणा की प्रवृत्तियाँ।

सन् 1980-81 के दौरान बाईसवीं राष्ट्रीय बाल-साहित्य पुरस्कार-प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता के लिए 15 भाषाओं की 800 प्रविष्टियाँ आईं। मणिपुरी और कश्मीरी भाषा में कोई प्रविष्टि नहीं आई। बाईसवीं राष्ट्रीय पुरस्कार-प्रतियोगिता में 14 भाषाओं के लेखकों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह और एक परिचर्चा, नई दिल्ली के परिषद्-मुख्यालय में 27 से 31 मार्च 1981 तक हुई। शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती शीला कौल ने पुरस्कार दिए।

हिन्दी बाल-साहित्य के मूल्यांकन के लिए एक कार्यगोष्ठी की गई। रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा बनाए गए निकष पर 1200 से अधिक पुस्तकों को परखा गया। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए क्रमशः तीन संदर्भ साहित्य सूचियाँ बन रही हैं।

5

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण

संविधान का निदेश है कि 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क, अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा मिलेगी। इस निदेश को जल्दी से जल्दी पूरा करने की दृष्टि से प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण सर्वोच्च प्राथमिकता वाला कार्य है। परिणामस्वरूप इस दिशा में शीघ्र सफलता की विधियों के विकास की ओर परिषद् का ध्यान गया है और उसके प्रयास भी अब उसी ओर हो रहे हैं। राज्य सरकारों को प्रासंगिक तरीकों को अपनाने में मदद देने वाले अनुभव मुहैया कराने की दृष्टि से अनेक प्रायोगिक परियोजनाएँ शुरू की गई हैं।

प्राथमिक शिक्षा : व्यापक-उपागम

यूनिसेफ़-सहायता-प्राप्त परियोजना 'प्राथमिक शिक्षा का व्यापक उपागम' (केप) के माध्यम से स्कूल न जाने वाले बच्चों, जल्दी स्कूल छोड़ देने वाले और कुछ समय बाद स्कूल छोड़ने वाले बच्चों तक पहुँचा जा सकता है। छह से चौदह वर्ष की उम्र वाले ऐसे बच्चों को सार्थक शिक्षा दिलाना इसके प्रयासों में आता है जो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से वंचित हैं।

परियोजना के उद्देश्य

इस परियोजना के प्रमुख उद्देश्य हैं—औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में एक अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था का विकास करना, विशेषकर देहात में रहने वालों के लिए और उन बच्चों के लिए कार्य करना, जो औपचारिक या अनौपचारिक दोनों में से किसी भी शिक्षा प्रणाली में हैं।

9 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप, प्रासंगिक और समस्या प्रधान अधिगम-सामग्री (अधिगम युक्तियों) के पर्याप्त मात्रा और प्रकार में विकास एवं जाँच-परख द्वारा इन उद्देश्यों को पूरा किया जाएगा; इस अधिगम सामग्री को प्राथमिक अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों में या प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के सेवाकालीन शिक्षा-कार्यक्रमों में प्रविष्ट किया जाएगा। अधिगम स्थितियों की बहुलता के कारण सुविधावंचित विद्यार्थियों के लिए उनके विकास में यह अधिगम सामग्री अधिगम प्रसंगों के रूप में होगी।

परियोजना की प्रमुख अवस्थाएँ

परियोजना की बुनियादी गतिविधियाँ निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में की जा रही हैं—

- **प्रथम अवस्था** — पर्याप्त संख्या में अधिगम-युक्तियों के निर्माण और उत्पादन की ओर ले जाने वाली गतिविधियाँ।
- **द्वितीय अवस्था** — अधिगम केन्द्रों की स्थापना और कार्यविधि से संबंधित गतिविधियाँ।
- **तृतीय अवस्था** — मूल्यांकन केन्द्रों की स्थापना से सम्बद्ध गतिविधियाँ।

परियोजना का कार्यान्वयन

अरुणाचल प्रदेश और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों के साथ इस परियोजना को लागू करने के समझौते किए जा चुके हैं। परियोजना की पहली अवस्था को अमल में लाने का काम 18 राज्यों और 5 संघ क्षेत्रों में अनवरत चल रहा है। जम्मू और

श्मीर, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा दादरा और नागर हवेली एवं लक्षद्वीप संघ क्षेत्रों में परियोजना की गतिविधियाँ अभी शुरू होनी हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के केप समूह के केन्द्रीय स्रोत न्द्रों द्वारा अभी तक किए गए कार्यकलाप इस प्रकार हैं—

—प्राथमिक स्कूल शिक्षकों, अध्यापक-शिक्षकों, अध्यापक प्रशिक्षुओं तथा क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत साधन केन्द्रों (राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों) की परियोजना टीमों के इस्तेमाल के लिए प्रशिक्षण पैकेजों की योजना, विकास और उत्पादन/मुद्रण। तीन प्रशिक्षण पैकेज अब तक छप चुके हैं जिनमें आठ माड्यूल और बाइस कैप्सूल हैं।

—अधिगम-युक्तियों के विकास की विधियों पर क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत साधन केन्द्रों की टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कोर्स व बीस राज्यों और पाँच संघ क्षेत्रों में स्थित राज्य शिक्षा संस्थानों के क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत साधन केन्द्रों की टीम के पचासी सदस्यों को अब तक प्रशिक्षित किया जा चुका है।

—जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पैकेजों का उत्पादन/मुद्रण। एक प्रशिक्षण पैकेज छप रहा है जिसमें दो माड्यूल और पचीस कैप्सूल हैं।

—नमूने की अधिगम-युक्तियों की योजना, विकास और उत्पादन/मुद्रण। अभी तक छह कैप्सूल छप चुके हैं और पचीस कैप्सूल छप रहे हैं।

— अधिगम-युक्तियों की प्रक्रिया के तरीके पर क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत साधन केन्द्रों की टीम के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कोर्स। राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत साधन केन्द्रों की टीम के बीस सदस्यों को इस कोर्स द्वारा प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इस परियोजना में भाग लेने वाले राज्यों और संघ क्षेत्रों द्वारा 31 मार्च 1981 तक किए गए प्रमुख कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है—

—प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों (अ० प्र० स०) के प्रिंसिपलों के लिए अनुकूलन कोर्स। परियोजना के शैक्षणिक और प्रशासनिक पहलुओं पर 755 अ० प्र० संस्थानों के प्रिंसिपलों को अनुकूलित किया जा चुका है।

—अधिगम-युक्तियों के प्रयोग की विधियों पर अ० प्र० स० के अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स। अ० प्र० स० के 3761 अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है।

—एक नए किस्म की प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा के कार्यान्वयन के लिए पायठचर्या-रूपरेखाओं और अनुदेशीय सामग्री के विकास के लिए कार्यगोष्ठी। आठ राज्यों

और एक संघ क्षेत्र के क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत साधन केन्द्रों द्वारा दस कार्यगोष्ठियाँ की जा चुकी हैं। इन कार्यगोष्ठियों में 301 अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया।

—प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम (केप) परियोजना के नियोजन और प्रबंध पक्षों पर जिला स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए अनुकूलन कोर्स। सात राज्यों के जिला स्तर के 379 शिक्षा अधिकारियों को केप परियोजना के नियोजन और प्रबंध पक्षों पर अनुकूलित किया जा चुका है।

—केप परियोजना के नियोजन और प्रबंध पक्षों पर खण्ड स्तर के शिक्षा अधिकारियों के लिए अनुकूलन कोर्स। आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु के खण्ड स्तर के 163 शिक्षा अधिकारियों को अनुकूलित किया जा चुका है।

—अधिगम-युक्तियों के विकास के लिए अ० प्र० स० के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण-उत्पादन मोड का प्रवेश। तेरह राज्यों और चार संघ क्षेत्रों ने प्रशिक्षण-उत्पादन मोड का प्रवेश अ० प्र० स० के पाठ्यक्रम में करा दिया है।

—अ० प्र० स० के अध्यापक-शिक्षकों और अध्यापक-प्रशिक्षुओं द्वारा अधिगम-युक्तियों के प्रारूप (माड्यूल और कैप्सूल के रूप में) का विकास। अ०प्र०स० के अध्यापक-शिक्षकों और अध्यापक-प्रशिक्षुओं द्वारा 17 हज़ार कैप्सूल बनाए जा चुके हैं।

—केप परियोजना के शैक्षणिक और प्रशासनिक पक्षों पर अ० प्र० स० के प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों के लिए अनुकूलन कोर्स। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अ० प्र० स० के 42 प्रिंसिपलों और शिक्षा अधिकारियों को अनुकूलित किया जा चुका है।

—अधिगम-युक्तियाँ विकसित करने के तरीकों पर अ०प्र०स० के अध्यापक-शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कोर्स। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों में स्थित अ० प्र० स० के 48 अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

—अधिगम-युक्तियाँ विकसित करने के लिए शिक्षकों के वास्ते कार्यगोष्टी। चंडीगढ़ में हुई एक कार्यगोष्ठी में चालीस प्राथमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

—अधिगम युक्तियों की प्रक्रिया के लिए कार्यगोष्ठी। बिहार की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित एक कार्यगोष्ठी में तीस माड्यूल बनाए गए।

अनौपचारिक शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लिए अनौपचारिक शिक्षा एक वैकल्पिक विधि के रूप में सामने आई है। राज्यों को प्रासंगिक अनुभव प्रदान करने के ख्याल से, रा० शै० अ० और प्र० परिषद् ने एक प्रायोगिक परियोजना को अमल में लाने का काम शुरू किया। परिषद् ने अपने क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों और क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों के तत्वावधान में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करने के साथ ही, इन केन्द्रों के बच्चों के लिए शिक्षण-सामग्री और शिक्षकों के लिए संदर्शिकाएँ बनाने का काम भी अपने हाथ में लिया है।

इस कार्यक्रम के आवश्यक तत्व हैं—

—पाठ्यक्रम में देहाती, शहरी और जनजातीय बच्चों की समस्याओं को प्रतिफलित करने वाली एक एकीकृत विधि।

—समस्याओं को समझने और उनका विश्लेषण करने में बच्चों का प्रशिक्षण।

—कामचलाऊ साक्षरता और गिनती के ज्ञान के लिए बच्चों का प्रशिक्षण।

—बच्चों को अपने परिवेश के प्रति अनुकूलित करने के लिए साक्षरता और गिनती के ज्ञान का इस्तेमाल।

—शिक्षण के लिए दैनंदिन गतिविधियों का इस्तेमाल।

—केन्द्रीय, राज्य, जिला, खंड और ग्राम स्तर पर कार्मिकों के लिए अनुकूलन-कार्यक्रम का आयोजन।

—आदर्श प्रतिरूपों और अन्य सामग्री का निर्माण।

—मूल्यांकन और पुनर्निवेशन के लिए आंतरिक तंत्र-व्यवस्था।

—कार्यक्रम के प्रतिपादन और कार्यान्वयन के लिए समुदाय की प्रतिभागिता।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने लगभग 238 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र बना रखे हैं। विभिन्न राज्यों के इन केन्द्रों की संख्या नीचे की सारणी से पता चल जाएगी—

राज्य	कौन चलाता है	केन्द्रों की संख्या
1. असम	क्षेत्र सलाहकार, असम	10
	क्षे०शि०म०, भुवनेश्वर	10
2. आंध्र प्रदेश	क्षेत्र सलाहकार, हैदराबाद	10
3. उड़ीसा	क्षेत्र सलाहकार, भुवनेश्वर	10
	क्षे०शि०म०, भुवनेश्वर	10
4. उत्तर प्रदेश	क्षे०शि०म०, अजमेर	4
5. कर्नाटक	क्षेत्र सलाहकार, बंगलोर	10
	क्षेत्रीय शि० म०, मैसूर	10
6. केरल	क्षेत्र सलाहकार, त्रिवेंद्रम	10
7. गुजरात	क्षेत्र सलाहकार, अहमदाबाद	10
	क्षे० शि० म०, भोपाल	10
8. जम्मू एवं कश्मीर	क्षेत्र सलाहकार, श्रीनगर	7
	क्षे० शि० म०, अजमेर	10
9. तमिलनाडु	क्षेत्र सलाहकार, मद्रास	9
10. पंजाब	क्षेत्र सलाहकार, चंड़ीगढ़	8
11. पश्चिम बंगाल	क्षेत्र सलाहकार, पश्चिम बंगाल	10
	क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर	10
12. बिहार	क्षेत्र सलाहकार, पटना	10
	क्षे० शि० म०, भुवनेश्वर	10
13. मध्यप्रदेश	क्षेत्र सलाहकार, भोपाल	10
	क्षे० शि० म०, भोपाल	12
14. महाराष्ट्र	क्षेत्र सलाहकार, पुणे	10
	क्षे० शि० म०, भोपाल	10
15. राजस्थान	क्षेत्र सलाहकार, जयपुर	9
	क्षे० शि० म०, अजमेर	9
	कुल	238

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को सहारा देने के तौर पर अनुसंधान और विकास की अनेक गतिविधियाँ की जा रही हैं। ये हैं—

(i) बच्चों के शब्द भांडार और पाठ्यपुस्तकों के शब्द भांडार का अध्ययन

परिषद् की एक पुरानी परियोजना है—"हिन्दी-प्रदेशों के प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के शब्द भांडार का संग्रह और भाषावैज्ञानिक विश्लेषण"। यह नई परियोजना उसी परियोजना की एक प्रशाखा है। पुरानी परियोजना के परिणामों के आ जाने के बाद यह नई परियोजना शुरू की जाएगी।

(ii) उर्दू के अनौपचारिक शिक्षण के लिए अनुदेशीय सामग्री का विकास (दूसरी अवस्था)

राज्यों के इस्तेमाल के लिए, उर्दू के अनौपचारिक शिक्षण की अनुदेशीय सामग्री बना ली गई है।

(iii) अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का स्थितिपरक अध्ययन

अनौपचारिक शिक्षा के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर चार सर्वेक्षण-उपकरण और प्रश्नावलियाँ बना ली गई हैं। आधार-सामग्री का विश्लेषण किया जा रहा है।

(iv) दूसरे स्तर के संसाधन व्यक्तियों के लिए अनुकूलन कार्यक्रम

संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों के लिए एक अनुकूलन और उत्पादन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में 5 से 7 मार्च 1981 तक किया गया जिसमें 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतिभागियों में सहायक क्षेत्र सलाहकारों और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के सहायक संयोजकों की उपस्थिति भी शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था दूसरी अवस्था के लिए सामग्री बनाना।

(v) अनौपचारिक शिक्षा बुलेटिन

अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को एक दूसरे के कामों से परिचित कराने के लिए यह तय किया गया कि एक बुलेटिन निकाला जाय। इसका नमूना बना लिया गया है और उसे सम्मति के लिए लोगों के पास भेजा गया है। सुझावों के

आधार पर सूचना-संकलन के लिए मार्गदर्शी रेखाएँ बना ली गई हैं जिनके अनुसार बुलेटिन की सामग्री एकत्र की जाएगी ।

सामग्री-उत्पादन

कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ अनुदेशीय सामग्री तैयार कर ली गई थी । वर्ष 1980-81 के दौरान 'नई रोशनी' (देहाती और शहरी लड़कियों के लिए उर्दू प्रवेशिका) की दर्शिका छापी गई थी । निम्नलिखित अनुदेशीय सामग्री छपने के लिए भेजी गई है—

हिन्दी

—हिन्दी प्रवेशिका—'ज्ञान बाती' (लड़कियों के लिए)

—प्रवेशिका—'हम भी पढ़ेंगे' की दर्शिका

—हिन्दी में कारोबारी गणित की एक पुस्तक बन रही है

उर्दू

—'नई किरन'—प्रवेशिका

—'नई किरन' की गाइड

—'नई रोशनी'—प्रवेशिका

—'कारोबारी हिसाब'

—'पढ़ो और बढ़ो'—प्रवेशिका

—'पढ़ो और बढ़ो' की गाइड

शिक्षक-दर्शिका में शामिल विभिन्न विषयों पर उन्नीस चार्ट भी बनाए गए हैं । वे छप रहे हैं ।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की निर्देशिका

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की एक निर्देशिका तैयार कर ली गई है । इसमें केन्द्रों के नाम, खंड का नाम, स्थापना की तारीख, लड़के-लड़कियों की संख्या (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) और कुल बच्चों की संख्या आदि की जानकारी दी गई है । शिक्षकों के बारे में भी जानकारी दी गई है—उनके नाम और पते, उम्र, क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं, योग्यताएँ और अनुभव ।

प्राथमिक पाठ्यक्रम नवीकरण

परियोजना का उद्देश्य

प्राथमिक-शिक्षा-पाठ्यक्रम-नवीकरण की यूनिसेफ़-सहायता-प्राप्त परियोजना को रा० शै० अ० और प्र० प० लागू कर रही है। परियोजना का मुख्य उद्देश्य है—देहाती, जनजातीय और शहरी गरीब इलाकों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं के विशेष संदर्भ में, छह से ग्यारह साल की उम्र के बच्चों के लिए नव परिवर्तन वाले पाठ्यक्रमों का विकास करना। मूल आधार-वाक्य है—शैक्षिक सुविधाओं के प्रसार के साथ पाठ्यक्रम का गुणात्मक सामंजस्य भी होना चाहिए ताकि वह बच्चे की जीवन प्रणाली और उपलब्ध सामाजिक-आर्थिक अवसरों से मेल खा जाए। दूरगामी उद्देश्य है—

प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में प्रायोगिक शैक्षिक कार्यक्रमों में परखे गए नव परिवर्तन वाले विचारों के क्रमिक-प्रवेश के द्वारा प्राथमिक शिक्षा की सार्थकता को बढ़ाना।

परियोजना की मुख्य बातें

परियोजना की कुछ विशिष्टताएँ हैं—

—परियोजना-स्कूलों के शिक्षकों, परियोजना-स्कूलों का निरीक्षण करने वाले अध्यापक-शिक्षकों, राज्य शिक्षा संस्थानों/ राज्य शै० अ० और प्र० परिषदों में स्थित राज्य प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास कोष्ठों के सदस्यों तथा राज्य के अन्य अनुभवी लेखकों/कार्यकर्ताओं के रुचिपूर्वक शामिल होने से पाठ्यक्रम-विकास की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।

—समुदाय के विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा प्रासंगिक पाठ्यक्रम का उद्भव।

—सार्थक रूप से सीखने के लिए परिवेश का उपयोग।

—आर्थिक और सामाजिक रूप से सुविधा-वंचित वर्गों के बच्चों की विशेष ज़रूरतें।

—शैक्षिक कार्यक्रमों में स्थानीय समुदाय का रुचिपूर्वक शामिल होना।

—समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के आयोजन के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग।

परियोजना का कार्यान्वयन

परियोजना रा० शै० अ० और प्र० प० के माध्यम से सन् 1975-76 में शुरू की

गई। प्रथम चरण में 13 राज्यों और 2 संघ क्षेत्रों ने परियोजना में भाग लिया। हर राज्य ने परियोजना के लिए 30 स्कूल चुने। ये स्कूल 3 जिलों में स्थित थे और सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से पर्याप्त विभिन्नताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। सभी आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के थे। चुने गए परियोजना-स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए उनकी बोलियों में प्रासंगिक अनुदेशीय सामग्री और पढ़ाने-पढ़ने की विधियों का निर्माण किया गया।

प्राथमिक-शिक्षा-पाठ्यक्रम-नवीकरण परियोजना के पहले चरण के अनुभवों से बढ़ावा पाकर, इस परियोजना को अब अरुणाचल प्रदेश के अलावा सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में ले जाया गया है। प्रथम चरण वाले राज्यों और संघ क्षेत्रों में परियोजना के क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत अब सौ और स्कूल भी चुन लिए गए हैं। नए राज्यों और संघ क्षेत्रों ने तीस-तीस स्कूल चुने हैं।

विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में परियोजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रसार-चरण के लिए उनके साथ समझौते कर लिए गए हैं। हर क्षेत्र की प्रमुख सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विभिन्नताओं की पहचान कर ली गई है। ऐसी विभिन्नताओं वाले स्कूलों को, परिषद् द्वारा बनाए निकष के आधार पर, परियोजना-स्कूलों के रूप में, चुन लिया गया है।

पाठ्यक्रम विकास के सेल

हर राज्य/संघ क्षेत्र में परियोजना का अनुश्रवण राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्/राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है। हरेक में राज्य प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास का एक सेल (कोष्ठ) बनाया गया है जिसमें तीन चार शैक्षणिक कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार देश भर में राज्य प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास के सेलों का एक जाल सा बिछ गया है। परियोजना स्कूलों के अनेक समूह बनाए गए हैं। हर समूह का पर्यवेक्षण पास में स्थित जूनियर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट द्वारा किया जाता है। इस काम के लिए 183 टीचर ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट या इसी किस्म के अन्य संस्थान (जहाँ टी० ट्रे० इंस्टीच्यूट नहीं है) पहचान लिए गए हैं।

परियोजना के कर्मचारियों का अनुकूलन

सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त आधार-सामग्री के विश्लेषण और प्रक्रिया के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० ने तकनीकी उपकरण बनाए हैं। राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शै० अ० और प्र० प० में परियोजना के कार्य का अनुश्रवण करने वाले परियोजना कर्मचारियों को एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुकूलित किया गया। यह कार्यक्रम 21 से 26 अप्रैल 1981

तक हुआ। कार्यक्रम का प्रधान उद्देश्य यह था कि राज्य/संघ क्षेत्र सर्वेक्षण कार्य वैज्ञानिक विधि से कर सकें और आधार-सामग्री का विश्लेषण प्रभावकारी ढंग से हो सके। इस कार्यक्रम में 25 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 35 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सन् 1980-81 के दौरान लगभग सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य किया गया। 18 राज्यों/संघ क्षेत्रों ने सर्वेक्षण रिपोर्ट परिषद् को भेज भी दी है।

विविधता वाले बहुप्रयोजनी पाठ्यक्रम

प्रसार-चरण के अंतर्गत पाठ्यक्रम-विकास प्रक्रिया का एक विशेष कार्य है—विविधता वाले बहुप्रयोजनी पाठ्यक्रमों का निर्माण। विभिन्न परिवेशों में रहने वाले बच्चों की विशिष्ट शैक्षिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली विभिन्न प्रकार की शिक्षण-सामग्री इसके अंतर्गत आ जाती है। इस कार्य को करने में राज्य पाठ्यक्रम टीमों की मदद के लिए सितम्बर, अक्तूबर और दिसम्बर 1980 में रा० शै० अ० और प्र० प० ने तीन अनुकूलन कार्यक्रम किए। इन कार्यक्रमों में 22 राज्यों/संघ क्षेत्रों ने हिस्सा लिया। परियोजना के प्रथम चरण के दौरान उद्भूत पाठ्यक्रम के मूल्यांकन, सर्वेक्षण के जाँच-परिणाम, न्यूनतम अधिगम सांतत्यक, वर्तमान राज्य पाठ्यक्रम के मूल्यांकन/विश्लेषण के निष्कर्षों ने वह महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया है जिस पर प्रसार-चरण के अंतर्गत नया पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है।

क्रिया-विधि की योजनाएँ

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने जो प्रशिक्षण और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया है, उसी को आधार बना कर राज्य-टीमों ने 1981-82 के लिए अपनी क्रिया-विधि की योजनाएँ बनाई हैं, जो नए पाठ्यक्रमों के विभिन्न चरणों में बँटे कार्यक्रम का विकास और जाँच-परख करेंगी। सामान्यतः राज्य यह कोशिश कर रहे हैं कि मुख्य सामाजिक-आर्थिक और भौगोलिक विभिन्नताओं की ज़रूरतों के अनुरूप विविधता वाले पाठ्यक्रमों के बहुप्रयोजनी सेट बनाए जाएँ।

शिक्षण-सामग्री का मूल्यांकन

परियोजना के प्रथम चरण के अंतर्गत 13 राज्यों व 2 संघ क्षेत्रों में विकसित शिक्षण-सामग्री के मूल्यांकन का काम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपने हाथ में लिया है। संबद्ध राज्यों/संघ क्षेत्रों के राज्य प्राथमिक-पाठ्यक्रम-विकास सेलों को सलाह दी गई थी कि वे राष्ट्रीय परिषद् द्वारा प्रदत्त उपकरणों के आधार पर शिक्षण-सामग्री के प्रथम स्तर के मूल्यांकन का काम अपने हाथ में ले लें। हर पुस्तक की मूल्यांकन रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए तीन कार्यगोष्ठियाँ आयोजित की गईं। मूल्यांकन के प्रमुख उद्देश्य थे—प्रथम चरण के दौरान निर्मित शिक्षण-सामग्री का मूल्यांकन; शिक्षण-सामग्री की गुणवत्ता सुधारने के लिए सुझाव; ऐसी सामग्री की पहचान जिसे राज्य में

वृहत्तर स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। कुल मिलाकर 85 भाषा की पुस्तकों, 59 गणित की और 35 समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा की पुस्तकों का मूल्यांकन किया गया।

पाठ्यक्रम में वैचारिक साहित्य

पाठ्यक्रम-निर्माताओं और शिक्षण-सामग्री के लेखकों के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने वैचारिक साहित्य तैयार किया है। यह साहित्य पुस्तिकाओं के रूप में है जो भाषा, गणित, परिवेश अध्ययन, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, और कला (सृजनात्मक अभिव्यक्ति) पर हैं। यह साहित्य विषय की प्रकृति, विषय से संबद्ध कुशलताओं और क्षमताओं, पढ़ाने-पढ़ने की विधियों, शिक्षण-सामग्री के लेखकों के मार्गदर्शन और संबद्ध क्षेत्रों में छात्र-मूल्यांकन की योजना के बारे में है। इन पुस्तिकाओं के प्रारूपों पर कार्य-दल बैठकों में विचार-विमर्श हो चुका है (भाषा की पुस्तिका छोड़कर)। इनको अब प्रकाशन के योग्य बनाया जा रहा है।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए विकसित सामग्री में सम्मिलित विषयों का मूल्यांकनात्मक अध्ययन

अनौपचारिक शिक्षा के लिए विकसित की गई सामग्री में जो विषय शामिल किए गए हैं, उनके अध्ययन के लिए, 17 से 20 दिसंबर 1981 तक एक कार्य-दल की बैठक की गई। आठ राज्यों की 93 पुस्तकों का अध्ययन किया गया। रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा बनाए गए एक उपकरण की सहायता से उनका विश्लेषण किया गया। अध्ययन की रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

प्राथमिक शिक्षा में सार्थक अधिगम के लिए आधार के रूप में परिवेश का उपयोग

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने एक पुस्तिका प्रकाशित की है जिसका नाम है—"प्राथमिक शिक्षा में सार्थक अधिगम के लिए आधार के रूप में परिवेश का उपयोग"। जानकारी और मार्गदर्शन के लिए इस पुस्तिका की प्रतियाँ राज्यों और संघ क्षेत्रों के सभी संबद्ध व्यक्तियों को भेजी गई हैं।

समुदाय की शिक्षा और प्रतिभागिता

परियोजना के उद्देश्य

समुदाय की शिक्षा और प्रतिभागिता में विकासात्मक गतिविधियों की यूनिसेफ़-सहायता-प्राप्त परियोजना को लागू करने का काम भी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और

प्रशिक्षण परिषद् कर रही है। इस परियोजना के सुनिश्चित उद्देश्य हैं—जिस जन समूह को किसी भी प्रकार की शिक्षा, पूरी या अधूरी, नई या पुरानी, नहीं मिली है, उसकी न्यूनतम शैक्षिक ज़रूरतों को पूरी करने के साधन के रूप में, नए प्रकार के शैक्षिक कार्य-कलाप को विकसित और परीक्षित करना। यह दृष्टिकोण इस आधार-वाक्य पर टिका है कि बच्चों की शिक्षा की सार्थकता इसी में है कि सामाजिक-आर्थिक परिवेश में आने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ वह चले। इसको तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समुदाय शिक्षित और जागरूक हो। इसका अर्थ यह भी है कि शिक्षा की ज़रूरत केवल उन बच्चों को ही नहीं है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं बल्कि उनको भी है जो पढ़ाई बीच में ही छोड़ कर स्कूल जाना बंद कर चुके हैं और उन माताओं को भी है जो स्कूल का नाम तक नहीं जानतीं।

एक प्रासंगिक उद्देश्य इस बात की जाँच करना है कि यदि स्कूलों और समुदाय के बीच का द्विभाजन हटा दिया जाए तो क्या स्कूल समुदाय की इतनी मदद कर सकते हैं कि स्कूल सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन जाएँ।

अतएव, परियोजना अनौपचारिक शिक्षा के ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का ध्यान रखती है जो वय-क्रम 0-3 और माताओं, 3-6, 6-14 और 15-35 और वयस्कों की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इस परियोजना की चुनौती इस बात में भी है कि चुने गए हर समुदाय में उपलब्ध संसाधनों को उस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावकारी ढंग से काम में लाया जाये, जिसे विभिन्न विकासात्मक और कल्याणकारी माध्यमों ने पहले ही प्रस्तुत कर रखा है।

परियोजना अनौपचारिक शिक्षा के भारत सरकार के व्यापक कार्यक्रम के साथ है। परियोजना के अंतर्गत बने कार्यक्रम और क्रियाकलाप लोगों के 'जीवन और दिनचर्या' को सुधारने के वृहत्तर उद्देश्यों की पूर्ति उनकी स्वेच्छया प्रतिभागिता से करते हैं। कार्यक्रम अपेक्षित क्षमताओं की व्यवस्था भी 'न्यूनतम अधिगम-ज़रूरतों' को पूरा करने के लिए करते हैं।

परियोजना के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है—विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रस्तुत विविध विकासात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए समुदाय के सदस्यों में अपेक्षित ज्ञान एवं कुशलताएँ उत्पन्न करना। विकासात्मक कार्यकलाप को समुदायों के शैक्षिक कार्यक्रमों के साथ जोड़ दिया जाता है। परियोजना बड़े प्रभावपूर्ण तरीके से देश के प्राथमिकता वाले कार्यक्रम (प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण) को बढ़ावा और सहारा देती है। अनौपचारिक शिक्षा-विधियों के माडलों और विभिन्न वय-क्रम विशेष कर 6 से 14 और 15 से 35 के लिए बनी सामग्रियों को संबद्ध राज्य और संघ क्षेत्र अपना सकते हैं।

शिक्षा के लिए समुदाय के लोगों में सम्भाव्य अभिवृत्तियों के विकास को भी परियोजना सुनिश्चित कर लेती है। जो बच्चे पढ़ाई पूरी करने के पहले ही स्कूल जाना छोड़

देते हैं और जिन्होंने कभी स्कूल का मुँह ही नहीं देखा—उन लोगों को अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका दिया जाता है। स्त्रियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों में ये बातें शामिल हैं—प्रसव-पूर्व और प्रसवोत्तर देखरेख, शिशुओं की सँभाल और पोषण, आर्थिक गतिविधियाँ, घर का इंतज़ाम, आदि का प्रशिक्षण। स्कूल-पूर्व के शिशुओं के शैक्षिक कार्यक्रमों द्वारा शिशुओं में ऐसी अभिवृत्तियाँ विकसित की जाती हैं जिनसे वे स्कूल जाने में दिलचस्पी ले सकें। ऐसे शिशुओं के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक खेल-कौतुक और रचनात्मक कार्यकलाप बनाए गए हैं।

6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा के जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, उनका लक्ष्य है—जो बच्चे पढ़ाई के बीच में ही स्कूल जाना बंद कर चुके हैं या जो कभी स्कूल गए ही नहीं उनको पार्ट टाइम शिक्षा प्रदान करना। ऐसी शिक्षा बच्चों में शैक्षणिक योग्यताएँ और जानकारी तो उत्पन्न करेगी ही, साथ ही उनके खानदानी धंधों तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के लिए उनकी कुशलताओं को भी बढ़ाएगी। इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद यदि बच्चों में शिक्षा के प्रति रुझान पैदा हो जाती है तो वे औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में जा सकते हैं।

वयस्क स्त्री-पुरुषों के लिए बने शैक्षिक कार्यक्रमों का लक्ष्य है—पढ़ने-लिखने की योग्यता पैदा करना, उनकी ज्ञान वृद्धि करना और कारोबारी साक्षरता तथा गिनती-जोड़-घटाना-गुणा-भाग आदि सिखलाना। कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम है—अच्छी सेहत बनाने, स्वच्छ आदतें डालने, खेती के कौशलों को अपनाने आदि के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्रदान करना। साथ ही विभिन्न कल्याणकारी और विकासात्मक कार्यक्रमों के प्रति उचित दृष्टिकोण बनाने में उनकी मदद करना। इस प्रकार यह परियोजना समुदाय में ऐसा स्फुरण पैदा करना चाहती है जिससे समाज का कायाकल्प हो सके। समुदायों के विस्तृत सर्वेक्षण द्वारा पहचाने गए स्थानीय परिवेश और शैक्षिक ज़रूरतों के आधार पर, विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रमों और कार्यकलापों की योजना बनाने का काम तथा विविध प्रकार की शिक्षण-सामग्रियों के निर्माण का काम हाथ में लिया गया है।

परियोजना को लागू करना

इस परियोजना को प्रारंभ में, 15 राज्यों और संघ क्षेत्रों में, प्रायोगिक आधार पर, हर राज्य के दो-दो सामुदायिक केंद्रों में शुरू किया गया था। अधिकांश केंद्र बहुत गरीब, देहाती, जनजातीय और पहाड़ी इलाकों में तथा शहरों की गरीब बस्तियों में बने थे। परियोजना से जो लाभ हुए हैं, उनसे बढ़ावा पाकर इन 15 राज्यों में और भी सामुदायिक केंद्र खोले जा रहे हैं तथा प्रारंभ में जिन राज्यों और संघ क्षेत्रों ने परियोजना में रुचि नहीं दिखाई थी, वहाँ भी केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। इस प्रकार सामुदायिक केंद्रों की संख्या 30 से बढ़कर 102 हो जाएगी और सामाजिक-आर्थिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताओं के

बड़े भूभाग की सेवा हो सकेगी एवं समाज की अनौपचारिक शिक्षा के समुचित माडलों का विकास हो सकेगा।

ऊपर गिनाए गए 15 राज्यों में, परियोजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों के लिए, अनौपचरिक शिक्षा के नाना प्रकार के माडल बनाए जा रहे हैं। स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए और सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर, राज्यों ने विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम व कार्यकलाप विकसित किए हैं, साथ ही अनौपचारिक शिक्षा की कुछ समुचित सामग्री भी विकसित की गई है। इन सबको सामुदायिक केंद्रों में लागू किया गया है और प्राप्त अनुभवों के आधार पर इन्हें सुधारा जा रहा है। नए राज्यों और संघ क्षेत्रों ने समुदायों के विस्तृत सर्वेक्षण आयोजित किए हैं, उनकी आवश्यकताओं और स्थानीय परिवेश का पता लगाया है ताकि उनके लिए वैज्ञानिक तरीके से कार्यकलाप, सामग्री और विधियों को विकसित किया जा सके।

कार्यक्रमों का विकास

राज्यों/संघ क्षेत्रों की पाठ्यक्रम-टीमों के चार अनुकूलन-कोर्स आयोजित किए गए, जिनमें से दो पाठ्यक्रम-नवीकरण की परियोजना के साथ संयुक्त थे और दो स्वतंत्र रूप से विभिन्न वर्गों के लिए कार्यक्रम और कार्यकलाप के विकास के विविध पक्षों के बारे में टीमों को अनुकूलित करने के लिए थे। इन अभ्यासों में सभी राज्य और संघ क्षेत्र लगे हुए हैं। कुछ राज्यों में कार्यक्रमों को राज्य के अनौपचारिक-शिक्षा कार्यक्रमों में इस्तेमाल करने के लिए अनुकूलित किया जा रहा है।

परियोजना का अनुश्रवण

परियोजना का अनुश्रवण राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के समुदाय-शिक्षा समूह द्वारा किया जा रहा है। इसको अमल में लाने का काम राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों, और ग्राम खंडों के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है। सामुदायिक केंद्रों में कार्यक्रम और कार्यकलाप के आयोजन और कार्यान्वयन में अध्यापकों और सामुदायिक कार्यकर्ताओं जैसे लोग लगे हुए हैं।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण-कार्यक्रमों का अनुश्रवण और मूल्यांकन

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के कार्यक्रम में उच्च निवेश हुआ है, इसलिए इस के अनुश्रवण और मूल्यांकन की महती और तत्काल आवश्यकता है। इस बात को ध्यान में रखकर यूनेस्को के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने सैद्धांतिक रूपरेखा की कार्यप्रणाली और उपकरण तैयार किए हैं।

इस विधि का लक्ष्य है—

—कम से कम निवेश ।

—अधिक से अधिक परिणाम ।

—संसाधनों की बरबादी पर रोक।

—लक्ष्य को संधान योग्य बनाना ।

—असफलता के कम से कम खतरे ।

—समय रहते उपचार ।

—ज़रूरत पड़ने पर निर्णयों में तनिक सी हेर फेर ।

अनुश्रवण और मूल्यांकन की कार्यविधि और साधनों की जाँच परख के लिए, चार राज्यों में बहस-मुबाहसे हुए । इन चर्चाओं में, संबद्ध राज्यों के शैक्षिक सोपान के अलग-अलग स्तरों के कार्यकर्ता शामिल हुए । राज्य स्तर की बैठकों में प्राप्त किए गए सुझावों को बाद में होने वाली उच्चस्तरीय सभा के सम्मुख रखा गया । इस उच्चस्तरीय सभा में विचार-विमर्श के लिए योजना आयोग, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन और प्रशासन संस्थान, राष्ट्रीय सूचना केंद्र के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था ।

उच्चस्तरीय सभा में हुए विचार-विमर्श के आधार पर, कार्यविधि की एक योजना बना ली गई है जिसे जाँचा जा रहा है ।

6

लाभ-वंचित वर्गों की शिक्षा

जो बच्चे स्कूलों में दाखिल नहीं हो पाते वे आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से लाभ-वंचित वर्गों के होते हैं जिनमें स्त्रियाँ, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लोग आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए परिषद् इन वर्गों में शिक्षा के प्रसार के लिए विभिन्न तरीकों से प्रयास करती रही है। इस दिशा में वास्तविक कार्य करने की परिषद् की चिंता औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के निर्णयों से ज़ाहिर होती है। परिषद् इस क्षेत्र में मुख्य रूप से अनुसंधान

और शैक्षणिक सहायता देती रही है। यद्यपि प्रयोग के तौर पर विकास संबंधी कुछ कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। इस क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए धन की भी विशेष रूप से व्यवस्था की गई है।

राजस्थान के जन जातीय क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा को सार्वजनीन बनाने के कार्य में बाधा डालने वाले कारकों के अध्ययन शुरू किये गये हैं। राजस्थान के बाड़मेर जिले में अनुसंधान के साधन तैयार कर लिए गए हैं और क्षेत्रीय काम पूरा हो गया है।

सितंबर 1980 में परिषद् के जनजातीय शिक्षा एकक को और अधिक सुदृढ़ बना कर उसे 'अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक' नाम दे दिया गया है। तब से अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के बारे में काफी विचार किया गया है। अनुसूचित जातियों के संबंध में अनुसंधान, विकास तथा प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रमों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आशा है कि इन्हें शीघ्र ही शुरू किया जाएगा। विचाराधीन कुछ कार्यक्रम ये हैं :

(i) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए पूरक-पठन सामग्री का निर्माण।

(ii) उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल के अनुसूचित जातियों तथा गैर-अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों की तुलना के लिए अनुसंधान योजना।

(iii) अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के लिए प्रदत्त विशेष शैक्षिक सुविधाओं के उपयोग तथा उनकी व्यवस्था के अध्ययन के लिए अनुसंधान योजना।

अनुसंधान

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए अनौपचारिक शिक्षा की विधियों, प्रक्रियाओं तथा अभ्यासों का अध्ययन शुरू किया गया। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में योजनागत अनुसंधान के साधन तैयार किए गए और क्षेत्रीय कार्य शुरू किया गया।

जनजातीय विद्यार्थियों की शैक्षिक अवसरों में समानता के अध्ययन हेतु योजनागत अनुसंधान के साधन तैयार किए जा रहे हैं।

उड़ीसा की साओरा जनजाति के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं तथा उनके लिए पाठ्यक्रम के विकास का विश्लेषण शुरू किया गया। पाठ्यक्रम के प्रारूप पर विचार किया गया है।

केंद्रीय मंत्रियों के नाम अपने पत्र में प्रधान मंत्री ने अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष संघटक योजना शीघ्र तैयार कराने पर जोर दिया था। तदनुसार अनुसूचित जातियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तैयार करने के लिए शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय में एक

बैठक बुलाई गई थी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की शिक्षा के क्षेत्र में शुरू करने के निमित्त विशेष अध्ययनों को जानने के लिए परिषद् में भी एक बैठक बुलाई गई थी। विशेष अध्ययन के कुछ विषय थे—

(i) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की व्यावसायिक ज़रूरतें और आकांक्षाएँ।

(ii) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के दाखिला न लेने और पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने के कारण।

(iii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की शैक्षिक विकास संबंधी समस्याएँ।

(iv) अनुसूचित जातियों में शिक्षा के क्षेत्र में अस्पृश्यता किस प्रकार निवारक भूमिका अदा करती है, इस बात का अध्ययन।

(v) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्कूल स्तर के छात्रों/छात्राओं के दाखिले और अपलब्धि के नमूनों तथा उनके माता-पिता की शिक्षा के स्तर और व्यवसाय का अध्ययन।

(vi) सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक तथा व्यावसायिक योग्यता और व्यावसायिक समस्याओं के संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्कूली अध्यापकों/अध्यापिकाओं का विषय परक अध्ययन।

(vii) स्कूल स्तर पर विभिन्न जन परीक्षाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की असफलताओं का अध्ययन।

(viii) जातीयता के दृष्टिकोण से स्कूली पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण।

ऊपर बताए गए क्षेत्रों में से किसी पर भी योजना तैयार करने के लिए, देश के विश्वविद्यालयों के शिक्षा तथा मानवशास्त्र विभागों और जनजातीय अनुसंधान संस्थानों से अनुरोध किया गया है। इसके लिए परिषद् वित्त-पोषण करेगी। वर्ष 1980 के दौरान निम्नलिखित सात अनुसंधान प्रस्ताव परिषद् में प्राप्त किए गए हैं। ये परियोजनाएँ प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों पर हैं :

(i) व्यावसायिक आकांक्षाओं तथा रोजगार संबंधी रुचियों के स्तर के संदर्भ में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मनोवैज्ञानिक-सामाजिक कारकों का अध्ययन।

(ii) धारवाड़ के हरिजनों में शिक्षा के मार्ग में छुआछूत द्वारा निवारक भूमिका।

(iii) अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के स्कूल स्तर के छात्रों/छात्राओं के दाखिले और उपलब्धि के नमूनों तथा उनके माता-पिता की शिक्षा के स्तर और व्यवसाय का अध्ययन ।

(iv) हरियाणा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के दाखिले और उपलब्धि के नमूनों का अध्ययन ।

(v) हिमाचल प्रदेश में मिडिल और मैट्रीकुलेशन परीक्षा के स्तरों पर असफल होने वाले अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामलों का अध्ययन ।

(vi) बोधात्मक तथा अबोधात्मक विभिन्नताओं के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश के जनजातीय और अजनजातीय विद्यार्थियों की सर्जनात्मक विचारशीलता का अध्ययन ।

(vii) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों में शामिल न होने, अनुपस्थिति तथा पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ने के कारणों का अध्ययन ।

पाठ्यचर्या/सामग्री का निर्माण

जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लिए, शिक्षण-सामग्री के निर्माण का कार्य, संबंधित राज्य सरकारों के साथ किया जा रहा है ।

'संताल लोक गीत और लोक कथाएँ' नामक पूरक पठन की पुस्तक की समीक्षा की गई, उसे अंतिम रूप दिया गया और छपने के लिए भेजा गया ।

जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा-कार्यक्रम के प्रमुख कार्मिकों के अनुकूलन के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया । इसमें जनजातीय सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन संबंधी विषय, जनजातीय शिक्षा की समस्याएँ, जनजातीय क्षेत्रों के अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के संयोजन से संबंधित समस्याएँ तथा गिनती, साक्षरता और परिवेशीय अध्ययन पर प्रदर्शनात्मक पाठ शामिल थे । यह पाठ्यक्रम भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में हुई एक दो-दिनों वाली गोष्ठी में संसाधित किया गया जिसमें मानवशास्त्र, शिक्षा, और पाठ्यक्रम-विकास के विशेषज्ञ तथा अनौपचारिक शिक्षा के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था ।

इस अनुकूलन कोर्स के उद्देश्य हैं : जनजातीय जीवन तथा संस्कृति वाले जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को चलाने वाले मुख्य कार्मिकों का प्रशिक्षण, जनजातीय शिक्षा की समस्याएँ, जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों की संगठन विषयक समस्याएँ और साक्षरता, गिनती के ज्ञान तथा परिवेशीय-अध्ययन संबंधी पढ़ाने-पढ़ने की वास्तविक समस्याएँ ।

मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के लिए अनुदेशीय-सामग्री तैयार की जा रही है।

पश्चिमी बंगाल तथा सिक्किम राज्यों ने इस कार्यक्रम में रुचि दिखाई है तथा पश्चिमी बंगाल के संतालों और सिक्किम के लेपचाओं के लिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

अब तक हिन्दी में निम्नलिखित पूरक पठन सामग्री का विकास कर लिया गया है :

(i) जनजातीय वीरों की जीवनियाँ—प्रकाशित तथा वितरित।

(ii) संताली जीवन तथा संस्कृति की झाँकियाँ। } प्रकाशनाधीन

(iii) मुंडा लोक कथाएँ और लोकगीत } प्रकाशनाधीन

(iv) ओराँव लोक कथाएँ और लोकगीत। } प्रकाशनाधीन

(v) संताल लोक कथाएँ और लोक गीत } प्रकाशनाधीन

(vi) माँडिया, गोंड तथा मुड़िया की लोक कथाएँ तथा लोक गीत और अबुझ माड़िया (बस्तर के गोंड) का जीवन और संस्कृति— पाण्डुलिपियाँ समीक्षित और अंतिम रूप में

प्रशिक्षण

जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शिक्षकों के लिए कोर्स का आयोजन उदयपुर के राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान में जुलाई 1980 में किया गया था। इसमें राजस्थान के 26 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के शिक्षकों ने भाग लिया। इस प्रशिक्षण कोर्स का उद्देश्य, जनजातीय क्षेत्रों में अवस्थित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के इन शिक्षकों को, जनजातीय जीवन और संस्कृति, जनजातीय शिक्षा की समस्याओं, जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के संगठन से परिचित कराना था तथा उन्हें साक्षरता, गिनती के ज्ञान और परिवेशीय अध्ययन के शिक्षण की विभिन्न विधियों में प्रशिक्षित करना था।

यह इसलिए और भी आवश्यक था क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अधिकतर शिक्षक अजनजातीय क्षेत्रों के होते हैं और इस कारण वे जनजातीय सांस्कृतिक और शैक्षिक समस्याओं को ठीक प्रकार समझ और सराह नहीं पाते।

जनजातीय बोलियों में पाठ्यपुस्तकें लिखने के लिए शब्द एकत्र करने के निमित्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का प्रशिक्षण-कार्यक्रम भुवनेश्वर में आयोजित किया गया ।

जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा शैक्षिक विकास की नवीनतम धाराओं से जनजातीय क्षेत्रों के जिला शिक्षा अधिकारियों को अवगत कराने के लिए एक अनुकूलन कोर्स का आयोजन किया गया । इसमें गुजरात, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, उड़ीसा, राजस्थान तथा त्रिपुरा राज्यों के पंद्रह जिला शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया ।

एक अनुकूलन कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें छः राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के 24 प्रमुख कार्मिकों ने भाग लिया ।

स्त्री-शिक्षा

स्त्री-शिक्षा एकक ने शिक्षा, विद्यार्थी तथा माता-पिता का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण और शिक्षा तथा कार्यरत-जीवन से संबद्ध सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पर कार्य किया ।

भारत में स्त्री-शिक्षा के अनुरूप पहचाने गए मूल्यों के आधार पर इस एकक ने सामान्य शिक्षा के दस वर्षीय पाठ्यक्रम पर कार्य किया और शिक्षक-पुस्तिका तैयार की । स्त्री-शिक्षा के लिए शिक्षक-पुस्तिकाओं को तैयार किया गया जिनमें एक प्राथमिक स्तर और दूसरी माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए हैं । गणित के अध्यापकों के लिए पूरक पठन सामग्री भी तैयार की गई ।

शिक्षा के सार्वजनीकरण तथा व्यावसायीकरण के परिप्रेक्ष्य में लड़कियों तथा स्त्रियों के लिए कार्यक्रम तैयार करने के बारे में सलाह देने के लिए एकक ने एक उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श-गोष्ठी का आयोजन किया ।

7

अध्यापकों और अन्य कर्मियों की शिक्षा

अध्यापक-शिक्षा

बच्चों की शिक्षा में अध्यापक का स्थान प्रमुख होता है, इसलिए देश में प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर और सेवा-पूर्व तथा सेवा-कालीन दोनों अवस्थाओं में, अध्यापक-शिक्षा के सुधार के लिए, रा० शै० अ० और प्र० प० निरंतर प्रयास करती रहती है। इस उद्देश्य के लिए, परिषद् अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास के कार्य करती रहती है। रा० शै० अ० और प्र० प० अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् के शैक्षणिक सचिवालय के रूप में भी काम करती है, जिसे शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने अध्यापक-शिक्षा से सम्बद्ध मामलों पर सलाह देने के लिए बनाया है।

अनुसंधान

वर्ष के दौरान रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यापक-शिक्षा विभाग ने अनेक अध्ययन-कार्यों को हाथ में लिया। उनमें से जो महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा नीचे की जा रही है :

कक्षा में प्रश्न पूछने और छात्रों द्वारा उत्तर दिए जाने की संरचनात्मक विशेषताएँ : कक्षा VI में सामाजिक अध्ययन पढ़ाने वाले दिल्ली और हरियाणा के 25 अध्यापकों के कक्षा में प्रश्न पूछने के व्यवहार को इस अध्ययन में विश्लेषित किया गया। कथा में पूछे गए प्रश्नों की स्पष्टता, छात्रों के उत्तरों की किस्म आदि के अंतर संबंधों को समझा गया।

विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित संबद्धता की शर्तों के न लागू किए जाने के कारण : प्रश्नावली और साक्षात्कारों द्वारा चार राज्यों, नौ विश्वविद्यालयों और दस शिक्षा महाविद्यालयों से आधार-सामग्री एकत्र की गई। शिक्षा-महाविद्यालयों की संबद्धता से जुड़े विश्वविद्यालय के अधिकारियों, शिक्षा विभागों के अध्यक्षों और शिक्षा महाविद्यालयों के प्रिंसिपलों से साक्षात्कार किए गए। महत्वपूर्ण निष्कर्ष थे—

—संबद्धता की शर्तों में व्यापकता का अभाव।

—संबद्धता की शर्तों के लागू किए जाने के लिए विशिष्ट तंत्र की अनुपस्थिति।

—कुछ खास किस्म के संस्थानों को अधिक स्वायत्तता।

—बी. एड. कोर्स शुरू करने की अनुमति प्रदान करने के लिए उचित कार्यविधि की कमी।

—विश्वविद्यालय और राज्य सरकारों के बीच विभाजन।

भारत में अध्यापक-शिक्षा पर अध्ययन (1973-75) : एम. एड. के छात्रों, भारतीय विश्वविद्यालय में पी-एच. डी. के शोधकर्ताओं, शिक्षा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों के अध्यापक-शिक्षकों द्वारा अध्यापक-शिक्षा पर की जा रही शोध का एक सर्वेक्षण किया गया। 324 शीर्षकों का एक वर्गीकरण किया गया है। 162 अध्ययनों के महत्वपूर्ण निष्कर्षों को नीचे लिखे शीर्षकों के अंतर्गत किया गया है—

—शिक्षण की प्रभावकारिता।

—अध्यापक-शिक्षा की समस्याएँ और राज्यों के अध्ययन।

—शिक्षण की विधियाँ और उनमें अंतर्निहित समस्याएँ।

—अध्यापक-शिक्षा का कार्यक्रम और पाठ्यचर्याएँ।

—दृश्य-श्रव्य साधन।

—मूल्यांकन।

—सेवाकालीन शिक्षा और विस्तार के कार्यक्रम ।

—प्रशासन और संगठन ।

शिक्षण कौशलों के एकीकरण की विभिन्न विधियों की सापेक्ष प्रभावकारिता : छात्र-शिक्षकों की सामान्य कुशलता पर स्थानापन्न, योगात्मक, संकलनीय और दूयग्र एकीकरण विधियों की प्रभावकारिता की तुलना की गई । अध्ययन से पता चला कि संकलनीय माडल का अनुसरण करने वाले शिक्षण कौशलों के एकीकरण में प्रशिक्षण अधिक प्रभावकारी है, बनिस्वत कि योगात्मक और स्थानापन्न विधियों के ।

शिक्षण-सामग्री का विकास

प्रारंभिक और माध्यमिक अध्यापक-शिक्षा के लिए पाठ्यपुस्तकें बनाने में रा० शै० अ० और प्र० प० लगी हुई है । पाठ्यपुस्तकें निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में हैं । माध्यमिक स्तर की अध्यापक-शिक्षा के लिए निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें छप रही हैं—

—विज्ञान-शिक्षण ।

—केन्द्रीय शिक्षण कौशलों की पाठ्यपुस्तक ।

—उभरते हुए भारतीय समाज में अध्यापक और शिक्षा ।

नीचे लिखी पाठ्यपुस्तकों की पांडुलिपियाँ विशेषज्ञों द्वारा संपादित किए जाने के लिए तैयार हैं—

—शैक्षिक मनोविज्ञान ।

—पाठ्यक्रम और मूल्यांकन ।

—समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की दीपिका ।

—गणित-शिक्षण की पाठ्यपुस्तक बन रही है ।

प्रारंभिक स्तर की अध्यापक-शिक्षा के लिए, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य की दीपिका की पांडुलिपि, विशेषज्ञों द्वारा संपादित किए जाने के लिए तैयार है । निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकें बन रही हैं—

—उभरते भारत में अध्यापक और शिक्षा ।

—शिशु मनोविज्ञान ।

—समुदाय के साथ कार्य करते हुए ।

—गणित-शिक्षण ।

—सामाजिक-अध्ययन-शिक्षण ।

अध्यापक-शिक्षा के गहन कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, रा० शै० अ० और प्र० प० राज्यों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर अध्यापक-शिक्षा के सुधार और सम्पन्नीकरण के लिए काम करती आ रही है। पिछले वर्ष अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा संस्तुत पाठ्यक्रम पर मुख्य बल दिया जाता रहा है। इसके अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में, पाठ्यक्रम को लागू करने में राज्यों और विश्वविद्यालयों की सहायता की जा रही है। व्यावहारिक कार्य, मूल्यांकन की योजना, और इकाई योजनाओं की तैयारी के ब्यौरे बनाने के लिए सभाएँ की गई हैं। कार्यक्रम को माध्यमिक स्तर पर तमिलनाडु तक और प्रारंभिक स्तर पर उत्तर प्रदेश तक बढ़ा दिया गया है।

प्रशिक्षण

इस वर्ष के दौरान अनेक अनुकूलन कोर्स किए गए। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए अल्पकालिक कोर्स आयोजित करने के निमित्त, संसाधन व्यक्तियों को अनुकूलित करने के उद्देश्य से, मार्च 1981 में छह दिनों का एक कोर्स आयोजित किया गया। शिक्षकों को प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में पूरे दिल से शामिल करने के लिए और क्षेत्र में हो रहे अधुनातन विकास से उन्हें परिचित कराने के लिए इन कोर्सों की अनिवार्यता समझी गई। कोर्स के दौरान प्राथमिक स्कूल पाठ्यक्रम के बदलते स्वरूप पर विचार-विमर्श किया गया और कुछ शिक्षण-सामग्री बनाई गई। इस शिक्षण-सामग्री पर आधारित एक दीपिका प्रकाशित करने की बात सोची जा रही है।

लघु-शिक्षण पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम, एक उत्तरी क्षेत्र के लिए देहरादून में और दूसरा दक्षिणी क्षेत्र के लिए हैदराबाद में, किए गए। प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए लघु-शिक्षण पर दो कार्यगोष्ठियाँ की गईं, एक दक्षिणी क्षेत्र के लिए मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में और दूसरी पश्चिमी क्षेत्र के लिए भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में।

गुजरात के अध्यापक-शिक्षकों के लिए एक अनुकूलन-प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। इसमें राज्य के प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रिंसिपलों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य था प्रतिभागियों को अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम से परिचित कराना। समुदाय के साथ काम करना, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि पर इसमें चर्चा हुई।

छात्र-शिक्षण और दूसरे व्यावहारिक कार्य के मूल्यांकन के लिए साधनों के विकास पर बँगलोर में एक कार्यगोष्ठी हुई। बी. एड. कोर्स के व्यावहारिक कार्य के विविध पक्षों को समाहित करने वाले साधनों का विकास किया गया। जाँच-परख के बाद इन्हें अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

सारे भारत के अध्यापक-शिक्षकों के लिए जीव विज्ञान शिक्षण की विधियों का एक अनुकूलन कोर्स किया गया। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य थे—रा० शै० अ० और प्र० प० के कर्मचारियों द्वारा लिखी गई जीव विज्ञान की सामग्री की जाँच-परख करना, विभिन्न राज्य-विश्वविद्यालयों की एक वर्षीय बी. एड. पाठ्यचर्याओं पर विचार-विमर्श करना, और प्रयोगों को करने में अनुभूत सुविधाओं का पता लगाना।

भूटान के यूनेस्को वृत्ति पाने वालों के लिए 16 फरवरी से 13 मार्च 1981 तक प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा पर एक प्रशिक्षण-कोर्स किया गया। कोर्स में ये कार्य थे—अध्यापक-शिक्षा के विविध पक्षों पर विचार-विमर्श; तथा दिल्ली, जयपुर, बम्बई और पुणे के आरंभिक अध्यापक-शिक्षा संस्थानों व प्राथमिक स्कूलों का अध्ययन-भ्रमण।

सभाएँ-परिचर्चाएँ

राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों तथा राज्य विज्ञान-शिक्षा-संस्थानों के निदेशकों/प्रिंसिपलों की वार्षिक सभा जनवरी 1981 में रा० शै० अ० और प्र० प० के दिल्ली स्थित मुख्यालय में हुई। सभा के मुख्य उद्देश्य थे अतीत में किए गए कार्यों की समीक्षा करना और आगामी वर्षों के लिए कार्यक्रमों की रूपरेख बनाना। सभा ने कई महत्वपूर्ण और उपयोगी सिफ़ारिशें कीं।

सेमीनार रीडिंग्स परियोजना के अंतर्गत, 1980-81 की प्रतियोगिता में, राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए प्राथमिक स्तर के छह लेख और माध्यमिक स्तर के चार लेख चुने गए। पुरस्कार पाने वाले अध्यापक-शिक्षक, लेख पढ़ने और पुरस्कार लेने के लिए एकत्र हुए।

प्रकाशन

वर्ष के दौरान अध्यापक-शिक्षा विभाग ने अनेक दस्तावेज़ प्रकाशित किए जिनमें प्रमुख हैं—

—लघु शिक्षण के अवयवों की विभेदक प्रभावकारिता।

—केन्द्रिक शिक्षण कौशल : लघु शिक्षण की विधि।

—कक्षा में प्रश्न पूछने का व्यवहार : समीक्षा।

—कक्षा में प्रश्न पूछने और छात्रों द्वारा उत्तर दिए जाने की संरचनात्मक विशेषताएं।

—सेवा कर रहे शिक्षकों की शिक्षण-कुशलता के सुधार के लिए लघु शिक्षण।

—भारत में अध्यापक-शिक्षा (सांख्यिकीय आधार-सामग्री)

—अन्य व्यावहारिक कार्य—एक समीक्षा

इनमें से पहला दस्तावेज़ छप चुका है। शेष सभी मिमियोग्राफ किए गए हैं।

प्राथमिक शिक्षा के कायाकल्प में शिक्षकों के व्यावसायिक संगठनों का शामिल होना

प्राथमिक शिक्षा के कायाकल्प के लिए, अध्यापकों और अध्यापक-शिक्षकों के संगठन बड़ी सम्भावना वाले काम करते हैं। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के लिए, प्राथमिक शिक्षा के कायाकल्प पर एक अनुकूलन कोर्स, रा० शै० अ० और प्र० प० के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में किया गया। इस कोर्स के आयोजन के उद्देश्य थे—संघ के कार्यकारी सदस्यों को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में चल रही नई प्रवृत्तियों से परिचित कराना, ताकि नए विचारों को फैलाने में मदद मिले और उत्पादकता तथा रोजगार की संभावनाओं में सुधार हो एवं धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों का विकास हो सके।

अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्

अध्यापक-शिक्षा के पाठ्यक्रम के संशोधन के लिए अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा बनाई गई मार्गदर्शन की रेखाओं को लगभग सभी राज्यों ने प्राथमिक स्तर पर और बी. एड. स्तर पर लगभग 15 विश्वविद्यालयों ने अपना लिया है। पाठ्यक्रम संशोधन के कार्य को तेजी से किया जायेगा क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् को मान्यता दे दी है। प्राथमिक और माध्यमिक अध्यापक-शिक्षकों को अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् की पाठ्यक्रम-मार्गदर्शी रेखाओं से परिचित कराने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० के क्षेत्र सलाहकारों ने एक दर्जन से भी अधिक अनुकूलन-गोष्ठियाँ आयोजित कीं। अध्यापक-शिक्षा विभाग विशिष्ट विषयों में अध्यापक शिक्षकों का अनुकूलन करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू कर रहा है। ये विशिष्ट विषय हैं—उभरते हुए भारतीय समाज में अध्यापक और शिक्षा; समाजोपयोगी उत्पादक कार्य आदि। समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की पाठ्यपुस्तकें छपने के लिए तैयार हैं। अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् ने समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के प्रमुख कार्मिकों के लिए चार अनुकूलन कार्यक्रम आयोजित किए ताकि स० उ० का० में अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए ये मुख्य कार्मिक संसाधन सम्पन्न व्यक्तियों के रूप में कार्य कर सकें।

अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् ने कक्षा की समस्याओं और अध्यापक-शिक्षा के सामाजिक मूल्यों पर भी परिचर्चाएँ आयोजित कीं।

निरीक्षकों की एक टीम ने कुल बच्चों की 'केस स्टडीज़' संकलित कीं जिन्हें 'भारतीय शिशु' नाम से प्रकाशित किया गया। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के शिशु विकास विभाग द्वारा संचालित योजना 'अध्यापक-शिक्षकों की गाँवों में

स्थिति' की रिपोर्ट को भी प्रकाशित किया गया है ताकि अन्य संस्थान भी इससे प्रेरित होकर समुदायों के साथ कार्य करना सीख सकें। अंधों, बहरों और मानसिक रूप से अपंगों के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बने क्षेत्रीय केन्द्रों के सर्वेक्षण की रिपोर्टें भी प्रकाशित की गई हैं।

सोलह राज्यों में राज्य अध्यापक-शिक्षा बोर्ड बन चुके हैं। नौ राज्य और संघ क्षेत्र इस बात के लिए रजामंद हैं कि देश में सभी स्तरों पर अध्यापक-शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्य करने वाले माध्यमों के रूप में अध्यापक-शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद्/राज्य अध्यापक-शिक्षा बोर्ड को मान्यता दे दी जाए।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय

चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों ने नवाचार के सेवा-पूर्व शिक्षा-कार्यक्रमों के आयोजन को जारी रखा। उन्होंने राज्यों के लिए प्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक क्षेत्रों में अनेक सेवाकालीन अध्यापक-शिक्षा कार्यक्रम, कार्यगोष्ठियाँ और परिसंवाद आयोजित किए। प्रार्थना किए जाने पर उन्होंने परामर्श भी दिए और विस्तार के कार्यकलाप किए। वर्ष के दौरान क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किए गए कार्यों का विवरण नीचे के अनुच्छेदों में दिया जा रहा है—

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर

उत्तरी क्षेत्र के राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के राज्यों एवं चंडीगढ़ और दिल्ली के संघ क्षेत्रों की अध्यापक-प्रशिक्षण सम्बन्धी ज़रूरतों को यह महाविद्यालय पूरी करता है।

सेवा-पूर्व के कोर्स

सन् 1980-81 में महाविद्यालय ने अपने नियमित बी. एड. और एम. एड. कोर्सों में 367 छात्रों को प्रवेश दिया जिनका विवरण इस प्रकार है—

कोर्स		प्रवेशार्थी
एम. एड.	...	20
बी. एड. विज्ञान	...	106
बी. एड. कृषि	...	37
बी. एड. वाणिज्य	...	46
बी. एड. अंग्रेज़ी	...	53
बी. एड. हिन्दी	...	66
बी. एड. उर्दू	...	39
	कुल	367

सेवाकालीन कोर्स

इसमें प्रवेश लेने वाले उत्तरी क्षेत्र के सेवा कर रहे 225 शिक्षकों में से 218 अप्रशिक्षित शिक्षकों ने बी. एड. ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार पाठ्यक्रम की परीक्षा दी। इसके पहले उन्होंने दस महीनों के पत्राचार पाठों और चार महीनों के व्यावहारिक शिक्षण इंटर्नशिप को पूरा किया। यह परीक्षा राजस्थान विश्वविद्यालय ने ली थी जिसमें छह परीक्षार्थी असफल रहे।

अनौपचारिक शिक्षा

फरवरी 1979 में जिला अजमेर (राजस्थान), जिला वाराणसी (उ० प्र०) के जखनी खंड, जिला जम्मू (जम्मू व कश्मीर) के धानसाल खंड में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले गए थे। अनौपचारिक शिक्षा की यह परियोजना इस वर्ष भी चलती रही। विभिन्न खंडों के इन केन्द्रों की औसत मासिक उपस्थिति क्रमशः इस प्रकार रही—257, 108 और 357। केन्द्रों की संख्या अजमेर जिले में 9, वाराणसी जिले में 4 और जम्मू जिले में 9 थी। वाराणसी जिले के केन्द्रों में कई कारणों से काम नहीं हो रहा था, अब वे फिर से खुल गए हैं। इन केन्द्रों में जाने वाले बच्चों को गिनती और हिन्दी सिखाई जाती है। परिवेश शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की शिक्षा, कृषि शिक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं की शिक्षा इन बच्चों को दी जाती है। भाषा और गिनती सिखाने के लिए शिक्षण साधनों, चार्टों, ब्लाकों और घर में खेले जाने वाले खेलों का इस्तेमाल किया जाता है। इनसे बच्चे जल्दी सीखते हैं। इन केन्द्रों में बच्चों को कुछ समय पहले नेशनल बुक ट्रस्ट की किताबें दी गई थीं, उनसे बच्चों को अपनी संस्कृति और विरासत की कुछ जानकारी मिल जाती है। क्षेत्र-कार्यकर्त्ताओं के लिए अनुकूलन के जो कार्यक्रम जम्मू और राजगीर (बिहार) में आयोजित किए गए थे, वे बड़े प्रभावकारी साबित हुए, खास कर गणित सिखाने वाले खेलों का कार्यक्रम।

विस्तार के कार्यक्रम

महाविद्यालय के विस्तार सेवा विभाग ने, अंचल के राज्यों के सुझाव और शैक्षणिक वर्ग के प्रस्ताव पर, निम्नलिखित कार्यक्रम किए—

—लघु शिक्षण पर अजमेर में हुई क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी जिसमें 27 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

—उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के कहने पर, विज्ञान पढ़ाने की नई विधियों में प्रमुख व्यक्तियों को अनुकूलित करने का कार्यक्रम इलाहाबाद में हुआ जिसमें 35 व्यक्तियों ने भाग लिया।

—उत्तरी अंचल और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अधिकारियों के लिए शैक्षिक

प्रौद्योगिकी पर एक परिसंवाद अजमेर में हुआ। इसमें राजस्थान और पंजाब के एक-एक प्रतिभागी और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा शिक्षण साधन विभाग के प्रतिनिधि आए।

—स्कूल-स्तर पर भौतिकी पढ़ाने के लिए आवश्यक गणितीय कौशलों पर अजमेर में हुई एक क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी जिसमें हरियाणा, राजस्थान और जम्मू व कश्मीर के नौ प्रतिभागी आए।

—सहयोगी स्कूलों के प्रिंसिपलों/हेडमास्टरों और शिक्षकों के अनुकूलन के लिए क्षेत्रीय गोष्ठी जिसमें 27 व्यक्तियों ने भाग लिया। यह गोष्ठी कालेज इंटर्नशिप कार्यक्रम के सम्बन्ध में हुई जिसे क्षेत्र के कई राज्यों में फैलाना था।

—जम्मू और कश्मीर सरकार की प्रार्थना पर भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति-शास्त्र और जन्तु विज्ञान के शिक्षकों के अनुकूलन के लिए जम्मू में हुई कार्य-गोष्ठी जिसमें 55 प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया।

—प्रस्तावित एम. एग्रीकल्चर (एड.) कोर्स के लिए पाठ्यचर्या-प्रारूप को अंतिम रूप देने के निमित्त, सभी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कृषि विज्ञान के शैक्षणिक कार्मिकों की अजमेर में हुई बैठक जिसमें 11 सदस्य आए।

—उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के आग्रह पर, इलाहाबाद में, संस्थान-नियोजन पर हुई कार्यगोष्ठी जिसमें शिक्षा विभाग के 37 अधिकारी आए।

—हमारे बी० एड० (ग्रीष्म स्कूल-सह-पत्राचार पाठ्यक्रम) छात्रों के लिए पत्राचार-पाठ लिखने के निमित्त अध्यापक-शिक्षकों की एक क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी जलंधर में हुई जिसमें 15 अध्यापक-शिक्षक आए।

—ग्राफ़िक-साधनों के निर्माण पर जम्मू में हुई क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी जिसमें पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के 20 प्रमुख व्यक्ति आए।

—उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग की माँग पर, शिक्षा की अनुसंधान-विधियों पर एक कार्यगोष्ठी इलाहाबाद में की गई, जिसमें 60 प्रतिभागी आए।

—समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के क्रियाकलापों के अंतर्गत मुर्गीपालन और सब्ज़ी-उत्पादन पर शिक्षक-संदर्शिकाओं के निर्माण के लिए, कृषि विभाग द्वारा अजमेर में आयोजित क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी।

उपरोक्त कार्यक्रमों के अलावा, विस्तार सेवा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों और क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों का सहयोग लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए।

अनुवर्ती शिक्षा

उत्तरी अंचल के अनुवर्ती शिक्षा केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों की एक क्षेत्रीय गोष्ठी अजमेर में की गई। प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष के दौरान नीचे लिखे केन्द्र काम कर रहे थे—

राजस्थान	7 केन्द्र
हिमाचल प्रदेश	2 केन्द्र
चंडीगढ़	1 केन्द्र

उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने 5 नए केन्द्र शुरू करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रकट की।

केप परियोजना

प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम (केप) परियोजना की इस महाविद्यालय की टीम ने अपना कार्य जारी रखा और उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा राजस्थान के अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

अधिगम पैकेज

महाविद्यालय का शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग बी० एड० के छात्रों के लिए जीव-विज्ञान में वस्तु तत्व एवं विधि पाठ्यचर्या पर अधिगम पैकेजों का निर्माण कर रहा है। +2 स्तर के स्नातकोत्तर शिक्षकों के लिए "जीवविज्ञानी अध्ययनों के लिए साधन और तकनीकों" पर सम्पन्नीकरण अधिगम पैकेज का निर्माण कुछ कार्यकर्त्ता कर रहे हैं।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश और गोवा राज्यों के अध्यापक बनना चाहने वालों की शैक्षिक ज़रूरतों को भोपाल का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय पूरी करता है।

सेवा-पूर्व के कोर्स

इस महाविद्यालय में इस समय निम्नलिखित कोर्स पढ़ाए जाते हैं :

---एक वर्षीय बी० एड० (भाषा, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि में)

—बी० एड० (प्रारंभिक शिक्षा)

—एम० एड० विशेषज्ञता के साथ (विज्ञान शिक्षा, अध्यापक शिक्षा, शैक्षिक प्रशासन और मार्गदर्शन में)

—एम० एड० (प्रारंभिक शिक्षा)

इन कोर्सों में इस वर्ष जो प्रवेश लिए गए उन्हें नीचे की सारणी में दिखाया गया है—

कोर्स का नाम		प्रवेशार्थी
बी० एड० (भाषा)	—	80
बी० एड० (वाणिज्य)	...	39
बी० एड० (विज्ञान)	...	68
बी० एड० (कृषि)	...	कोई नहीं
बी० एड० (प्रारंभिक शिक्षा)	...	75
एम० एड०	...	8
एम० एड० (प्रारंभिक शिक्षा)	...	7
	कुल	277

बी० एड० ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार पाठ्यक्रम, महाविद्यालय अप्रशिक्षित विज्ञान-शिक्षकों के लिए चलाता है। उसमें इस वर्ष 247 प्रवेशार्थी आए।

विस्तार के कार्यक्रम

इन नियमित कोर्सों के अलावा, महाविद्यालय ने नीचे लिखे सेवाकालीन-विस्तार-कार्यक्रम आयोजित किए—

कार्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
माध्यमिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए लघु शिक्षण में प्रशिक्षण के कार्यक्रम	34
कक्षा XI के लिए बुक कीपिंग में अभ्यास पुस्तिका की जाँच-परख के लिए कार्य विधि बनाने के लिए एम० एस० के वाणिज्य-अध्यापकों की कार्यगोष्ठी	12
—उपरोक्त—	5
गुजरात राज्य के अध्यापकों के लिए रेडियो-स्क्रिप्ट-लेखन की कार्यगोष्ठी	15
महाराष्ट्र राज्य के अध्यापकों के लिए रेडियो-स्क्रिप्ट-लेखन की कार्यगोष्ठी	20
मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए अंग्रेजी में सम्पन्नीकरण कार्यक्रम	29

मध्यप्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों के अध्यापकों के लिए हिन्दी में अनुकूलन कार्यक्रम	21
मध्यप्रदेश की राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन के लिए साधनों के विकास पर कार्यगोष्ठी	10
अध्यापक-शिक्षकों के लिए रचनात्मकता में आधुनिक अनुसंधान प्रवृत्तियों पर परिचर्चा	24
केन्द्रीय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों के कला-शिक्षकों के लिए ग्रैफ़िक टैक्नीक्स की कार्यगोष्ठी	24
महाराष्ट्र और गोआ के उच्चतर माध्यमिक स्कूल शिक्षकों के लिए भूगोल के शिक्षण में वस्तु तत्व-विधि-प्रणाली में रिफ्रेशर कोर्स	19
महाराष्ट्र और गोआ के प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए सृजनात्मक शिक्षण-विधियों में कार्यगोष्ठी	58
शिक्षण में परिवेशीय एप्रोच के इस्तेमाल में प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों का प्रशिक्षण	24
कक्षा XII की वाणिज्य की अभ्यास पुस्तिका की समीक्षा के लिए महाराष्ट्र के वाणिज्य शिक्षकों की कार्यगोष्ठी	—
अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों की वार्षिक बैठक	—

उपरोक्त विस्तार-कार्यक्रमों के अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रम भी महाविद्यालय में हुए, जिनमें महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मी सम्मिलित हुए।

अनौपचारिक शिक्षा

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय 30 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाता है, जिसमें 1176 छात्र हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में क्षे० शि० म० ने नीचे लिखे कार्यकलाप किए—

—मध्य प्रदेश के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के क्षेत्र शिक्षकों और निरीक्षकों के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० के क्षेत्र सलाहकारों के सहयोग से एक अनुकूलन कोर्स।

—महाराष्ट्र राज्य के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के क्षेत्र-शिक्षकों और निरीक्षकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा में एक अनुकूलन-उत्पादन कार्यगोष्ठी।

—गुजरात के अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों के क्षेत्र-शिक्षकों और निरीक्षकों के लिए अनौपचारिक शिक्षा में एक अनुकूलन-उत्पादन कार्यगोष्ठी।

—मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर के बच्चों के निष्पादन को जाँचने वाली भाषा, गणित एवं परिवेश-अध्ययन की परीक्षण-इकाइयों के निर्माण के लिए एक चार-दिवसीय कार्यगोष्ठी।

केप परियोजना

महाविद्यालय केप (प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम) परियोजना को लागू करने में सहायता कर रहा है और उसके कार्यकलापों में हिस्सा ले रहा है। केप टीम के दो सदस्यों ने उन अधिगम युक्तियों की प्रक्रिया की कार्यगोष्ठी में भाग लिया, जिन्हें विभिन राज्यों ने छापने के लिए तैयार किया है, ताकि अधिगम केंद्रों के अध्यापक प्रशिक्षार्थी उनका इस्तेमाल कर सकें। भोपाल के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय की केप टीमों ने मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य शिक्षा संस्थानों की केप टीमों को अधिगम युक्तियों की प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग दिया है ताकि राज्य शिक्षा संस्थान उन्हें छाप सकें और छाप कर विभिन्न स्तरों पर उनकी जाँच-परख कर सकें।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर का क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह की शैक्षिक जरूरतें पूरी करता है।

सेवा-पूर्व के प्रशिक्षण-कार्यक्रम

ऐसे कुशल शिक्षकों की एक सेना तैयार करने के लिए, जो स्कूलों की शिक्षा में अभीप्सित परिवर्तन ला सकें, महाविद्यालय नीचे लिखे नियमित कोर्स चला रहा है जो उड़ीसा के उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हैं—

—कला, विज्ञान और वाणिज्य में स्नातकों तथा स्नातकोत्तरों के लिए एक-वर्षीय बी० एड० (माध्यमिक) डिगरी कोर्स।

—कला और विज्ञान में स्नातकों और स्नातकोत्तरों के लिए एक-वर्षीय बी० एड० (प्रारंभिक) डिगरी कोर्स।

—शिक्षा के स्नातकों के लिए एक-वर्षीय एम० एड० डिगरी कोर्स।

—विज्ञान स्नातकों के लिए दो-वर्षीय आल-इंडिया एम० एस-सी० (लाइफ साइंस) डिगरी कोर्स।

नीचे की सारणी बताती है कि 1980-81 में कितने छात्रों ने प्रवेश लिया और 1979-80 में विश्वविद्यालय-परीक्षा के क्या परिणाम रहे—

कोर्स का नाम	प्रवेशार्थी	विश्वविद्यालय-परीक्षा के परिणाम				
		परीक्षा में बैठे	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	कुल	%
बी० एड० (विज्ञान) माध्यमिक	100	87	24	25	69	79.3%
बी० एड० (कला) माध्यमिक	62	54	21	23	44	81.4%
बी० एड० (वाणिज्य)	21	19	9	8	17	89.4%
बी० एड० (विज्ञान) प्रारंभिक	8	6	4	1	5	83.3%
बी० एड० (कला) प्रारंभिक	10	10	8	—	8	80.0%
म० एड०	31	22	7	10	17	77.0%
आल इंडिया एम० एस-सी० लाइफ़ साइंस) एड०	40	16	16	—	16	100.0%

सेवाकालीन प्रशिक्षण-कार्यक्रम

अध्यापकों की शिक्षण-कुशलता बढ़ाने वाले कुछ अन्य कार्यक्रम हैं—

—ग्रीष्म स्कूल-सह-पत्राचार-पाठ्यक्रम ।

—पत्राचार-सह-संपर्क पाठ्यक्रम ।

—विस्तार-कार्यक्रम ।

ग्रीष्म स्कूल-सह-पत्राचार-पाठ्यक्रम

उत्कल विश्वविद्यालय की बी० एड० डिगरी दिलाने वाला यह पाठ्यक्रम विशेष कर उन अप्रशिक्षित स्नातकों और स्नातकोत्तर अध्यापकों के लिए है, जो पूर्वी अंचल के मान्यता-प्राप्त मिडिल/हाई/हायर सेकंडरी स्कूलों में कम से कम पाँच वर्ष तक पढ़ा चुके हैं । सन् 1960 के गीष्म में भर्ती हुए शिक्षकों की कुल संख्या और 1979-80 के परीक्षा-परिणाम आगे की सारणी में दिए जा रहे हैं—

कोर्स का नाम	सत्र	प्रवेशार्थी 1980	शिक्षकों की संख्या	विश्वविद्यालय-परिणाम 1979-80			
				प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	कुल	%
बी० एड०	प्रथम ग्रीष्म	338	—	—	—	—	—
(माध्यमिक)	द्वितीय ग्रीष्म	251	298	63	182	245	82.3%
बी० एड०	प्रथम ग्रीष्म	100	—	—	—	—	—
(प्रारंभिक)	द्वितीय ग्रीष्म	100	102	28	58	86	84.3%
कुल :		789	400	91	240	331	82.7%

पत्राचार-सह-संपर्क पाठ्यक्रम

विभिन्न स्कूली विषयों में, सेवा कर रहे ऐसे 127 अध्यापकों के अनुकूलन के लिए चार संपर्क-कार्यक्रम किए गए, जिन्होंने छह महीने वाले पत्राचार और 15 दिन वाले संपर्क कार्यक्रमों का पत्राचार वाला अंश सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।

रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा बनाए गए आदर्श के आधार पर विभिन्न राज्यों के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्मित्त नई पाठ्यचर्या को लागू करने के लिए बहुत बड़ी संख्या में शिक्षकों को तैयार करने के लिए ये पाठ्यक्रम शुरू किए गए थे। पूरे किए गए संपर्क-कार्यक्रमों और विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित किए गए अध्यापकों की संख्या आगे की सारणी में दी जा रही है—

1980-81 में
पत्राचार-सह-संपर्क पाठ्यक्रम की संपर्क-अवस्थाओं
की सूची

विषय	तारीखें	प्रतिभागियों की संख्या
जैविक विज्ञान	8-9-80 से 22-9-80 तक	34
हिंदी	10-11-80 से 24-11-80 तक	34
हिंदी	5-12-80 से 19-12-80 तक	26
भौतिकीय विज्ञान	28-2-81 से 14-3-81 तक	33
कुल		127

वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने विस्तार के अनेक कार्यक्रम भी किए। इनका विवरण आगे की सारणी में मिलेगा—

सन् 1980-81 के दौरान आयोजित विस्तार-कार्यक्रम

कार्यक्रम का शीर्षक	राज्य/क्षेत्र	किनके लिए	प्रतिभागियों की संख्या
प्रमुख कार्मिकों के लिए कम खर्च वाली शिक्षण-साधन की सामग्री के उत्पादन पर कार्यगोष्ठी ।	पश्चिम बंगाल	माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूलों के अध्यापकों, अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	11
अनुवर्ती शिक्षा केंद्रों से संबद्ध कार्मिकों की क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी ।	पूर्वी अंचल	अ० शि० के० के अवैतनिक निदेशकों, राज्य शिक्षा सचिवों, क्षेत्र सलाहकारों के लिए ।	20
प्रमुख व्यक्तियों के लिए बुक-कीपिंग के शिक्षण में सुधार लाने वाला कार्यक्रम ।	पूर्वी अंचल	अध्यापकों और प्रवक्ताओं के लिए ।	1
गणित के प्रमुख व्यक्तियों के लिए वस्तुतत्व-सम्पन्नीकरण-कोर्स ।	उड़ीसा	प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	16
प्रमुख व्यक्तियों के लिए आधुनिक भाषा प्रयोग का, और द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए व्याकरण का कोर्स ।	उड़ीसा	प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	29

कार्यक्रम का शीर्षक	राज्य/क्षेत्र	किनके लिए	प्रतिभागियों की संख्या
माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूलों में मातृभाषा बांग्ला के शिक्षण पर प्रमुख व्यक्तियों के लिए कोर्स ।	पश्चिम बंगाल	प्राथमिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	4
शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर प्रमुख व्यक्तियों के लिए कोर्स ।	बिहार	प्रशिक्षण स्कूलों और कालेजों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	28
माध्यमिक स्कूल स्तर पर द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेज़ी-शिक्षण पर प्रमुख व्यक्तियों के लिए कोर्स ।	अरुणाचल प्रदेश	माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए ।	11
मेथड मास्टर्स के लिए जीवविज्ञान में प्रमुख व्यक्तियों के लिए कोर्स ।	बिहार	माध्यमिक शिक्षकों के लिए ।	12
अध्यापक-शिक्षकों के लिए शोध-विधि ।	उड़ीसा, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	13
भाषा-शिक्षण में भाषा शास्त्र पर प्रमुख व्यक्तियों के लिए परिसंवाद ।	उड़ीसा और पश्चिम बंगाल	प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के लिए ।	14

कार्यक्रम का शीर्षक	राज्य/क्षेत्र	किनके लिए	प्रतिभागियों की संख्या
प्रमुख व्यक्तियों के लिए जेनेरल बिज़नेस में सुधार ।	पूर्वी अंचल	माध्यमिक-स्कूलों के शिक्षकों और पाली-टेक्नीक्स के प्रवक्ताओं के लिए ।	7
गणित के प्रमुख व्यक्तियों के लिए वस्तुतत्व-सम्पन्नीकरण कोर्स ।	मेघालय	नवीं-दसवीं के शिक्षकों के लिए ।	22
सामाजिक विज्ञानों अर्थात् इतिहास और नागरिक शास्त्र में वस्तुतत्व-सम्पन्नीकरण कार्यक्रम ।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए ।	35
प्रमुख व्यक्तियों के लिए जीवविज्ञान में वस्तुतत्व-सम्पन्नीकरण कोर्स ।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नवीं-दसवीं के शिक्षकों के लिए ।	23
प्रमुख व्यक्तियों के लिए भौतिकीय विज्ञानों में वस्तुतत्व सम्पन्नीकरण कोर्स ।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	नवीं-दसवीं के शिक्षकों के लिए ।	7
प्रमुख व्यक्तियों के लिए गणित में वस्तुतत्व-सम्पन्नीकरण कोर्स ।	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए ।	32
पूर्वी अंचल के ई० एस० डी० (माध्यमिक/प्राथमिक) के अवैतनिक निदेशकों और समन्वयकों की सभा ।	पूर्वी अचल	ई० एस० डी० के अवैतनिक निदेशकों/समन्वयकों के लिए ।	15

इसके अलावा, पूर्वी अंचल के अध्यापकों और अध्यापक-शिक्षकों के लिए, महाविद्यालय ने छह से पन्द्रह दिनों तक की 18 कार्यगोष्ठियाँ, परिसंवाद और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी किए। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य थे—विभिन्न विषयों में प्रतिभागियों के ज्ञान में वृद्धि करना, कक्षा की पढ़ाई को दिलचस्प और पुरअसर बनाने वाले तरीकों और कौशलों को बताना। इन कार्यक्रमों के द्वारा 300 अध्यापकों और अध्यापक-शिक्षकों को अनुकूलित किया गया।

अनौपचारिक-शिक्षा

असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में अनौपचारिक प्रणाली द्वारा प्रारंभिक शिक्षा के प्रसार के लिए, महाविद्यालय प्रयास करता रहा। इनमें से हर राज्य में दस-दस अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र गाँवों में खोले गए। हर केन्द्र के लिए एक-एक अनुदेशक और निरीक्षक पार्ट टाइम के रूप में, नियुक्त किए गए। ये लोग छह से चौदह वर्ष तक के उन बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा देंगे जो स्कूल नहीं जा पाते। सभी 40 केन्द्रों में लगभग 1600 बच्चों ने दाखिला लिया है।

पिछले वर्ष के अनुभव के आधार पर, इस वर्ष उड़िया और हिन्दी में स्थानीय रूप से प्रासंगिक शिक्षण-सामग्री बनाई गई।

इन सभी 40 केन्द्रों में भर्ती हुए बच्चों के पढ़ने, लिखने और गिनने के निष्पादन की जाँच की गई और यह पाया गया कि सत्तर प्रतिशत बच्चों का इन विषयों का ज्ञान औपचारिक स्कूलों के कक्षा 4 के बच्चों के ज्ञान के बराबर है।

केप परियोजना

पहले बनी 'अधिगम युक्तियाँ' इस वर्ष के दौरान जाँच का विषय रहीं। इस परियोजना को लागू करने के लिए, बिहार और उड़ीसा की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों के सहयोग से इन प्रदेशों के अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही, उड़ीसा के जिला और खंड स्तर के शैक्षिक प्रशासकों का अनुकूलन भी किया गया ताकि वे इस परियोजना के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में अपनी भूमिका को समझ सकें।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य और व्यावसायीकरण के कार्यक्रम

महाविद्यालय के शिल्पविज्ञान विभाग ने मोटर कारों की मशीनों की सफ़ाई आदि से सम्बन्धित कोर्स चलाए।

इसके अलावा महाविद्यालय के नीचे लिखे विभागों ने बी० एड० के छात्रों के लिए

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य के निम्नलिखित क्षेत्रों के प्रशिक्षण का प्रबंध भी किया :

विभाग	कोर्स	स० उ० का० के क्षेत्र
शिल्पविज्ञान	बी० एड०	1. रेडियो बनाना 2. काष्ठ-कला 3. कम खर्च वाले सामान बनाना
वाणिज्य	बी० एड०	1. टंकण कला 2. कार्यालय-कार्य
कृषि	बी० एड०	सब्जी-उत्पादन

पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यचर्याओं का निर्माण

वर्ष के दौरान शुरू की गईं कुछ गतिविधियाँ—

—केन्द्रीय विद्यालयों की कक्षा VIII के लिए एक पूरक-पठन रीडर की पाण्डु-लिपि, अंग्रेज़ी विभाग के कार्मिकों ने तैयार की ।

—चार-वर्षीय एकीकृत बी०एससी०, बी०एड० और बी०ए०, बी०एड० (पास और ऑनर्स कोर्स) के लिए नव परिवर्तनों वाली पाठ्यचर्याओं का निर्माण महाविद्यालय के विभिन्न विभागों के कार्मिकों ने किया है ।

—महाविद्यालय के शिक्षा विभाग ने दो पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं—"शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, अंक III" और "प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण" विशेषांक ।

—वर्ष के दौरान महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों ने 58 शोध प्रबंध व्यक्तिगत रूप से लिखे । ये प्रबंध या तो छप चुके हैं या छापने के लिए स्वीकार किए जा चुके हैं । विस्तृत विवरण इस प्रकार है—

विषय-क्षेत्र	सन् 1980-81 में प्रकाशित हुए शोध-प्रबंधों की संख्या	प्रकाशन के लिए स्वीकृत हुए शोध-प्रबंधों की संख्या	कुल
भौतिकी	15	18	33
रसायन विज्ञान	—	2	2
जीवविज्ञान	4	4	8
शिक्षा	12	3	15
कुल	31	27	58

पूरे किए गए या शुरू किए गए अनुसंधान

कुछ शैक्षणिक कर्मचारियों ने पीएच० डी० के शोध-छात्रों का मार्गदर्शन किया।

नीचे की विवरणिका से पता चलता है कि सन् 1980-81 के दौरान महाविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों के मार्गदर्शन में किन-किन विषय-क्षेत्रों में कितने शोध-छात्रों को पीएच० डी० मिल गई, कितनों ने अपने लघु-प्रबंध जमा कर दिए हैं और कितने अभी भी पीएच० डी० की उपाधि के लिए अध्ययन कर रहे हैं—

विषय-क्षेत्र	जितनों को पीएच० डी० मिल गई	लघु-प्रबंध जमा करने वाले शोध-छात्रों की संख्या	पीएच०डी० के लिए अभी भी अध्ययन करने वाले शोध-छात्रों की संख्या
भौतिकी	—	—	1
गणित	—	—	1
जीवविज्ञान	2	—	6
शिक्षा	1	1	24
सामाजिक विज्ञान	—	—	2
भाषाएँ	—	—	5
कुल	3	1	39

अन्य माध्यमों के साथ मिल कर काम करना

महाविद्यालय के शिल्प विज्ञान विभाग ने उड़ीसा राज्य के स्कूलों में स० उ० का० को लागू करने के लिए वहाँ के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निरंतर सहायता की। शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग ने उड़ीसा की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को, उस राज्य के माध्यमिक स्कूलों के लिए समुचित फिल्म-आलेख तैयार करने में मदद दी। इस विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के शिक्षण-साधन विभाग को माध्यमिक स्कूलों के लिए 'भारत का स्वाधीनता-संग्राम' पर तैयार दृश्य-सामग्री की समीक्षा करने में मदद दी। इसी विभाग ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग को 'कक्षा I से X तक की ललित कलाओं की पाठ्यचर्या का प्रारूप' विकसित करने में सहायता दी। महाविद्यालय का शिल्पविज्ञान विभाग पूर्वी अंचल की ज़रूरतों का सर्वेक्षण करने में लगा रहा। यह सर्वेक्षण इस दृष्टि से शुरू किया गया कि अभियांत्रिकी में +2 स्तर के लिए शिक्षक तैयार करने के उद्देश्य से एक ढाई-वर्षीय अध्यापक-शिक्षा का कार्यक्रम शुरू किया जा सके।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर

दक्षिणी अंचल के तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों की शैक्षिक ज़रूरतें पूरी करने का काम मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के जिम्मे है। इस महाविद्यालय में बी०एससी०, एड० के चारों कार्यक्रम चलाए जाते हैं जबकि अन्य महाविद्यालय ऐसे कार्यक्रमों को बंद कर चुके हैं।

महाविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में, वर्ष के दौरान दाखिले की स्थिति इस प्रकार रही—

पाठ्यक्रम	दाखिले
एक-वर्षीय बी०एड०	176
चार-वर्षीय बी०एससी०एड०	255
दो-वर्षीय एम०एससी०एड०	107

बी० एड० डिगरी दिलाने वाला ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार-पाठ्यक्रम चारों राज्यों में बहुत लोकप्रिय है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी 250 जगहें योग्य प्रत्याशियों से भर गईं। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 90 रहा।

विज्ञान-विभाग

बी० एससी० एड० और एम० एससी० एड० के एकीकृत कार्यक्रमों के वस्तुतत्व के सुधार की दिशा में विज्ञान-विभाग निरंतर लगा रहा है। इस विभाग ने अनेक सेवाकालीन कार्यक्रम किए हैं। प्रयोगशाला के नवीनतम उपकरण खरीद कर प्रयोगशाला की सुविधाओं को सुधारने का काम भी विभाग ने किया है। क्रमिक कठिनाई स्तर की धारणाओं पर आधारित प्रयोगशाला दर्शिकाओं और शिक्षण-सामग्री के निर्माण के कार्यक्रम भी विभाग ने आयोजित किए हैं।

शिक्षा-विभाग

सहयोगी स्कूलों के अध्यापकों के लिए मार्गदर्शन एवं अनुकूलन के अनेक कार्यक्रम शिक्षा-विभाग ने सफलतापूर्वक किए। बी० एससी० एड० के छात्रों के लिए नेगरकोएल और बेलारी में तथा बी० एड० के छात्रों के लिए शिमोगो, विजयवाड़ा, कांचीपुरम और पालाघाट में इस वर्ष हुए इंटर्नशिप के कार्यक्रम काफी सफल रहे। बहुमाध्यमी विधि के कारण विभाग का नियमित शिक्षण-कार्य काफी सुधर गया है। अभियांत्रिकी के जयचामराजेन्द्र महाविद्यालय और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में, भारत के अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के कार्मिकों के लिए शिक्षण और प्रशिक्षण की विधियों में एक कार्यक्रम के आयोजन और नियोजन में विभाग के कर्मचारी लगे रहे। इस अंचल के विभिन्न

महाविद्यालयों के लिए विभिन्न केन्द्रों पर हुए अनेक सेवाकालीन कार्यक्रमों में विभाग के कार्मिकों ने सहायता की। महाविद्यालय का एजुकेशन फ़ोरम भी बड़ा सक्रिय रहा जहाँ शिक्षा की वर्तमान समस्याओं पर चर्चाएँ हुईं जिनके अच्छे परिणाम निकले। मार्गदर्शन और सूचना केन्द्र ने एक व्यवसाय-सभा आयोजित की जिसमें विभिन्न संस्थानों के अतिथि वक्ताओं को व्यवसाय सम्बन्धी वार्ताओं के लिए आमंत्रित किया गया।

भाषाओं और सामान्य शिक्षा का विभाग

भाषाओं और सामान्य शिक्षा के विभाग ने बी-एस० सी० एड० एवं बी० एड० स्तरों पर भाषाओं के शिक्षण की विधियों के सुधार की दिशा में अच्छी प्रगति की है। विभाग ने भूगोल और परिवेश-शिक्षा में वस्तुतत्व के सम्पन्नीकरण के लिए भी कार्यक्रम किए हैं। पी० यू० सी० स्तर की पाठ्यपुस्तकों के सम्पादन के लिए हुई अनेक कार्यगोष्ठियों में विभाग के शैक्षणिक कर्मचारी सम्मिलित हुए। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए शिक्षण-सामग्री के निर्माण में भी वे शामिल हुए। केप के कार्यक्रमों में भी कुछ कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।

अंग्रेज़ी-विभाग ने बी०एससी०एड० के छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ महाविद्यालय के उन छात्रों को बोली जाने वाली अंग्रेज़ी का अभ्यास कक्षा के बाद में करवाया, जो अंग्रेज़ी नहीं पढ़ते। इस विभाग ने प्रश्न बैंक के लिए मल्टीपुल चॉयस के कुछ प्रश्न भी बनाए।

सेवाकालीन कार्यक्रम

अंचल के राज्यों की शैक्षिक आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुसार स्कूल-शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के विचार से महाविद्यालय ने अनेक प्रकार के सेवाकालीन कार्यक्रम आयोजित किए। विभिन्न राज्यों में बने अनुवर्ती शिक्षा केन्द्रों को इसने मार्गदर्शन दिया एवं प्रभावी तरीके से सेवाकालीन कार्यक्रम करने में क्षेत्र कार्यालयों की मदद की।

नए पाठ्यक्रम के संदर्भ में सेवाकालीन कार्यक्रमों की योजना बनाने और उन्हें करने में मदद देने की राज्य विभागों की प्रार्थनाओं को पूरा किया गया। महाविद्यालय में विविध प्रकार के सेवाकालीन कार्यक्रम करने में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के विभागों की मदद भी महाविद्यालय ने की।

इस वर्ष के दौरान महाविद्यालय ने जो सेवाकालीन कार्यक्रम किए, उनमें से कुछ थे—नए पाठ्यक्रमों के लिए अध्यापक-शिक्षकों के अनुकूलन; स्कूल के विषयों में वस्तुतत्व-सह-विधियों का सम्पन्नीकरण; कार्य अनुभव एवं व्यावसायीकरण; मार्गदर्शन तथा परामर्श; प्रायोगिक परियोजनाएँ; शिक्षण-सामग्री का निर्माण; विशेष शिक्षा; शैक्षिक प्रौद्योगिकी; शैक्षिक अनुसंधान; परिवेशीय शिक्षा; शैक्षिक प्रशासन एवं संस्था की योजना; शैक्षिक मूल्यांकन आदि।

नीचे की सारणी से पता चल जाएगा कि कौन-कौन से कार्यक्रम किए गए तथा उनमें कितने अध्यापकों और संसाधन-सम्पन्न व्यक्तियों ने भाग लिया—

सेवाकालीन कार्यक्रम

क्रम संख्या	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या
1.	नांजनगुड ताल्लुके के शिक्षकों के लिए परिवेश अध्ययनों की कार्यगोष्ठी ।	11
2.	तमिलनाडु के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम पर गोष्ठी ।	5
3.	केरल के शिक्षकों के लिए भूगोल में दस दिनों का कोर्स ।	34
4.	बी० एस-सी० एड० के छात्रों के लिए शिक्षण में इंटर्नशिप के निमित्त सहयोगी शिक्षकों की गोष्ठी (प्रिइंटर्नशिप गोष्ठी) ।	80
5.	बी० एस-सी० एड० इंटर्नशिप शिक्षण-कार्यक्रम के लिए बेलारी और नेगरकोएल के सहयोगी शिक्षकों के लिए अनुकूलन-गोष्ठी ।	30
6.	कर्नाटक के स्कूल पुस्तकालयों के प्रभारी शिक्षकों के लिए कार्य-गोष्ठी एवं प्रशिक्षण-कार्यक्रम ।	19
7.	शिक्षण-कार्यक्रम में बी० एड० इंटर्नशिप के लिए सहयोगी स्कूलों के हेडमास्टरों और शिक्षकों की सभा ।	248 (छात्रों को मिलाकर)
8.	कर्नाटक के प्राथमिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए उद्यान-विज्ञान में प्रशिक्षण-कार्यक्रम ।	13
9.	आंध्र प्रदेश के जूनियर कालेजों के लेक्चररों के लिए वाणिज्य में अनुकूलन पाठ्यक्रम ।	17
10.	कर्नाटक के प्राथमिक स्कूलों के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के शिक्षकों के लिए उद्यान-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य-अनुभव के प्रशिक्षण कार्यक्रम ।	17
11.	मैसूर विश्वविद्यालय से संबद्ध शिक्षा महाविद्यालयों के अध्यापक-शिक्षकों के लिए लघु-शिक्षण में कार्यगोष्ठी ।	12
12.	+2 स्तर पर रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में संसाधन-सामग्री बनाने की कार्यगोष्ठी ।	23

13. तमिलनाडु के शिक्षकों के लिए भौतिकी एवं रसायन विज्ञान में अनुकूलन कोर्स । 30

14. शैक्षिक अनुसंधान और विधि पर अनुकूलन कार्यक्रम । 30

मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में किए गए, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के कार्यक्रम

1. मैसूर में शिक्षक-प्रशिक्षण-महाविद्यालय-पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्यगोष्ठी । 26

2. दक्षिणी क्षेत्र के अनुवर्ती-शिक्षा-केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों एवं समन्वयकों की गोष्ठी । 30

अनुसंधान और विकास

शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार की समिति के अंतर्गत कई अनुसंधान-परियोजनाओं में महाविद्यालय लगा हुआ है । अनुसंधान के परिणामों की सहायता से शिक्षा की वर्तमान समस्याओं में से कुछ को सुलझाया जा सकेगा । महाविद्यालय के कुछ शैक्षणिक कर्मचारियों ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में व्यक्तिगत रूप से डाक्टरेट के लिए अनुसंधान-कार्य किया है ।

अनौपचारिक शिक्षा की परियोजना जिसने अब ग्रामीण विकास के लिए एकीकृत शिक्षा का रूप ले लिया है, बड़ी सफल हुई है । अतिथियों ने इस परियोजना का जो मूल्यांकन किया है उससे पता चलता है कि समाज में असली परिवर्तन लाने में यह कितनी उपयोगी है । शुरू किए गए कुछ कार्यकलाप हैं—किसानों, शिक्षकों और कारीगरों को उनके धन्धों में निपुण बनाने के लिए प्रशिक्षण; कोश कीटपालन (रेशम उत्पादन) के क्षेत्र में कुछ युवकों का प्रशिक्षण; परिवेशीय विधि से शिक्षण सुधारने और शिक्षण-साधनों के निर्माण के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षण; अनौपचारिक शैली और कारोबारी अक्षर-ज्ञान तथा गिनती सीखने में ग्राम-स्तर के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण; एवं उद्यान-विज्ञान और सजावटी बाग़बानी में शिक्षकों का प्रशिक्षण ।

स्कूली बच्चों की सेहत सुधारने की दृष्टि से, अध्यापकों की पोषण सम्बन्धी जानकारी की जाँच करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है । स्कूलों और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में ब्रिटिश काउंसिल की सहायता से प्राप्त 'किटों' को बाँटा गया है। समाज के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, विभिन्न विकासात्मक विभागों ने सहयोग दिया है और गहरी दिलचस्पी ली है । परियोजना में होनहार होने के सभी लक्षण हैं ।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के कार्यक्रमों की छाप, सेवा-पूर्व और सेवाकालीन दोनों दृष्टियों से, बड़ी फलदायक दीखती है । महाविद्यालय में सोचे गए अभिनव परिवर्तनों वाले

कुछ विचारों ने राज्यों के स्कूलों में मूर्त रूप ग्रहण कर लिया है। अनुसंधान और प्रयोगों के द्वारा बनाई गई योजनाओं को कुछ राज्य शिक्षा महाविद्यालयों ने स्वीकार कर लिया है। उनमें प्रमुख हैं—शिक्षण में इंटर्नशिप; लघु-शिक्षण शैली में प्रशिक्षण; कार्य अनुभव के अंगों का समावेशन; समुदाय के साथ काम करना; बहुमाध्यमी विधियों का उपयोग-प्रयोग; कम खर्च वाले सुधरे हुए उपकरणों तथा स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आदि।

भविष्य पर निगाह

इस संस्था को एक आदर्श रूप प्रदान करने के लिए, यहाँ नव परिवर्तनों वाले कई काम शुरू किए गए हैं। अपने उद्देश्यों को पाने के लिए, यह महाविद्यालय भविष्य में भी उन कामों को करता रहेगा। इस बात की पूरी तैयारी कर ली गई है कि शैक्षिक प्रौद्योगिकी, स्कूल-पूर्व की शिक्षा, प्रलेखन और सूचना जैसे विभागों का पूर्ण विकास किया जाए।

महाविद्यालय की यह कोशिश रही है कि इन कामों की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया जाए—प्रायोगिक और विकासात्मक कार्य के आधार पर आदर्श प्रतिरूपों का निर्माण; प्रमुख व्यक्तियों का प्रशिक्षण; परामर्श सेवाओं का प्रावधान। महाविद्यालय में जो सुविधाएँ और संसाधन अभी उपलब्ध हैं, उनका अधिकतम उपयोग।

प्रदर्शन स्कूल

प्रदर्शन स्कूल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध है। इस वर्ष के दौरान इसने अच्छी प्रगति की है। इस वर्ष प्राथमिक स्तर पर कक्षा IV को बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार अब यहाँ केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12 वर्षीय स्कूल का कार्यक्रम चलेगा। इस स्कूल में सामान्य शिक्षा कार्यक्रम 10 वर्षों की समाप्ति तक चलता है और इसके बाद +2 स्तर का दो वर्षों का वैकल्पिक कार्यक्रम चलता है।

+2 स्तर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, जीवविज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग को वैकल्पिक रूप में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। वार्षिक परीक्षाओं और जन-परीक्षाओं के परिणाम उत्साहवर्धक रहते आए हैं। आल इंडिया सेकंडरी स्कूल परीक्षा में 92% और आल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा में 90% परिणाम स्कूल के पक्ष में गए हैं। सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों में स्कूल छात्रों के लिए अनेक सुविधाएँ जुटाता है। यहाँ के छात्र स्कूल-स्तर और अंतर-स्कूल-स्तर की अनेक प्रतियोगिताओं में शामिल होते हैं। इस वर्ष के दौरान स्कूल-स्तर की और अंतर-स्कूल-स्तर की जो उल्लेखनीय प्रतियोगिताएँ हुईं, उनमें से कुछ ये हैं—

—देवारानम प्रतियोगिताएँ।

—ड्राइंग और पेंटिंग की ऑन द स्पॉट प्रतियोगिताएँ ।

—सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रतियोगिताएँ ।

—विज्ञान परिसंवाद ।

—सामान्य-ज्ञान-प्रतियोगिताएँ ।

—फैंसी ड्रेस प्रतियोगिताएँ ।

—नाटक प्रतियोगिताएँ ।

—बाल-दिवस-समारोह ।

स्कूल ने राष्ट्रीय एकीकरण शिविर, एन० सी० सी० वार्षिक ट्रेनिंग कैंप, ज़ोनल विज्ञान मेले आदि में भी भाग लिया । इस बात से बड़ी प्रसन्नता होती है कि स्कूल के एन० सी० सी० दस्ते को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया । हमारे एक एन०सी०सी० कैडेट को बँगलोर के गणतंत्र-दिवस-पूर्व-समारोह के लिए भी चुना गया । स्कूल के एक अध्यापक को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम के अंतर्गत गणित में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए यू० के० भेजा गया था । उन्होंने नौ महीनों की अवधि वाले कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समाप्त कर लिया है । स्कूल का कार्य संतोषजनक प्रगति से हो रहा है ।

शैक्षिक मनोविज्ञान

शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्यक्रमों के केंद्र में तीन तत्व रहे हैं—सीखने वाला या अधिगम कर्ता; सिखाने-सीखने या शिक्षण-अधिगम की प्रक्रियाएँ; और शिक्षण-अधिगम की स्थितियाँ। अधिगम और शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया के सुधार की लक्ष्य-प्राप्ति के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० ने तीन प्रकार के प्रशिक्षण-कार्यक्रम नियोजित और आयोजित किए। ये कार्यक्रम (क) प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षा संस्थानों और (ख) माध्यमिक अध्यापक-शिक्षा संस्थानों के लिए थे। परिषद् का शैक्षिक मनोविज्ञान एकक कई प्रशिक्षण-कार्यक्रम करता है। नीचे उनकी चर्चा की जा रही है—

मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना और परीक्षण-अंकों की व्याख्या करना : इस कार्यक्रम का उद्देश्य है—अध्यापक-शिक्षकों में वे आवश्यक कौशल उत्पन्न करना जिनसे वे मनोवैज्ञानिक परीक्षण ले सकें; इन परीक्षणों के प्राप्तांकों की व्याख्या कर सकें और प्राप्तांकों को छात्र तक सम्प्रेषित करने की कला जानते हों। इस कोर्स की लंबी पहुँच वाला उद्देश्य है—अध्यापक-शिक्षकों का एक ऐसा केंद्रिक समूह बनाना जो मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के इस्तेमाल में सेवा-पूर्व कोर्सों के दौरान व्यावहारिक अधीक्षित प्रशिक्षण जुटा सके । इस प्रकार के कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हालाँकि शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम के केंद्र में रहता है, फिर भी परीक्षणों की कला न जानने के कारण, शिशु को समझने की मनोवैज्ञानिक विधि का बहुत कम इस्तेमाल हो पाता है । सिद्धांत और व्यवहार में बड़ा फ़ासला है । इस फ़ासले को पाटने की दृष्टि से आठ दिनों वाले कोर्स बनाए गए ।

हर कोर्स में 15 प्रतिभागियों को रहना है। इस कार्यक्रम में तीन मनोवैज्ञानिक साधनों को रखा गया—(क) कल्चर फ़ेयर इंटेलिजेंस टेस्ट, (ख) इंटेरेस्ट इंवेंटरी, (ग) पर्सनैलिटी क्वैश्चनेयर। समूह ने मेधा, रुचि और व्यक्तित्व कारकों की व्याख्या करना सीख लिया। वर्ष के दौरान चार कोर्स किए गए—

राज्य	स्थान	तारीखें	प्रतिभागियों की संख्या
मध्य प्रदेश राजस्थान	दिल्ली	31 मार्च से 7 अप्रैल 1980 तक	14
हरियाणा पंजाब हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़	चंडीगढ़	20 से 27 नवंबर 1980 तक	13
तमिलनाडु केरल	कोयम्बतूर	29 जनवरी से 27 फरवरी 1981 तक	18
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	28 मार्च से 4 अप्रैल 1981 तक	19
		कुल :	64

वर्ष के दौरान 64 अध्यापक-शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है और आशा है कि इन संस्थानों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण अगले शैक्षणिक सत्र से शुरू हो जाएँगे।

स्कूल-परिस्थितियों में व्यवहार-परिष्करण-तकनीक का इस्तेमाल : इच्छित दिशा में उल्लेखनीय तरीके से व्यवहार को परिष्कृत करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अधिगम-सिद्धांत-विधि शिक्षक को व्यवहार-परिष्करण-तकनीकों की अनेक किस्में प्रदान करती है ताकि शिक्षक उनका इस्तेमाल कक्षा की समस्याओं के सिलसिले में रोज़ कर सकें। व्यवहार परिष्करण एक ऐसा साधन है जिसे पुरअसर तरीके से छात्रों के मार्ग-दर्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और इस प्रकार पूरी कक्षा को इच्छित दिशा में बदला जा सकता है। शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया में बाधा डालने वाले तत्वों को इनसे कम किया जा सकता है। रा० शै० अ० और प्र० प० ने 8 से 10 दिनों के प्रैक्टिकल कोर्स बनाए हैं। वर्ष के दौरान नीचे लिखे कोर्सों को चलाया गया—

राज्य	स्थान	तारीखें	प्रतिभागियों की संख्या
तमिलनाडु	मद्रास	2 से 8 मार्च 1981 तक	10
जम्मू व कश्मीर हिमाचल प्रदेश	जम्मू	23 से 29 मार्च 1981 तक	14
		कुल :	24

माध्यमिक अध्यापक-शिक्षा-संस्थानों और राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अध्यापक-शिक्षकों के लिए अधिगम और विकास पर सम्पन्नीकरण पाठ्यक्रम : अध्यापक अनुदेशों पर बल देते हैं और समझते हैं कि सीखने वाला उनसे सीख जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि अध्यापक अधिगम-प्रक्रिया के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, फिर भी लगता है कि वे यह तथ्य नहीं जानते कि कक्षा की शिक्षण-अधिगम स्थितियों में कैसे सफल ढंग से अधिगम हों। इन्हीं सब पर छह दिनों वाला एक कोर्स आयोजित किया गया जो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए था। 24 व्यक्तियों ने 24 से 29 मार्च 1981 तक इसमें प्रतिभागिता की।

प्रारंभिक अध्यापक-शिक्षा-संस्थान/राज्य शिक्षा संस्थान/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के शैक्षणिक सदस्यों व अध्यापक-शिक्षकों के लिए अधिगम और विकास पर सम्पन्नीकरण पाठ्यक्रम : बच्चों की अधिगम और विकास प्रक्रिया में प्राथमिक स्कूल शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर सामान्यतः यह देखा जाता है कि शिक्षक या शिक्षिका को अधिगम अथवा विकास प्रक्रियाओं की गहरी जानकारी नहीं होती। वे इनके सिद्धांतों को भी नहीं जानते। इतना ही नहीं, वे 'रिइनफोर्समेंट' के सिद्धांतों को भी नहीं जानते जिनकी ज़रूरत कक्षा संचालन के लिए पड़ती है। छह से ग्यारह वर्ष के बच्चों के अधिगम और विकास की प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षकों के ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक कोर्स आयोजित किया गया। 22 से 28 फरवरी 1981 तक चलने वाला यह कोर्स मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए था।

शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन का डिप्लोमा कोर्स

परिषद् का शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक एक नौ महीने वाला स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में चलाता आ रहा है। सन् 1980-81 में इक्कीसवाँ कोर्स आयोजित किया गया। 25 प्रशिक्षार्थी, जिनमें चार जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक राज्य सरकारों द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए थे, इस कोर्स

के लिए भर्ती किए गए। प्रशिक्षुओं को शैक्षिक-भ्रमण के लिए बंबई भी ले जाया गया। उन्होंने व्यावसायिक और शैक्षिक महत्व के अनेक स्थल देखे। प्रशिक्षुओं ने अभ्यास-स्कूलों में से दो में एक गोष्ठी-सह-कैरियर-प्रदर्शनी भी की। कोर्स के छात्र स्कूल-परामर्शक, प्रशिक्षण महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान या शिक्षा विभागों या रा० शै० अ० और प्र० प० के शैक्षणिक कर्मचारियों के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किए जाते हैं। अन्य क्षेत्रों में राज्य स्तर की एजेंसियों के मार्गदर्शन के काम को भी वे ही संभालते हैं।

केंद्रीय जन सेवा आयोग, महाराष्ट्र सरकार, समाज कल्याण मंत्रालय, विद्या भारती संस्थान समूह को विस्तार-परामर्श-कार्यक्रम के अंग के रूप में सहायता प्रदान की गई। इजिप्ट के दो अधिकारियों का अनुकूलन भी इसी में शामिल था।

मार्गदर्शन-प्रयोगशाला

सूचना सेवा को गठित और संचालित करने का काम तथा साहित्य-संकलन का काम हो रहा है। एकत्र की गई सामग्री को वर्गीकृत किया जा रहा है। मार्गदर्शन-प्रयोग-शाला का उपयोग प्रशिक्षण के अनुबद्ध के रूप में किया गया।

प्रकाशन

नीचे लिखी सामग्री प्रकाशित की गई—

(क) माध्यमिक स्कूल के छात्रों में व्यावसायिक सूचना के विकीर्णन में समस्याएँ।

(ख) पहली पीढ़ी के अधिगम कर्ताओं पर अनुसंधान—कक्षा X के स्तर पर अध्ययन की रिपोर्ट।

(ग) 'अनुभवातीत ध्यान' पर वैज्ञानिक अनुसंधानों की समीक्षा।

(घ) कैरियर-विकास के लिए कार्यक्रमों और मार्गदर्शन सेवाओं को मज़बूत करना।

8

शैक्षिक प्रौद्योगिकी और शिक्षण-साधन

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

आलोच्य वर्ष में शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए। इनमें बहुमाध्यमी माड्यूलों का विकास, शैक्षिक फिल्मों और वीडिओ कार्यक्रमों का निर्माण तथा श्राव्य-कार्यक्रमों का आयोजन शामिल हैं। इस वर्ष के दौरान आयोजित कार्यक्रम नीचे दिए गए हैं।

शैक्षिक दूरदर्शन/रेडियो

शैक्षिक दूरदर्शन तथा रेडियो के लिए कई कार्यगोष्ठियाँ और शैक्षणिक कोर्स आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का सार-संक्षेप नीचे दी गयी तालिका में दिखाया गया है।

कार्यक्रम	भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या/समय	भाग लेने वाले राज्य। कार्यक्रम की उपलब्धियाँ
दूरदर्शन केन्द्रों के शैक्षिक आलेख लेखकों के अभिनवीकरण तथा चयन के लिए कार्यगोष्ठियाँ	5 दिन	दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा
शैक्षिक दूरदर्शन के लिए आलेख-लेखन का गहन प्रशिक्षण-कोर्स	19 व्यक्ति	38 शैक्षिक दूरदर्शन-आलेखों का विकास।
1/2 इंच पोर्टेबुल वीडिओ में प्रशिक्षण कोर्स	12 व्यक्ति	वीडिओ निर्माण की विधि का ज्ञान भाग लेने वालों को दिया गया।
शैक्षिक दूरदर्शन में बाल कार्यक्रम निर्माताओं तथा आलेख-लेखकों के लिए अभिनवीकरण विचारगोष्ठी	4 दिन 35 व्यक्ति	शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम किए गए।
शैक्षिक दूरदर्शन के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण	7 दिन	राजस्थान, बिहार, मध्यप्रदेश।
प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए शैक्षिक दूरदर्शन के आलेखों के निर्माण हेतु कार्यगोष्ठी	10 व्यक्ति	सामाजिक विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञान के विषयों पर आलेख तैयार किए गए।
प्राथमिक स्तर के विषयों के शिक्षण में दूरदर्शन के योगदान संबंधी अध्यापकों और विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर कार्यगोष्ठी	19 व्यक्ति	विभिन्न विषयों में ऐसे प्रकरणों को चुना गया जिनमें दूरदर्शन का प्रयोग सफलतापूर्वक किया जा सकता है।
शैक्षिक रेडियो के लिए आलेख लेखकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	15 दिन 20 व्यक्ति	कार्यक्रम का आयोजन श्रीनगर में किया गया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी में मूल्यांकन

शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों के कर्मचारियों के लिए नवम्बर 1980 में "शैक्षिक

प्रौद्योगिकी में मूल्यांकन" पर एक दो-सप्ताह वाला प्रशिक्षण तथा अभिनवीकरण कोर्स का आयोजन किया गया।

प्रौढ़ शिक्षा

राँची, देवघर, उदयपुर और लखनऊ में चार कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनका विषय था "राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के शिक्षकों के लिए शिक्षण अधिगम तकनीकों में नवाचारीय पद्धतियाँ"। इन कार्यगोष्ठियों के फलस्वरूप "प्रौढ़ शिक्षण : नई विधि, नई विधा" नामक पुस्तिका तैयार कर ली गयी।

प्रौद्योगिकी पर विचारगोष्ठी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, महाराष्ट्र तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, तमिलनाडु द्वारा क्रमशः पुणे और मद्रास में शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर राज्य स्तर की तीन-दिवसीय विचारगोष्ठियों में प्रौद्योगिकी केन्द्र ने भाग लिया तथा इन विचार गोष्ठियों के आयोजन में भी सहयोग दिया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र का अगले वर्ष से शैक्षिक प्रौद्योगिकी में एक डिप्लोमा कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव है। इस डिप्लोमा कोर्स के लिए व्यापक पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए तथा उसे अन्तिम रूप देने के लिए एक तीन-दिन वाली विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के विभागों से लगभग 30 शिक्षा-शिल्पवैज्ञानिकों ने इसमें भाग लिया।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मूल्यांकन

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा निर्मित सामग्री तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मूल्यांकन केन्द्र के सभी कार्यकलापों का एक अनिवार्य अंग है। इस वर्ष केन्द्र द्वारा चलाए गए अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सामग्री का मूल्यांकन किया गया। मूल्यांकन के परिणामों की जानकारी कार्यक्रमों के संयोजकों तथा सामग्री के निर्माताओं को कार्यक्रमों तथा सामग्री में सुधार लाने की दृष्टि से दी गई।

निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययनों को पूरा कर लिया गया :

—दिल्ली के स्कूलों के लिए रेडियो प्रसारण, एक अध्ययन। यह रिपोर्ट छप चुकी है।

—दिल्ली में स्कूली दूरदर्शन कार्यक्रमों की बोधगम्यता और प्रयोग का अध्ययन।

—"दिल्ली में माध्यमिक स्तर पर पत्राचार शिक्षा" विषय पर अनुसंधान रिपोर्ट पूरी कर ली गयी है और उसे लिपिबद्ध किया जा चुका है।

—एक अध्ययन रिपोर्ट "स्कूलों के लिए रेडियो कार्यक्रम तथा राज्य के शैक्षिक प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठों की भूमिका" विषय पर निकाली गयी है जिसमें स्कूलों के लिए रेडियो कार्यक्रमों से संबंधित अनुभवों की माला संश्लिष्ट है।

प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी-शिक्षण की रेडियो परियोजना

प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण की परियोजना, जिसमें मुद्रित सामग्री के साथ रेडियो का भी प्रयोग किया गया हो, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र द्वारा चलायी जा रही है। इसका उद्देश्य है प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों द्वारा भाषा अधिगम में सुधार। यह प्रयोग राजस्थान के अजमेर और उदयपुर जिलों के अन्तर्गत 15 पंचायत समितियों के 483 प्राथमिक विद्यालयों में चलाया जा रहा है। सन् 1979-80 में कक्षा I से यह प्रयोग शुरू किया गया था। आलोच्य वर्ष में इसे कक्षा II तक बढ़ाया गया। सन् 1980-81 में, कक्षा I और II के लिए क्रमशः 15-15 मिनट के दो रेडियो प्रसारण प्रतिदिन किए गए। अप्रैल 1980 में शैक्षिक सत्र की समाप्ति पर विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन किया गया। यह पाया गया कि परियोजनेतर विद्यालयों की तुलना में परियोजना विद्यालयों के बच्चों ने पठन, लेखन, श्रवण और भाषा विकास की दृष्टि से अधिक योग्यता अर्जित की। इस वर्ष परियोजना को कक्षा II और III तक बढ़ाया जाएगा।

बुनकरों की अनुवर्ती-शिक्षा संबंधी परियोजना

दिल्ली में बुनकरों के आवासीय क्षेत्र नन्दनगरी के बुनकरों की सतत-शिक्षा के लिए पाठ्यक्रमीय-सामग्री के मूल रूप को विकसित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। आलोच्य समय के दौरान दिल्ली और पानीपत में कई कार्यगोष्ठियों का आयोजन किया गया जिनका उद्देश्य ऐसी पठन-सामग्री तैयार करना था जिसे बुनकरों के प्रशिक्षण में प्रयुक्त किया जा सके ताकि वे अपने बुनाई के तरीकों, डिजाइनिंग, अपने बने माल की बिक्री और व्यवस्था आदि में सुधार ला सकें। प्रशिक्षण-सामग्री का मसौदा अब तैयार कर लिया गया है और इसे बुनकरों के प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के शिक्षकों की अनुवर्ती शिक्षा के लिए बहुमाध्यमी माड्यूल

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने इस संबंध में देश के कई भागों में कार्यगोष्ठियों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। इन कार्यगोष्ठियों के परिणामस्वरूप एक प्रवेशिका, एक अभ्यास-पुस्तिका और एक अध्यापक-पुस्तिका (हैंडबुक) का अब तक निर्माण किया जा चुका है जिन्हें प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों में प्रयोग किया जाएगा।

फिल्मों, वीडिओ और श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण

अधिगम प्रक्रिया में सहायता देने के लिए कई फिल्मों और रेडियो श्रव्य-कार्यक्रमों का निर्माण किया गया। इन्हें मूल कार्यक्रमों के रूप में निर्मित किया गया ताकि प्रौद्योगिकी केन्द्र में इन्हें प्रशिक्षण के लिए प्रयोग में लाया जा सके।

—रूसी कठपुतलियों पर दो फिल्मों का निर्माण पूरा हो चुका है। इनके नाम हैं— (i) "जादू की किताब" और (ii) "सेमुर्ग" अथवा "आह्लाद का पक्षी"। 16 मि० मी० की ये फिल्में ईस्टमैनकलर में हैं।

—35 मिलीमीटर और 16 मिलीमीटर (ब्लैक ऐंड ह्वाइट) में एक फिल्म 'साइंटिफिक ऐटीच्यूड' नाम से तैयार की गई है।

—16 मिलीमीटर की एक रंगीन फिल्म 'सोलर एक्लिप्स' पूरी होने वाली है।

—'इन्नोवेशंस इन एजूकेशन नं० 2' (मोबाइल क्रेशेज़) पूरी होने वाली है।

—प्रशिक्षण सत्र के दौरान जो आलेख तैयार किए गए थे उन पर आधारित 12 दूरदर्शन कार्यक्रम बच्चों के लिए तैयार किए गए।

—रेडियो कार्यक्रमों की एक शृंखला तथा अन्य सहायक सामग्री कक्षा I और II के विद्यार्थियों को प्रथम भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ाने के लिए तैयार की गई। आलोच्य वर्ष में कक्षा I के लिए कुल 157 कार्यक्रम और कक्षा II के लिए कुल 155 कार्यक्रम तैयार किए गए।

—शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण की परियोजना के अन्तर्गत आकाशवाणी के पुरालेख भण्डार की सामग्री के उपयोग से कई नये श्रव्य कार्यक्रम तैयार किए गए, जिससे कुल कार्यक्रमों की संख्या बढ़कर 267 हो गई।

फिल्में

आलोच्य समय के दौरान विद्यालय पाठ्यक्रम से संबंधित नीचे लिखी फिल्मों का निर्माण किया गया :

—शिक्षण में ग्राफ़िक साधन

—लचीलापन

इन फिल्मों का हिन्दी रूपांतरण करने और सेंसर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की ओर केन्द्र अग्रसर है।

एजूकेशनल फिल्म लाइब्रेरी एसोसियेशन द्वारा 1980 में न्यूयार्क में आयोजित अमेरिकन शार्ट फिल्म फ़ेस्टीवल में रा० शै० अ० और प्र० प० की फिल्म "किशन ऐंड द मैजिक चैरियट" ने गौरवशाली "रेड रिबन अवार्ड" जीता। न्यूयार्क की चर्चित फिल्म्स के

साथ इस फिल्म के सिनेमा और दूरदर्शन पर वितरण संबंधी बातचीत चल रही है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी केंद्र ने कोई 1600 से अधिक अमरीकी डालर अग्रिम राशि के रूप में अर्जित किए हैं। जर्मन संघीय गणतंत्र की बायोस्कोप फिल्म्स के साथ एक और सौदे पर बातचीत चल रही है जिससे प्रौद्योगिनी केंद्र को 5000 जर्मन डोइचमार्क की आय होगी।

शिक्षण-साधन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, अध्यापकों के प्रयोग के लिए कई प्रकार के शैक्षणिक उपकरणों का निर्माण तथा उनका डिजाइन तैयार करती है ताकि अध्यापक उनका प्रयोग कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को उत्कर्ष प्रदान कर सकें। इन उपकरणों में चार्ट, माडल, फिल्में और फिल्म स्ट्रिपें शामिल हैं। इन उपकरणों के उपयोग और निर्माण के लिए राज्य स्तर पर शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करना भी इस विभाग का एक मुख्य काम है। आलोच्य वर्ष में किए गए कार्यों का विवरण निम्नलिखित है।

सामाजिक कार्य अनुसंधान केन्द्र, तिलोनिया (राजस्थान) में कम कीमत के शैक्षणिक साधन तैयार करने के लिए कार्यगोष्ठी

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने कम कीमत के शैक्षणिक साधन तैयार करने के लिए 10 से 15 जुलाई 1980 तक राजस्थान के 32 ग्रामीण प्राथमिक अध्यापकों के लिए सामाजिक कार्य अनुसंधान केन्द्र (एस० डब्ल्यू० आर० सी०) में एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया। सामाजिक कार्य अनुसंधान केन्द्र द्वारा चलाए जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के 18 अध्यापकों और ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों के 13 अध्यापकों ने इस कार्यगोष्ठी में भाग लिया। इस कार्यगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य कार्यगोष्ठी में भाग लेने वाले अध्यापकों द्वारा 25 माडलों के ड्राफ्ट मैनुअल का परीक्षण करवाना था।

कार्यगोष्ठी के दौरान जनजातीय प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा पाँच अन्य कार्यगोष्ठियों में तैयार किए गए कम कीमत के चुने हुए शैक्षणिक साधनों का परीक्षण किया गया, जो विज्ञान के विषय में प्रयोगों और माडलों के रूप में थे। एक साइकिल और उसके भागों का विज्ञान के पाठ्यक्रम के साथ समन्वय करके विज्ञान की संकल्पनाओं/साधनों की पहचान कराई गई। एस० सी० ई० आर० टी०, उदयपुर, यू० एस० सी० एस० अहमदाबाद तथा दिल्ली के विशेषज्ञों द्वारा कम कीमत के शैक्षणिक साधनों का प्रदर्शन दिया गया। इस के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में एक मैनुअल तैयार किया जा रहा है जिसे ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों में वितरित किया जाएगा।

बच्चों के लिए अनौपचारिक विधि से अधिगम के दृश्य-श्रव्य साधन

बच्चों के लिए अनौपचारिक विधि से अधिगम के दृश्य-श्रव्य साधनों पर एक चार-दिन वाली कार्यगोष्ठी तथा विचारगोष्ठी का आयोजन विश्वेश्वरैया औद्योगिक तथा तकनीकी संग्रहालय, बंगलौर के सहयोग से किया गया। समुदाय में बच्चों की शिक्षा के लिए दृश्य-श्रव्य साधनों के उपयोग संबंधी निम्नलिखित अत्यंत महत्वपूर्ण और संबंधित प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया :

अधिगम किसके लिए ?
अधिगम किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ?
अधिगम किन साधनों द्वारा (दृश्य श्रव्य साधन) ?
प्रशासकीय/संगठनात्मक ढाँचा
साफ्ट-वेअर
क्षेत्र/विषय
सीमाएँ

पचमढ़ी में कक्षा VI से VIII के लिए विज्ञान के चार्टों का निर्माण

कक्षा VI से VIII के लिए विज्ञान के चार्टों के निर्माण के लिए पचमढ़ी, मध्य प्रदेश में मध्यप्रदेश के शिक्षा निदेशालय तथा किशोर भारती, बांखेड़ी के सहयोग से एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यगोष्ठी में मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव, होशंगाबाद के माध्यमिक विद्यालयों के 31 अध्यापकों तथा शिक्षण साधन विभाग के संकाय के सदस्यों ने भाग लिया। संबंधित दृश्य सामग्री सहित तीन विज्ञान के चार्ट बनाए गए तथा अन्य दस चार्टों के विषयों को अन्तिम रूप दिया गया। अब इन चार्टों को किशोर भारती, बाँखेड़ी की सहायता और मार्ग दर्शन में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा संशोधित करके छापा जाएगा।

फिल्म प्रसारण पर भारत-अमरीकी उपसमिति के अधीन फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे में विज्ञान-फिल्मों के लिए आलेख-लेखन

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् चार्टों, टेप स्लाइडों, फिल्मों और अन्य कम कीमत के शैक्षिक साधनों पर कार्यगोष्ठियाँ करने और अध्यापकों को प्रशिक्षण

देने में लगी हुई है। परिषद् ऐसे दृश्य-श्रव्य साधनों के निर्माण में भी लगी हुई है जिनके व्यापक प्रयोग और विस्तार की संभावनाएँ हैं।

देश में शैक्षिक साफ्टवेअर सभ्यता के निर्माण के एक प्रयास के रूप में परिषद् देश के वैज्ञानिकों को अपने कार्यक्रमों में अधिकाधिक समविष्ट करने का प्रयत्न कर रही है। भारत में दूरदर्शन के आगामी प्रसार को ध्यान में रखते हुए, जो कि अगले वर्ष भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इनसेट) के चालू होने के साथ शुरू हो जाएगा, ऐसा किया जा रहा है।

विज्ञान-फिल्मों के आलेख-लेखन पर परिषद् ने 5 से 24 जनवरी 1981 तक एक कार्य-गोष्ठी का आयोजन किया जो कि इस शृंखला की दूसरी कार्यगोष्ठी थी। यह कार्यगोष्ठी, फिल्मों और प्रसारण पर भारत-अमरीकी उपसमिति तथा शिक्षा और संस्कृति पर भारत-अमरीकी उपआयोग के तत्वावधान में की गई। भारतीय फिल्म और दूरदर्शन संस्थान, पुणे के सहयोग से एक कोर्स का आयोजन किया गया जिसमें दो अमरीकी विशेषज्ञों और 32 वैज्ञानिकों, अध्यापकों और संचार साधन विशेषज्ञों ने भाग लिया।

इस कार्यगोष्ठी के निम्नलिखित उद्देश्य थे :

—चलचित्रों की भाषा में विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

—विभिन्न प्रकार की विज्ञान फिल्मों का प्रदर्शन करना।

—शिक्षा के संचार माध्यमों तथा प्रौद्योगिकी का विश्लेषण करके देखना कि देश के विकास में विज्ञान फिल्में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं या नहीं।

—समूह में आलेख तैयार करना तथा दो कम अवधि की फिल्में बनाना, तथा

—वैज्ञानिकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से 5 से 10 मिनट की अवधि के आलेख तैयार करवाना जो आम जनता में लोकप्रिय हों।

तीन सप्ताह के दौरान पाँच-पाँच मिनट की दो फिल्में निर्मित की गईं। इन में से एक "घर्षण" पर थी और दूसरी "प्रैशर कुकर" की कार्यविधि पर। इसके अतिरिक्त, फिल्म के लोकप्रिय माध्यम से विज्ञान के संचार के अभ्यास के रूप में 25 आलेख लिखे गए। लगभग 50 फिल्में और वीडियो टेप पर दस कार्यक्रम दिखाए गए।

भूगोल के चार्टों का निर्माण

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्राकृतिक भूगोल पर चार्टों को अन्तिम रूप देने के लिए एक कार्यगोष्ठी का आयोजन 2 से 4 फरवरी 1981 तक किया गया। इस गोष्ठी में 10 विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, राज्य शिक्षा संस्थान दिल्ली के विशेषज्ञ तथा कुछ अध्यापक शामिल थे। ये चार्ट पहले राज्य शिक्षा संस्थान, दिल्ली के सहयोग से सितम्बर 1978 में आयोजित एक कार्यगोष्ठी में तैयार किए गए थे। इस गोष्ठी में भाग लेने वालों ने प्राकृतिक

भूगोल पर इन चार्टों की दर्शनीयता तथा विषय-वस्तु की दृष्टि से भलीभाँति समीक्षा की और उन्होंने सुधार के लिए कुछ सुझाव भी दिए। चार्टों में इन सुझावों की दृष्टि से सुधार किया जा रहा है।

चार्टों के निर्माण पर कार्यगोष्ठी

दिल्ली के शैक्षिक योजना ग्रुप की प्रार्थना पर सरदार पटेल विद्यालय, नई दिल्ली में 26 से 28 फरवरी 1981 तक चार्टों के निर्माण पर एक तीन-दिन वाली कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। शैक्षिक योजना ग्रुप के 11 सहयोगी संस्थानों के 21 अध्यापकों ने इस गोष्ठी में भाग लिया। विभिन्न प्रकार के चार्ट बनाने की विधि में इस गोष्ठी में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास पर शैक्षणिक साधनों के निर्माण के लिए कार्यगोष्ठी

भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास पर शैक्षणिक साधनों के निर्माण के लिए दूसरी कार्यगोष्ठी का आयोजन 4 से 7 मार्च 1981 तक किया गया। इस कार्यगोष्ठी में प्रस्तुत करने के लिए लगभग 50 नामिकाएँ तैयार की गईं। ये नामिकाएँ स्वतंत्रता आंदोलन के 1922 बाद से स्वतंत्रता की प्राप्ति (15 अगस्त 1947) तक आंदोलन के विभिन्न पक्षों को दर्शाती हैं। इनके साथ विभिन्न घटनाओं से संबंधित आलेख भी तैयार किए गए। इस गोष्ठी में लगभग 20 विशेषज्ञों ने भाग लिया जिनमें विक्टोरिया मैमोरियल संग्रहालय, कलकत्ता, राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद् तथा देश के अन्य कई संस्थानों के अध्यापक-शिक्षक, शिक्षक, विषय-विशेषज्ञ तथा संचार-साधन विशेषज्ञ शामिल थे।

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अध्यापकों के सम्मुख भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को तस्वीरों तथा संबंधित आलेखों द्वारा इस प्रकार प्रस्तुत करना है जिससे कि यह विषय उनके लिए चित्ताकर्षक बन जाए। इन नामिकाओं में दर्शाई गई कुछ मुख्य घटनाएँ ये हैं—साइमन आयोग का बहिष्कार, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, कामगारों व किसानों का आंदोलन तथा सोशिलिष्ट आंदोलन, इनकलाबी नेता, विश्व में स्वतंत्रता आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिन्द फ़ौज, केबिनेट मिशन, देश का विभाजन तथा स्वतंत्रता प्राप्ति।

चार दिन की कार्यगोष्ठी में प्रत्येक नामिका की भलीभांति समीक्षा और निरीक्षण विषय विशेषज्ञों तथा संचार-साधन विशेषज्ञों ने किया। विशेषज्ञों ने सुधार हेतु बहुत से सुझाव दिए। इन विशेषज्ञों तथा कार्यगोष्ठी के संचालकों के विचारों, प्रतिक्रियाओं और सुझावों के आधार पर इन नामिकाओं को संशोधित किया जा रहा है ताकि इन्हें पूर्ण किया

जा सके और इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करके 1981-82 के दौरान स्कूलों को प्रयोग हेतु दिया जा सके ।

फ़ोलियो के रूप में इस सामग्री का समायोजन हो जाने पर, इस विषय को माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को पढ़ाना अध्यापकों के लिए न केवल सुगम हो सकेगा अपितु यह अधिक प्रभावोत्पादक भी होगा । ये तस्वीरें ऐतिहासिक घटनाओं के मौलिक चित्रों की फोटो कापी हैं जो उस समय की पत्र-पत्रिकाओं अथवा पुस्तकों में छपी थीं । इसी प्रकार तस्वीरों से संबंधित आलेख भी उस समय के जाने माने नेताओं के भाषणों तथा लेखों से लिए गए हैं तथा उन प्रस्तावों से उद्धृत किए गए हैं जो उस समय की राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा पास किए गए थे । इस सामग्री के अधिगम द्वारा अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास के उन मौलिक स्रोतों तक पहुँच पाना सुगम हो जाएगा जिन पर राष्ट्रीय परिषद् की आधुनिक भारतीय इतिहास की पाठ्यपुस्तक आधारित है । इन नामिकाओं (पैनलों) के निर्माण के लिए इतिहास के विशेषज्ञों की एक टीम ने राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेहरू स्मारक संग्रहालय, गांधी स्मारक संग्रहालय, विक्टोरिया मैमोरियल हाल, नेताजी अनुसंधान ब्यूरो, कलकत्ता से सभी स्रोतों की खोज की तथा इस तरह बहुत-सी तस्वीरों, अखबारों की कतरनों तथा दस्तावेज़ों का नामिकाओं के निर्माण के लिए चुनाव किया ।

विचारगोष्ठियाँ

बहुत-सी अन्य विचारगोष्टियों/कार्यगोष्ठियों का आयोजन भी किया गया । इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है ।

राज्य फिल्म लाइब्रेरियों का विस्तार एवं विकास : 10 से 12 मार्च 1981 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें राज्य फिल्म लाइब्रेरियों से संबंधित 12 व्यक्तियों ने भाग लिया । नेशनल फिल्म आरकाइव्ज़, पुणे के संग्रहयाल (क्यूरेटर), श्री पी० के० नायर को विशेष निमंत्रण द्वारा कार्यगोष्ठी के संचालन हेतु बुलाया गया। इस कार्यगोष्ठी में राज्य फिल्म लाइब्रेरियों की वर्तमान अवस्था और उनके उपयोग के विभिन्न पक्षों पर तथा शिक्षाप्रद फिल्मों की प्राप्ति संबंधी विभिन्न समस्याओं पर चर्चा हुई ।

शिक्षण साधन विभाग के उत्पादनों और मूल कार्यक्रम रूपों का मूल्यांकन : शिक्षण साधन विभाग के उत्पादनों और मूल कार्यक्रम रूपों पर एक कार्यगोष्ठी का आयोजन 23 से 26 मार्च 1981 तक किया गया जिसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा उत्पादित सामग्री का मूल्यांकन/परीक्षण प्राथमिक विद्यालयों और पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा अन्य अधिकारियों ने किया ।

पर्यावरण पर फिल्म : इस कार्यक्रम में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका और पब्लिक स्कूलों के 12 प्राथमिक अध्यापकों ने 23 और 24 मार्च 1981 को भाग

लिया । फिल्म को थोड़ा-थोड़ा करके कई भागों में दिखाया गया तथा अध्यापकों की प्रतिक्रियाओं को प्राप्त किया गया ।

लैम्पों पर तस्वीरों/शब्दों का प्रस्तुतीकरण : इस कार्यक्रम में दिल्ली के माध्यमिक विद्यालयों के 8 अध्यापकों और परिषद् के विशेषज्ञों ने भाग लिया । नवम्बर 1980 में तीन-मूर्ति भवन में हुई राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में 33 फोटो चित्रों और उनके विवरणों को लैम्पों पर प्रदर्शित किया गया । भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति से प्रत्येक चित्र पर और उस के विवरण पर अपने विचार प्रकट करने के लिए कहा गया । उनकी इन प्रतिक्रियाओं को तस्वीरों और आलेखों में सुधार के लिए नोट कर लिया गया ताकि बाद में इन से एक टेप-स्लाइड बनाई जा सके ।

'सोलर एक्लिप्स' आलेख का पूर्व परीक्षण : इस आलेख का मसौदा उसमानिया विश्वविद्यालय के खगोल विज्ञान विभाग के सहयोग से तैयार किया गया। आलेख पर स्कूलों के विज्ञान शिक्षकों के साथ विवेचना की गई। कार्यगोष्ठी 26 मार्च 1981 को सम्पन्न हुई ।

कार्यकारी दलों की सभाएं

मैसूर में फरवरी-मार्च 1980 में हुई कार्यगोष्ठी में तैयार किए गए विज्ञान चार्टों को अंतिम रूप देने के लिए भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्राणि विज्ञान के विषयों पर कार्यकारी दलों की तीन सभाएँ हुईं । इन दलों की सिफारिशों के अनुसार कक्षा--IX और X के लिए इन चार्टों को संशोधित किया जा रहा है ।

दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग और रख रखाव पर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रणिक्षण परिषद् ने राज्य शिक्षा संस्थान, श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) के सहयोग से दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग/रख रखाव एवं उपयोग पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । राज्य शिक्षा संस्थान तथा श्रीनगर, भोपाल, चंडीगढ़ और उदयपुर की राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों से 20 व्यक्तियों ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया । इस कार्यक्रम का उद्देश्य भाग लेने वाले व्यक्तियों को दृश्य-श्रव्य उपकरणों को चलाने और उनकी देखभाल करने में प्रशिक्षण देना था ।

टेप-स्लाइड कार्यक्रमों में जनसंख्या-शिक्षा पर टेप-स्लाइडों के सेट का निर्माण

पिछले वर्ष की कार्यगोष्ठी के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में, शिक्षण साधन विभाग, परिषद् के जनसंख्या शिक्षा विभाग के साथ मिलकर जनसंख्या शिक्षा पर एक बहु-माध्य-

मीय किट का निर्माण कर रहा है।

नेत्रहीन बच्चों के लिए श्रव्य-टेप

नेत्रहीनों के लिए पेरीमल उच्चतर माध्यमिक अंध विद्यालय, नई दिल्ली के सहयोग से भूसा भरे पक्षियों और जानवरों पर 15-15 मिनट के आडियो टेपों पर सात संयुक्त कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं। ये श्रव्य-टेप कार्यक्रम कक्षा की विभिन्न स्थितियों की आवश्यकता पूर्ति करते हैं और इनका उद्देश्य विभिन्न संस्थाओं से आए हुए 14 वर्ष की आयु तक के नेत्रहीन बच्चों के अनुभवों को अधिक समृद्ध बनाना है। इन कार्यक्रमों के निर्माण से संबंधित ज्ञान को एक न्यूज़लेटर द्वारा अन्य अन्ध-संस्थाओं तक पहुँचाया जाएगा। यह न्यूज़लेटर पेरीमल विद्यालय द्वारा अन्य अन्ध-विद्यालयों के लाभार्थ प्रकाशित किया जाता है।

कम कीमत के शैक्षणिक साधनों पर टेप-स्लाइड सिस्टम

कम कीमत के शैक्षणिक साधनों की शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर एक टेप-स्लाइड कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। इसके हिंदी रूपांतरण को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। आलोच्य समय के दौरान मैसूर के क्षे० शि० म० के सहयोग से आक्सीडेशन और रिडक्शन पर शैक्षणिक टिप्पणियों सहित एक टेप-स्लाइड कार्यक्रम तैयार किया गया।

फिल्मों का सूचीपत्र

केन्द्रीय फिल्म लाइब्रेरी का नई फिल्मों पर एक पूरक सूचीपत्र तैयार किया गया और उसे मुद्रित किया गया। यह सूचीपत्र केंद्रीय फिल्म लाइब्रेरी के सदस्य-संस्थानों को भेजा गया है।

अभिनवीकरण कार्यक्रम

विभिन्न शैक्षिक एवं तकनीकी संस्थाओं के अध्यापकों और विद्यार्थियों के लिए कई अभिनवीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्प्रिंग्डेल्स स्कूल, नई दिल्ली; व्यावसायिक प्रशिक्षण कालिज, जामिया मिलिया; सहकारिता शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली; पालिटेक्निक, जम्मू; एम० आई० बी० ई० नर्सिंग कालिज, इन्दौर; तथा देश के विभिन्न भागों से केंद्रीय विद्यालयों ने इसमें भाग लिया।

विज्ञान किटें : डिज़ाइन और परिवर्धन

समन्वित विज्ञान किटों के डिज़ाइन जो पहले बनाए गए थे उनका पुनरीक्षण किया गया तथा उन्हें विज्ञान कार्यशाला द्वारा स्कूलों में निरीक्षण हेतु लगाया गया। इलेक्ट्रॉनिक किट का आदिप्ररूप तैयार कर लिया गया है। इलेक्ट्रानिक घटकों की पहचान पर भी एक

किट तैयार है। इन दो किटों के अतिरिक्त, एक कम कीमत का मल्टी-मीटर और एक कैथोड्रे आसिलोस्कोप भी बनाया जा रहा है और इनका निर्माण कार्य अन्तिम चरणों में है।

नवम्बर 1980 में तीनमूर्ति भवन में आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी में कई विज्ञान प्रदर्शों को डिज़ाइन करके नुमाइश के लिए रखा गया।

निर्माण कार्य

विज्ञान कार्यशाला ने 31 मार्च 1981 तक 5,330 किटों के घटकों का निर्माण पूरा कर लिया था। इनमें से 104 किटें लद्दाख, 465 जम्मू और 761 त्रिवेंद्रम भेज दी गई हैं। बाकी की 4000 किटें जम्मू और केरल में भेजे जाने के लिए तैयार हैं।

प्रशिक्षण/परामर्श

सात आई० टी० आई० शिक्षार्थियों को फिटर, इलेक्ट्रिशियन, सीट मेटल और मशीनिस्ट के व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया गया। बढ़ईगीरी का एक शिक्षार्थी विभाग में अभी अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

विज्ञान कार्यशाला ने जबलपुर के विज्ञान शिक्षा संस्थान को माध्यमिक स्कूल स्तर पर विज्ञान उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पर सुविज्ञता प्रदान की।

मरम्मत और रखरखाव

कार्यशाला ने निम्नलिखित मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया।

—वाहनों, एअर कंडीशनरों, रूम कूलरों, बिजली के उपकरणों तथा पी० ए० सिस्टम की मरम्मत और रखरखाव।

—कक्षा के कमरों के निर्माण के लिए ढाँचा खड़ा करना और उसमें कला की सुविधाओं का प्रावधान।

—फर्नीचर और अन्य सामग्री की मरम्मत और रखरखाव।

—बैठने की व्यवस्था की संरचना।

9

जनसंख्या-शिक्षा

राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा-परियोजना

भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत कार्य कर रहीं अनेक संस्थाओं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक नियोजन तथा प्रशासन संस्थान और योजना आयोग के साथ विचार-विमर्श के बाद एक राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा-परियोजना बनाई गई।

इस परियोजना के मूल उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

—जनसंख्या-वृद्धि और विकास के बीच के संबंध को समझने में छात्रों की सहायता करना ।

—देश की जनसंख्या की स्थिति से बच्चों और शिक्षकों को अवगत कराना ।

—औपचारिक शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या-शिक्षा को संस्थापित करना ।

—जनसंख्या संबंधी मसलों के संबंध में शिक्षकों, छात्रों और समाज के बीच उपयुक्त मनोवृत्ति और व्यवहार को विकसित करना ।

अब यह प्रस्ताव किया गया है कि इस परियोजना को छठी पंचवर्षीय योजना के साथ सह-केन्द्र बनाया जाए । आशा की जाती है कि इस अवधि में जनसंख्या-शिक्षा स्कूल तथा अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभिन्न अंग बन जाएगी ।

बिहार, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान तथा तमिलनाडु जैसे राज्य/संघ क्षेत्र तो प्रारंभ में ही इस परियोजना में सम्मिलित हो गए और आशा की जाती है कि आंध्रप्रदेश, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल अप्रैल 1981 में इसमें शामिल हो जाएँगे ।

रा० शै० अ० और प्र० प० का विशिष्ट कार्य यह है कि वह पाठ्यचर्या के विकास, शिक्षा-सामग्री के निर्माण तथा मुख्य व्यक्तियों के अभिविन्यास और प्रशिक्षण के मामलों में सम्मिलित होने वाले राज्यों को शैक्षिक निर्देशन की व्यवस्था करे । परिषद् से यह भी आशा की जाती है कि वह इन सभी क्षेत्रों में चल रही राज्यों की परियोजना के कार्यों का परिवीक्षण और समन्वय करेगी ।

कार्यगोष्ठियाँ

इस वर्ष के अंतर्गत परिषद् ने श्रीनगर तथा पुणे में आठ-आठ दिन की दो कार्यगोष्ठियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान से कहा गया कि वे अपने प्रतिनिधियों को श्रीनगर भेजें तथा गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से कहा गया कि वे अपने प्रतिनिधियों को पुणे में आयोजित कार्यक्रम में भेजें । जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त अन्य नौ राज्यों के 39 प्रमुख व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया ।

परिषद् ने विचार-विमर्श के लिए एक विस्तृत मूल कार्यचालन प्रलेख तैयार किया । इन दो कार्यगोष्ठियों में यह स्पष्ट किया गया कि हमारी आवश्यकताओं और स्थितियों को देखते हुए जनसंख्या-शिक्षा की संकल्पना क्या होनी चाहिए । कार्य और महत्व के संबंध में विचार-विमर्श के फलस्वरूप एक संश्लेषित रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसका शीर्षक है :

'जनसंख्या-शिक्षा—कार्य और चुनौतियाँ : राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी और प्रशिक्षण कार्यक्रम की सिफ़ारिशें'।

जनसंख्या-शिक्षा संबंधी पाठ्यपुस्तकों के पाठों के लेखकों के लाभ के लिए कोयंबटूर के श्री अविनाशलिंगम् कालेज ऑफ होम साइंस एंड एजूकेशन फॉर वीमेन में 7 से 16 मार्च 1981 तक एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें देश के विभिन्न भागों के विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त 25 व्यक्तियों ने भाग लिया।

इस कार्यगोष्ठी में जनसंख्या-शिक्षा में संभाव्य विषयों का एक मास्टर चार्ट, पाठ्यपुस्तकों के पाठों को तैयार करने के निर्देश तथा मूल्यांकन-सामग्री तैयार की गई।

प्रशिक्षण-कार्यक्रम

इस परियोजना की अनुसूची के अनुसार प्रथम गहन राष्ट्रीय प्रशिक्षण-कार्यक्रम और कार्यगोष्ठी का आयोजन हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में 17 से 29 नवम्बर 1980 के बीच की 13 दिन की अवधि में किया गया। यह कार्यक्रम उन पूर्णकालिक कर्मचारियों के लिए विशेषरूप से तैयार किया गया था जिन्हें दस राज्यों ने अपने शिक्षा सेलों को चलाने के लिए चुना था। पंजाब को छोड़कर अन्य सभी दस राज्यों ने इसमें भाग लिया। मेज़बान राज्य आंध्रप्रदेश तथा स्थानीय भारतीय परिवार नियोजन संघ को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम में कुल मिलाकर 40 व्यक्ति प्रशिक्षित किए गए।

इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य था राज्यों के जनसंख्या-शिक्षा सेलों के कर्मचारियों को कुशल और दक्ष बनाना। इसमें भाग लेनेवालों ने वैयक्तिकरूप से तथा छोटे-छोटे समूहों में कार्य करके छात्रों और अध्यापकों के लिए जनसंख्या-शिक्षा संबंधी सामग्री तैयार की।

द्वितीय गहन कार्यगोष्ठी का आयोजन इसी ढंग पर न्यूज़ीलैंड हॉस्टेल, गोरे गाँव, बम्बई में 30 जनवरी 1981 तक हुआ।

प्रथम गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम में तो पाठ्यचर्या-विकास तथा शिक्षा-सामग्री के निर्माण पर जोर दिया गया था परन्तु द्वितीय कार्यगोष्ठी और प्रशिक्षण-कार्यक्रम को अभिविन्यास की समस्याओं, प्रशिक्षण, परिवीक्षण, मूल्यांकन तथा अनुसंधान तक सीमित रखा गया। इसमें राज्यों से भेजे गए 41 व्यक्तियों ने भाग लिया। बैंकाक स्थित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के डा० आर० सी० शर्मा ने भी इसमें भाग लिया। कार्यगोष्ठी में निम्नलिखित पुस्तिकाओं के मसौदे को अंतिम रूप दिया गया :

—राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा-कार्यक्रम का विज्ञप्ति पत्रक (तमिलनाडु)।

—स्कूल और जनसंख्या : कुल मिलाकर स्कूल के क्या कार्य हो सकते हैं (कर्नाटक)।

—माध्यमिक शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय और जनसंख्या-शिक्षा (हरियाणा)।

—प्रारंभिक शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थान और जनसंख्या-शिक्षा (मध्यप्रदेश)।

—प्रशिक्षण-कार्यक्रम के आयोजन की जाँच-सूची (चंडीगढ़)।

—प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की संपुटित दीपिका (बिहार)।

—मिडिल स्कूलों में सामाजिक अध्ययन के अध्यापकों की प्रशिक्षण-दीपिका (राजस्थान)।

—मिडिल स्कूलों में विज्ञान-शिक्षकों की प्रशिक्षण दीपिका (पंजाब)।

—राज्य शिक्षा संस्थान के परियोजना-कर्मचारियों के प्रयोग में आनेवाली परिवीक्षण और कार्यक्रम-मूल्यांकन की जाँच-सूची (महाराष्ट्र)।

—मूल्यों के विकास में सहायक अधिगम स्थिति के आयोजन की सचित्र जाँच-सूची (गुजरात)।

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य

भारत सरकार के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने, जो एक प्रायोजन एजेन्सी है, इस परियोजना के कार्यान्वियन में गति लाने के लिए अनेक कार्य किए हैं। इन कार्यों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा परियोजना (औपचारिक प्रणाली) के शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के केन्द्रीय क्षेत्रक में योजना स्कीम के रूप में मान्यता, दस राज्यों की राज्य जनसंख्या-शिक्षा परियोजना की स्वीकृति, इसमें भाग लेने वाले दस राज्यों को 29,40,300-रु० देना, जनसंख्या-शिक्षा सेलों की स्थापना संबंधी आवश्यक कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध; और परियोजना के समन्वय और कार्यान्वियन हेतु राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन।

परियोजना के द्वितीय चरण के संबंध में रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा किए गए कार्य

रा० शै० अ० और प्र० प० ने राज्य जनसंख्या-शिक्षा परियोजना के कार्य में नौ अतिरिक्त राज्यों और संघ क्षेत्रों की सहायता की। ये राज्य अप्रैल 1981 से राष्ट्रीय जनसंख्या-शिक्षा परियोजना में शामिल होने वाले थे। इनके नाम हैं : आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश।

योजना प्रस्ताव बनाने के कार्य में राज्य सरकारों के कर्मचारियों की सहायता के लिए जनसंख्या-शिक्षा एकक ने दो कार्यगोष्ठियाँ आयोजित कीं। उत्तर में लखनऊ में तथा दक्षिण में तिरुपति में।

राज्यों के प्रतिनिधि जब प्रस्ताव-मसौदे बना चुके तब रा० शै० अ० और प्र० प० ने इन परियोजना-प्रलेखों को अंतिम रूप देने के लिए अक्तूबर 1980 में नई दिल्ली में अनेक बैठकों का आयोजन किया। इन बैठकों में राज्यों के उच्चाधिकारियों ने भाग लिया। शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, रा० शै० अ० और प्र० प० तथा यूनेस्को के प्रतिनिधियों ने लखनऊ, तिरुपति तथा नई दिल्ली में आयोजित इन तीनों ही कार्यक्रमों में भाग लिया।

राज्य परियोजनाएँ

रा० शै० अ० और प्र० प० के सहयोग से विभिन्न राज्यों के जनसंख्या-शिक्षा सेलों ने भी कुछ कार्यक्रमों को चलाया। इन कार्यक्रमों तथा कुछ अन्य कार्यगोष्ठियों के काम निम्नलिखित हैं :

पाठ्यचर्या को विकसित करने के लिए 31 दिसम्बर 1980 से 5 जनवरी 1981 तक मद्रास में आयोजित कार्यगोष्ठी; जनसंख्या-शिक्षा पाठ्यचर्या को विकसित करने के लिए 5 से 10 फरवरी 1981 तक उत्तर प्रदेश में आयोजित कार्यगोष्ठी तथा हरियाणा में जनसंख्या-शिक्षा संबंधी सामग्री विकसित करने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा गुड़गाँव में आयोजित कार्यगोष्ठी।

इस वर्ष रा० शै० अ० और प्र० प० ने 'न्यूज़लेटर ऑन पोपुलेशन एजुकेशन' के दो अंक निकाले। ये दो अंक कार्यक्रम के विभिन्न पक्षों से संबंधित थे, जैसे संकल्पनात्मक ढाँचा, परियोजना की प्रगति, स्लाइडों-टेपों और फिल्म-पट्टियों का निर्माण, कार्यक्रमों में राज्यों द्वारा भाग लेना, आदि-आदि।

जनसंख्या-शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय ने जनसंख्या-शिक्षा (औपचारिक प्रणाली) संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया है। इस समिति के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :

—जनसंख्या-शिक्षा-कार्यक्रम संबंधी सभी मामलों में भारत सरकार को सलाह देना।

—राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन को निरापद रखना।

—केन्द्र और राज्य सरकारों तथा अन्य सरकारी, गैर सरकारी और दूसरी तरह की कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

—समय-समय पर कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा और मूल्यांकन।

जनसंख्या-शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति की प्रथम बैठक 12 दिसम्बर 1980 को हुई । समिति ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की तथा रा० शै० अ० और प्र० प० के जनसंख्या-शिक्षा एकक द्वारा किए गए कार्यों के प्रति संतोष प्रकट किया । उसने यह भी देखा कि वर्ष के शेष महीनों में क्या कार्य किये जाने हैं । समिति में यह तय किया गया कि इसकी अगली बैठक में शिक्षा सचिवों तथा परियोजना निदेशकों जैसे राज्यों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित किया जाए । इसमें यह सिफ़ारिश भी की गई कि परियोजना-योजनाओं का मार्च, 1985 तक चलने वाली छठी पंचवर्षीय योजना के साथ सह-केन्द्र बनाया जाय ।

अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप

एशिया और ओसनिया में शिक्षा से संबंधित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय ने 18 अगस्त से 5 सितंबर 1980 तक बैंकाक में क्षेत्रीय समूह-प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम का आयोजन किया जो सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों के लिए था । प्रशिक्षण कार्यक्रम की मुख्य बात यह थी कि पाठ्यचर्या का विकास किस प्रकार किया जाए । इसमें विद्यालय के अंदर और विद्यालय के बाहर इन दोनों पक्षों का समावेश था ।

अंतर्राष्ट्रीय संतति नियोजन संघ के हिन्द महासागर क्षेत्र तथा भारतीय परिवार नियोजन संघ ने 6 से 10 अक्टूबर 1980 तक बंबई में "विशेषत: विद्यालय के बाहर के युवजनों की जनसंख्या-शिक्षा" के संबंध में एक क्षेत्रीय गोष्ठी का आयोजन किया ।

10

मापन और मूल्यांकन

वर्ष के दौरान परिषद् ने शैक्षिक मूल्यांकन, शैक्षिक परीक्षणों के विकास तथा परीक्षा-सुधार के लिए परामर्श सेवाओं के क्षेत्र में अनुसंधान अध्ययन, प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम तथा वैचारिक साहित्य के निर्माण का काम शुरू किया।

शैक्षिक मूल्यांकन

निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए गए/पूरे हुए :

(क) **आवासीय स्कूलों में रहने वाले भारत सरकार के विशेष योग्यता छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थियों का गहन अध्ययन :** इस

योजना पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी आवासीय स्कूलों को एक प्रश्नावली भेजी गई थी जिसमें वहाँ रहने वाले विशेष योग्यता छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों के बारे में जानकारी माँगी गई थी। 67 में 30 शिक्षण संस्थानों से सूचना प्राप्त हो गई है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। अन्य संस्थानों से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ख) **प्रतिभा की खोज और विकास :** मौलिकता के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्र वृत्ति के वर्ष 1977 के परीक्षार्थियों के विवरण का विश्लेषण किया जा चुका है। इसकी रिपोर्ट तैयार है। यह उस अध्ययन का प्रथम भाग है जिसमें दो विभिन्न परीक्षणों पर दो रिपोर्टें लिखी जानी थीं। वर्ष 1978 के मौलिकता परीक्षण के विवरण का कम्प्यूटर द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। रिपोर्ट के दूसरे भाग के लिए अध्ययन के विवरण का विश्लेषण हो गया है और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

(ग) **राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों की उपलब्धियों का गहन अध्ययन :** जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के अध्ययन के लिए 230 राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों का पता लगा लिया गया है। एक प्रश्नावली, जिसका मसौदा तैयार है, के आधार पर उनकी उपलब्धियों का अध्ययन करने का विचार है। व्यक्तित्व तालिका मापदंड को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(घ) **बच्चों में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन तथा उनकी मौलिक क्रिया-विधि :** कुछ प्रश्नों के उत्तर में जो विवरण प्राप्त हुए थे उनका विश्लेषण पूर्ण हो चुका है। कुछ प्रश्न ये थे :

—1975 की परीक्षा में बैठे बच्चों और 1961 के बच्चों के दल की व्यावसायिक आकांक्षाओं अथवा आशाओं में कितना तुलनात्मक अंतर था ?

—1977 में अध्यापकों का आदर्श छात्र संबंधी बोध 1961 के अध्यापकों के बोध की तुलना में कैसा था ?

—1977 और 1961 के अध्यापकों के शैक्षिक विचारों और आचरण में तुलनात्मक अंतर क्या था ?

लगभग दो हज़ार विद्यार्थियों के मौखिक तथा अमौखिक मौलिकता के विवरण को तालिका-बद्ध कर दिया गया है और उसका कम्प्यूटर द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। विश्लेषण की योजना तैयार है।

(ङ) **नौ, दस और ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा अपनाई गई व्यापक आंतरिक मूल्यांकन योजना का मूल्यांकन :** माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अपनाई गई यह व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के गहन अध्ययन की योजना है। इसका उद्देश्य इसकी अच्छाइयों और कमियों को जानना है। योजना के

क्रियान्वयन में अनुभूत समस्याओं और उनके निराकरण के उपायों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए प्रधानाध्यापकों, अध्यापकों, विद्यार्थियों तथा माता-पिता के साथ साक्षात्कार किए गए। इस अध्ययन द्वारा योजना की विषय-वस्तु और उसके क्रियान्वयन के बारे में बहुमूल्य सूचना प्राप्त हुई है।

(च) कक्षा आठ के लिए कक्षा में भूगोल पढ़ने में सुधार तथा उसे साधिकार पढ़ने का ढंग : वर्ष 1980-81 में केन्द्रीय विद्यालय (आई० आई० टी०) की कक्षा आठ के विद्यार्थियों के कक्षा के कार्य में सुधार की जाँच और एकक आधारित अध्यापन के मूल्यांकन के लिए इस अन्वेषण को शुरू किया गया था। कक्षा में प्रशिक्षण के लिए सामग्री का निर्माण किया गया और प्रयोग किया गया, उसके बाद विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानने के लिए एकक परीक्षण किया गया। इसके तुरंत बाद स्वाध्यायी अभ्यासों तथा अनुशिक्षकीय सहायता द्वारा लाभकारी प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण पद्धति के असर के विश्लेषण के मूल्यांकन की योजना है।

मापन और मूल्यांकन विभाग ने "कुछ चुने हुए प्राथमिक/मिडिल स्कूलों में मूल्यांकन पद्धति" शीर्षक से एक रिपोर्ट निकाली है। प्राथमिक स्तर पर बेहतर मूल्यांकन पद्धति का अभ्यंतर कार्यक्रम विकसित करने के उद्देश्य से इस रिपोर्ट को राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है। "प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के तरीकों को विशेष महत्व प्रदान करना" विषयक एक रिपोर्ट सम्मति तथा जाँच के लिए राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को भेजी गई है।

(छ) 1978 तथा 1979 की माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त परीक्षार्थियों का प्रतिशत : माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक बोर्डों की परीक्षाओं की जाँच की गई। इससे यह बात ज्ञात हुई कि विभिन्न बोर्डों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों के प्रतिशत में विशाल अंतर है। यह बात उच्च अंक प्राप्त करने वालों में अधिक पाई गई। उदाहरणार्थ 0.77 प्रतिशत से 63.47 प्रतिशत के बीच के प्रथम श्रेणी पाने वालों के प्रतिशत में अंतर था। 1978 तथा 1979 की परीक्षाओं के आधार पर इस घटना के कारणों की जाँच के लिए एक मार्गदर्शक अध्ययन की शुरुआत की गई।

(ज) परीक्षाओं में गलत कार्यों को रोकने के लिए विशेष कदम : परिषद् ने प्रत्येक बोर्ड के बारे में "परीक्षाओं में गलत कार्यों को रोकने के लिए विशेष कदम" शीर्षक लेख निकालने की योजना बनाई है। गोआ, दमन और दीव पर एक संक्षिप्त लेख अन्य बोर्डों को भेजा गया है। ऐसे ही लेख आंध्र प्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल के माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् कलकत्ता तथा इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट परीक्षा परिषद् के विषय में भी तैयार करके संबंधित बोर्डों को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं।

विकास कार्यक्रम

(क) "मिडिल कक्षाओं के लिए जीव विज्ञान : अध्यापन तथा परीक्षण की एकक पद्धति" शीर्षक प्रबंध-लेख तैयार किया गया है। इसे राज्य शिक्षा संस्थानों/केन्द्रीय विद्यालयों को भेजा गया है।

(ख) पर्यावरण अध्ययन संबंधी मूल्यांकन के एक भाग के रूप में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के लिए विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के मापदण्ड संदर्भ परीक्षणों और हिन्दी तथा गणित के नैदानिक परीक्षणों के विकास के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(ग) 30 तथा 31 जुलाई 1980 को विशेषज्ञों की एक योजना गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान में हुई इस गोष्ठी का उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर मूल्यांकन की एक पुस्तक को तैयार करना था।

(घ) "कक्षा सात के लिए भूगोल अध्यापन तथा परीक्षण की एकक पद्धति" तथा "माध्यमिक कक्षाओं में इतिहास इकाई योजना द्वारा शिक्षण मूल्यांकन" शीर्षकों की दो पुस्तिकाएँ निकाली गई हैं। इन क्षेत्रों में आगे का कार्य करने के लिए इन्हें चुने हुए स्कूलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया है।

(ङ) "ग्यारहवीं कक्षा के लिए इतिहास के एकक परीक्षण भाग 1" शीर्षक पुस्तिका निकाली गई और उसे केंद्रीय विद्यालयों, राज्य शिक्षा संस्थानों, क्षेत्र सलाहकारों आदि को भेजा गया।

प्रशिक्षण/विस्तार कार्यक्रम

प्रशिक्षण और विस्तार मापन और मूल्यांकन विभाग के महत्वपूर्ण कार्य हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित कार्यक्रम किए गए :

मई 1980 में बिहार स्कूल परीक्षा समिति, पटना के सहयोग से नेतरहाट में प्रश्न पत्र बनाने वालों के प्रशिक्षणार्थ तथा नमूने के प्रश्न पत्र बनाने के लिए एक आठ दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। अँग्रेज़ी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी तथा गणित विषयों पर कार्य हुआ। नमूने के प्रश्न पत्र तैयार किए गए और उन्हें बिहार बोर्ड ने स्कूलों में प्रचारित किया।

प्रश्न पत्र बनाने वालों के प्रशिक्षण के लिए तथा प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बिहार, पटना ने 9 से 16 जून 1980 तक एक कार्यशाला का आयोजन किया। उर्दू, हिंदी, वाणिज्य, गृह विज्ञान तथा बांग्ला भाषा में प्रश्न पत्र तैयार करने में बोर्ड के अधिकारियों की सहायता चार अधिकारियों तथा विभागाध्यक्षों ने कार्यशाला में सम्मिलित होकर की।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से सोलन में प्रश्न पत्र बनाने वालों के प्रशिक्षण के लिए तथा नमूने के प्रश्न पत्रों को तैयार करने के लिए एक दस-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें गणित, जीव विज्ञान, भूगोल, नागरिक शास्त्र, इतिहास, हिंदी आदि विषयों पर कार्य हुआ। नमूने के प्रश्न पत्रों को मार्गदर्शन हेतु प्रश्न पत्र बनाने वालों में बोर्ड द्वारा प्रचारित किया जाएगा।

विभाग ने जीव विज्ञान में शिक्षण-सामग्री को अंतिम रूप दिया जिसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ऊटी में आयोजित कार्यशाला में विकसित किया गया था। सामग्री केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली के पास भेज दी गई।

मापन और मूल्यांकन विभाग के सहयोग से महाराष्ट्र के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रश्न पत्र बनाने वालों के प्रशिक्षण के लिए 26 अगस्त से 4 सितम्बर 1980 तक पुणे में एक कार्यशाला का आयोजन किया।

विभाग ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड गुजरात के सहयोग से 17 से 24 सितम्बर 1980 तक बड़ौदा में प्रश्न पत्र बनाने वालों की एक कार्यशाला का आयोजन किया। लगभग 55 अध्यापकों, जो प्रश्न पत्र बनाने तथा संसाधन व्यक्तियों का कार्य करेंगे, को हिंदी, गुजराती, सामाजिक अध्ययन, गणित, संस्कृत, अंग्रेज़ी, विज्ञान तथा भूगोल में संतुलित प्रश्न पत्र बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

विभाग ने शैक्षिक मूल्यांकन में संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बिहार के सहयोग से राजगीर (बिहार) में एक दस-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें बिहार के 59 अध्यापकों ने भाग लिया। भाग लेने वालों को मूल्यांकन के विभिन्न पहलुओं पर व्यावहारिक और सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया गया। अंग्रेज़ी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र विषयों में 59 एकक परीक्षण कार्यशाला में भाग लेने वालों ने तैयार किए। कुछ और संशोधनों के बाद ये एकक परीक्षण माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, बिहार द्वारा मुद्रित करा कर राज्य के स्कूलों में वितरित किए जाएँगे।

गोआ दमन और दीव बोर्ड के पंजिम स्थित कार्यालय में एक चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें भूगोल और राजनीति विज्ञान के चार-चार शिक्षकों को कक्षा बारह के लिए प्रश्न पत्र तैयार करने की विधि में प्रशिक्षण दिया गया। इन नमूने के प्रश्न पत्रों को स्कूलों में प्रचारित किया जाएगा।

महाराष्ट्र के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 7 से 16 जनवरी 1981 तक औरंगाबाद में एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें 45 प्रतिभागियों के अलावा 5 संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया। भाग लेने वालों ने अंग्रेज़ी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा इतिहास विषयों के कई प्रकार के वस्तुनिष्ठ परीक्षणों की मदें तैयार कीं।

मापन और मूल्यांकन विभाग ने कक्षा बारह के लिए इतिहास तथा अर्थशास्त्र के एकक परीक्षणों को अंतिम रूप देने के लिए कई कार्यशालाओं/कार्य दल गोष्ठियों का आयोजन किया। विभाग ने कक्षा आठ के लिए इतिहास के एकक परीक्षण तथा गणित और जीव विज्ञान के प्रश्न बैंकों के लिए परीक्षण मदों को अंतिम रूप देने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया।

हाई स्कूल तथा इण्टर मीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश के सहयोग से संसाधन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन इलाहाबाद (उ० प्र०) में किया गया। इसमें 50 शिक्षकों, शिक्षक-प्रशिक्षकों तथा सामाजिक विज्ञानों तथा भाषा के विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यशाला की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी—संसाधन व्यक्तियों का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार करने की विधि से संबंधित प्रशिक्षण तथा प्रश्न पत्र बनाने का तीन दिवसीय तहसील स्तरीय, तथा आठ दिवसीय जिला स्तरीय पाठ्यक्रम बनाना।

गणित और जीव विज्ञान में प्रश्न बैंक पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन परिषद् के दिल्ली स्थित मुख्यालय में किया गया। छः राज्यों से गणित के 15 तथा जीव विज्ञान के 12 लोगों ने भाग लिया। कार्यशाला में जिन मदों को अंतिम रूप दिया गया उन्हें एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया जाएगा।

उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के शिक्षा विभाग में अर्थशास्त्र, भूगोल तथा राजनीति विज्ञान में शैक्षिक मूल्यांकन पर एक दस-दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। एकक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्नों के विकास के अलावा सामाजिक विज्ञानों में लिए गए कामों और योजनाओं के मूल्यांकन के लिए सामग्री के विकास का कार्य भी किया गया। सामाजिक विज्ञानों में मूल्यांकन की एक विस्तृत योजना पर कार्य किया जा रहा है। एक पुस्तिका विकसित करने का प्रस्ताव है।

चार ब्रिगेडियरों और 21 लेफ्टीनेंट कर्नलों के लिए सेना प्रशिक्षण निदेशालय की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप उनके ही आग्रह पर परीक्षा सुधार संबंधी एक बारह-सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षित अधिकारी सेना प्रशिक्षण-निदेशालय में सरकार द्वारा स्थापित एक विशेष परीक्षा अनुसंधान तथा सुधार विभाग की देख भाल का कार्य करेंगे। इसका उद्देश्य पदोन्नति तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वस्तुनिष्ठ प्रणाली का विकास करना है।

समन्वय तथा निकासी गृह

'चुने हुए विश्वविद्यालयों में उभरती हुई मूल्यांकन-विधियाँ' शीर्षक एक समाचार बुलेटिन का प्रकाशन विभाग द्वारा किया गया है। मूल्यांकन के क्षेत्र में चुने हुए विश्व-

विद्यालयों द्वारा लागू की गई नवीन जानकारी से परिचित कराने के लिए इसे विश्वविद्यालयों और प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रचारित किया गया है।

कार्यक्रम मूल्यांकन

प्रबोधन तथा मूल्यांकन पर कार्य दल

पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षिक योजना संस्थान तथा हेम्बुर्ग स्थित यूनेस्को शिक्षा संस्थान के सहयोग से परिषद् के योजना, समन्वय तथा मूल्यांकन एकक द्वारा तैयार प्रबोधन तथा मूल्यांकन के साधनों पर विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रियाओं को जानने के लिए परिषद् ने मई-जून 1980 में त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, द्वारिका तथा मसूरी में चार कार्य दलों की गोष्ठियों का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 100 लोगों ने भाग लिया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षकों, ब्लाक शिक्षा अधिकारियों, ज़िला शिक्षा अधिकारियों, क्षेत्रीय अधिकारियों तथा राज्य अधिकारियों के स्तर पर प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने के कार्यक्रम के प्रबोधन तथा मूल्यांकन के निमित्त **आजमाइशी प्रोफार्मा द्वारा** निचले स्तर पर प्रस्तावित साधन को लागू करने की सम्भावनाओं का पता लगाना था।

भाग लेने वालों को मूल्यांकन की सामग्री से परिचित कराया गया तथा उनसे अपने स्वयं के राज्य में मूल्यांकन के कार्यक्रम को तैयार करने का अभ्यास करने को कहा गया।

प्रबोधन पर उच्चस्तरीय गोष्ठी

परिषद् के मुख्यालय में 15 और 16 दिसंबर 1980 को प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण-कार्यक्रम के प्रबोधन और मूल्यांकन पर एक उच्चस्तरीय गोष्ठी हुई। गोष्ठी में योजना आयोग, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केंद्र और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन संस्थान एवं चार राज्यों के उच्च स्तर के प्रतिनिधियों तथा परिषद् के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इस विचार विमर्श द्वारा प्रक्रिया और साधनों की कार्य-उपयोगिता तथा उनमें और अधिक सुधार लाने के बारे में और भी बारीकी से जानने का अवसर मिला। प्राथमिक शिक्षा को विश्वव्यापी बनाने के कार्यक्रम के प्रबोधन तथा मूल्यांकन के लिए एक न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम तैयार किया गया जिसे योजना आयोग और शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया।

11

सर्वेक्षण, आधार-सामग्री प्रक्रिया और प्रलेखन

शैक्षिक सर्वेक्षण

चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण

चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण कार्य को 1978 में शुरू किया गया था जो 31-12-1980 को सम्पन्न हुआ और "चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण—स्कूल शिक्षा संबंधी कुछ आँकड़े" नामक पुस्तिका प्रकाशित की गई। 30-9-1978 को विद्यमान सभी स्कूलों और गाँवों को इस सर्वेक्षण में लिया गया था। इस सर्वेक्षण से अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों से संबंधित आधार-सामग्री उपलब्ध हुई : प्राथमिक, मिडिल या माध्यमिक स्तर की शिक्षा की सुविधाओं से युक्त

या उनसे रहित गाँव, जिन स्थानों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की संख्या अत्यधिक है वहाँ पर शिक्षा की सुविधाएँ, स्कूल जाने की आयु वाले बच्चों की अनुमानित जनसंख्या, विभिन्न प्रकार के स्कूलों की संख्या, प्रत्येक क्लास में लड़के-लड़कियों की अलग-अलग संख्या, स्कूल पहुँचने के लिए बच्चों को कितनी दूर चलना पड़ता है, शिक्षक और उनकी पेशेवर तथा शैक्षिक योग्यता, प्रकार तथा स्वामित्व के आधार पर स्कूलों के भवन, प्रसार की योग्यता तथा उसके लिए उपलब्ध स्थान तथा फर्नीचर, ब्लैकबोर्ड, पुस्तकालय, पीने का पानी, आदि की सुविधाएँ। छठी पंचवर्षीय योजना के शिक्षा संबंधी भाग को बनाने में इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों का प्रयोग किया गया है।

स्कूलों में उपस्थिति का परिवीक्षण

प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में औसत दैनिक उपस्थिति के, त्रैमासिक आधार पर, परिवीक्षण के कार्यक्रम को चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के साथ-साथ चलाया गया था और यह इस वर्ष भी चलता रहा। प्रत्येक तीन महीनों संबंधी आधार-सामग्री का प्रक्रमण राष्ट्रीय सूचना केन्द्र में कम्प्यूटर पर हुआ। अनेक राज्यों से आने वाली सूचना की दर गिरती गई है।

तृतीय अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रकाशन

सर्वेक्षण की मुख्य रिपोर्ट तथा अन्य रिपोर्टों में से अधिकतर का प्रकाशन तो 1979-80 में ही हो चुका था और 1980-81 में निम्नलिखित रिपोर्टें छपीं :

—स्कूलों में पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा वैज्ञानिक सामग्री की सुविधा।

—संस्कृत पाठशाला और मदरसा।

—स्कूलों में भाषा तथा शिक्षा के माध्यम।

आधार-सामग्री प्रक्रिया सेवा

परिषद् का आधार-सामग्री-प्रक्रिया-एकक मुख्यतः आधार-सामग्री तैयार करने, कम्प्यूटर कार्यक्रमों को विकसित करने और कम्प्यूटर पर आधार-सामग्री के प्रक्रमण के कार्य में लगा रहा। रा० शै० अ० और प्र० प० में कम्प्यूटर केन्द्र के खुल जाने से इस कार्य में बहुत मदद मिली है। 1980-81 वर्ष में अनेक अनुसंधान परियोजनाओं के सांख्यिकीय विश्लेषण के कार्य को हाथ में लिया गया। इनमें से एक मुख्य कार्य था 1980 की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (XI और XII कक्षा) के परिणामों का प्रक्रमण। इसके अतिरिक्त रा० शै० अ० और प्र० प० के शैक्षिक स्टाफ़ की पीएच० डी० परियोजनाओं से संबंधित आधार-सामग्री को पंच/सत्यापित किया गया और कम्प्यूटर पर उनका और अधिक प्रक्रमण हुआ।

चतुर्थ शैक्षिक सर्वेक्षण का गौण विश्लेषण

सर्वेक्षण के तात्कालिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर चतुर्थ सर्वेक्षण की आधार-सामग्री का विश्लेषण किया गया। जिन विभिन्न चरों की आधार-सामग्री इकट्ठी की गई थी उनके पारस्परिक संबंधों को निश्चित करने के लिए आधार-सामग्री की और अधिक विश्लेषण की गुंजाइश थी और इसीलिए सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों से स्कूलों के लिए नमूना की सर्वेक्षण-तालिकाएँ संकलित की जा रही हैं ताकि कम्प्यूटर पर और अधिक विश्लेषण किया जा सके। कुछ जिलों से तो ये तालिकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं और कुछ से अभी आनी हैं। इस परियोजना पर कार्य जारी है।

आठ चुने हुए राज्यों में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का प्रतिदर्श सर्वेक्षण

स्कूल न जाने वाले बच्चों में बालिकाओं की संख्या अत्यधिक है। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए नौ राज्यों में से सात तथा हरियाणा के संबंध में यह बात विशेष रूप से लागू होती है जहाँ स्कूल जाने की उम्र (6 से 10) वाली 50% से अधिक बालिकाएँ स्कूल जाती ही नहीं हैं। इसलिए बालिकाओं की नामांकन संबंधी वास्तविक स्थिति को जानने, अल्प नामांकन के कारणों का अध्ययन करने तथा स्थिति को सुधारने वाले उपायों का पता लगाने के उद्देश्य से इन आठ राज्यों के कुछ जिलों में प्रतिदर्श अध्ययन का काम शुरू किया गया है। इस परियोजना के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति हैं : प्रख्यात शिक्षाविद् और समाजविज्ञानी तथा अध्ययन के लिए चुने गए आठ राज्यों के एवं शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, योजना आयोग और यूनिसेफ के प्रतिनिधि। इस समिति की बैठक 15 जनवरी 1981 को हुई जिसमें अध्ययन संबंधी कुछ मुख्य निर्देशक बातें निर्धारित की गईं। आधार-सामग्री के संकलन के लिए ऐसी अनेक तालिकाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिनके आधार पर कार्य करने का प्रयास किया जाएगा। संबंधित राज्यों ने राज्य स्तर पर अपने अधिकारियों को नामज़द किया है जो अपने राज्यों में कार्यक्रम को चलाएँगे।

शिक्षा में प्रतिदर्श सर्वेक्षण की भूमिका पर संगोष्ठी

तीन दिन चलने वाली एक संगोष्ठी आयोजित की गई जिसके प्रयोजन थे—शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदर्श सर्वेक्षणों की भूमिका के संबंध में विचार-विमर्श करना, उन क्षेत्रों का पता लगाना जिनमें प्रतिदर्श सर्वेक्षण की आवश्यकता है तथा उन उपायों की सिफ़ारिश करना जो शैक्षिक आधार-सामग्री के संकलन में प्रतिचयन विधि के अधिकाधिक उपयोग में सहायक सिद्ध होते हैं। इस संगोष्ठी में निम्नलिखित व्यक्ति थे : विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं से आए हुए प्रख्यात प्रतिचयन विशेषज्ञ एवं केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, योजना आयोग, अनुप्रयुक्त जनशक्ति अनुसंधान संस्थान,

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय और कुछ राज्यों के शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि । इस संगोष्ठी में शिक्षा के वे क्षेत्र निर्धारित किए गए जिनमें प्रतिदर्श सर्वेक्षण की आवश्यकता है ।

प्रतिदर्श सर्वेक्षण विधि का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों एवं विभिन्न राज्यों के सांख्यिकीय एककों या शिक्षा सर्वेक्षण एककों में काम करने वाले अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए दो सप्ताह के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इस पाठ्यक्रम का आयोजन 22 अक्टूबर से 4 नवम्बर 1980 तक भोपाल के क्षे० शि० म० में किया गया था । इसमें 27 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें 15 राज्यों के, 2 संघ राज्य क्षेत्रों के तथा शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के एक प्रतिनिधि थे ।

चतुर्थ सर्वेक्षण की आधार-सामग्री पर आधारित शिक्षा की जिला विकास योजना

चतुर्थ अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण में यह पता लगाया गया है कि किन ग्राम-क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाएँ हैं और किन में नहीं । इसके अतिरिक्त इसमें इसी तथ्य को दर्शाने वाले ब्लॉक मानचित्र भी दिए गए हैं । प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने के कार्यक्रम को बल देने की दृष्टि से यह आवश्यक समझा गया कि स्कूलों की योजना इस प्रकार बनाई जाए तथा उन्हें ऐसे स्थान पर खोला जाए कि वे अधिकाधिक संख्या में बच्चों को आकर्षित कर सकें तथा जो प्राथमिक स्कूल परिपूरक स्कूलों की मौजूदगी, आर्थिक क्षमता, बच्चों के घर से स्कूल की दूरी तथा जनसंख्या जैसे विशिष्ट मापदंड के अनुकूल हों उन्हें मिडिल स्कूल का दर्जा दे दिया जाए । फार्म बनाए गए तथा उनके संबंध में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ 3-4 फरवरी 1981 को विचार-विमर्श हुआ । 1981-82 में सभी राज्यों में कार्यगोष्ठियों के आयोजन का प्रस्ताव है जिनमें उपर्युक्त निर्देशकों का उपयोग इस प्रकार किया जाएगा कि सभी राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण की आधार-सामग्री का उपयोग करके सभी ब्लॉकों के लिए ब्लॉक स्तर पर शिक्षा-योजना बना सकें ।

राज्यों में शिक्षा-प्रणाली संबंधी विशिष्ट सूचना का संकलन

रा० शै० अ० और प्र० प० ने स्कूल-शिक्षा के कुछ महत्त्वपूर्ण पक्षों से संबद्ध सूचना के संकलन के कार्य को अपने हाथ में लिया है । इनमें से कुछ यों हैं : राज्यों में स्कूलों का स्वरूप, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी विधान, स्कूल-पाठ्यचर्या जिसके अंतर्गत कार्य-दिवसों, छुट्टियों तथा विषयों के अनुसार प्रति सप्ताह के अध्यापन समय की भी व्य-

वस्था होती है, स्कूल के विभिन्न स्तरों पर पढ़ाई जाने वाली भाषाएँ, शिक्षा-माध्यम, नामांकन, शिक्षकों का कार्यभार, वेतन-प्रारूप और पूर्व-प्राथमिक, प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण। विभिन्न राज्यों ने विभिन्न स्वरूपों का आश्रय लिया है, इस स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर इस सूचना को यदि समेकित रूप में प्रस्तुत किया जाए तो वह अधिक लाभदायक सिद्ध होगी। अब तक बारह राज्यों और पाँच संघ राज्य-क्षेत्रों से सूचना प्राप्त की जा चुकी है।

प्रतिदर्श आधार पर शिक्षा संबंधी आँकड़ों के संकलन की प्रायोगिक परियोजना

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है जिसमें कुछ विषयों संबंधी शिक्षा आधार-सामग्री का संकलन केवल प्रतिदर्श संस्थाओं से ही किया जाएगा। इस प्रकार आयोजना तथा प्रशासनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक शिक्षा संबंधी आँकड़ों को इकट्ठा करने में समय की बचत होगी। इस समय इस प्रयोगिक परियोजना के अंतर्गत विहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और हरियाणा राज्य हैं।

परामर्श और प्रशिक्षण

रा० शै० अ० और प्र० प० ने कुछ अन्य शिक्षा संस्थाओं के अनुसंधान-कार्यकर्त्ताओं को अनुसंधान डिज़ाइन और सांख्यिकीय सेवा की योजनाओं को तैयार करने में सहायता तथा परामर्श की व्यवस्था की तथा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए विशेषज्ञों का प्रबंध किया। परिषद् ने उत्तर प्रदेश के भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा-सुविधाओं के सर्वेक्षण की डिज़ाइन बनाने में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की मदद भी की।

पुस्तकालय और प्रलेखन

इस वर्ष पुस्तकालय में 1524 नई पुस्तकें आईं और इस प्रकार पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की कुल संख्या लगभग 1.15 लाख हो गई। पुस्तकालय की कुल सदस्य संख्या 1723 थी। लगभग 170 अनुसंधान छात्रों ने पुस्तकालय की परामर्श-सेवाओं से लाभ उठाया। पुस्तकालय में प्रलेखन सेवाओं की भी व्यवस्था की गई।

1980-81 **वर्ष में पुस्तकालय की सुविधाओं संबंधी कुछ महत्त्वपूर्ण आँकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :**

(क) नई पुस्तकों की कुल संख्या	1524
(ख) खरीदी गई पुस्तकें	1330
(ग) मुफ्त में मिली पुस्तकें	194

(घ) सदस्य-संख्या 1723

(ङ) पुस्तकालय की परामर्श-सुविधा से लाभ उठाने वाले अनुसंधान छात्रों की संख्या 166

(च) पुस्तकों की कुल संख्या 1.15 लाख

प्रलेखन प्रकाशन

(क) न्यूज़ ऐंड व्यूज़ : खंड 1, संख्या 3

(ख) परिग्रहण सूची : मार्च 1981

(ग) करेन्ट कन्टेन्ट्स : खंड 1, संख्या 1-4

रिप्रोग्राफिक सेवाएँ

रा० शै० अ० और प्र० प० बहुत बड़ी मात्रा में रिप्रोग्राफिक सेवाएँ प्रदान करती रही और मार्च 1981 तक बनाई गई फोटो प्रतियों की संख्या 7492 थी ।

पत्रिकाएँ

रा० शै० अ० और प्र० प० में जो पत्रिकाएँ आती हैं वे या तो खरीदी जाती हैं या नि:शुल्क और आदान-प्रदान के रूप में होती हैं । उनका विवरण यों है :

(क) खरीदी गई पत्रिकाएँ 335

(ख) आदान-प्रदान के आधार पर प्राप्त पत्रिकाएँ 15

(ग) नि:शुल्क प्राप्त पत्रिकाएँ लगभग 50

अप्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

रा० शै० अ० और प्र० प० ने मई/जून 1980 में अंडमन और निकोबार द्वीपों के अप्रशिक्षित पुस्तकाध्यक्षों के लिए छ: सप्ताह के अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन किया । परिषद् ने 5 से 11 सितंबर 1980 तक पोर्टब्लेयर में अंडमन और निकोबार द्वीपों के पुस्तकाध्यक्षों के लिए अभिविन्यास पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया ।

पुस्तकालयों के विकास के लिए कार्यगोष्ठी

रा० शै० अ० और प्र० प० ने अक्टूबर, 1980 में मैसूर के क्षे० शि० म० में अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के पुस्तकालयों के विकास के संबंध में एक कार्यगोष्ठी का आयोजन किया । दक्षिणी क्षेत्रों के अध्यापक प्रशिक्षण कालेजों के लगभग 30 पुस्तकाध्यक्षों ने इसमें भाग लिया ।

कर्मचारियों की उन्नति

श्री आर० बी० राय और श्री आर० के० गौड़ नामक व्यावसायिक सहायकों को सूचना भंडारण और उपयोजन पद्धति के संबंध में चार सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया गया। सर्वश्री राधाकृष्ण, आर० बी० राय, जी० के० मिश्र और श्रीमती पॉली अलग को भारतीय पुस्तकालय संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा गया।

12

अनुसंधान और नव परिवर्तन

शैक्षिक अनुसंधान

अनुसंधान-कार्य और अनुसंधान-कार्यों को प्रोत्साहन तथा पोषण देना परिषद् का मुख्य कार्य है। परिषद् के विभागों/एककों और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों द्वारा किए जा रहे अनुसंधानों के अतिरिक्त परिषद् बाहर की संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करके शैक्षिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देती है। परिषद् कनिष्ठ और वरिष्ठ फैलोशिपों को भी इस उद्देश्य से पोषण देती है कि शैक्षिक समस्याओं के अनुसंधानों को निश्चित किया जा सके और देश के विभिन्न भागों में सक्षम अनुसंधानकर्ताओं की टोलियाँ बनाई जा सकें। परिषद् द्वारा किए जा रहे अथवा पोषित

अधिकांश अनुसंधान-कार्य वरीयता के क्षेत्रों में से लिए गए हैं।

सन् 1974 में स्थापित शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार समिति (एरिक) अनुसंधानों को प्रोत्साहन/पोषण देने वाला प्रमुख तंत्र है। समिति में बाहर के विभिन्न विश्वविद्यालयों/अनुसंधान संस्थाओं और राज्य शिक्षा संस्थानों/राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों से गृहीत दस सदस्य हैं। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागाध्यक्ष, सभी क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के प्रिंसिपल, डीन (शैक्षणिक) और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रोफ़ेसर स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। एरिक के मुख्य क्रिया कलाप इस प्रकार हैं :

—शैक्षिक और सहयोगी विज्ञानों की नवाचारीय परियोजनाओं पर अनुसंधानों को समर्थन-पोषण देना।

—पीएच० डी० शोधों और प्रबंधों को प्रकाशन-अनुदान देना।

—शोध-निष्कर्षों को समय-समय पर फैलाते रहना।

—अनुसंधान-सम्मेलन आयोजित करना।

सम्मेलन/परिसंवाद

अनुसंधान-कार्य को वित्तीय पोषण देने के अलावा, रा० शै० अ० और प्र० प० ने वर्ष के दौरान अनेक महत्वपूर्ण सम्मेलन और परिसंवाद आयोजित किए। इनमें प्रमुख थे—अधिगम पर वंचनाओं के प्रभाव पर भारत-अमरीकी परिसंवाद तथा अखिल भारतीय शैक्षिक अनुसंधान सम्मेलन।

शिक्षा और संस्कृति के भारत-अमरीकी उप-आयोग की सन् 1976 में जो बैठक हुई थी, उसके अनुसरण में रा० शै० अ० और प्र० प० ने 12 से 23 मई 1980 के बीच "प्रारंभिक वर्षों की वंचनाओं का अधिगम पर प्रभाव" पर एक भारत-अमरीकी परिसंवाद आयोजित किया। इस परिसंवाद का उद्घाटन श्री के० आर० नारायणन ने किया जो उस समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के उपकुलपति और शिक्षा एवं संस्कृति के भारत-अमरीकी उप-आयोग के सह-अध्यक्ष थे। संयुक्त राज्य के सात और भारत के दस प्रतिनिधियों ने इस परिसंवाद में भाग लिया। दिल्ली में कुछ पर्चे पढ़ने और विचार-विमर्श करने के अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधि दिल्ली की कुछ प्रायोगिक परियोजनाओं के स्थल देखने भी गए। अमरीकी प्रतिनिधि पांडीचेरी और हैदराबाद की प्रायोगिक परियोजनाएँ देखने गए। नई दिल्ली में 17 और 22 मई के बीच मोबाइल क्रेश केन्द्रों को देखने का कार्यक्रम रहा। अमरीकी प्रतिभागी पांडीचेरी के अंतर्राष्ट्रीय स्कूल और श्री अरविंद आश्रम को तथा हैदराबाद के भारत-डच शिशु-कल्याण परियोजना को देखने गए। विचार-विमर्श के मुख्य विषय थे—वंचनाओं के विविध पक्ष, अधिगम पर उनका प्रभाव, विकास की

कठिन घड़ियाँ, प्रभावित अधिगम की किस्में, अनुसंधान रूपरेखाओं की समस्याएँ और अंतर-विषयी अनुसंधान के क्षेत्र ।

शैक्षिक अनुसंधान का तीसरा अखिल भारतीय सम्मेलन

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के परिसर में यह सम्मेलन 22 और 23 अप्रैल 1981 को हुआ । विषय था—"विकलांगों की शिक्षा" । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षा डा० श्रीमती माधुरी आर० शाह ने इसका उद्घाटन किया । इस सम्मेलन में पढ़े जाने के लिए अनुसंधान-प्रबंध समाचार पत्रों के विज्ञापनों द्वारा आमंत्रित किए गए थे । अंधापन, गूँगापन, मानसिक विकलांगता जैसी अपंगताओं के क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक जाँच समिति ने इन प्रबंधों की जाँच की । सम्मेलन में पढ़े जाने के लिए 13 प्रबंध और प्रचारित किए जाने के लिए 8 प्रबंध चुने गए । जो लेख पढ़े गए उनके लेखकों को ढाई ढाई सौ रुपए पत्र-पुष्प के रूप में भेंट किए गए । चुने गए अनुसंधान प्रबंधों के अलावा विकलांगता के विशिष्ट क्षेत्रों से सम्बद्ध प्रेरक लेख भी पढ़े गए । अंतिम सत्र में विकलांगों की शिक्षा से सम्बद्ध अनुसंधान की प्रमुख समस्याओं और विषयों को समझने की ओर ध्यान दिया गया । सम्मेलन के साथ ही एक छायाचित्र-प्रदर्शनी भी की गई जिसके लिए फ़ोटो यूनिसेफ़ और ब्रिटिश काउंसिल से प्राप्त किए गए थे ।

पूरी हुई परियोजनाएँ

इस वर्ष के दौरान अनेक अनुसंधान परियोजनाएँ पूरी की गईं । उनका ब्यौरा नीचे दिया जा रहा है :

क्रम संख्या	परियोजना का शीर्षक	प्रमुख अन्वेषक का नाम-पता
1	2	3
(1)	राजस्थान के एक-शिक्षक-वाले स्कूलों की कार्य प्रणाली और समस्याएँ	डा० पी० एल० शर्मा शोध अधिकारी, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ।
(2)	परिवेशीय विधि पर आधारित उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान शिक्षा का विकास	डा० बी० पी० जोशी निदेशक, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उदयपुर ।

1	2	3
(3)	अपर सेकंडरी और अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में कविता शिक्षण के दृष्टिकोण से नई हिन्दी कविता में सम्प्रेषण का निर्धारण	डा० श्रीमती निर्मला जैन रीडर, हिन्दी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ।
(4)	छात्र-शिक्षकों की आत्म-संकल्पना के शिक्षण और शिक्षण-योग्यता पर माइक्रो-टीचिंग का प्रभाव	डा० मैथ्यू जॉर्ज उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलाङ ।
(5)	हिन्दी में भाषागत अशुद्धियों के निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण की योजना	श्री एल० के० ओड प्रिंसिपल, वनस्थली विद्यापीठ शिक्षा महाविद्यालय, वनस्थली ।
(6)	राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर सेवा-पूर्व अध्यापक-प्रशिक्षण कार्य-क्रम की प्रभावशीलता	श्री बी० एल० व्यास निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान उदयपुर ।
(7)	प्राथमिक स्कूलों में कार्य-शिक्षा का परिचय—एक मार्गदर्शी अध्ययन	प्रो० एस० सी० दाश निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान भुवनेश्वर ।
(8)	गाँव की ग़रीबी में छोटे बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास और अधि-गम, तथा हस्तक्षेप के प्रभाव : पहली अवस्था	डा० श्रीमती सुशीला सिंहल स्कूल ऑफ़ सोशल साइंस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली ।
(9)	स्कूल काम्प्लेक्स	प्रो० जे० बी० पी० सिन्हा ए०एन० एस० सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना ।
(10)	माध्यमिक स्कूल फाइनल परीक्षाओं में बड़ी संख्या में नकल	श्री जगदीन्द्र मंडल व्यावहारिक मनोविज्ञान विभाग यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलाजी, कलकत्ता ।
(11)	वाराणसी की गंदी बस्तियों में रहने वाले माध्यमिक छात्रों की समस्याएँ और आवश्यकताएँ	डा० सूर्यनाथ सिंह शिक्षा संकाय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी ।

इन परियोजनाओं के प्रमुख निष्कर्षों को संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है।

(1) राजस्थान के एक-शिक्षक-वाले स्कूलों की कार्यप्रणाली और समस्याएँ

इस अध्ययन के लक्ष्य थे—एक-शिक्षक-वाले स्कूलों की अवस्थिति, कार्मिकों, कार्य-प्रणाली की समस्याओं और सुविधाओं की पहचान करना। इस अध्ययन ने इन स्कूलों की कार्यप्रणाली को प्रभावकारी बनाने के लिए एक रूपरेखा सुझाई है।

राजस्थान के छह जिलों के पचीस स्कूल आबादी, आकार, अवस्थिति आदि की दृष्टि से चुने गए थे। स्कूल के आँकड़े, निरीक्षण, साक्षात्कार, समय-सारणी के विश्लेषण आदि का प्रयोग किया गया। डेढ़ सौ शिक्षकों, तीन सौ अभिभावकों और अठारह अधीक्षक अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया गया और विभिन्न दस्तावेजों को विश्लेषित किया गया।

प्रमुख निष्कर्ष हैं :

(i) हर स्कूल में दाखिले का औसत 47 था और दाखिले की दर 11 से 130 के बीच थी।

(ii) शैक्षिक क्षति की दर बहुत ज्यादा रही। कक्षा I में 70 बच्चे पढ़ने आते थे, पर कक्षा V तक पहुँचते-पहुँचते केवल 7 बच्चे रह गए। इस शैक्षिक क्षति का कारण गरीबी और अभिभावकों की उदासीनता है।

(iii) भौतिक सुविधाएँ अपर्याप्त थीं—4.6% स्कूलों में संतोषप्रद इमारत नहीं थी, केवल 34% स्कूलों में ही संतोषप्रद इमारत व्यवस्था थी। 13% स्कूल ऐसे थे जहाँ ब्लैक बोर्ड भी न था और 44% स्कूलों में पूरे स्कूल पीछे एक ही ब्लैक बोर्ड था।

(iv) ज़्यादातर शिक्षक स्कूल के मुहल्ले से दूर ही रहना पसंद करते हैं। बीच-बीच में स्कूल बिना किसी नोटिस के और बिना इजाज़त के छुट्टी कर जाते हैं। शिक्षक के छुट्टी जाने पर पास के स्कूल के शिक्षक या पास पड़ोस के पढ़े लिखे लोग एवजी पर आते हैं।

(v) शिक्षकों को ऐसे बहुत से काम दिए जाते हैं जो पढ़ने पढ़ाने के नहीं होते, फलस्वरूप स्कूल का रोज का काम बुरी तरह से पिछड़ या बिगड़ जाता है।

(vi) स्कूलों की कार्यप्रणाली के लिए तीस प्रतिशत स्कूलों में कोई ओपेरेशनल प्लैन नहीं है। जहाँ एक कक्षा के लिए टाइम-टेबुल मौजूद है वहाँ बाकी कक्षाओं का जिक्र भी नहीं है।

(vii) हर कक्षा की अपनी अपनी अलग अलग जगह नहीं है।

(viii) स्कूलों का निरीक्षण दोषपूर्ण तरीके से होता है। निरीक्षण करने वाले व्यक्ति सुधार की कोई बात नहीं करते।

(2) परिवेशीय विधि पर आधारित उच्च प्राथमिक स्तर के लिए विज्ञान-शिक्षा का विकास

एक नए किस्म की शिक्षा प्रणाली बनाने की कोशिश को यह अध्ययन प्रतिफलित करता है। हालाँकि राजस्थान के राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान ने उच्च प्राथमिक स्तर पर नई विज्ञान पाठ्यचर्याएँ गढ़ने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाई है, फिर भी राजस्थान के विविध प्रकार के भागों—रेगिस्तानी इलाकों, डूंगरपुर के जनजातीय हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के घने जंगलों—के लिए प्रासंगिक और विशिष्ट पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। अध्ययन ने इस विषय पर और भी खोज-पड़ताल की है। इन क्षेत्रों को आर्थिक और भौगोलिक कसौटियों के आधार पर बाँटा गया, उपविभाजन के आधार पर चुने गए 18 प्रतिनिधि खंडों से स्कूलों का चयन किया गया। हर खंड के उच्च प्राथमिक स्कूलों के पाँच प्रतिशत अर्थात् 50 प्रतिशत ने नियंत्रण समूह को बनाया। हर स्कूल से कक्षा VI, VII और VIII के एक-एक सेक्शन को लिया गया और जिन स्कूलों में एक से ज़्यादा सेक्शन थे, एक सेक्शन नियंत्रण समूह में चला गया। इस प्रकार एक कक्षा अध्ययन की इकाई बनी।

अध्ययन ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के पाठ्यक्रम को इन बातों से जुड़े होने की आवश्यकता समझी—

(i) सीखने वाले के वास्तविक जीवन और कार्यों के अनुभव, विशेष कर बदलते परिवेश में।

(ii) परिवार और समुदाय के सदस्य के रूप में या व्यक्ति रूप में सीखने वाले की ज़रूरतों की पूर्ति।

(iii) छोटे बच्चों की परिपक्वता और अपेक्षित संसाधनों की प्राप्यता।

(iv) नया ज्ञान।

(v) स्वास्थ्य और पोषण, ऊर्जा की संरक्षा, संसाधनों का प्रभावी उपयोग, प्रदूषण से बचाव आदि की शिक्षा द्वारा राष्ट्रीय विकास के प्रयत्न प्राथमिक स्तर से ही शुरू किए जाने चाहिए ताकि जीवन की गुणवत्ता सुधर सके।

(vi) रचनात्मकता, वैज्ञानिक विचार विधि और प्रवृत्ति, समस्या उन्मूलक कौशलों का विकास।

(vii) वैज्ञानिक धारणाओं, सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का विकास।

(viii) सीखने वालों का परिवेश, विशेष कर बिलकुल आस पास का।

(ix) अधिगम के सातत्य के लिए छात्रों को तैयार करना।

(x) पाठ्यक्रम की विषयवस्तु और अन्य क्षेत्र।

(3) अपर सेकण्डरी और अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं में कविता-शिक्षण के दृष्टिकोण से नई हिन्दी कविता में सम्प्रेषण का निर्धारण

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि नई हिन्दी कविता के प्रति छात्रों और शिक्षकों के क्या भाव हैं तथा नई हिन्दी कविता को कक्षा में पढ़ाने के लिए क्या विधि अपनाई जा रही है। अन्वेषकों ने इस परियोजना के लिए तीन बड़े शहरों—दिल्ली, चंडीगढ़ और इलाहाबाद के कुछ स्कूलों और कालेजों को चुना।

पाठ्यक्रम में नई कविता की स्थिति जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। अन्वेषक इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि स्कूल पाठ्यक्रम में नई कविता को प्रतिष्ठित स्थान नहीं दिया गया है और कालेज स्तर पर तो उसका कोई जिक्र ही नहीं है। सामग्री का चयन करते समय कवियों को महत्व दिया जाता है, उनकी कविताओं को नहीं।

यह भी पता चला कि नई हिन्दी कविता पढ़ाते समय शिक्षक के सामने अनेक मुश्किलें आती हैं, जैसे कि कविता के रूप को लेकर या कविता की सराहना को लेकर। सर्वेक्षण से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि दस में से नौ छात्र काव्य की अपेक्षा गद्य को पसंद करते हैं। इसी तरह, शिक्षकों में भी कविता के प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति ही रहती है।

सर्वेक्षण से पता चला कि नई कविता पढ़ाने की विधि संतोषप्रद नहीं है। अधिकांश शिक्षक पहले कठिन शब्दों के अर्थ बताकर फिर कविता के मूल स्वर की बाबत बताते हैं।

सर्वेक्षण से पता चला कि 50% विद्यार्थी रीतिकाल की कविता पसंद करते हैं, 15% विद्यार्थी छायावादी कविता को और 25% सांस्कृतिक पुनर्जागरण से सम्बद्ध कविताओं को। केवल 10% विद्यार्थी ही नई कविता को चाहते हैं। इसी तरह शिक्षकों में 40% रीतिकालीन और छायावादी कविता को एक जैसा पसंद करते हैं। 40% राष्ट्रीय और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की कविताओं की सराहना करते हैं और बाकी के 20% शिक्षक नई कविता को पसंद करते हैं।

(4) छात्र-शिक्षकों की आत्म-संकल्पना के शिक्षण और शिक्षण-योग्यता पर माइक्रो-टीचिंग का प्रभाव

अनुसंधान से पता चला है कि अध्यापक-शिक्षा में, करने की बजाय बताने पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षण-अभ्यास का अधीक्षण यों ही अंधाधुंध तरीके पर किया जाता है। छात्र-शिक्षण के प्रति जो धारणा है, यह भी बहुत कुछ सोचने को मजबूर करती है। इस कमी को दूर करने में माइक्रो-टीचिंग सहायता कर सकता है।

इस अध्ययन ने छात्र-शिक्षकों की आत्म-संकल्पना के शिक्षण पर माइक्रो-टीचिंग के प्रभाव का विश्लेषण किया। साथ ही उनकी शिक्षण-योग्यता पर माइक्रो-टीचिंग तथा कुशलताओं के एकीकरण के प्रभाव का भी विश्लेषण किया।

शिलाङ के एक प्रशिक्षण महाविद्यालय से बीस ऐसे छात्र-शिक्षकों को चुना गया जो इस परियोजना के लिए रज़ामंद थे। इन्हीं लोगों ने नियंत्रण और प्रयोगात्मक समूह बनाए जो आई० क्यू०, सेक्स, उम्र, योग्यताओं और शिक्षण-अनुभव से मेल खाते थे। कल्चर फ़ेयर इंटेलिजेंस टेस्ट (स्केल 2) को मेल के लिए प्रयुक्त किया गया। शिक्षण कौशलों के एकीकरण के रूप में शिक्षण-योग्यता के लिए इन्दौर शिक्षण योग्यता मान (आई० टी० सी० एस०), एकीकरण के अंतर्गत चारों कौशलों—अर्थात् भेदक प्रश्न, उद्दीपक विचरण, संबलन, सोदाहरण समझाना—की निरीक्षण सारणियों और आत्म-संकल्पना के शिक्षण मान (टी० एस० सी० एस०) का प्रयोग किया गया।

मेल बैठाने के बाद छात्र-शिक्षकों को माइक्रो-टीचिंग में अनुकूलित किया गया। हर शिक्षण कौशल पर विचार विमर्श हुआ, फिर ये काम किए गए—शिक्षण कौशल का निरीक्षण और रेटिंग, आदर्श पाठ की चर्चा, माइक्रो पाठ का प्रस्तुतीकरण, पीयर व अधीक्षक का पुनर्निवेशन और पुनर्शिक्षण सत्र, तदुपरांत पुनः पुनर्निवेशन। दूसरा माइक्रो पाठ किसी भिन्न इकाई का था जो उसी विषय की थी या किसी और विषय की। पाँचों कौशलों के लिए यही विधि अपनाई गई। नियंत्रण और प्रायोगिक दोनों समूहों के लिए हर सत्र में 8 से 10 पीयर तक थे। नियंत्रण समूह वाले छात्र-शिक्षकों को चार पाठ मिले जिनमें पीयर के रूप में 30 मिनट के लिए छात्र थे। इसके बाद पाँच मिनट का पारंपरिक पुनर्निवेशन था। प्रायोगिक समूह का शिक्षण कौशलों के एकीकरण में 20 मिनट के लिए अनुकूलन किया गया और उस पर शिक्षण सामग्री प्रदान की गई। इसके बाद अधीक्षक ने 25 मिनट के लिए एकीकृत कौशलों का प्रदर्शन किया, तदुपरांत पाठ और आइ० टी० सी० एस० पर विचार विमर्श हुआ। हर छात्र ने पीयरों को चार पाठ दिए। इसके बाद पुनर्निवेशन पुनर्शिक्षण का सत्र नहीं चला। दोनों समूहों पर जो परीक्षणोत्तर किए गए उनमें दो नियमित पाठ वास्तविक कक्षा में 30 मिनट के लिए, निरीक्षण आइ० टी० सी० एस० और टी० सी० एस० एस० थे।

नियंत्रण और प्रायोगिक दोनों समूहों के लिए आत्म-संकल्पना के शिक्षण के प्राप्तांकों के विश्लेषण से पता चला कि माइक्रो-टीचिंग की सुविधाओं ने छात्र-शिक्षकों द्वारा आत्म-संकल्पना अधिगम में वृद्धि की है, मतलब यह कि विधि छात्र-शिक्षकों को शिक्षण में स्थिति-परिवर्तन को देखने में मदद करती है। परीक्षणोत्तर प्राप्तांक, दोनों ही समूहों में बताते हैं कि शिक्षण योग्यता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रायोगिक समूह की शिक्षण-योग्यता नियंत्रण समूह की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इस अध्ययन के निष्कर्ष, भले ही सीमित नमूने में, यह थे कि माइक्रो-टीचिंग के द्वारा शिक्षण योग्यता को सुधारा जा सकता है। कौशलों के एकीकरण के साथ इस योग्यता को और भी बढ़ाया जा सकता है।

(5) हिन्दी में भाषागत अशुद्धियों के निदान तथा उपचारात्मक शिक्षण की योजना

इस अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य लिखित हिन्दी की गलतियों का पता लगाकर उन्हें भाषा वैज्ञानिक रीति से वर्गीकृत करना, इस प्रकार की अशुद्धियों पर स्थानीय बोलियों के प्रभाव को विश्लेषित करना, और कुशलता के सुधार पर उपचारात्मक शिक्षण का प्रभाव खोजना था।

राजस्थान के कक्षा VI से X तक के छात्रों की लगभग ढाई हज़ार उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच इस अन्वेषण के लिए की गई। मुख्य उद्देश्यों के अलावा इस अन्वेषण ने अशुद्धियों की जाँच और वर्गीकरण के लिए अपेक्षित साधनों का विकास किया और उपचारात्मक सामग्री लिखी। अध्ययन के लिए राजस्थान की पाँच बोलियों के आधार पर पाँच अंचलों से पाँच स्वतंत्र नमूने लिए गए। अशुद्धियों को नौ मुख्य वर्गों में बाँटा गया है—मात्राओं की अशुद्धियाँ, स्वरभेद चिह्न, स्वर व्यंजन, विराम चिह्न विधान, वाक्य संरचना, व्याकरण आदि की अशुद्धियाँ। हर बोली की अपनी विशिष्ट अशुद्धियाँ पाई गईं। कक्षा VIII तक अशुद्धियाँ कम होती जाती हैं लेकिन कक्षा IX-X तक पहुँचते-पहुँचते फिर बढ़ने लगती हैं। हर वर्ग की उपचारात्मक सामग्री को 15 दिनों के अभ्यास घंटे में जाँचा गया। परीक्षण पूर्व और परीक्षण-उत्तर के प्राप्तांकों की तुलना स्वरों, व्यंजनों और वाक्य-संरचना के लिए अलग-अलग की गई।

(6) राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर सेवा-पूर्व अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता

राजस्थान में प्राथमिक स्तर पर दो-वर्षीय अध्यापक-प्रशिक्षण कार्यक्रम की सापेक्ष प्रभावकारिता के मूल्यांकन, कुछ संभाव्य कक्षा-व्यवहार नमूनों, विभिन्न परिप्रेक्ष्यों तथा निरीक्षणों, और शिक्षकों की बौद्धिक व भावात्मक विशेषताओं की पहचान व विश्लेषण के लिए यह अध्ययन शुरू किया गया था।

अध्यापक-प्रशिक्षकों की राय, कक्षा व्यवहार के विश्लेषण, प्राथमिक स्कूलों में काम करने वाले प्रशिक्षित-अप्रशिक्षित शिक्षकों-शिक्षिकाओं के नमूनों, और 'फ्लैंडर्स इंटरऐक्शन ऐनालिसिस कैटेगरी सिस्टम' के अनुसार संग्रहीत सूचनाओं के द्वारा अधीक्षकों की राय के आधार पर इसे किया गया।

इस प्रकार के प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित शिक्षकों के कक्षा की अंतर क्रिया के नमूनों की तुलना शुरू की गई।

अध्यापक-शिक्षकों से निम्नलिखित का पता लगाने के लिए चार साधनों का विकास किया गया—अध्यापक ने क्या पढ़ाया है इस संबंध में अध्यापकों के निष्पादन की भूमिका, अध्यापकों की तैयारी और अध्यापकों को दिये गए प्रशिक्षण के प्रयोग पक्ष का मूल्यांकन,

प्रशिक्षित-अप्रशिक्षित शिक्षकों-शिक्षिकाओं के कक्षा-शिक्षण का निरीक्षण, और स्कूलों में काम कर रहे अध्यापकों के बारे में अधीक्षकों का साक्षात्कार।

राजस्थान के 25 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों के पचास शिक्षकों का प्रश्नावली-उपलब्धि परीक्षण लिया गया। प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 363 प्रशिक्षित और 187 अप्रशिक्षित शिक्षकों का मूल्यांकन किया गया। कुल मिलाकर 280 शिक्षक और 270 शिक्षिकाएँ थीं।

यह पाया गया कि प्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षिकाएँ अप्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षिकाओं से बेहतर थे। यह बात सभी विषयों पर लागू होती थी, सिवाय हिन्दी के जिसमें कोई अंतर नहीं था। प्रशिक्षित-अप्रशिक्षित शिक्षकों की शिक्षण-अभिवृत्तियों में कोई अंतर न था। प्रशिक्षित शिक्षिकाएँ अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं की तुलना में अधिक सहयोग करने वाली और बेहतर नैतिक आचरण वाली थीं।

अन्वेषण से यह तथ्य भी उजागर हुआ कि प्रशिक्षित शिक्षक अपनी कक्षा में कुछ अधिक बात करते थे, कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कक्षा में शांति कुछ अधिक रहती थी यानी कि भ्रांति फैली रहती थी अर्थात् प्रशिक्षित शिक्षक अधिक अधिकारवादी थे। लेकिन अप्रशिक्षित शिक्षकों के साथ छात्र अधिक बात करते थे और अप्रशिक्षित शिक्षक विषयोन्मुखी अंतर-क्रिया के प्रति अधिक सजग थे।

शिक्षित-अप्रशिक्षित शिक्षक-शिक्षिकाओं के पारंपरिक मूल्यांकन से यह भी पता चला कि प्रशिक्षित शिक्षिकाएँ किसी पाठ को शुरू करने में, उसे समझाने में और शिक्षण साधनों के प्रयोग में बेहतर साबित हुईं जबकि प्रशिक्षित शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में प्रश्न करने में, कक्षा के माहौल और अंतरक्रिया में, तथा विषय की सिद्धहस्तता में श्रेष्ठ थे। प्रशिक्षित शिक्षिकाएँ अप्रशिक्षित शिक्षिकाओं के मुकाबले पढ़ाए गए पाठ के मूल्यांकन में श्रेष्ठ थीं। अधीक्षकों की नज़र में प्रशिक्षित शिक्षिकाओं की तुलना में शिक्षक कक्षा शिक्षण के सभी पक्षों में, सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों के आयोजन में और व्यक्तिगत विशेषताओं में बेहतर होते हैं।

अन्वेषण से इस मान्यता की पुष्टि होती है कि सेवा-पूर्व प्रशिक्षण से शिक्षक अप्रशिक्षित शिक्षकों की तुलना में बेहतर स्थिति में रहते हैं।

(7) प्राथमिक स्कूलों में कार्य-शिक्षा का परिचय— एक मार्गदर्शी अध्ययन

इस अध्ययन का लक्ष्य था—प्राथमिक स्कूलों के लिए कार्य-शिक्षा में पाठ्यक्रम के माडलों का विकास करना। उद्देश्य थे—कार्य-स्थिति और सम्बद्ध ज्ञान एवं अनुभव की पहचान करना, छात्र-गतिविधियों के लिए अपेक्षित शिक्षण-सामग्री और मूल्यांकन साधनों का विकास करना।

गाँव, स्कूल के दाखिले आदि के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए एक प्रश्नावली बनाई गई। विद्यार्थियों की कार्य-स्थिति, आदतों आदि के बारे में सूचनाएँ इकट्ठी करने के उद्देश्य से एक इंटर्व्यू कार्यक्रम बनाया गया।

हर वर्ग के पाँच-पाँच के हिसाब से, कुल दस स्कूलों ने बेंत और ताड़ की पत्तियों से काम करना शुरू किया। स्कूल में और स्कूल के बाहर के समय में कार्य शिक्षा की स्थितियाँ कैसी रहती हैं यह पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किए गए। सर्वेक्षण और अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रमों को तीन भागों में बाँट दिया गया :

कक्षा I और II के लिए
कक्षा III से V तक के लिए
कक्षा VI और VII के लिए

सर्वेक्षण से पता चला कि हर कक्षा या इकट्ठी की गई कक्षाओं के समूहों के छात्रों द्वारा प्राप्त की जाने वाली निपुणताओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट कर पाना बहुत कठिन है।

स्कूल में और स्कूल के बाहर के अनुभवों को समाहित करने वाला एक पाठ्यक्रम विकसित किया गया। अध्ययन में प्रयुक्त कुछ शिक्षण सामग्री भी पहचानी गई। एक समय-सारणी भी बनाई गई।

छात्रों के कार्य के पाँचों पक्षों का मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण बनाया गया। सभी पक्षों को समाहित करने वाला पाठ्यक्रम सुझाया गया जिसमें संगठनात्मक युक्तियाँ भी थीं।

यह अध्ययन बच्चों की स्कूल के अंदर की और स्कूल के बाहर की गतिविधियों में समन्वय स्थापित करने में मदद कर सकता है। स्थानीय संसाधनों के इस्तेमाल से उत्पादन बढ़ाने में भी यह सहायक हो सकता है। भौगोलिक अंतरों को ध्यान में रखते हुए, स्थानीय संसाधनों और कार्य की गतिविधियों को इस्तेमाल करते हुए कार्य शिक्षा की योजना बनाई जा सकती है।

(8) गाँव की गरीबी में छोटे बच्चों का मनोवैज्ञानिक विकास और अधिगम, तथा हस्तक्षेप के प्रभाव : पहली अवस्था

इस अध्ययन के उद्देश्य थे— एक ही जिले के कई गाँवों की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं की तुलना करना, स्कूल जाने वाले और स्कूल न जाने वाले गरीब बच्चों की तुलना करना, और बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के स्तरों को नापने के लिए देसी उपकरणों का विकास करना।

राजस्थान के भरतपुर जिले को इस काम के लिए चुना गया। वहाँ की 1971 की

जनगणना के साक्षरता, रोज़गार आदि के आँकड़ों को आधार बनाया गया। कामन तहसील के गुरीरा-सोनूखार, पाई और बोडोली गाँवों को शामिल किया गया। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की करछना तहसील के शंकरगढ़ खंड को भी चुना गया क्योंकि वहाँ पर केन्द्रीय सरकार की एकीकृत शिशु विकास योजना चल रही है।

एक परिवार योजना चलाई गई जिसमें इन बातों का समावेश है--पृष्ठभूमि की जानकारी, रहने और खाने की दशाएँ, आमदनी और मिल्कियत, परिवार-संरचना, नाज भंडारण और आदतें, स्वास्थ्य, बच्चों का पालन-पोषण, तथा शिशु शिक्षा के प्रति माता-पिता के विचार। दस वर्ष से छोटे शिशु जिन घरों में हैं, उन्हें अध्ययन के लिए लिया गया। निरीक्षण के लेखे-जोखे के अनुसार हस्तक्षेप की आवश्यकता है क्योंकि बढ़ोतरी और विकास धीमी गति से होते हैं और बच्चे के सीखने (अधिगम) की क्रिया भी मंद गति से ही होती है।

गुरीरा-सोनूखार में 90% वयस्क पुरुषों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदतें नियमित हैं किंतु बोडोली और पाई गाँवों में यह प्रतिशत नीचा है। औरतों और बच्चों में यह कम है। रहने की व्यवस्था खराब है। 50% मकानों में ढोर-डंगर के लिए अलग घारी का प्रबंध नहीं है। काम भी नियमित रूप से नहीं मिलता। 60% से अधिक लोग अपढ़ हैं। खाने की आदतों में बहुत अंतर है। गुरीरा-सोनूखार और पाई में 70% परिवारों में साथ बैठकर खाने का रिवाज़ है जबकि बोडोली में औरतें मर्दों के खा लेने के बाद खाती हैं और कभी-कभी तो उनके लिए खाना कम भी पड़ जाता है। माँ बच्चों की बातचीत भौतिक ज़रूरतों के बारे में नहीं होती, पिता और अन्य पुरुषों के साथ व्यक्तिगत अनुभवों का आदान-प्रदान होता है या सामान्य जिज्ञासा के सवालों पर ही बातचीत होती है। कोई भी बच्चा मिरगी का शिकार नहीं मालूम पड़ता। केवल एक बच्चा मानसिक रूप से अपंग था।

आठ प्रतिशत बच्चे सक्रिय थे लेकिन कद काठी में औसत या औसत से कम थे। उपभोग के नमूनों में काफ़ी अंतर देखा गया। बीस प्रतिशत अभिभावक स्कूल कार्य को बढ़ावा देते हैं। नब्बे प्रतिशत महसूस करते हैं कि बच्चों को गाँव में जो शिक्षा मिलती है उसका उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। लेकिन 80% लोगों का विचार था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चों को गाँव के बाहर भी जाना चाहिए।

(9) स्कूल काम्प्लेक्स

बिहार के सीतामढ़ी, नालंदा और पालामऊ ज़िलों में स्कूल काम्प्लेक्सों की स्थापना के कार्यक्रम की जाँच इस अध्ययन ने की। सच तो यह है कि यह कार्यक्रम केवल नालंदा में ही ज़ोर शोर से चलाया गया था। औसतन चार प्राथमिक स्कूलों को एक मिडिल स्कूल के साथ नत्थी किया गया था और तीन मिडिल स्कूलों को संचार और अन्य सुविधाओं के आधार पर काम्प्लेक्स में लिया गया था।

अध्ययन से पता चला कि शुरू के दो वर्षों में निरीक्षणों की आवृत्तियाँ बढ़ीं, लेकिन जैसे ही यह ख़बर फैली कि योजना बंद हो रही है, आवृत्तियों की दर घटने लगी। अध्यापकों का विचार है कि निरीक्षण होते रहने से उनके कार्य में सुधार आता है क्योंकि निरीक्षण में उन्हें मार्गदर्शी रेखाएँ मिल जाती हैं। समुदाय और निरीक्षण करने वाले अधिकारियों के मध्य कोई संचार नहीं हो सका। निरीक्षण का सबसे ज़्यादा असर यह पड़ा कि अध्यापक नियम से समय पर आने-जाने लगे। क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारियों के कथनानुसार शिक्षण में कोई सुधार नहीं हुआ। हाँ, छात्रों ने सुधार महसूस किया।

शिक्षकों—विशेषकर प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों ने बढ़ गए काम के बोझ की शिकायत की। समुदाय ने देखा कि शिक्षण और अध्यापकों के आचरण में सुधार हुआ है। स्कूलों के भौतिक संसाधनों में कोई बढ़ोतरी या सुधार नहीं दिखा। योजना के सामने जो तरीके थे अर्थात् गरीब बच्चों को मुफ्त किताबें बाँटना, ब्लैक बोर्ड जैसी सामग्री प्रदान करना, केन्द्रीकृत परीक्षाएँ, उत्तर पुस्तिकाओं की जिलावार मानकीकृत जाँच—उन पर असर पड़ा लेकिन शुरू में ही। छात्रों की उपस्थिति बढ़ी, इतनी कि नियंत्रण समूह से उल्लेखनीय रूप में बढ़ गई। माध्यमिक और मिडिल स्कूलों के अधिकांश हेडमास्टरों ने ग़ौर किया कि छात्र पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे। प्राथमिक कक्षाओं में भर्ती हुए छात्र विशेष कर घर से करके लाने वाले पढ़ाई के काम में भी दिलचस्पी लेने लगे। विज्ञान प्रयोगशालाएँ दिखाने के लिए उन्हें बड़े (केन्द्रीय) स्कूल कभी नहीं ले जाया गया। हालाँकि योजना ने खेल-कूद, पत्रिकाओं और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से भावनात्मक एकीकरण पर बल दिया, फिर भी इस दिशा में कोई उल्लेखनीय प्रयास नहीं किया गया।

इमारत की मरम्मत या ज़मीन के लिए समुदाय ने आधे से भी कम हेडमास्टरों को कुछ मदद दी। अध्यापकों ने महसूस किया कि वे लोग सार्वजनीन साक्षरता, स्वास्थ्य और स्वच्छता की शिक्षा की व्यवस्था करके गरीब छात्रों की सहायता कर सकते हैं। स्कूल की इमारत की मरम्मत, छात्रों की हाज़िरी और अच्छी पढ़ाई में समुदाय की सहायता अध्यापकों ने चाही। केवल एक चौथाई अध्यापकों ने स्कूल जा सकने लायक बच्चों को स्कूल में लाने की कोशिश की। उनमें से भी केवल एक तिहाई को कुछ सफलता मिल सकी। समुदाय की इच्छा थी कि निरीक्षण अधिकारी उसके साथ विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श करें।

(10) माध्यमिक स्कूल फ़ाइनल परीक्षाओं में बड़ी संख्या में नक़ल

मार्गदर्शी अध्ययन ने कलकत्ता के स्कूलों में नक़ल करते हुए पकड़े गए छात्रों के एक समूह की तुलना उस दूसरे समूह से की जिसके छात्रों ने नक़ल नहीं की। स्कूलों में दो वर्ग बनाये गए—(i) वे स्कूल जहाँ बड़ी संख्या में नक़ल हुई, (ii) वे स्कूल जहाँ बड़ी संख्या में नक़ल नहीं हुई। इन स्कूलों से (N=92) छात्रों के नमूने लिए गए। स्कूल के परिवेश को तीन उप-प्रणालियों में बाँटा गया—शैक्षणिक वर्ग, छात्र वर्ग और प्रशासन वर्ग। पहले वर्ग

को इन बातों से मतलब था—भौतिक जगह, सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ, पुस्तकालय और शिक्षण सुविधाएँ। प्रशासन के क्षेत्र थे—दाखिले की कसौटी, परीक्षाएँ, और शिक्षकों का कार्य-भार। अध्ययन के लिए तीन प्रवृत्ति-मान विकसित किए गए।

दोनों प्रकार के स्कूलों से चुने हुए छात्रों की प्रतिक्रियाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि जहाँ तक शैक्षणिक वर्ग और प्रशासन वर्ग का संबंध है, भौतिक जगह, सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों, पुस्तकालय, शिक्षकों के प्रशिक्षण और अनुभव, मूल्यांकन और दाखिलों के लिए अपनाए गए तरीकों में उल्लेखनीय अंतर था। जिन स्कूलों में बड़ी संख्या में नक़ल नहीं हुई, वे इन सभी पहलुओं में बेहतर तरीके से सम्पन्न थे। अध्यापक-छात्र अनुपात और उनके कार्य-भार में कोई अन्तर न था।

दोनों प्रकार के स्कूलों में सबसे उल्लेखनीय अंतर छात्र वर्ग को लेकर था। अभिभावकों की शैक्षिक योग्यताएँ, परिवार का आकार और पढ़ाई के लिए कमरे का होना न होना इस उप-प्रणाली के अंतर्गत था।

जहाँ तक व्यक्तित्व का सवाल है, नक़ल न करने वाले छात्र सुझावों को मान लेने और दूसरों के नेतृत्व को स्वीकार कर लेने में उल्लेखनीय रूप से प्रवण थे। वे दूसरों की मदद करने में भी प्रवृत्त थे। यह बताता है कि उनके व्यक्तित्व में परोपकारिता थी। सब मिला कर बड़ी संख्या में नक़ल न करने वाले स्कूलों के छात्र उल्लेखनीय रूप से बेहतर थे।

(11) वाराणसी की गंदी बस्तियों में रहने वाले माध्यमिक छात्रों की समस्याएँ और आवश्यकताएँ

इस अन्वेषण के उद्देश्य थे—वाराणसी की गंदी बस्तियों में रहने वाले कक्षा IX, X, XI और XII के छात्रों की आवासीय, भौतिक, आर्थिक, भोजन संबंधी, परिवेशीय, शैक्षणिक, मनोरंजन संबंधी, सामाजिक, और मनोवैज्ञानिक समस्याओं में पैठना। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को लिया गया था। छात्रों का चयन उनके मकानों के मुहल्लों के आधार पर किया गया था।

माध्यमिक स्कूल के छात्रों की समस्याओं और आवश्यकताओं के अध्ययन के लिए एक प्रश्नावली हिन्दी में बनाई गई। गंदी बस्तियों में रहने वाले अधिकांश छात्रों को अनेक आवासीय समस्याएँ घेरे रहती हैं, जिनके कारण वे स्कूल के शैक्षणिक कार्यक्रम से लाभ नहीं उठा पाते। 60% छात्रों को पढ़ने की जगह व रोशनी जैसी सामान्य जीवन-सुविधाएँ भी नहीं मिल पातीं। 70% छात्रों को ऐसा लगता है कि उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ उन्हें पढ़ाई में कुछ कर दिखाने का मौका नहीं देतीं। 40% छात्रों को समुचित पोषण नहीं मिलता। 50% से अधिक को खराब परिवेशीय दशाओं में रहना पड़ता है। 50% ऐसे मुहल्लों में रहते हैं जो असामाजिक गतिविधियों के लिए बदनाम हैं। 40% से अधिक ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्वस्थ मनोरंजन नहीं मिल पाता। लगभग 30% मनोवैज्ञानिक समस्याओं

से ग्रस्त रहते हैं जैसे कि हीनता की भावना और मन की उदासी ।

अधिकांश छात्रों को पूरी पढ़ाई के दौरान निःशुल्क और सुव्यवस्थित छात्रावास पसंद हैं न कि रुपए पैसे की मदद जिसमें यह खतरा है कि माता-पिता उसे उड़ा देंगे। वे बेहतर शैक्षिक सामग्री के भी इच्छुक हैं । उनकी नजर में यदि एक बार खेलकूद की सुविधाओं से युक्त छात्रावास में रहने को मिल जाए तो बाकी सामाजिक, परिवेशीय, और मनोवैज्ञानिक समस्याएँ अपने आप छू मंतर हो जाएँगी ।

प्रकाशन

सन् 1980-81 के दौरान नीचे लिखे प्रकाशन पीएच० डी० प्रकाशन-अनुदान की योजना के अंतर्गत छापे गए ।

क्रम सं०	शीर्षक	नाम-पता
1.	अंग्रेज़ी प्राथमिक स्कूलों में पठन पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके और सामान एवं भारत के संदर्भ में उनकी प्रासंगिकता का अध्ययन	डा० राजेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली ।
2.	व्यक्तित्व संकल्पना के संदर्भ में शैक्षणिक निदर्शन का अध्ययन	डा० एस० के० नारंग प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालय पोर्ट ब्लेयर ।
3.	दूर-शिक्षण—सम्भावना और समस्याएँ	डा० जी० एस० सैनी पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना ।
4.	द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी पढ़ने के लिए शिक्षण प्रविधियों का निर्माण	डा० जयपालसिंह तरंग जामिया हायर सेकंडरी स्कूल शिक्षा संकाय जामिया मिल्लिया इस्लामिया नई दिल्ली ।
5.	वैज्ञानिक सृजनशीलता और व्यक्तित्व	डा० दीदार सिंह राजकीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल ।
6.	तुलसीकृत गीतावली का भाषाशास्त्रीय अध्ययन और वैज्ञानिक पद पाठ	डा० श्रीमती सरोज शर्मा बनस्थली विद्यापीठ बनस्थली ।

क्रम संख्या	शीर्षक	नाम-पता
7.	व्यावसायिक विकास के साथ जुड़े कुछ सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन	डा० विश्वनाथ रॉय रीडर, रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली ।

सन् 1980-81 के दौरान अनुसंधान-परियोजनाएँ और डाक्टरेट के शोध-प्रबंधों के लिए प्रकाशन अनुदान

अनुसंधान-परियोजनाएँ

1.	छात्र-शिक्षकों की आत्म-संकल्पना के शिक्षण और शिक्षण-योग्यता पर माइक्रो-टीचिंग का प्रभाव	डा० मैथ्यू जॉर्ज उत्तर-पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय शिलाङ ।
2.	इफैक्ट ऑफ़ मास्टरी लर्निंग स्ट्रैटेजी ऑफ़ पिउपिल एचीवमेंट (एम० एल० एस०)	डा० रामचन्द्र सी० आर० कालेज आफ़ एजुकेशन, रोहतक
3.	हिन्दी शिक्षण से सम्बद्ध अनुदेशीय सामग्री के विकास और विशिष्ट शिक्षण-कौशलों की पहचान की व्यापक अनुसंधान परियोजना एवं सम्भाव्य हिन्दी शिक्षकों की शिक्षण-योग्यता पर इन विशिष्ट कौशलों के प्रभाव का अध्ययन	डा० दामोदर लाल शर्मा लेक्चरर बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान सरदार शहर ।
4.	ग्रामीण शिशुओं की अधिगम असमर्थताओं का अध्ययन	डा० वाई० रामोजी राव निदेशक, शैक्षिक अनुसंधान संस्थान, मद्रास ।
5.	प्राथमिक स्कूलों को छोड़ जाने वाले बच्चों पर नॉन ग्रेडेड स्कूल-प्रणाली का प्रभाव	डा० जी० सुब्रह्मणिया पिल्लै शिक्षा विभाग मदुरै कामराज विश्वविद्यालय मदुरै ।
6.	प्रोफ़ाइल ऑफ़ रेजिस्ट्रैंट्स—एन इंक्वायरी इंटू वैरिएबुल्स रिलेटिंग टु स्टुडेंट्स ऑफ़ कारेस्पौंडेंस इंस्टीट्यूशंस एट दि सेकंडरी लेवेल इन इंडिया	डा० ओ० एस० देवल निदेशक ओपेन स्कूल, सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली ।

क्रम संख्या	शीर्षक	नाम-पता
7.	डेवेलपमेंट ऑफ़ काम्पेटेंस, रिलेटेड पर्सनैलिटी कैरेक्टेरिस्टिक्स एंड कापीइंग स्ट्रैटेजीज़ ऑफ़ स्कूल ब्वायज़ एंड गर्ल्स	डा०श्रीमती टी०एस० सरस्वती एम० एस० यूनिवर्सिटी ऑफ़ बड़ौदा, बड़ौदा ।
8.	डेवेलपिंग एंड टेस्टिंग मॉडेल्स ऑफ़ एनवाइरनमेंटल एजुकेशन इन बॉटनी रेलिवेंट फॉर दि स्पेशली डिसऐडवांटेजेड चिल्ड्रेन इन दि स्कूल्स ऑफ़ केरल	प्रो० एन० वी० मैनुएल अध्यक्ष, शिक्षा विभाग केरल विश्वविद्यालय त्रिवेंद्रम ।
9.	अनौपचारिक शिक्षा में सुविधा-वंचित वर्गों विशेषकर कुम्हारों के वयस्क सीखने वालों की ज़रूरतों का अनुमान	श्रीमती शांता कृष्णन रामकृष्णपुरम नई दिल्ली ।
10.	हिन्दी के ध्वनिग्रामिक परिवर्तनों का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन	डा० भोलानाथ तिवारी दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली ।
11.	दिल्ली और बम्बई के शहरी मिडिल/हायर सेकंडरी स्कूलों के शिक्षकों के लिए सेक्सिज़्म में एक अनुकूलन कोर्स का विकास	श्रीमती के० निश्चल गुजरात रिसर्च सोसायटी सेन शोधन सदन साउथ एवेन्यू, खार बम्बई ।
12.	प्राथमिक स्कूल के बच्चों की सोशियोमीट्रिक स्थिति पर शिक्षक-अपेक्षाओं के प्रभावों का अध्ययन	श्री एन० सी० धौंडियाल लेक्चरर, शिक्षा संकाय कुमाऊँ विश्वविद्यालय अलमोड़ा ।
13.	एचीवमेंट नॉर्म स्टडी ऑफ एलीमेंटरी चिल्ड्रेन ऑफ़ तमिलनाडु विद स्पेशल रेफ़रेंस टु सर्टेन स्कूल फैक्टर्स एंड स्टूडेंट कम्पोज़ीशंस	श्री एम० दुरैस्वामी एस० आइ० टी० यू० काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च 169, रामकृष्ण मठ रोड रामकृष्णपुरम, मद्रास ।
14.	देहाती/शहरी बच्चों में रचनात्मकता के विकास पर शैक्षिक वंचनाओं के प्रभाव का अध्ययन	श्री एल० पी० पांडेय महासचिव और परियोजना निदेशक, भारतीय सामाजिक विज्ञान अकादमी, ईश्वर शरण डिगरी कालेज, इलाहाबाद ।

क्रम संख्या	शीर्षक	नाम-पता
डाक्टरेट के शोध-प्रबंध		
15.	बस्ती जिले की किशोर छात्राओं (13-18) की शैक्षिक उपलब्धियों पर पारिवारिक चिंताओं के प्रभाव	डा० श्रीमती किरण कुमारी श्रीवास्तव शोहरतगढ़, बस्ती ।
16.	पंजाब राज्य में स्कूल स्तर पर पंजाबी-शिक्षण का समीक्षात्मक मूल्यांकन ।	डा० इन्द्रपाल सिंह निदेशक पंजाब शिक्षा मंडल एस० ए० एस० नगर चंडीगढ़ ।
17.	कक्षा I से VIII तक समेकित बुनियादी हिन्दी शब्द-भांडार	प्रो० उदयशंकर शिक्षा के अवकाश प्राप्त प्रोफ़ेसर विश्वविद्यालय परिसर कुरुक्षेत्र ।
18.	महाराष्ट्र के सेकंडरी स्कूलों के निरीक्षण और अधीक्षण के विचार और व्यवहार का उद्भव	डा० ए० वी० गाडगिल भारतीय शिक्षा संस्थान पुणे ।
19.	रचनात्मकता, मेधा और रुचियों की क्रियाविधि के रूप में शिक्षण में प्रवीणता	डा० श्रीमती रश्मि जैन 84-बी, टैगोर नगर लुधियाना ।
20.	अभियांत्रिकी के बहुत अच्छा और बहुत खराब कर दिखाने वाले छात्रों की कुछ अबौद्धिक विशेषताएँ	डा० आर० एन० नागपाल एल० 16, ग्रीन पार्क नई दिल्ली ।
21.	ए स्टडी ऑफ़ क्रिएटिविटी इन स्कूल टीचर्स ऐज़ मेज़र्ड बाई मेहदीज़ टेस्ट इन रिलेशन टु देयर सेल्फ़-कन्सेप्ट, ऐटीच्यूड टुवर्ड्स टीचिंग ऐंड क्लासरूम वर्बल इंस्ट्रक्शंस	डा० अजित सिंह लेक्चरर अध्यापक-शिक्षा विभाग रा० शै० अ० और प्र० प० नई दिल्ली ।

सन् 1980-81 के दौरान पूरी हुई, विभाग की कुछ अनुसंधान-परियोजनाओं का ब्यौरा आगे दिया जा रहा है :

शिक्षा महाविद्यालयों में छात्र-शिक्षण और दूसरे सम्भाव्य कार्यों के निरीक्षण व मूल्यांकन के लिए साधनों का विकास

प्रमुख अन्वेषक : प्रो० सी० एस० सुब्बा राव
श्री टी० एन० एस० भटनागर

बी० एड० स्तर पर शिक्षा महाविद्यालयों में किए जाने वाले प्रैक्टिकल काम के मूल्यांकन के लिए सत्तरह मूल्यांकन-साधन बनाए जा चुके हैं। प्रैक्टिकल काम में ये शामिल हैं—निरीक्षण के लिए स्कूल जाना, पाठ-योजना, छात्र-शिक्षण, दृश्य-श्रव्य साधनों का उत्पादन, पुस्तक-समीक्षाएँ, सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ, सामुदायिक सेवाएँ, छात्र-स्व-शासन, अन्वेषणीय रिपोर्टें, सत्र-पर्चे, समाजोपयोगी उत्पादक कार्य, नागरिकता-शिविर, उप-लब्धि परीक्षणों का निर्माण, केस स्टडीज़ आदि। निष्पत्ति-निर्देशिका को 1 से 7 तक के पैमाने पर या 'विशेष योग्यता' से 'अनुत्तीर्ण' के बीच में या प्रतिशत में दिखाया जा सकता है। हैदराबाद में बने साधनों को कर्नाटक में प्राथमिक स्तर के अध्यापक-प्रशिक्षण और बी० एड० स्तर के लिए सुधारा गया है।

सीरम यूरेट कंसेंट्रेशंस, इंटेलेक्चुअल स्टाइल और पर्सनैलिटी

प्रमुख अन्वेषक : डा० एम० के० रैना

इस अध्ययन को यह पता लगाने के लिए किया गया था कि सीरम यूरेट कंसेंट्रेशंस और इंटेलेक्चुअल स्टाइल व पर्सनैलिटी में क्या संबंध है। विभिन्न जीव-रासायनिक विचारों के आधार पर सावधानी से चुने गए (ग्रुप ए और बी के अलग अलग) 150 प्रयोग-व्यक्तियों को इसमें प्रयुक्त किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि मेधा, सृजनात्मकता, और यूरिक एसिड के साथ बहिर्मुखता के एक समूह के बीच उल्लेखनीय सम्बन्ध है। यूरिक एसिड कंसेंट्रेशंस ने भी जीवनी-कारकों के साथ उल्लेखनीय सहसम्बन्ध जाहिर किया।

कक्षा VIII में भूगोल में छात्रों की निष्पत्ति को सुधारने के लिए शिक्षण और मूल्यांकन को एकीकृत करना

प्रमुख अन्वेषक : श्रीमती कमला शेषन

इस परियोजना को यह सत्यापित करने और एक आदर्श बनाने के लिए हाथ में लिया गया था कि शिक्षण और मूल्यांकन को प्रभावी तरीके से एकीकृत किया जाए ताकि छात्रों की उपलब्धि को सुधारने का एक जरिया मिल सके। परियोजना से यह तथ्य प्रकाश में आया कि समूह में उपचारात्मक शिक्षण औसत और अच्छे छात्रों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका है तथा औसत से नीचे के विद्यार्थियों के लिए ट्यूशन ही उपचारात्मक शिक्षण का सर्वोत्तम तरीका है।

विज्ञान प्रतिभा के अध्ययन

प्रमुख अन्वेषक : डा० एम० के० रैना

इस परियोजना के अंतर्गत चार अन्वेषण किए गए। चारों के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

(क) सन् 1976 की राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज के परीक्षार्थियों के पृष्ठभूमि चरों का विश्लेषण

राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा (1976) में बैठने वाले अधिकांश छात्र उत्तर प्रदेश के थे, इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल का नाम आता है। सबसे अधिक छात्रवृत्तियाँ दिल्ली के छात्रों को मिलीं। उनके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और केरल के छात्र आते हैं। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में शहर के छात्रों ने गाँवों के छात्रों की तुलना में अच्छे अंक प्राप्त किए। पब्लिक स्कूलों से आने वाले छात्रों ने साक्षात्कार और अंतिम चयन दोनों ही में बेहतर निष्पादन किया जबकि सरकारी स्कूलों के छात्रों का निष्पादन सबसे खराब था। लिखित परीक्षा में अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्रों ने बेहतर निष्पादन किया जबकि साक्षात्कार में अन्य भाषाओं वाले छात्रों ने बेहतर कर दिखाया। अन्य भाषाओं वाले छात्रों की तुलना में अंग्रेज़ी माध्यम वाले छात्र 65% अधिक चुने गए। जिन परीक्षार्थियों में अनेक शौक (हॉबीज़) थे, उनके लिए साक्षात्कार में बुलाए जाने और चुने जाने के अधिक अवसर थे। जिन छात्रों में बेहतर शैक्षणिक उपलब्धियाँ थीं, उनके चुने जाने के अवसर ज्यादा थे हालाँकि उच्च शैक्षणिक उपलब्धि राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज में अच्छे निष्पादन की पक्की सूचक हो, ऐसा नहीं पाया गया। परीक्षा-परिणामों से पता चलता है कि परिवारों की शैक्षणिक, आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति एवं स्तर का परीक्षार्थी के चुने जाने में गहरा हाथ होता है। यह बात तब और भी पक्की हो जाती है जब पता चलता है कि अभिभावक शैक्षिक धन्धे में लगे हुए थे।

(ख) विज्ञान प्रतिभा खोज योजना में संनिघर्षण

हर साल और हर स्तर की शिक्षा के लिए, विज्ञान प्रतिभा खोज योजना में संनिघर्षण की दर का पता लगाने की कोशिश की गई। सन् 1967 से प्राप्त आधार सामग्री का विश्लेषण किया गया। विज्ञान प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत चुने गए अनेक छात्र योजना के प्रारंभ में ही खिसक लेते हैं। इस प्रकार से योजना छोड़ने वालों की दर 1967 से 29% से 49% के बीच रही है। योजना को बीच में ही छोड़ देने वालों की दर संधिकाल में सबसे अधिक रही है अर्थात् बी० एससी० प्रथम वर्ष में, एम० एससी० प्रथम वर्ष में और पीएच० डी० के प्रथम तथा अंतिम वर्षों में जो छात्र चुने जाते हैं या छात्रवृत्ति स्वीकार करते हैं, उनका एक अल्पांश ही पीएच० डी० के चार वर्ष पूरे करता

है। उदाहरण के लिए, 1967 में जो लोग चुने गए, उनके 6% ने ही पीएच० डी० के चार वर्ष पूरे किए और जिन्होंने प्रथम वर्ष में छात्रवृत्तियाँ स्वीकार कीं, उनके 9% ने ही पीएच० डी० के चार वर्ष पूरे किए।

(ग) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज में छात्रवृत्तियाँ पाने वालों के खिसक जाने के कारण

अधिकांश प्रतिभाएँ बिल्कुल आरंभ की अवस्था में ही योजना छोड़ती हैं। हालाँकि उनकी प्रतिभा को मान्यता मिल जाती है और उन्हें छात्रवृत्ति का हक़दार भी घोषित कर दिया जाता है, फिर भी लगभग 48% हक़दार छात्रवृत्ति ग्रहण किए बिना ही ग़ायब हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे मूल विज्ञानों के कोर्सों में नहीं रहते। कारणों का वर्ष क्रम का अध्ययन भी यही बताता है कि खिसकने का सबसे बड़ा कारण वर्षों से यही रहा है कि मूल विज्ञानों की बजाय खिसकने वाले दूसरे कोर्सों में चले जाते हैं। बी० एससी० स्तर पर खिसकने का कारण (22%) प्रायः यह रहा कि छात्रों को प्रथम श्रेणी नहीं मिली या उन्होंने अति दरिद्र निष्पादन किया। एम० एससी० स्तर पर छात्रवृत्ति छोड़ने के दो प्रमुख कारण थे—विदेश जाना और प्रथम श्रेणी न पाना। एम० एससी० में कुछ छात्रों ने छात्रवृत्तियों का त्याग इसलिए किया कि उन्हें नौकरी मिल गई थी। पीएच० डी० स्तर पर छात्रवृत्ति छोड़ने के प्रायः तीन कारण रहे हैं—विदेश जाना, नौकरी पाना और पढ़ाई छोड़ देना।

(घ) विज्ञान के प्रतिभावान छात्रों के शैक्षणिक निष्पादन का अनुदैर्ध्य अध्ययन

यह अध्ययन यह पता लगाने के लिए किया गया था कि—(i) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज में छात्रवृत्ति पाने वाले क्या हमेशा श्रेष्ठ शैक्षणिक निष्पादन करते रहते हैं; (ii) बी० एससी० और एम० एससी० स्तरों पर औसत उपलब्धि में क्या कोई संबंध है; (iii) चुने जाने के समय मिले दर्जे का क्या बाद की शैक्षणिक उपलब्धि से कोई सम्बन्ध है? अध्ययन के निष्कर्षों से पता चला कि, (क) राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा में चुने गए छात्र आगे चलकर बी० एससी० स्तरों पर भी श्रेष्ठ शैक्षणिक निष्पादन करते हैं; (ख) ऐसा कोई संगत चित्र नहीं उभरता जो यह दिखाए कि एम० एससी० का निष्पादन बी० एससी० के निष्पादन की तुलना में बेहतर हो जाता है; (ग) चयन प्रक्रियाएँ यह नहीं बता पाईं कि आगे चलकर शैक्षणिक निष्पादन कैसा रहेगा।

कक्षा V, VI और VII के लिए उर्दू में श्रेणीकृत क्रमिक सामग्री का निर्माण

प्रमुख अन्वेषक : श्रीमती जमीला बेगम

पहले बने शब्द भांडार और संरचना के आधार पर आदर्श पाठ बनाए गए। इस संरचना और शब्द भांडार को प्रयुक्त करते हुए, बच्चे के परिवेश पर आधारित, विभिन्न प्रकार के विषयों वाली समुचित पठन-सामग्री का निर्माण किया गया। पठन-सामग्री में निम्नलिखित जीवन मूल्य प्रतिफलित होते हैं : देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, सर्व धर्म समभाव, नेतृत्व, आत्मविश्वास, सह अस्तित्व, कर्तव्य बोध, ईमानदारी, त्याग भावना, वसुधैव कुटुम्बकम, शालीनता, अहिंसा, मानव मात्र से प्रेम, सहानुभूति, सहनशीलता, दया, क्षमा, बड़ों के प्रति सम्मान, दानशीलता, आपस में एक दूसरे की सहायता, तुरंत स्पष्ट निर्णय लेना, चौकस फैसला। उर्दू में विभिन्न प्रकार की संसाधन सामग्री जाँचने, चुनने और क्रमिक रूप से श्रेणीकृत करने के लिए इकट्ठा की गई।

हाई स्कूल जीव विज्ञान कोर्सों में कोशिका-वैज्ञानिक प्रदर्शनों के लिए जीवद्रव्यक तकनीकों का मानकीकरण और सरलीकरण

प्रमुख अन्वेषक : डा० अरुणकुमार मिश्र

तीन शोध पत्र छपे—

(i) माध्यमिक स्कूल जीवविज्ञान कोर्सों के लिए सरलीकृत जीवद्रव्यक वियोजन तकनीकें। (**जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन** में प्रकाशित)

(ii) सरलीकृत तकनीकों द्वारा पादप जीवद्रव्यक वियोजन और विभेदन के अध्ययन। (**जर्नल ऑफ़ साइकोलॉजी एंड जेनेटिक्स** में प्रकाशित)

(iii) वियोजित पादप जीवद्रव्यक में प्लाज़्मोलिसिस और सेल वेल रिजेनेरेशन का अध्ययन।

हायर सेकण्डरी स्तर के लिए ओपेन एंडेड प्रयोगों पर आधारित भौतिकी में प्रयोगशाला कोर्स का विकास

प्रमुख अन्वेषक : डा० एस० जी० गंगोली

इस परियोजना में छह स्कूल-अध्यापकों को शामिल किया गया था। ओपेन एंडेड प्रयोगों की विचारधारा पर विचार-विमर्श किया गया। भारतीय स्कूलों के लिए उपयोगी ओपेन एंडेड प्रयोगों के एक फार्म का प्रस्ताव किया गया। प्रयोगशाला के सम्पर्क घंटों पर दस प्रयोग विकसित किए गए हैं। रिपोर्ट पुस्तिका के रूप में छप चुकी है। कुछ प्रयोगों को आगामी वर्ष सक्रिय रूप से जाँचा-परखा जाएगा।

भारत में बी० एड० कार्यक्रम में छात्र-शिक्षण और दूसरे प्रैक्टिकल कार्य पर अध्ययन और साहित्य—एक समीक्षा

प्रमुख अन्वेषक : श्री टी० एन० एस० भटनागर

इस विषय पर विविध अध्ययनों एवं आगे गिनाए गए विभिन्न प्रकार के साहित्य को यह समीक्षा जाँचती है—सन् 1950 से 1978 के बीच आयोगों, परिसंवादों, कार्य-गोष्ठियों की रिपोर्टें, अध्ययन निष्कर्ष और अन्य प्रकार का साहित्य। अध्ययन में इस प्रकार का साहित्य लिया गया है—(क) छात्र-शिक्षण, (ख) छात्र-शिक्षण और दूसरे प्रैक्टिकल कार्य का मूल्यांकन, और (ग) अध्ययन एवं प्रयोग।

विभागीय अनुसंधान परियोजनाएँ

जो अनुसंधान परियोजनाएँ अभी चल रही हैं और जिन्हें इस वर्ष के दौरान पोषित किया गया, उनकी सूची नीचे दी जा रही है :

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रमुख अन्वेषक (समाप्ति की संभाव्य तिथि)
	शिशु अध्ययन एकक	
1.	दो से तीन वर्षों के भारतीय शिशुओं का बोधात्मक विकास—अनुदैर्घ्य अध्ययन	डा० श्रीमती यू० बेवली (मार्च 1983)
2.	कक्षा I और II के सुविधा-वंचित बच्चों के लिए घरेलू हस्तक्षेप कार्यक्रम की संभाव्यता का अध्ययन	कुमारी इंदिरा मलानी (अगस्त 1981)
	केप समूह	
3.	ग्रामीण क्षेत्रों की 11 से 14 वर्ष की लड़कियों की अनौपचारिक शिक्षा के लिए अधिगम-सामग्री का विकास	डा० एस० पी० मलिक (दिसंबर 1981)
	पाठ्यक्रम समूह	
4.	स्कूल पाठ्यक्रम का प्रभावी उपयोग	डा० बी० पी० गुप्ता (मार्च 1983)
5.	विभिन्न राज्यों में सेकंडरी स्तर पर पाठ्यक्रम भार की तुलना	डा० जी० एल० अरोड़ा (मार्च 1982)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रमुख अन्वेषक (समाप्ति की संभाव्य तिथि)
6.	नौ से चौदह वर्ष के स्कूल न जाने वाले बच्चों की जीवन शैली की खोज	डा० बी० आर० गोयल
	विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग	
7.	जीवविज्ञान में आवश्यकता-आधृत और समुदाय-अभिमुखी स्व अधिगम की शिक्षण-सामग्री के विकास की प्रायोगिक परियोजना	डा० जे० मित्रा (मार्च 1982)
8.	परिवेश और स्थानीय संसाधनों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के लिए प्लांट बेस्ड प्रयोग विकसित करना	डा० श्रीमती एस० भट्टाचार्य (जुलाई 1981)
9.	कक्षा XI या फर्स्ट ईयर स्तर पर भौतिकी—व्यक्ति-परक शिक्षण का कार्यान्वयन	डा० आर० एन० माथुर (मार्च 1982)
10.	हायर सेकंडरी स्तर पर पारम्परिक तरीके बनाम भौतिकी के प्रयोगों को ओपेन एंडेड तरीकों से करने की प्रभावकारिता का तुलनात्मक अध्ययन	डा० एस० जी० गंगोली (मार्च 1984)
	मापन और मूल्यांकन विभाग	
11.	आवासीय स्कूलों में रह कर पढ़ने वाले भारत सरकार की योग्यता छात्रवृत्ति पाने वालों का अध्ययन	श्री के० वी० राव (नवंबर 1981)
12.	सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन और बच्चों में सृजनात्मक क्रियाविधि के परिवर्तन	डा० एम० के० रैना (सितंबर 1981)
13.	स्कूल-परिवेश का मूल्यांकन	डा० प्रफुल्ल एम० पटेल
14.	प्राथमिक स्कूल शिक्षा के असर डालने वाले परिणामों का मापन	डा० प्रफुल्ल एम० पटेल
15.	प्रतिभा में शोध और विकास	डा० एम० के० रैना (सितंबर 1981)
16.	राष्ट्रीय विज्ञान प्रतिभा छात्रवृत्ति पाने वालों की उपलब्धियों का गहन अध्ययन	डा० एम० के० रैना (दिसंबर 1982)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रमुख अन्वेषक (समाप्ति की संभाव्य तिथि)
17.	अजमेर स्थित राजस्थान माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा IX, X और XI के लिए अपनाई गई व्यापक आंतरिक मूल्यांकन योजना का मूल्यांकन	श्री जे० पी० अग्रवाल (फरवरी 1982)
18.	कक्षा अधिगम में सुधार—कक्षा VIII के लिए भूगोल में मास्टरी अधिगम विधि	श्रीमती कमला शेषन (जनवरी 1982)
	अध्यापक-शिक्षा विभाग	
19.	माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए साधनों का विकास	डा० जे० सी० गोयल (मार्च 1982)
20.	समुदाय के साथ काम के मूल्यांकन के लिए मापन साधनों (निरीक्षण सूची और रेटिंग मान) का विकास	डा० सी० एस० सुब्बा राव (मार्च 1982)
21.	प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों में सामाजिक संबद्धता और संस्थानों की निष्पत्ति से इसका सम्बन्ध	डा० एन० के० जांगीरा (मार्च 1981)
22.	अपने आस पास के पौधों को जानिए	प्रो० जी० आर० घोष (जून 1982)
23.	प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अध्यापक-शिक्षा के लिए पत्राचार पाठ्यक्रमों के विकास की दृष्टि से समुदाय के साथ काम करने वाले प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों से अपेक्षित भूमिका का अध्ययन	प्रो० सी० एस० सुब्बा राव श्री टी० एन० एस० भटनागर (मार्च 1982)
24.	माध्यमिक अध्यापक-शिक्षा महाविद्यालयों के लिए प्रतिमानों का विकास	प्रो० सी० एस० सुब्बा राव श्री टी० एन० एस० भटनागर (मार्च 1982)
	शैक्षिक मनोविज्ञान एकक	
25.	राष्ट्रीय परीक्षण पुस्तकालय का विकास	प्रो० आत्मानंद शर्मा (चल रही है)
26.	बच्चों को प्रेरित करने की समूह प्रक्रिया की प्रकृति और कार्यविधि का अध्ययन	डा० विश्वनाथ रॉय (जनवरी 1981)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रमुख अन्वेषक (समाप्ति की संभाव्य तिथि)
27.	उच्चतर माध्यमिक स्तर पर प्रवाह के भीतर ही प्रवाह और कोर्सों के चुनाव के लिए निकष का विकास	प्रो० आत्मानंद शर्मा (मार्च 1981)
28.	बी० एड० पत्राचार पाठ्यक्रम के छात्रों को प्रेरित करना	डा० के० कुमार (मार्च 1981)
29.	व्यावसायीकरण के लिए माध्यमिक स्कूल स्तर पर व्यावसायिक खोज कार्यक्रम की प्रभावकारिता का अन्वेषण	प्रो० आत्मानंद शर्मा (मार्च 1985)
30.	बीच में ही स्कूल छोड़ जाने वाले की 'स्कूल छोड़ने की प्रक्रिया' और 'लाक्षणिक विशेषताओं' का अनुदैर्ध्य अन्वेषण	प्रो० आत्मानंद शर्मा (मार्च 1983)
31.	आकस्मिक प्रबंध द्वारा प्राथमिक छात्रों के ज्ञानात्मक कार्यकलाप और कक्षा आचरण को सुधारना	डा० वी० के० सिंह श्री० आर० के० शर्मा (नवंबर 1981)
32.	स्कूलों में विज्ञान की पढ़ाई को सर्वोच्च बनाने की खोज	डा० श्रीमती एस० राव (अगस्त 1980)
	शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक	
33.	पहली पीढ़ी के सीखने वालों का अध्ययन	प्रो० श्रीमती पेरिन एच० मेहता डा० श्रीमती सी० धर (जुलाई 1981)
34.	उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले लड़कों की आत्म-संकल्पना	प्रो० पी० एच० मेहता
35.	उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले लड़कों की शैक्षिक एवं व्यावसायिक योजना	डा० श्रीमती सी० धर डा० जे० एस० गौड़ डा० श्रीमती ए० भटनागर
	अनौपचारिक शिक्षा एकक	
36.	हिन्दी शब्द भांडार का संग्रह और भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण	डा० कृष्ण गोपाल रस्तोगी (मार्च 1982)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रमुख अन्वेषक (समाप्ति की संभाव्य तिथि)
	प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास सेल	
37.	बदलते हुए समाज (प्राचीन से आधुनिक काल तक, विशेषकर आधुनिक काल का) के संदर्भ में पाठ्य-पुस्तकों की उत्पत्ति और औपचारिक शिक्षा में उनकी भूमिका का अध्ययन	डा० बी० एस० गोयल (मार्च 1981)
38.	प्राथमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा की पाठ्यपुस्तकों में प्रयुक्त भाषा की बोध-गम्यता का अध्ययन	डा० इन्द्रसैन शर्मा
39.	भूगोल में क्षेत्र अध्ययनों के प्रयोग में मार्गदर्शन	श्री इक़बाल मोहिउद्दीन
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शिक्षा एकक	
40.	राजस्थान के जनजातीय इलाक़ों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में बाधा पहुँचाने वाले कारकों का अध्ययन	श्री बी० पी० अवस्थी (जुलाई 1981)
41.	जनजातीय छात्रों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्य-क्रमों की विधियों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का अध्ययन	डा० एल० आर० एन० श्रीवास्तव डा० बी० एस० गुप्ता (मार्च 1982)
42.	जनजातीय छात्रों को मिलने वाले शैक्षिक अवसरों की समानता का अध्ययन	डा० एल० आर० एन० श्रीवास्तव डा० बी० एस० गुप्ता (मार्च 1982)
	सर्वेक्षण और आधार-सामग्री प्रक्रिया एकक	
43.	नमूने के तौर पर चौथे शैक्षिक सर्वेक्षण की आधार-सामग्री का गौण विश्लेषण	प्रो० ए० बी० एल० श्रीवास्तव (मार्च 1982)
44.	आठ चुने हुए राज्यों की लड़कियों के शैक्षिक रूप से पिछड़ेपन का नमूने का सर्वेक्षण	प्रो० ए० बी० एल० श्रीवास्तव (अक्तूबर 1982)
45.	चुने हुए राज्यों में नमूने के तौर पर शैक्षिक आधार-सामग्री के संकलन की मार्गदर्शी परियोजना	प्रो० ए० बी० एल० श्रीवास्तव (मार्च 1982)
	शिक्षा के व्यावसायीकरण का एकक	
46.	महाराष्ट्र में शिक्षा के व्यावसायीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समीक्षात्मक अध्ययन	डा० प्रभाकर रायज़ादा (मार्च 1981)

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	प्रमुख अन्वेषक (समाप्ति की सम्भाव्य तिथि)
	स्त्री-शिक्षा एकक	
47.	राज्यों और संघ क्षेत्रों में अविभेदीकृत पाठ्यक्रम	श्रीमती जे० दुग्गल (सितंबर 1981)
48.	भारत के राज्यों और संघ क्षेत्रों में सहशिक्षा की स्थिति का अध्ययन	कुमारी प्रभा पुरी (अगस्त 1981)
	अजमेर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय	
49.	किशोरावस्था के दौरान विज्ञान में विचारों की योजनाओं का निर्धारण और विकास	प्रो० एन० वैद्या (जून 1982)
	भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय	
50.	उच्च/उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए कार्य अनुभव/व्यावसायिक कार्यक्रम के रूप में खाए जाने वाले कुकुरमुत्तों की खेती और सर्वेक्षण	डा० एम० पी० सिन्हा (मार्च 1983)
51.	ज्वार-भाटा के बीच के जीवन को जानिए	डा० ए० एल० एन० शर्मा
	मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय	
52.	रिलेशनशिप बिटवीन लेसन किनेटिक स्ट्रक्चर्स एंड लर्निग आउट कम्स इन स्कूल साइंस	डा० जी० आर० राजू
53.	सेकंडरी स्कूल के भौतिकी के शिक्षकों की कठिनाइयों और कमियों की पहचान और उन्हें दूर करने के उपाय	डा० सोमनाथ दत्त (फरवरी 1983)
54.	दक्षिण क्षेत्र के स्कूलों में प्रचलित नव परिवर्तन वाले व्यवहारों-अभ्यासों का अध्ययन	डा० पी० सी० ईपन
55.	समझ के साथ द्रुत गति में अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए विधि ढूँढ़ना और उसे अमल में लाना	श्रीमती लक्ष्मी अरड्या
56.	स्कूलों में जीव विज्ञान के लिए कार्य क्रमित अनुदेशीय सामग्री	श्री आर० के० भरतिया (मार्च 1982)
	भोपाल का क्षेत्र एकक	
57.	भारत में जनसंख्या-विस्फोट के ज्ञान, विश्वास और प्रवृत्तियों के बारे में कक्षा IX और X को जनसंख्या-शिक्षा पढ़ाने की शिक्षक-नेतृत्व वाली और तीन अन्य कक्षा विधियों का प्रभाव	डा० आर० पी० कथूरिया (अक्तूबर 1983)

13

विस्तार कार्यक्रम और राज्यों के साथ कार्य करना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की गतिविधियों में अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रमों का प्रमुख स्थान है। विस्तार के कार्यक्रमों का मतलब है राज्यों, राज्यों के शैक्षिक संस्थानों और शिक्षकों तथा अध्यापक-शिक्षकों के व्यवसाय से संबंधित संस्थाओं के साथ घनिष्ठता से मिलकर कार्य करना। राज्यों के साथ उचित संपर्क बनाए रखने के लिए परिषद् ने राज्यों की राजधानियों में अपने 16 क्षेत्र कार्यालय बना रखे हैं। वे क्षेत्र कार्यालय अपने आप राज्यों की ज़रूरतों के कुछ कार्यक्रम किया करते हैं। साथ ही वे राज्यों की ज़रूरतों का पता लगाकर

राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान और क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों को बताते हैं ताकि बदले में ऐसे कार्यक्रम किये जा सकें जो राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करें। वर्ष के दौरान परिषद् के मुख्यालय ने विस्तार के अनेक कार्यक्रम किए। उनमें जो महत्वपूर्ण हैं, उन्हें नीचे लिखा जा रहा है :

अनुवर्ती शिक्षा केन्द्रों की योजना

इस योजना को 1978-79 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था देश के विभिन्न भागों में काम करने वाले माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्राथमिक स्कूलों के अध्यापक-शिक्षकों की व्यावसायिक योग्यता को निरंतर बढ़ाते रहना। इस काम को शुरू करने के लिए, तय किया गया कि राज्यों/संघ क्षेत्रों की सरकारों के सक्रिय सहयोग से शुरू में सौ केन्द्रों की स्थापना की जाए जिनके आवर्तक खर्चों के पचास प्रतिशत का भार-वहन सम्बद्ध राज्य/संघ क्षेत्र करें। अभी तक इन राज्यों/संघ क्षेत्रों में 97 केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं : असम, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, पांडिचेरी, तमिलनाडु और त्रिपुरा।

97 केन्द्रों में से लगभग 70 केन्द्रों ने 1980-81 के अंत तक काम करना शुरू कर दिया था। हर केन्द्र वर्ष में लगभग 600 अध्यापकों और अध्यापक-शिक्षकों को अनुकूलित कर सकेगा। सन् 1980-81 के दौरान इन केन्द्रों द्वारा आयोजित किए गए विभिन्न पाठ्य-क्रमों में लगभग बारह-पन्द्रह हज़ार शिक्षकों व अध्यापक-शिक्षकों ने भाग लिया।

सन् 1980-81 में मैसूर, भुवनेश्वर और अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों तथा पुणे के राज्य शिक्षा संस्थान में चार क्षेत्रीय गोष्ठियाँ हुईं। समस्याओं को पहचानने के लिए अनुवर्ती शिक्षा केन्द्रों के अवैतनिक निदेशकों/समन्वयकों, राज्य शिक्षा विभाग के कर्मचारियों (जिनमें शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव भी शामिल हैं), और रा० शै० अ० और प्र० प० के सम्बद्ध क्षेत्र के क्षेत्र सलाहकारों ने गोष्ठी में भाग लिया।

राष्ट्रीय एकीकरण परियोजना

वर्ष 1980-81 के दौरान, छह अंतर-राज्यीय छात्र-शिविर और चार अध्यापक-शिविर आयोजित किए गए। इन शिविरों में लगभग 450 छात्रों और 400 अध्यापकों ने भाग लिया जो सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों से आए थे। अपनी योजना "स्कूली बच्चों और शिक्षकों के लिए पूरक-पठन-सामग्री के निर्माण" के अंतर्गत "चेतना" नामक कठपुतली नाटकों का संकलन भी तैयार किया गया।

स्कूलों में नव परिवर्तन के सेमीनार रीडिंग्स

इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों द्वारा अपनाए

गए नवाचारीय अभ्यासों के विवरण प्राप्त किए गए। अंतिम मूल्यांकन बाहर के विशेषज्ञों ने किया। प्राथमिक स्कूल शिक्षकों द्वारा भेजी गई 30 पांडुलिपियों और माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की 20 पांडुलिपियों को पाँच-पाँच सौ रुपये के नगद पुरस्कारों तथा योग्यता प्रमाण-पत्रों के योग्य समझा गया।

संयुक्त-राष्ट्र-दिवस और मानव-अधिकार-दिवस के समारोह

रा० शै० अ० और प्र० प० ने संयुक्त-राष्ट्र-दिवस और मानव-अधिकार-दिवस के समारोहों का आयोजन किया। इन जलसों में दिल्ली के स्कूलों के प्रिंसिपल, विख्यात शिक्षा शास्त्री, यूनिसेफ़, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि आए।

10 दिसंबर 1980 को 'मानव-अधिकार-दिवस' रा० शै० अ० और प्र० प० ने मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र सूचना केन्द्र के निदेशक ने एक भाषण दिया जिसका शीर्षक था 'मानव-अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया है और क्या कर रहा है'। दिल्ली के स्कूलों के कुछ प्रिंसिपल, अन्य शैक्षिक संस्थाओं के कुछ शिक्षाशास्त्री और यूनिसेफ़, यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधि इस अवसर पर आए।

क्षेत्र सलाहकारों के काम

क्षेत्र सलाहकारों के कार्यालयों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें सर्वप्रमुख था अनौपचारिक शिक्षा का प्रायोगिक कार्यक्रम। क्षेत्र कार्यालय ने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों को विभिन्न बस्तियों में खोला है, विशेषकर देहाती और गंदी बस्ती वाले शहरी इलाकों में, तथा उन घने बसे टोलों मुहल्लों में जहाँ सुविधा वंचित पिछड़ा वर्ग रहता है।

स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं द्वारा शुरू किए गए अनेक प्रायोगिक कार्यकमों को क्षेत्र कार्यालयों ने पोषित किया। माँगने पर इन कार्यालयों ने रा० शै० अ० और प्र० प० के तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कार्यक्रमों के बारे में छात्रों, स्कूल शिक्षकों, अध्यापक-शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं को जानकारी दी। परिषद् के विभागों और एककों को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने के लिए, विशेषकर शिक्षण-सामग्री के निर्माण और राज्य स्तर के प्रमुख कार्मिकों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यक्रमों से सम्बद्ध महत्वपूर्ण तंत्र प्रदान करने के लिए इन क्षेत्र कार्यालयों ने बहुत कुछ किया।

अहमदाबाद का क्षेत्र एकक वहाँ के दस अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की गतिविधियों में समन्वय बनाए रखता है। इन केन्द्रों में 7 देहाती या गंदी बस्तियों में हैं और 3 शहरी क्षेत्रों में। ये केन्द्र बड़ौदा के म० स० विश्वविद्यालय के एम० एड० के छात्रों द्वारा सँभाले जाते हैं।

इलाहाबाद के क्षेत्र सलाहकार ने स्कूलों और कालेजों में नव परिवर्तन वाले कार्यों को जो बढ़ावा दिया है, उसकी प्रशंसा वहाँ के राज्य शिक्षा विभाग ने की है। एतदर्थ राज्य

शिक्षा विभाग को एक प्रस्ताव दिया गया, जिसके अनुसार क्षेत्र एकक शैक्षणिक मार्गदर्शन देगा और प्रशासकीय तथा वित्तीय भार राज्य शिक्षा विभाग को वहन करना होगा। फल-स्वरूप राज्य सरकार ने डेढ़ लाख रुपयों का अनुदान स्कूलों में नव परिवर्तन वाले कार्यों के लिए दे दिया है। इस प्रकार की योजनाएँ बनाने और लागू करने की विधियों में प्रशिक्षित करने के लिए, क्षेत्र एकक ने माध्यमिक स्कूलों के प्रिंसिपलों/हेडमास्टरों और क्षेत्रीय अधिकारियों के वास्ते एक अनुकूलन कार्यगोष्ठी आयोजित की।

अक्तूबर 1980 में क्षेत्र कार्यालय द्वारा प्रायोगिक परियोजनाओं पर आयोजित अनुकूलन कार्यगोष्ठी में निर्मित सामग्री से एक प्रकाशन 'नवाचारीय परियोजनाएँ' तैयार किया गया। इसे राज्य शिक्षा विभाग को दे दिया गया जिसने इसे हिन्दी में सुन्दर ढंग से छापकर राज्य स्तर पर बँटवाया।

बँगलोर के क्षेत्र कार्यालय ने बँगलोर जिले के कनकपुरा ताल्लुके में दस गाँवों के एक समूह में अनौपचारिक शिक्षा के प्रायोगिक कार्यक्रम चला रखे थे। इस वर्ष इन दस गाँवों में काम चलता रहा। अब एक दूसरा समूह भी ले लिया गया है जहाँ 2-10-1980 से काम शुरू किया गया है। इन कामों में स्थानीय समुदाय ने अपना सहयोग दिया। केन्द्रों को चलाने के लिए समुदाय ने मुफ्त आवास की व्यवस्था की, साथ ही रोशनी का प्रबंध भी उसीने किया ताकि केन्द्रों को रात में भी खोला जा सके। हर केन्द्र में प्रवेश और उपस्थिति उत्साहवर्धक रही। प्रवेश तो हर केन्द्र में चालीस से ऊपर ही रहा।

भोपाल के क्षेत्र कार्यालय द्वारा चलाये जा रहे अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के 56 छात्रों ने सन् 1981 की कक्षा V की बोर्ड की परीक्षा दी, 40 छात्र पास हुए और 4 छात्र पूरक सूची में आए। कक्षा V पास करने वाले कुछ छात्र कक्षा VI में नियमित छात्र की हैसियत से दाखिला लेने की तैयारी कर रहे हैं। कक्षा V की बोर्ड की परीक्षा में बैठने की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए विशेष तौर पर शिक्षण-सामग्री तैयार करने के लिए क्षेत्र कार्य-कर्ताओं और क्षेत्र अधीक्षकों के मासिक अनुकूलन शुरू किए गए हैं। मुल्ताई ब्लॉक में छह दिनों वाली एक प्रशिक्षण-उत्पादन कार्यगोष्ठी, प्रश्न और कार्यक्रमित अधिगम शिक्षण सामग्री बनाने के लिए की गई। क्षेत्र कार्यकर्ताओं और क्षेत्र अधीक्षकों के लिए, सात दिनों वाला एक अनुकूलन कार्यक्रम मुंडेश्वर के बी० एल० आई० में 9 से 15 जुलाई 1981 तक किया गया।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए, मुल्ताई के नगर निगम अध्यक्ष, जिला शिक्षा अधिकारी, सब डिवीज़नल अफ़सर, तहसीलदार, ए. डी. आइ. एस., सरपंच आदि पूरा सहयोग दे रहे हैं।

शिक्षा विभाग ने परीक्षा के उद्देश्य से अनौपचारिक शिक्षा के छात्रों को नियमित छात्रों के रूप में मान्यता दे दी है। इस प्रकार अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्र स्कूलों द्वारा दिए जाने वाले प्रमाणपत्रों के बराबर माने जाएँगे।

भुवनेश्वर के क्षेत्र कार्यालय ने कटक जिले के पहाड़ी इलाके वाले ब्लॉक दनगढ़ी के दस गाँवों में 10 अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले हैं। इनमें आने वाले बच्चों का अधिकांश अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है। छह से चौदह वर्ष के बच्चे, जिन्होंने कभी औपचारिक प्रणाली के स्कूलों का मुँह भी नहीं देखा, और न कभी देखेंगे, या जो कुछ दिनों के लिए औपचारिक प्रणाली के स्कूलों में गए थे पर कुछ पढ़ने के पहले ही घर बैठ गए, इस कार्यक्रम से लाभ उठा रहे हैं। इन बच्चों ने साक्षरता, गणित और स्वास्थ्य शिक्षा तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में अच्छी प्रगति की है। इन केन्द्रों के अनेक बच्चों ने अपेक्षित योग्यता उपार्जित कर औपचारिक शिक्षा प्रणाली अपना ली है।

स्थानीय स्तर की तीन बैठकें की गईं जिनमें अभिभावक, स्थानीय समुदाय के चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सक, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक लेवेल अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक आदि आए। सोचा गया है कि ऐसी बैठकें और जल्दी-जल्दी की जाएँ ताकि लोगों की प्रवृत्ति बदल सके और लोगों में जागरूकता आए। पढ़ना, लिखना, गिनना सीखने के साथ ही समाजोपयोगी उत्पादक कार्य पर विशेष बल दिया जा रहा है जैसे कि वृक्ष आरोपण, घरेलू उद्यान वाटिका, मुर्गी पालन, भेड़ और बकरी पालन, समुदाय की सफ़ाई, जूट से बोरे और झाड़ू तैयार करना आदि।

कलकत्ता का क्षेत्र कार्यालय पश्चिम बंगाल के एक ऐसे एकांत सुदूर स्थल में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है, जहाँ के 90 प्रतिशत लोग 'माँझी' सम्प्रदाय के हैं। इन केन्द्रों की मासिक औसत उपस्थिति 94.5% रहती आई है। इस प्रकार के और केन्द्र खोले जाने की माँग हो रही है। यहाँ के छात्रों के 15 से 20 प्रतिशत लोगों ने गणित के सरल सवाल हल करना सीख लिया है। बांग्ला की अपेक्षाकृत कठिन पुस्तक 'मिलांच' को पढ़ना भी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है।

चंडीगढ़ के क्षेत्र एकक ने 'अध्यापक संघों की भूमिका और संघ के सदस्यों की व्यावसायिक योग्यता में वृद्धि" विषय पर दो-दिनों वाली क्षेत्रीय परामर्श बैठक चंडीगढ़ के राजकीय शिक्षा महाविद्यालय में 25 और 26 मार्च 1981 को की। इस परामर्श बैठक में उन सम्भाव्य विधियों और शैलियों पर विचार-विमर्श हुआ जिनकी सहायता से अध्यापक संघ अपने सदस्यों की शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। संघ के नेताओं के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के वरिष्ठ शिक्षाशास्त्रियों और शैक्षिक प्रशासकों ने बैठक में भाग लिया। पंजाब के शिक्षा मंत्री ने समापन भाषण दिया।

गौहाटी के क्षेत्र कार्यालय ने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं और क्षेत्र अधीक्षकों के लिए सात दिनों वाला प्रशिक्षण-कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रशिक्षण

कार्यक्रम का मुख्य जोर इस बात पर था कि इन कर्मचारियों को अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने की विधियों में और भी निपुण कैसे बनाया जाए।

रा० शै० अ० और प्र० प० ने असम में अनौपचारिक शिक्षा के अपने कार्यक्रम के लिए एक प्रवेशिका बनाई है—"सीकू अहा"। इसे असम की सरकार ने अपने अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्रों के लिए अपना लिया है।

नौ से चौदह वर्ष के जिन बच्चों ने दस केन्द्रों में दाखिला लिया है, उनके 10 प्रतिशत ने इतनी योग्यता अर्जित कर ली है कि वे औपचारिक प्रणाली वाली कक्षा V में जा सकें।

हैदराबाद के क्षेत्र एकक ने, राज्य शिक्षा विभाग के क्षेत्र अधीक्षक, कृषि महाविद्यालय और कुछ क्षेत्र कार्यकर्ताओं के सहयोग से, तिपार्ती के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए एक पुनश्चर्या कोर्स के आयोजन में हिस्सा लिया।

ये केन्द्र संतोषजनक रीति से काम कर रहे हैं। लेकिन सूखे के कारण कुछ बच्चे अपने घर वालों के साथ चले जाते हैं फिर भी तुरंत ही नए छात्र केन्द्रों में आ जाते हैं।

जयपुर के क्षेत्र कार्यालय के तत्वावधान में राजस्थान के आठ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं जो बसई ब्लॉक में हैं। हर केन्द्र में औसतन 30 से 40 छात्र भर्ती हुए हैं। सन् 1980-81 के दौरान जो उल्लेखनीय कार्यक्रम हुए उनमें सर्वप्रमुख था एक कार्यगोष्ठी का आयोजन जो कलाओं और दस्तकारियों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए हुई थी। साथ ही एक सभा भी हुई जो इन केन्द्रों के मूल्यांकन के लिए थी।

राजस्थान के साढ़े चार सौ से अधिक स्कूलों में रेडियो द्वारा हिन्दी पढ़ाने के कार्यक्रम, जिसे सामान्यत: रा० शै० अ० और प्र० प० की रेडियो मार्गदर्शी परियोजना के नाम से जाना जाता है, में यहाँ का क्षेत्र एकक सन् 1980-81 के दौरान सक्रिय रूप से लगा रहा।

मद्रास के क्षेत्र सलाहकार का कार्यालय निम्नलिखित दस गाँवों में दस अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है :—चित्लपक्कम, मदम्बक्कम, ओट्टियम्बक्कम, पाडुवनचेरी, रामकृष्णपुरम, सम्मनचेरी, शीतलापक्कम नम्बर एक, शीतलापक्कम, तिरुवनचेरी और वेडपक्कम। क्षेत्र कार्यकर्ताओं और क्षेत्र अधीक्षकों को रद्दी के सामान से चार्ट और माडल बनाने, विभिन्न विषयों में अधिगम पैकेज तैयार करने और शिक्षा के लिए कठपुतलियों के इस्तेमाल करने के अवसर प्रदान किए गए।

क्षेत्र कार्यकर्ताओं ने गाँवों की स्थितियों और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए लगभग 50 विषयों पर शिक्षण सामग्री तैयार की। उन्होंने कई चार्ट और माडल भी बनाए।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में पढ़ाने-पढ़ने की प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है—परिवेश को जानना और परिवेशीय स्थितियों के साथ तालमेल करना।

पटना के क्षेत्र कार्यालय ने बिहार के समस्तीपुर में अनौपचारिक शिक्षा के नौ केन्द्र बना रखे हैं। इन केन्द्रों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं को किताबें, स्लेटें, रजिस्टर जैसे स्टेशनरी के सामान दिए गए हैं। नौ केन्द्रों में 347 छात्रों ने दाखिला लिया है। वर्ष के दौरान छह विद्यार्थी केन्द्र छोड़कर चले गए। बिहार और उत्तर प्रदेश के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के क्षेत्र कार्यकर्ताओं और क्षेत्र अधीक्षकों के लिए भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय ने राजगीर में 25 सितंबर से 1 अक्तूबर 1980 तक एक अनुकूलन-उत्पादन शिविर लगाया। इसके आयोजन में भी क्षेत्र एकक ने अपेक्षित सहायता प्रदान की।

पुणे के क्षेत्र एकक ने महाराष्ट्र और गोआ के पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए खिलौना बनाने की प्रतियोगिताएँ आयोजित कीं। महाराष्ट्र से 125 खिलौने भेजे गए। इस राज्य में जिस खिलौना बनाने वाले को प्रथम पुरस्कार मिला, उसी को राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी प्रथम पुरस्कार मिला है।

बम्बई नगर निगम, भारतीय शिक्षा संस्थान आदि जैसे अन्य संस्थानों/माध्यमों के कार्यक्रमों में भी इस क्षेत्र एकक ने सहयोग दिया।

शिलाङ के क्षेत्र सलाहकार ने मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के पूर्व-प्राथमिक और प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों के लिए खिलौना बनाने की एक प्रतियोगिता आयोजित की जिसे रा० शै० अ० और प्र० प० का शिशु अध्ययन एकक कराता है।

इस वर्ष के दौरान मेघालय के प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए समुदाय नेतृत्व और समाजोपयोगी उत्पादक कार्य में एक अनुकूलन शिविर क्षेत्र सलाहकार ने आयोजित किया। इस कार्यक्रम में मेघालय के 30 प्राथमिक स्कूल अध्यापक आए। इस कार्यक्रम के उद्देश्य थे—(i) शिक्षकों में काम के प्रति रुझान पैदा करना; (ii) शिक्षा और कार्य के बीच एकीकरण स्थापित करने में सहायता देना; (iii) पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए शिक्षकों में विशेष कौशल विकसित करना, और (iv) समुदाय का नेतृत्व करने में शिक्षकों की सहायता करना। इस कार्यक्रम का प्रभाव प्रतिभागियों और स्थानीय प्रशासन पर बहुत अच्छा रहा।

श्रीनगर का क्षेत्र कार्यालय जम्मू व कश्मीर के अशम, नौगाँव, रेक-शिलवट, शादीपुर्मा, शिलवट, सम्बल (इंदरकोट) और वंगीपोरा में सात अंशकालिक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चला रहा है। रेक-शिलवट और शिलवट के केन्द्र अपेक्षया कमज़ोर हैं। अन्य केन्द्रों में लगभग 40 छात्रों ने दाखिला लिया है। इस परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन अभी किया जाना है। फिर भी इस परियोजना ने समाज में शिक्षा के लाभों के प्रति चेतना जगा दी है।

इस क्षेत्र कार्यालय ने क्षेत्र कार्यकर्ताओं के लिए तीन दिनों का एक प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया। इसका मुख्य उद्देश्य था—अनौपचारिक शिक्षा की संकल्पना, विधियों

और कौशलों से शिक्षकों को परिचित-अनुकूलित करना। इस प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण अंग था शिक्षण-सामग्री और मूल्यांकन-सामग्री का निर्माण। एक और प्रशिक्षण-उत्पादन कार्यगोष्ठी इस क्षेत्र कार्यालय में 6 से 15 अप्रैल 1981 तक की गई।

त्रिवेंद्रम के क्षेत्र एकक ने इन कार्यक्रमों के आयोजन में प्रशासन-पोषण प्रदान किया:

—प्रायोगिक परियोजनाएँ।

—खिलौना बनाने की प्रतियोगिताएँ।

—शैक्षिक फिल्मों का प्रदर्शन।

14

प्रतिभा की खोज

वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने X, XI, और XII के लिए, सारे भारत में 430 केन्द्रों में राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाएँ कीं। तीनों कक्षाओं में लगभग 80 हज़ार परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे। परीक्षार्थियों की संख्या और छात्रवृत्तियों की राशि आदि का ब्यौरा आगे दिया जा रहा है :

क्रम संख्या	कक्षा	छात्रवृत्तियों की संख्या	परीक्षार्थियों की संख्या	छात्रवृत्ति की राशि
1.	X	250	42,000	(क) दो वर्षों के लिए 150 रु० प्रतिमास + 200 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान; (ख) इसके बाद मूल विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के लिए, और अभियांत्रिकी तथा औषध में पहली डिगरी तक के लिए 200 रु० प्रतिमास + 300 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान।
2.	XI	100	7,000	(क) एक वर्ष के लिए 150 रु० प्रति मास + 300 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान; (ख) इसके बाद मूल विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के लिए, और अभियांत्रिकी तथा औषध में पहली डिगरी तक के लिए 200 रु० प्रति मास + 300 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान।
3.	XII	150	31,000	मूल विज्ञानों तथा सामाजिक विज्ञानों में दूसरी डिगरी तक के लिए, और अभियांत्रिकी तथा औषध में पहली डिगरी तक के लिए 200 रु० प्रति मास + 300 रु० प्रति वर्ष पुस्तक अनुदान।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति पाने वाले स्नातक-पूर्व और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए परिषद् ने ग्रीष्म-स्कूलों और ग्रीष्म-नियोजन-कार्यक्रमों की व्यवस्था देश के 27 विभिन्न स्थानों में मई और जून 1980 के दौरान की। इन कार्यक्रमों में 379 छात्रवृत्ति पाने वालों ने भाग लिया।

परिषद् ने यह फ़ैसला भी किया है कि 1981 की परीक्षाओं से, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए 50 अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जाएगी।

राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में अध्ययन

परिषद् में इस कार्यक्रम के अनेक अध्ययन किए जा रहे हैं। इनमें से महत्वपूर्ण अध्ययन हैं—1977 की परीक्षा के परीक्षण-प्राप्तांकों और मदों का विश्लेषण एवं 1978 की कक्षा XI व XII की परीक्षाओं का विश्लेषण। इन अध्ययनों के अंतर्गत किए गए मुख्य कार्य को नीचे दिया जा रहा है :

1977 की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के परीक्षण-प्राप्तांकों और मदों का विश्लेषण

इसका मुख्य उद्देश्य था—कक्षा X के लिए राष्ट्रीय प्रतिभा छात्रवृत्तियों के परीक्षार्थियों की 1977 में हुई परीक्षा के परीक्षण-प्राप्तांकों और मदों के विश्लेषण द्वारा प्राप्त परिणामों को प्रस्तुत करना। परीक्षा के तीन भाग थे—भाग I : सामान्य बौद्धिक क्षमता परीक्षण (100 अंक); भाग II : स्कालैस्टिक ऐप्टीच्यूड परीक्षण (100 अंक); और भाग III : इंटर्व्यू (50 अंक)।

भाग I में नॉन वर्बल सिम्बलिक और न्यूमरिकल रीज़निंग, एनालिसिस, ऐप्लीकेशन आदि के 90 मल्टीपुल चॉयस आइटम्स थे। भाग II में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिकी, रसायन-विज्ञान, जीवविज्ञान और गणित के 100 मल्टीपुल चॉयस आइटम्स थे। दोनों भागों को तीन घंटे के संश्लिष्ट परीक्षण के रूप में रखा गया था। जून, 1977 में, सारे भारत में फैले 340 केन्द्रों में, 15 भाषाओं में, 28,955 छात्रों ने यह परीक्षा दी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर, 1458 छात्रों को इंटर्व्यू के लिए चुना गया। चुने गए हर छात्र को देश के सात विभिन्न स्थानों की ग्यारह चयन समितियों में से किसी एक के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ा।

जून 1977 में लिखित परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों में से हर दसवें परीक्षार्थी को नमूने के लिए लिया गया। इस प्रकार इस बेतरतीब नमूने में 10% छात्र आ गए। चूंकि परीक्षार्थियों के प्राप्तांक मैग्नेटिक टेप पर केन्द्र क्रम से लिखे गए थे, इसलिए इस नमूने में हर केन्द्र का प्रतिनिधित्व हो गया। इस प्रकार लिए गए नमूनों की संख्या 2896 थी।

मद-विश्लेषण के बाद, जी० एम० ए० परीक्षण के नब्बे मदों को, मदों की प्रकृति के अनुसार, पन्द्रह विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर दिया गया। इस अध्ययन के विस्तृत परिणाम, रा० शै० अ० और प्र० प० के अनुसंधान-प्रबंध 'स्टडीज़ ऑन नेशनल टैलेंट सर्च' में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अंग्रेज़ी में जो अनुसंधान-प्रबंध प्रकाशित किया है (राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के अध्ययन) उसमें प्रतिभा के सैद्धांतिक और शोधपरक अध्ययन दिए गए हैं।

कक्षा X, XI और XII की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (1978) का विश्लेषण : पृष्ठभूमि के अध्ययन

सन् 1978 की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षाओं में बैठने वाले तीन वर्गों के परीक्षार्थियों (क्रमशः कक्षा X, XI और XII के) की पृष्ठभूमि के तीन अध्ययन किए गए। हर अध्ययन के निष्कर्ष नीचे दिए जा रहे हैं :

(क) **राज्य क्रम से वितरण** : राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति के लिए कक्षा X की परीक्षा में बैठने वाले अधिकांश परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के थे। कक्षा XI के अधिकांश परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात के थे। हर राज्य से परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, छात्रवृत्ति पाने वालों की कक्षा X में सबसे अधिक संख्या पश्चिम बंगाल की थी। इसके बाद उड़ीसा, दिल्ली और चंडीगढ़ का नम्बर आता है। कक्षा XI के मामले में, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का क्रम बनता है। कक्षा XII की छात्रवृत्तियों में सबसे अधिक संख्या महाराष्ट्र की थी। इसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात के राज्य आते हैं। लेकिन चुने गए वर्ग की दृष्टि से, कक्षा X के अधिकांश परीक्षार्थी दिल्ली के थे। इसके बाद पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का नम्बर आता है। कक्षा XI के मामले में यह क्रम इस प्रकार बनता है—राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और पंजाब। कक्षा XII के सिलसिले में—महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का क्रम बनता है।

(ख) **शहरी-देहाती पृष्ठभूमि** : तीनों कक्षाओं में, आवेदन करने वाले अधिकतर शहरी छात्र थे। जिनको असफलता मिली उनमें अधिकतर देहात के छात्र थे। तीनों कक्षाओं में, इंटर्व्यू में शहर के छात्रों ने बेहतर किया। चुने गये वर्ग में, तीनों ही कक्षाओं में 91% प्रत्याशी शहरी इलाकों के थे।

(ग) **पुरुष-महिला प्रत्याशी** : तीनों कक्षाओं में आवेदनकर्ताओं में अधिकतर पुरुष वर्ग के थे (तीन चौथाई से भी अधिक)। असफलता की दर पुरुष वर्ग के लिए कक्षा XI और XII में अधिक थी जबकि कक्षा X में यह महिला वर्ग के लिए अधिक थी। इंटर्व्यू में, कक्षा X और XII में पुरुष वर्ग ने बेहतर कर दिखाया लेकिन XI में लड़कियों ने बेहतर प्रदर्शन किया। तीनों ही कक्षाओं में, अंतिम चयन में पुरुष छात्रों ने अधिकतर जगहें ले लीं।

(घ) **जाति की पृष्ठभूमि** : तीनों ही कक्षाओं में, आवेदनकर्ताओं में अधिकतर 'सवर्ण वर्ग' के थे, अर्थात् अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग के कम थे। असफल होने वालों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के ही छात्र अधिक थे। इंटर्व्यू में 'सवर्णों' ने निश्चय ही अन्य वर्णों के मुकाबले कहीं बेहतर कर दिखाया। चुने गए

वर्गों में भी 'सवर्ण' लोगों ने ही अधिकांश वृत्तियाँ पाईं।

(ङ) **किन संस्थाओं से पढ़ कर आए** : कक्षा XI के सिलसिले में, अधिकांश आवेदनकर्ता सरकारी स्कूलों के थे। लेकिन कक्षा X और XII के लिए, रा० प्र० खो० परीक्षा में बैठने वाले अधिकांश प्रत्याशी क्रमशः प्राइवेट स्कूलों और कालेजों के थे। तीनों ही परीक्षाओं में, असफल रह जाने वाले छात्रों का अधिकांश सरकारी स्कूलों और कालेजों में पढ़ने वालों का था। तीनों ही कक्षाओं में, चुने गए छात्रों का काफ़ी बड़ा भाग प्राइवेट संस्थानों से आया था।

(च) **शिक्षण का माध्यम और परीक्षा में उत्तर देने का माध्यम** : जिन लोगों की पढ़ाई अंग्रेज़ी भाषा के माध्यम से होती आई है और जिन्होंने इन परीक्षाओं में अंग्रेज़ी में उत्तर दिए, वे उन लोगों के मुकाबले जिनकी पढ़ाई किसी अन्य भाषा में होती है या जो परीक्षाओं में अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा का प्रयोग करते हैं, लाभ में रहे। यह बात तीनों ही कक्षाओं के बारे में लागू होती है। राज्य क्रम का विश्लेषण भी यही बताता है।

(छ) **परिवार की शैक्षिक पृष्ठभूमि** : जो लोग असफल हुए उनके परिवारों की पढ़ाई का स्तर, उन लोगों के मुकाबले जो इंटर्व्यू में बुलाए गए पर सफल न हो सके, नीचा था। तीनों ही कक्षाओं में, जो लोग चुने गए उनके परिवारों की पढ़ाई का स्तर कमोबेश ऊँचा ही था।

(ज) **औसत आय** : चुने गए छात्रों के पिता/अभिभावक की औसत आय अच्छी खासी थी, जबकि उनके मुकाबले असफल हुए छात्रों और इंटर्व्यू तक पहुँच कर असफल होने वाले छात्रों के पिता/अभिभावक की औसत आय कहीं कम थी। लेकिन ग्रुप बी के छात्रों के पिता/अभिभावक की औसत आय ग्रुप सी के मुकाबले ज़्यादा थी।

(झ) **व्यावसायिक स्थिति** : तीनों ही परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वालों में अधिकतर ऐसे छात्र थे जिनके पिता/अभिभावक लिपिक वर्ग के धन्धों में लगे हुए थे। तीनों ही परीक्षाओं में असफल हुए छात्रों के पिता/अभिभावक अधिकतर कृषि तथा सम्बद्ध व्यवसायों के थे। इंटर्व्यू में बुलाए गए छात्रों में, अधिकांश के पिता/अभिभावक व्यावसायिक, प्रशासनिक और तकनीकी नौकरियों वाले थे। चुने गए वर्गों के अधिकांश छात्रों के पिता/अभिभावक व्यावसायिक, तकनीकी और प्रशासनिक प्रकार की नौकरियों वाले थे।

इस प्रकार के अधिकांश निष्कर्ष, कमोबेश, पहले किए गए अध्ययनों के निष्कर्षों से मिलते-जुलते थे। पहले के अध्ययन 1976 और 1977 की परीक्षाओं के सिलसिले में किए गए थे।

ग्रामीण प्रतिभा खोज योजना का मूल्यांकन

कुछ वर्षों पहले शिक्षा मंत्रालय ने ग्रामीण प्रतिभा खोज की योजना शुरू की थी।

रा० शै० अ० और प्र० प० ने इस योजना के मूल्यांकन का काम शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य काफ़ी छोटी उम्र की प्रतिभाओं (कक्षा V के स्तर पर) की खोज करना है। एक औपचारिक परीक्षा के माध्यम से हर कम्यूनिटी डेवेलपमेंट ब्लॉक से दो छात्रों को चुने जाने की व्यवस्था है। चुने गए छात्रों को, यदि वे घर पर रह कर ही पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं, 500 रु० प्रति वर्ष दिए जाते हैं। किन्तु यदि वे छात्रावास में रह कर पढ़ना चाहते हैं, तो 1000 रु० प्रति वर्ष दिए जाते हैं।

यह योजना काफ़ी दिनों से लोकप्रिय रही है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय ने यह फ़ैसला किया है कि इसके विविध पक्षों का मूल्यांकन करवाया जाए। मूल्यांकन करने का काम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् को सौंपा गया है। परिषद् ने मूल्यांकन का काम चारों क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के जिम्मे डाल दिया है जिससे कि अधिक से अधिक राज्यों से आधार-सामग्री प्राप्त की जा सके। इस सिलसिले में प्रश्नावलियाँ तैयार कर ली गई हैं और उन्हें अंतिम रूप दे दिया गया है। कुछ राज्यों में तो आधार-सामग्री संकलित करने का काम शुरू भी कर दिया गया है।

15

अंतर्राष्ट्रीय सहायता और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने के नाते परिषद् यूनेस्को और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखती है। स्कूल स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए प्रयास करते हुए, इसने यूनिसेफ़ और यू० एन० एफ० पी० ए० जैसे अंतर्राष्ट्रीय माध्यमों से सहायता प्राप्त की है। स्कूल शिक्षा में, सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के लिए यह उल्लेखनीय माध्यम है। इस प्रकार के तथा इससे मिलते जुलते कार्यक्रमों के संक्षिप्त ब्यौरे आगे दिए जा रहे हैं :

यूनेस्को/एपीड

यूनेस्को के कार्यकलाप में परिषद् दो प्रकार से हिस्सा लेती रही है—यूनेस्को के कार्यक्रमों में सीधे भाग लेकर और यूनेस्को के कार्यों में एपीड (विकास के लिए शैक्षिक नवाचार का एशियाई कार्यक्रम) के माध्यम से भाग लेकर। यूनेस्को के कार्यकलाप में सीधे भाग लेने में शामिल हैं—विविध अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठियों, कार्यगोष्ठियों, विचारगोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए परिषद् के कर्मचारियों को भेजना और शिक्षा के विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण के लिए विदेशी नागरिकों को यहाँ बुलाना। इस प्रकार की प्रतिभागिता के ब्यौरे नीचे दिए जा रहे हैं :

—विकास-प्रक्रियाओं में बच्चों की भूमिका और परिवर्तनशील स्थितियों के लक्षणों के सविस्तार प्रतिपादन और उपयोग की समस्याओं पर, कोरिया के सिओल में 12 से 15 मई 1980 तक हुई, विशेषज्ञों की एक सभा में भाग लेने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० के सह निदेशक डा० त्रिलोक नाथ धर गए।

—विकास के लिए शैक्षिक नवाचार के एशियाई कार्यक्रम पर योजना और कार्यक्रम अध्ययन दल की, बैङ्काक में 5 से 8 अप्रैल 1980 तक हुई, बैठक में रा० शै० अ० और प्र० प० के सह निदेशक डा० त्रिलोक नाथ धर ने भाग लिया। अध्ययन दल ने प्राथमिकता वाले उन क्षेत्रों को बताया जहाँ यूनेस्को को तीसरे चक्र में अपने प्रयास करने हैं।

—श्रीलंका के कोलम्बो में 5 से 13 अगस्त 1980 तक आयोजित आठवीं कॉमनवेल्थ एजुकेशन कांफ्रेंस में शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के रूप में, रा० शै० अ० और प्र० प० के सह निदेशक डा० त्रिलोक नाथ धर ने भाग लिया। कांफ्रेंस ने सार्वजनीन प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और उच्च शिक्षा का विकास से संबंध जैसे शिक्षा के प्राथमिकता वाले विविध क्षेत्रों पर विचार किया।

—स्त्रियों के बारे में सूचनाओं के क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना के लिए, बैङ्काक में 5 से 9 मई 1980 तक हुई सभा में भाग लेने के लिए, स्त्री-शिक्षा एकक की अध्यक्ष डा० कुमारी सरोजिनी बिसारिया को प्रतिनियुक्त किया गया। यह सभा स्त्रियों और विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के एशियाई और प्रशांत केन्द्र (यूनाइटेड नेशंस एशियन ऐंड पैसिफिक सेंटर फॉर वीमेन ऐंड डेवेलपमेंट) द्वारा आयोजित की गई थी। उसका उद्देश्य था—स्त्रियों और विकास के बारे में सूचनाओं के क्षेत्रीय तंत्र की स्थापना करना और इस तंत्र के कार्यान्वयन के निमित्त मार्गदर्शी रेखाएँ विकसित करना।

—यूनेस्को ज्वाइंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट की "बिना स्कूली पढ़ाई वाले या अधूरी स्कूली पढ़ाई वाले बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए" बैङ्काक में

31 जुलाई से 9 अगस्त 1980 तक हुई बैठक में सहायक समन्वयक श्री० ए० ए० सी० लाल, भुवनेश्वर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के रीडर डा० जे० एन० वाजपेयी और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय के डा० के० डी० शर्मा ने भाग लिया ।

—एशिया में जीवविज्ञान शिक्षा की समीक्षा के लिए फिलीपाइंस के मनीला में 18 से 23 अगस्त 1980 तक हुई यूनेस्को की क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए परिषद् ने विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग के रीडर डा० अरुण कुमार मिश्र को प्रतिनियुक्त किया ।

—अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के प्रिंसिपल प्रो० राजेन्द्रपाल सिंह को अमरीका के छह सप्ताह के अध्ययन-भ्रमण पर प्रतिनियुक्त किया गया । यह भ्रमण मार्च 1980 के मध्य से शुरू हुआ और इसे नई दिल्ली के यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशनल फाउंडेशन्स इन इंडिया ने आयोजित किया था । प्रो० सिंह इंटर कालेजों के प्रिंसिपलों के एक दल के सदस्य के रूप में समाज और महाविद्यालय की अंतर-क्रिया; मूल्यांकन और अध्यापक-मूल्यांकन; तथा शैक्षणिक कर्मचारियों के सुधार के कार्यक्रमों का अध्ययन करने गए थे ।

—फिनलैंड में हुई इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द एवैलुएशन ऑफ एजुकेशनल एचीवमेंट (आइ० ई० ए०) की जनरल एसेम्बली की सभा में एरिक के सदस्य सचिव प्रो० चौधुरी हेमकांत मिश्र को भेजा गया । उन्होंने नीदरलैंड्स में हुई आइ० ई० ए० क्लासरूम एनवाइरनमेंट प्रोजेक्ट मीटिंग में भी 18 से 24 अगस्त 1980 तक भाग लिया ।

—सिडनी के इंटरनेशनल ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट द्वारा 10 सितंबर से 3 दिसंबर 1980 तक आयोजित शैक्षिक संसाधनों के विकास और उत्पादन में प्रशिक्षण के लिए, कोलम्बो योजना के अंतर्गत, शिक्षण-साधन विभाग के लेक्चरर श्री० ए० बी० मनकापुरी को आस्ट्रेलिया भेजा गया ।

—बैङ्काक में 18 अगस्त से 5 सितंबर 1980 तक हुए, जनसंख्या-शिक्षा के उपक्षेत्रीय दल प्रशिक्षण कोर्सों में भाग लेने के लिए जनसंख्या-शिक्षा एकक के जूनियर प्रोजेक्ट एसोशिएट श्री के० एस० चाको को प्रतिनियुक्त किया गया ।

—टोकियो में 30 सितंबर से 31 अक्टूबर 1980 तक हुए एशिया में पुस्तक प्रकाशन के तेरहवें प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने के लिए प्रकाशन विभाग के उर्दू-सम्पादक श्री मुज्तबा हुसैन को प्रतिनियुक्त किया गया । इस कोर्स का आयोजन एशियन कल्चरल सेंटर फॉर यूनेस्को ने यूनेस्को की सहायता और जैपनीज़ नेशनल कमीशन फॉर कोआपरेशन विद यूनेस्को के सहयोग से जापान के पुस्तक प्रकाशक संघ के साथ किया था ।

—22 से 29 सितंबर 1980 तक एशिया और ओसनिया में परिवेश शिक्षा पर हुई यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के लिए विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग के रीडर डा० ब्रजेशदत्त आत्रेय को प्रतिनियुक्त किया गया।

—टोकियो में 16 से 25 अक्तूबर 1980 तक जैपनीज़ नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर आयोजित दूसरे एशियाई परिसंवाद में भाग लेने के लिए शिक्षण साधन विभाग के रीडर श्री तिलकराज को परिषद् ने प्रतिनियुक्त किया।

—प्राथमिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण के लिए समुचित साधनों के विकास पर हुई तीसरी क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी में भाग लेने के निमित्त मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय में भौतिकी के रीडर श्री एस० एन० दत्त को प्रतिनियुक्त किया गया। यह कार्यगोष्ठी टोकियो में 14 अक्तूबर से 8 नवम्बर 1980 तक हुई थी। इसे एसीड (एशियन सेंटर फॉर एजुकेशनल इनोवेशंस फॉर डेवेलपमेंट) के सहयोग से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान संस्थान ने आयोजित किया था।

—प्राइमरी और इंटरमीडिएट शिक्षा में नीति-निर्माताओं और अंग्रेजी भाषी विशेषज्ञों के लिए, यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इन्फॉर्मेशन द्वारा नई दिल्ली में 3 से 21 नवम्बर 1980 तक आयोजित शिक्षकों के बीसवें वार्षिक फ़ेलोशिप कार्यक्रम के परिसंवाद में प्रो० आर० सी० दास ने भाग लिया। परिसंवाद का उद्देश्य था—सदस्य राज्यों के अध्यापक-प्रशिक्षण संस्थानों और स्कूलों में यूनाइटेड नेशंस के उद्देश्यों और कार्यकलापों के बारे में शिक्षा की प्रभावशीलता को बढ़ाना।

—बहुल वर्गों और सुविधावंचित समूहों की समस्याओं के संदर्भ में शिक्षण की नव परिवर्तन वाली विधियों के विकास और मूल्यांकन पर एपीड अध्ययन दल की बैठक में 17 से 26 नवम्बर 1980 तक भाग लेने के लिए जनजातीय शिक्षा एकक के अध्यक्ष डा० एल० आर० एन० श्रीवास्तव को इंडोनेशिया भेजा गया।

—प्राथमिक स्कूल विज्ञान शिक्षा पर विशेषज्ञों की क्षेत्रीय सभा में 4 से 10 नवंबर 1980 तक भाग लेने के लिए विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग के प्रो० ए० एन० बोस को कोरिया के सिओल भेजा गया।

—शैक्षिक प्रसारणों पर एपीड की राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी नई दिल्ली में 1 से 6 दिसंबर 1980 तक हुई। इसमें इन लोगों ने भाग लिया : अजमेर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के लेक्चरर डा० वी० जी० गुप्ते, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र की रीडर डा० श्रीमती सुमित्रा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के रीडर श्री आर० आर० शर्मा।

—एशिया और ओसनिया में मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और शान्ति के लिए शिक्षा में सामाजिक अध्ययन की भूमिका पर विशेषज्ञों की यूनेस्को क्षेत्रीय सभा में भाग लेने के लिए, सामाजिक विज्ञान और मानविकी शिक्षा विभाग के रीडर डा० गोविंदलाल आढ्या को प्रतिनियुक्त किया गया। यह सभा बैंङ्काक में 16 से 22 दिसंबर 1980 तक हुई।

—श्रीलंका के कोलम्बो में, दक्षिण एशिया सहकारी परिवेशीय कार्यक्रम चलाने की उच्च स्तरीय बैठक में शिक्षा के व्यावसायीकरण के एकक के प्रभारी प्रोफ़ेसर डा० अरुणकुमार मिश्र ने भाग लिया।

—फिलीपाइंस में सेवाकालीन प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा की प्रारंभिक नियोजन बैठक में भाग लेने के लिए मापन और मूल्यांकन विभाग के लेक्चरर श्री डी० एन० अब्रोल को प्रतिनियुक्त किया गया। यह बैठक 18 से 27 अगस्त 1980 तक हुई। बैंङ्काक में 22 से 29 जनवरी 1981 तक हुई, सेवाकालीन प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा की संयुक्त नव परिवर्तन वाली परियोजना की अंतरिम समीक्षा सभा में भी उन्होंने भाग लिया।

—प्राथमिक-शिक्षा-पाठ्यक्रम में विषय क्षेत्रों के एकीकरण की संयुक्त नव परिवर्तन वाली परियोजना में, जो सिओल में 30 अक्तूबर से 8 नवम्बर 1980 तक हुई, पी० सी० डी० सी० की अध्यक्षा प्रोफ़ेसर श्रीमती आदर्श खन्ना ने भाग लिया।

यूनेस्को द्वारा पोषित कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ साथ, परिषद् के अधिकारियों ने ऐसी गोष्ठियों और कार्यगोष्ठियों में भी भाग लिया जो अन्य माध्यमों के तत्वावधान में हुईं। उनका ब्यौरा आगे दिया जा रहा है—

एपीड के सहयोगी केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने नीचे लिखे कार्यक्रम भी किए—

—जनसंख्या-शिक्षा में दो राष्ट्रीय कार्यगोष्ठियाँ-सह-प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए। एक तो श्रीनगर में 7 से 14 जुलाई 1980 तक, और दूसरा 16 से 23 जुलाई 1980 तक पुणे में। कार्यगोष्ठी में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिभागी आए। जुलाई-अगस्त 1979 में हुई जनसंख्या-शिक्षा में क्षेत्रीय अंतर-देशीय सचल प्रशिक्षण कार्यगोष्ठी के अनुवर्ती कार्य के रूप में यह कार्यगोष्ठी आयोजित की गई थी।

—विज्ञान को ज़िन्दगी की सचाइयों, ग्रामीण परिवेश और सस्ती विज्ञान-सामग्री से जोड़ कर अभिनव वैज्ञानिक अनुभव प्रदान कराने के लिए, नई दिल्ली में 16 से 29 जुलाई 1980 तक एक राष्ट्रीय कार्यगोष्ठी की गई।

—स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा में पाठ्यक्रम बनाने के लिए, एक तकनीकी कार्य-

कारी दल की बैठक नई दिल्ली में 15 से 24 सितंबर 1980 तक की गई जिस में अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, फिलीपाइंस, बाङ्ला देश, भारत मलयेशिया और श्रीलंका के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए ।

यूनेस्को के क्षेत्रीय / अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी परिषद् ने भाग लिया—

—ज्वाइंट इनोवेटिव प्रोजेक्ट की 'विना स्कूली पढ़ाई वाले या अधूरी स्कूली पढ़ाई वाले बच्चों की शैक्षिक ज़रूरतें पूरी करने के लिए', बैङ्काक में 31 जुलाई से 9 अगस्त 1980 तक हुई बैठक ।

—एशिया में जीवविज्ञान-शिक्षा की समीक्षा के लिए, मनीला में 18 से 23 अगस्त 1980 तक हुई क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी ।

—जनसंख्या-शिक्षा में उप क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जो बैङ्काक में 18 अगस्त से 5 सितंबर 1980 तक हुआ ।

—परिवेश शिक्षा में क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी जो बैंङ्काक में 22 से 29 सितंबर 1980 तक हुई ।

—प्राथमिक स्तर पर विज्ञान-शिक्षण के लिए समुचित साधनों के विकास पर टोकियो में 14 अक्तूबर से 8 नवम्बर 1980 तक आयोजित तीसरी क्षेत्रीय कार्यगोष्ठी ।

—बहुल वर्गों और सुविधा वंचित समूहों की समस्याओं के संदर्भ में शिक्षण की नव परिवर्तन वाली विधियों के विकास और मूल्यांकन पर अध्ययन दल की बैठक जो इंडोनेशिया में 17 से 26 नवंबर 1980 तक हुई ।

—शैक्षिक प्रौद्योगिकी पर टोकियो में 16 से 25 अक्तूबर 1980 तक हुआ दूसरा एशियाई परिसंवाद ।

—प्राथमिक स्कूल विज्ञान शिक्षा पर, सिओल (कोरिया) में 4 से 10 नवम्बर 1980 तक हुई विशेवज्ञों की क्षेत्रीय सभा ।

—मानव अधिकारों के प्रति सम्मान और शान्ति के लिए शिक्षा में सामाजिक अध्ययन की भूमिका पर बैङ्काक में 16 से 22 दिसंबर 1980 तक हुई क्षेत्रीय सभा ।

नीचे लिखी केस स्टडीज़ शुरू करने के लिए परिषद् ने यूनेस्को के साथ अनुबंध किए—

—भारत में सस्ती/उचित शैक्षिक सामग्री और उपकरणों की केस स्टडी ।

—भारत में परिवेश शिक्षा की मार्गदर्शी परियोजना—माड्यूलों का प्रायोगिक कार्यान्वयन ।

—भारत में शैक्षिक नव परिवर्तनों वाली राष्ट्रीय गतिविधियाँ ।

—सदस्य राज्यों की ज़रूरतों की विविधता और परिवर्तनशील समाज में विज्ञान और शिल्पविज्ञान को अपनाने से उठने वाली समस्याओं की समीक्षा ।

—प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में विषय क्षेत्रों के एकीकरण की नव परिवर्तनों वाली संयुक्त परियोजना ।

—सेवाकालीन प्राथमिक अध्यापक-शिक्षा (द्वितीय चरण) की नव परिवर्तनों वाली संयुक्त परियोजना ।

द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

भारत सरकार विभिन्न विदेशों के साथ द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के जो करार करती है, उनको कार्यान्वित करने वाले माध्यमों में परिषद् भी एक है । विदेशों के साथ विचारों के आदान-प्रदान के लिए परिषद् अपने शिष्टमंडलों को वहाँ भेज कर शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन करवाती है और विकासशील देशों के कार्मिकों को यहाँ बुलाकर उनके प्रशिक्षण का प्रबंध करवाती है ।

इसके अलावा परिषद् शैक्षिक सामग्री (पाठ्यपुस्तकें, पूरक पठन सामग्री, अनुसंधान-प्रबंध) और फ़िल्मों व फ़िल्म स्ट्रिपों का आदान-प्रदान करती रही है ।

परिषद् के जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर विदेशी कार्यक्रमों में गए और विदेशी अतिथि जो यहाँ के कार्यक्रमों में आए, उनका ब्यौरा आगे दिया जा रहा है :

---भारत मेक्सिकन सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, जनजातीय शिक्षा और भाषा-विकास के कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए 16 से 31 अगस्त 1980 तक भारत की यात्रा पर प्रो० एस० हरनैंडीज़ आए जो मेक्सिको के नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इंडीजीनस पीपुल के शैक्षिक कार्यकलाप विभाग के अध्यक्ष हैं । जनजातीय शिक्षा के उनके कार्यक्रम की व्यवस्था मैसूर के सी० आइ० आइ० एल० के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० ने की थी ।

—इतिहास और भूगोल पढ़ाने की शिक्षण-सामग्री के उत्पादन और उपयोग के कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए सीरिया के शिक्षाशास्त्री श्री बाल्दीम कमाल अल कीरा 5 मई से 1 जून 1980 तक भारत की यात्रा पर आए ।

—स्कूली शिक्षा के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए रूस का एक प्रतिनिधि-मंडल भारत आया जिसमें ये लोग थे—श्री वी० एन० शतेव (चीफ़ ओर्लोव डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एजुकेशन), श्री सी० पी० रायबोव (डीन, डिपार्ट-

मेंट ऑफ़ इंटरप्रेटर्स, गोर्की पेडागाजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ़ फ़ॉरेन लैंग्वेजेज़) और श्री अला तैमरिन (विज्ञान प्रत्याशी, पेडागाजिकल इंस्टीच्यूट ऑफ़ मॉस्को)।

—भारत की शिक्षा प्रणाली का अध्ययन करने के लिए, इजिप्ट के शिक्षा संस्थान मंत्रालय के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष डा० मोहम्मद अब्देल फत्ता यासीन हिन्दी 20 जनवरी से 3 फरवरी 1981 तक भारत-यात्रा पर आए।

—भारत में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की संरचना को समझने के लिए, मारीशस के महात्मा गांधी संस्थान के माध्यमिक स्कूल के रेक्टर श्री प्रेम आर० हरीनाग 16 मार्च 1981 को छह सप्ताहों की यात्रा पर भारत आए। परिषद् के अलावा वे दिल्ली के और दिल्ली के बाहर के अनेक शैक्षिक संस्थानों को देखने गए।

—विज्ञान और गणित शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए परिषद् ने मैसूर के क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के रीडर डा० ए० सी० बनर्जी और व्यावसायिक शिक्षा एकक के रीडर श्री चंद्रकांत मिश्र को दो सप्ताहों के लिए 2 नवम्बर 1980 को डी० पी० आर० के० की यात्रा पर भेजा।

राष्ट्रीय विकास दल

विकास के लिए शैक्षिक नवाचार के एशियाई केन्द्र (एपीड) के राष्ट्रीय विकास दल के सचिवालय के रूप में भी परिषद् कार्य करती है। सचिवालय के कार्यों में बहुत सी और बातों के अलावा ये शामिल हैं—शिक्षा निदेशकों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों, राज्य शिक्षा संस्थानों, तथा एपीड के दूसरे सम्बद्ध केन्द्रों से सम्पर्क बनाए रखना, सूचना और प्रलेखन सेवाएँ उपलब्ध कराना, मूल्यांकन-कार्यक्रम का विकास और नवाचार के भारतीय कार्यक्रमों का संस्थापन।

नई दिल्ली में 19 मार्च 1981 को राष्ट्रीय विकास दल की एक बैठक एपीड के दूसरे चक्र के मूल्यांकन की रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए और तीसरे चक्र (1982-85) के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए, की गई। सन् 1978-80 के दौरान सहयोगी केन्द्रों द्वारा अपनाई गई नव परिवर्तन वाली मुख्य विधियों और ऐसी विधियों को बढ़ावा देने वाले तरीकों के लिए आए सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। पहले ढूँढ़े गए नौ समस्या-क्षेत्रों पर भी विचार किया गया और सुझावों को मान लिया गया। बैठक में उस निकष को भी बना लिया गया जिस पर कस कर एपीड की गतिविधियों में लगे हुए अन्य संस्थानों को चुना जाएगा।

अन्य कार्यक्रम

परिषद् के शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों को समझने के लिए विदेश की

विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं से अनेक अतिथि परिषद् में आए। परिषद् में आए इन अतिथियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

—विकास-प्रशिक्षण और संचार-योजना के एशियाई एवं प्रशांतीय कार्यक्रम की प्लैनर कुमारी मल्लिका रत्नेश 16 और 17 जून 1980 को परिषद् की अतिथि रहीं।

—दृश्य-श्रव्य उपकरणों के क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने के लिए भूटान के यूनेस्को फ़ेलो श्री साङे वाङ्दी 9 जुलाई से 8 अगस्त 1980 तक परिषद् में रहे।

—बैङ्काक के श्रीनक्षरिङ् विराट विश्वविद्यालय के शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डा० प्रुआङ् कुमुत 7 अगस्त 1980 को रा० शै० अ० और प्र० प० में आए।

—थाइलैंड के शिक्षा मंत्रालय के कर्मियों और स्कूल प्रिंसिपलों के बारह सदस्यीय दल ने 23 अगस्त से 5 सितम्बर 1980 तक राष्ट्रीय परिषद् के कार्यकलाप देखे समझे।

—कीनिया सरकार के उच्च शिक्षा के मंत्री, माननीय जे० जे० कमोठो 16 अगस्त 1980 को परिषद् में आए।

—जर्मन नेशनल कमीशन फॉर यूनेस्को के महा सचिव डा० हैंस मिनेल सपत्नीक परिषद् में 14 अगस्त 1980 को आए।

—अमरीका के पेम्ब्रीक स्टेट विश्वविद्यालय के सोलह शिक्षक 14 अगस्त 1980 को परिषद् में आए।

—घाना के शिक्षा, खेल और संस्कृति मंत्री माननीय डा० क्वानेना ओसरान 19 अगस्त 1980 को परिषद् में आए।

—एशियाई विकास बैंक के शिक्षा विशेषज्ञ श्री डब्ल्यू० वेब परिषद् की कार्य प्रणाली से परिचित होने के लिए 29 अगस्त 1980 को परिषद् में आए।

—अध्यापक-शिक्षा के संगठन और प्रशासन में, भूटान के साम्ची के अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल श्री चन्द्रकाल गुरुंग ने 18 अगस्त से 3 सितम्बर 1980 तक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

—यूनेस्को फ़ेलोशिप के अंतर्गत, शैक्षिक उपकरण संरचना के क्षेत्र में, छह महीने का प्रशिक्षण वियतनाम के शिक्षा मंत्रालय के टेक्नीशियन श्री त्रिन्ह वान ज़वान को रा० शै० अ० और प्र० प० में 21 अगस्त 1980 से दिया गया।

—प्रौढ़ शिक्षा के पाँच विशेषज्ञ फिलीपाइंस से 6 सितम्बर 1980 को रा० शै० अ० और प्र० प० देखने के लिए आए।

—रा० शै० अ० और प्र० प० तथा अफ़गानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग से क्या किया जा सकता है, यह पता लगाने के लिए अफ़गानिस्तान के शिक्षा मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा विभाग के अध्यक्ष श्री अब्दुल बदूद वफ़ामल परिषद् में पहली से आठ अक्तूबर 1980 तक रहे।

—यूनेस्को कार्यक्रम के अंतर्गत व्यावसायिक विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अध्ययन करने के लिए बैङ्काक के आइ० पी० एस० टी० के चार सदस्य अध्ययन-भ्रमण के लिए राष्ट्रीय परिषद् में एक से आठ अक्तूबर 1980 तक रहे।

—भारत और जापान के शैक्षिक-सुधारों का तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए जापान के अध्येता श्री कज़ुइको हिरोनेका परिषद् में 22 अक्तूबर से 17 नवंबर 1980 तक रहे।

—नौ एशियाई देशों और आस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जी०डी०आर० न्यूज़ीलैंड, कैरोलीन द्वीपसमूह, और सोवियत संघ के सोलह वरिष्ठ शिक्षक, जो यूनाइटेड नेशंस फेलोशिप कार्यक्रम के प्रतिभागी थे, 11 नवम्बर 1980 को परिषद् देखने के लिए आए। इन लोगों ने परिषद् के संयुक्त निदेशक और विभागाध्यक्षों से विचार-विमर्श किए। परिषद् की बनाई सामाजिक अध्ययन की शिक्षण-सामग्री उन्हें भेंट की गई। उन लोगों को परिषद् में बनी शैक्षिक फिल्में भी दिखाई गईं।

—प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों के मूल्यांकन और साक्षरता-शिक्षण के मूल्यांकन में चार सप्ताहों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए, बाङ्ला देश की बुनियादी शिक्षा अकादमी के विशेषज्ञ श्री ए० के० मोज़ाम्मेल हक़ 1 दिसम्बर 1980 से परिषद् में रहे। इस प्रशिक्षण की व्यवस्था यूनेस्को की एपीड के विशेष तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी।

—यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति के लिए शिक्षा प्रभाग में सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पाठ्यपुस्तकों के कार्यक्रम विशेषज्ञ श्री मिखाइल कैवाशांको 11 दिसंबर 1980 को परिषद् में आए और परिषद् के सम्बद्ध विभागों के अध्यक्षों से उन्होंने विचार-विमर्श किया।

—मारीशस के महात्मा गांधी संस्थान के श्री भागीरथी गोपाल 29 दिसंबर 1980 को परिषद् में आए और द्विपक्षी सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विभिन्न विषयों के कार्यान्वयन के बारे में उन्होंने विचार-विमर्श किया।

—घाना के शिक्षा मंत्रालय की श्रीमती फ्लोरेंस ओसिओ फ्रिमपॉङ 9 जनवरी 1981 को परिषद् में आईं।

—क्यूबा के उपमंत्री श्री जॉर्ज एम० फरनैंडीज़, सांख्यिकीय समिति के निदेशक

श्री रॉल ई० हरनैंडीज़ और श्री कीरो एच० फरनैंडीज़ 23 जनवरी 1981 को परिषद् में आए और उन्होंने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत की।

—यूनेस्की फ़ेलोशिप के अंतर्गत अध्ययन-भ्रमण पर 5 जनवरी से 19 फरवरी 1981 तक परिषद् में, भूटान के साम्ची स्थित अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान के टेक्नीशियन श्री चीमी दोर्जी आए। उन्हें दृश्य-श्रव्य उपकरणों विशेषकर इलेक्ट्रानिक उपकरणों के इस्तेमाल और रखरखाव की विधियों में प्रशिक्षित किया गया।

—फीजी के सुवा स्थित दक्षिण प्रशांत विश्वविद्यालय के विज्ञान शिक्षा के लेक्चरर श्री० एस० मुरलीधर 19 फरवरी 1981 को परिषद् में आए।

—कोलंबो विश्वविद्यालय के विज्ञान और शिल्पविज्ञान विभाग के सहायक लेक्चरर श्री० डब्ल्यू० सी० करुणारत्न 26 फरवरी 1981 से दो सप्ताहों के लिए परिषद् में रहे।

—नेपाल सरकार के शिक्षा सचिव श्री परसाई के नेतृत्व में पाँच सदस्यों का एक दल 5 मार्च 1981 को परिषद् में आया। यह दल भारत में शिक्षा नीतियों के प्रतिपादन/कार्यान्वयन को समझने लिए आया था।

—किसी वरिष्ठ शिक्षाशास्त्री को थोड़े समय के लिए यहाँ बुलाने के भारत सरकार के निर्णय के अनुसार घाना के शिक्षा मंत्रालय की मुख्य सचिव श्रीमती आइ० ए० वोन्तुमी परिषद् में 13 मार्च 1981 को आईं। उन्होंने परिषद् के निदेशक, संयुक्त निदेशक और विभागों के अध्यक्षों से विचार-विमर्श किए।

अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के कहने पर रा० शै० अ०और प्र० प० ने अफ़गानिस्तान के चालीस प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के लिए 7 मार्च से 4 अप्रैल 1981 तक के लिए "प्राथमिक शिक्षा में नव परिवर्तन वाली विधियाँ" विषय पर एक महीने का अध्ययन-निरीक्षण-कोर्स आयोजित किया।

16

प्रकाशन

परिषद् का एक महत्त्वपूर्ण कार्य स्कूलों के लिए पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण-सामग्री, छात्रों की अभ्यास-पुस्तिकाओं, शिक्षक-संदर्शिकाओं/दीपिकाओं, अनुसंधान-अध्ययनों/प्रबंधों आदि का प्रकाशन है। परिषद् शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यापक श्रेणी के प्रकाशनों को छापती और वितरित करती है जिनमें पूरक पठन सामग्री, शैक्षिक सर्वेक्षणों की रिपोर्टें, खोज रिपोर्टें, सहायक पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएँ आदि भी शामिल हैं।

वर्तमान प्रकाशन

इस वर्ष के दौरान, निम्नलिखित प्रकार के साहित्य का प्रकाशन हुआ—

	पुस्तकों की संख्या
प्रथम संस्करण वाली नई पुस्तकें 32+5 (उर्दू)	37
पाठ्यपुस्तकों के पुनर्मुद्रण 109+11 (उर्दू)	120
अनौपचारिक शिक्षा की पुस्तकें	2
अन्य सरकारी माध्यमों की पाठ्यपुस्तकें/अभ्यास पुस्तिकाएँ	14
रेडियो मार्गदर्शी परियोजना की पुस्तकें	6
अनुसंधान-प्रबंध/रिपोर्टें और अन्य प्रकाशन	24
पत्र-पत्रिकाएँ (अंक गिनकर)	17
कुल	220

वितरण

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशनों के वितरण और विक्रय का कार्य केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नई दिल्ली स्थित प्रकाशन विभाग ने अपने उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र के नई दिल्ली, कलकत्ता और बम्बई के सेल्स एम्पोरियम के माध्यम से किया। दक्षिणी क्षेत्र में पुस्तकों की बिक्री और वितरण का कार्य परिषद् का प्रकाशन विभाग स्वयं ही सँभालता रहा। परिषद् की पत्र-पत्रिकाओं की बिक्री और वितरण का कार्य भी परिषद् के ही पास रहा।

स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं को सीधे आदेश पर पाठ्यपुस्तकें बेची गईं।

वर्ष के दौरान, 430 सीधे आदेश प्राप्त किए गए जो इस प्रकार थे—केन्द्रीय विद्यालय संगठन (102), अन्य स्कूल (310), सैनिक स्कूल (13), और सेंट्रल स्कूल्स (5)। अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाठ्यपुस्तकों की ज़रूरतों के तिब्बतियों के 13 आदेशों की पूर्ति भी परिषद् ने सीधे ही की।

पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना

वर्ष के दौरान परिषद् ने निम्नलिखित पुस्तक मेलों में भाग लिया और अपने प्रकाशनों की प्रदर्शनियाँ आयोजित कीं :

(i) जयपुर में हुआ दसवाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला।

(ii) नई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय बाल विज्ञान प्रदर्शनी।

(iii) जम्मू में हुई अखिल भारतीय अध्यापक शिक्षा गोष्ठी।

(iv) नई दिल्ली में आयोजित शिक्षकों का पुरस्कार-वितरण समारोह ।

(v) नई दिल्ली में हुई बाईसवीं राष्ट्रीय बाल साहित्य पुरस्कार प्रतियोगिता ।

नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने चुने हुए प्रकाशनों को भेज कर परिषद् ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लिया :

(i) बाल पुस्तक प्रदर्शनी, बोलोन (इटली) ।

(ii) भारतीय उद्योग मेला, राटर्डम (नीदरलैंड्स) ।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, मेक्सिको ।

(iv) भारतीय पुस्तक मेला, नाइजीरिया ।

(v) सिंगापुर का बारहवाँ पुस्तकोत्सव ।

(vi) फ्रैंकफुर्त का बत्तीसवाँ पुस्तक मेला (1980) ।

(vii) भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी, मलयेशिया ।

(viii) भारतीय पुस्तकों की प्रदर्शनी, मारीशस ।

(ix) इंटर्नेशनल ट्रेड बुक फ़ेयर, मेलबोर्न (आस्ट्रेलिया) ।

(x) काहिरा का तेरहवाँ अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला ।

(xi) बैङ्काक का दसवाँ राष्ट्रीय पुस्तक मेला ।

विक्रय

वर्ष के दौरान राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के प्रकाशनों की रु० 1,15,41,034.79 पैसों और अमरीकी डालर 2.20 की बिक्री हुई । इस रकम में वह रकम नहीं शामिल है जो 1-10-1980 से 31-3-1981 के मध्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग के सेल्स एम्पोरियम द्वारा परिषद् के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त हुई है ।

पत्र-पत्रिकाएँ

रा० शै० अ० और प्र० प० की प्रकाशन-गतिविधियों में पत्र-पत्रिकाओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है । ये प्राथमिक स्कूल अध्यापक से लेकर अनुसंधानकर्ताओं तक के लिए पाठ्यसामग्री जुटाती हैं । हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में एक साथ प्रकाशित होने वाली पत्रिका "प्राइमरी शिक्षक"/"प्राइमरी टीचर" अध्यापकों तथा प्रशासकों को केन्द्रीय स्तर पर तय की जाने वाली शैक्षिक नीतियों के बारे में आधिकारिक जानकारी देती है । यह उनको प्राथमिक स्तर पर हो रहे शैक्षिक विकास के क्षेत्र की नव परिवर्तन वाली धारणाओं से भी परिचित कराती है । इसका उद्देश्य कक्षा में सीधे उपयोग के लिए सार्थक एवं प्रासंगिक सामग्री देना है । त्रैमासिक "इंडियन एजुकेशनल रिव्यू" शिक्षा-अनुसंधानों के प्रचार के लिए तथा शोधकर्ताओं, विद्वानों, अध्यापकों और शिक्षा-अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने

वाले अन्य व्यक्तियों को अनुभवों के विनिमय के लिए माध्यम मुहैया करता है। "दि जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन" वर्तमान शिक्षा-दृष्टियों पर विचार-विमर्श के द्वारा शिक्षा में मौलिक तथा समीक्षात्मक वैचारिकता को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों, अध्यापक-शिक्षकों तथा शोधकर्ताओं को मंच प्रदान करता है। यह एक द्वैमासिक प्रकाशन है। "स्कूल साइंस" विज्ञान शिक्षा का एक त्रैमासिक पत्र है जो अध्यापकों तथा छात्रों को विज्ञान शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, इनकी समस्याओं, सम्भावनाओं तथा निजी अनुभवों पर विचार-विमर्श के लिए एक खुले मंच का कार्य करता है।

वर्ष के दौरान पत्र-पत्रिकाओं के निम्नलिखित अंक प्रकाशित किए गए :

1.	स्कूल साइंस	दिसम्बर 1979, मार्च 1980, मई 1980, सितम्बर 1980, और दिसम्बर 1980।
2.	इंडियन एजुकेशनल रिव्यू	अक्तूबर 1979 और जनवरी 1980।
3.	जर्नल ऑफ़ इंडियन एजुकेशन	नवम्बर 1979, जनवरी 1980, मार्च 1980, मई 1980, और जनवरी 1981।
4.	प्राइमरी टीचर	जनवरी 1980, अप्रैल 1980, जुलाई 1980।
5.	प्राइमरी शिक्षक	जनवरी 1980 और अप्रैल 1980।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों में राज्य स्तर की कई एजेंसियों ने रुचि ली है। नीचे की सारणी से पता चलेगा कि किन माध्यमों ने कापीराइट अनुमति माँगी है :

बिहार

शिक्षा आयुक्त, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।	अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की नीचे लिखी पुस्तकों को अपने लिए प्रकाशित करने की अनुमति :— 1 पाठ्यचर्या 2. प्रवेशिका-निर्देशिका 3. शिक्षक संदर्शिका 4. हम भी पढ़ेंगे 5. उठो जागो प्रवेशिका 6. उठो जागो संदर्शिका
बिहार पाठ्यपुस्तक निगम, पटना।	बाल-भारती भाग III और भाग IV के आगे लिखे पाठों को पुनर्प्रकाशित करने की अनुमति—

बाल-भारती भाग III	बाल-भारती भाग IV
1. स्वच्छता	1. हिमालय
2. रक्षा बंधन	2. पहली उड़ान
3. लालच का फल	3. जब मैं पढ़ता था
4. एक किरण	4. अश्वमेध का घोड़ा
5. नीम	5. इन्द्र धनुष
6. ईद	6. जादू का दीपक
7. बढ़े चलो	7. कबीर
8. किसान	

हरियाणा

निदेशक, हरियाणा
शिक्षा विभाग, चंडीगढ़

विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की कक्षा III से V तक की पाठ्यपुस्तकों के संक्षिप्त संस्करण निकालने की अनुमति।

पंजाब

पंजाब बोर्ड ऑफ स्कूल
एजुकेशन, साहिबज़ादा
अजीत सिंह नगर, रोपड़

'धन की खोज' पाठ को अपनी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित करने की अनुमति।

पश्चिम बंगाल

शिक्षा विभाग
पश्चिम बंगाल सरकार
राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता

बाल-भारती भाग I और भाग II को अपनाने की अनुमति।

जापान

मेसर्स तीकोकू-शोइन
कम्पनी लिमिटेड,
29, कांडा जिम्बोशो 3 चोमे
चियाडा-कुम, टोकियो

'भारत विकास की ओर' पुस्तक का तीसरा जापानी संस्करण निकालने की अनुमति।

1980-81 में परिषद् के प्रकाशन

(वि० क० अर्थ विशेष सीरीज है और पु० का पुनर्मुद्रण)

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
	(क) हिन्दी-अंग्रेजी की पाठ्यपुस्तकें और अभ्यास-पुस्तिकाएँ (कक्षा-क्रम से)		
	कक्षा I		
	पाठ्यपुस्तकें		
1.	बाल-भारती भाग I (पु०)	मार्च	1981
2.	लेट अस लर्न इंग्लिश बुक I (वि० पु०)	अप्रैल	1980
3.	लेट अस लर्न इंग्लिश बुक I (वि० पु०)	फरवरी	1981
4.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल बुक I (पु०)	मई	1980
5.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल बुक I (पु०)	मार्च	1981
	कक्षा II		
	पाठ्यपुस्तकें		
6.	बाल-भारती भाग II (पु०)	मई	1980
7.	लेट अस लर्न इंग्लिश बुक II (वि० पु०)	जुलाई	1980
8.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल बुक II (प्र० स०)	मई	1980
	अभ्यास-पुस्तिका		
9.	बर्क बुक टु लेट अस लर्न इंग्लिश बुक II (पु०)	मई	1980
	कक्षा III		
	पाठ्यपुस्तकें		
10.	बाल-भारती भाग III (पु०)	मई	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
11.	लेट अस लर्न इंग्लिश बुक III (पु०)	मई	1980
12.	लेट अस लर्न इंग्लिश बुक III (पु०)	फरवरी	1981
13.	मैथेमेटिक्स फॉर प्राइमरी स्कूल बुक III (प्र० स०)	मई	1980
14.	एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ पार्ट I (पु०)	मई	1980
15.	पर्यावरण अध्ययन भाग I (पु०)	जून	1980
16.	एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ पार्ट II (पु०)	अप्रैल	1980
17.	एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ पार्ट II (पु०)	जनवरी	1981
18.	पर्यायवरण अध्ययन भाग II (पु०)	जून	1980
	अभ्यास-पुस्तिकाएँ		
19.	बाल-भारती भाग III की अभ्यास पुस्तिका (पु०)	मई	1980
20.	वर्कबुक टु लेट अस लर्न इंग्लिश बुक III (पु०)	जून	1980
	कक्षा IV		
	पाठ्यपुस्तकें		
21.	बाल-भारती भाग IV (प्र० स०)	जुलाई	1980
22.	इंग्लिश रीडर बुक I (वि० पु०)	मार्च	1981
23.	रीड फॉर प्लेज़र बुक I (प्र० स०)	जून	1980
24.	रीड फॉर प्लेज़र बुक I (पु०)	जनवरी	1981
25.	एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ पार्ट I (प्र० स०)	जुलाई	1980
26.	पर्यावरण अध्ययन भाग I (प्र० स०)	जून	1980
27.	एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ पार्ट II (पु०)	फरवरी	1981
	अभ्यास-पुस्तिकाएँ		
28.	बाल-भारती भाग IV की अभ्यास पुस्तिका (प्र० स०)	अगस्त	1980
29.	बाल-भारती भाग IV की अभ्यास पुस्तिका (पु०)	जनवरी	1981
30.	वर्कबुक टु इंग्लिश रीडर बुक I (वि० पु०)	फरवरी	1981
	कक्षा V		
	पाठ्यपुस्तकें		
31.	स्वस्ति भाग I (प्र० स०)	अगस्त	1980
32.	रीड फॉर प्लेज़र बुक II (प्र० स०)	जून	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
33.	इनसाइट इनटू मैथेमेटिक्स बुक V (पु०)	अप्रैल	1980
34.	इंडिया ऐंड दि वर्ल्ड (पु०)	जून	1980
35.	भारत और संसार (पु०)	जून	1980
36.	लर्निंग साइंस थ्रू एनवाइरनमेंट पार्ट III (पु०)	अगस्त	1980
	अभ्यास-पुस्तिका		
37.	वर्कबुक टु इंग्लिश रीडर बुक II (वि० पु०)	दिसम्बर	1980
	कक्षा VI		
	पाठ्यपुस्तकें		
38.	भारती भाग I (पु०)	अप्रैल	1980
39.	संक्षिप्त रामायण (पु०)	मई	1980
40.	स्वस्ति भाग II (प्र० स०)	जुलाई	1980
41.	इंग्लिश रीडर बुक III (वि० पु०)	फरवरी	1981
42.	रीड फॉर प्लेज़र बुक III (प्र० स०)	जुलाई	1980
43.	रीड फॉर प्लेज़र बुक III (पु०)	जनवरी	1981
44.	मैथेमेटिक्स बुक I (पु०)	मई	1910
45.	गणित पुस्तक I (पु०)	अप्रैल	1980
46.	लैंड्स ऐंड पीपुल पार्ट I (पु०)	अप्रैल	1980
47.	देश और उनके निवासी भाग I (पु०)	मई	1980
48.	हिस्ट्री ऐंड सिविक्स पार्ट I (पु०)	मई	1980
49.	इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग I (पु०)	जुलाई	1980
50.	लर्निंग साइंस पार्ट I (पु०)	मार्च	1981
51.	आओ विज्ञान सीखें भाग I (पु०)	जून	1980
	अभ्यास-पुस्तिका		
52.	वर्कबुक टु इंग्लिश रीडर बुक III (वि० पु)	फरवरी	1981
	कक्षा VII		
	पाठ्यपुस्तकें		
53.	भारती भाग II (पु०)	अप्रैल	1980
54.	नया जीवन (प्र० स०)	अगस्त	1980
55.	संक्षिप्त महाभारत (प्र०	अगस्त	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
56.	स्वस्ति भाग III (प्र० स०)	जुलाई	1980
57.	इंग्लिश रीडर बुक IV (वि० पु०)	मार्च	1981
58.	गणित पुस्तक II भाग I (पु०)	अप्रैल	1980
59.	मैथेमेटिक्स बुक II भाग II (पु०)	मार्च	1981
60.	गणित पुस्तक II भाग II (पु०)	अप्रैल	1980
61.	गणित पुस्तक II भाग II (पु०)	मार्च	1981
62.	हिस्ट्री ऐंड सिविक्स पार्ट II (पु०)	अप्रैल	1980
63.	इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग II (पु०)	जून	1980
64.	इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग II (पु०)	जनवरी	1981
65.	लैंड्स ऐंड पीपुल पार्ट II (पु०)	अप्रैल	1980
66.	लैंड्स ऐंड पीपुल पार्ट II (पु०)	फरवरी	1981
67.	देश और उनके निवासी भाग II (पु०)	मई	1980
68.	देश और उनके निवासी भाग II (पु०)	मार्च	1981
69.	लर्निंग साइंस पार्ट II (पु०)	मई	1980
70.	आओ विज्ञान सीखें भाग II (पु०)	जून	1980

कक्षा VIII
पाठ्यपुस्तकें

71.	भारती भाग III (प्र० स०)	जून	1980
72.	त्रिविधा (प्र० स०)	अगस्त	1980
73.	स्वस्ति भाग III (प्र० स०)	जुलाई	1980
74.	इंग्लिश रीडर बुक V (वि० पु०)	मार्च	1981
75.	गणित पुस्तक III भाग I (पु०)	फरवरी	1981
76.	मैथेमेटिक्स बुक III भाग II (पु०)	अप्रैल	1980
77.	गणित पुस्तक II भाग III (प्र० स०)	जून	1980
78.	हिस्ट्री ऐंड सिविक्स पार्ट II (प्र० स०)	जुलाई	1980
79.	इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग III (प्र० स०)	जुलाई	1980
80.	लैंड्स ऐंड पीपुल पार्ट III (प्र० स०)	जून	1980
81.	देश और उनके निवासी भाग III (प्र० स०)	जून	1980
82.	लर्निंग साइंस पार्ट III (पु०)	मई	1980
83.	आओ विज्ञान सीखें भाग III (प्र० स०)	सितम्बर	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
	कक्षा IX		
	पाठ्यपुस्तकें		
84.	मैथेमेटिक्स पार्ट I (पु०)	जुलाई	1980
85.	दि स्टोरी ऑफ सिविलिज़ेशन वॉलूम I (पु०)	जुलाई	1980
86.	मैन ऐंड एनवाइरनमेंट (पु०)	मई	1980
87.	मनुष्य और वातावरण (पु०)	मई	1980
88.	विज्ञान भाग I (पु०)	अप्रैल	1980
	कक्षा X		
	पाठ्यपुस्तकें		
89.	जनरल ज्योग्राफ़ी ऑफ द वर्ल्ड पार्ट II (पु०)	अप्रैल	1980
90.	विश्व का सामान्य भूगोल भाग II (पु०)	मई	1980
91.	दि स्टोरी ऑफ सिविलिज़ेशन वॉलूम II (पु०)	जुलाई	1980
92.	सभ्यता की कहानी भाग II खंड I व II (पु०)	जुलाई	1980
93.	साइंस पार्ट II (प्र० स०)	जुलाई	1980
94.	विज्ञान भाग II (प्र० स०)	जुलाई	1980
95.	वि ऐंड अवर गवर्नमेंट (पु०)	जुलाई	1980
96.	हम और हमारा शासन (पु०)	जुलाई	1980
	कक्षा XI		
	पाठ्यपुस्तकें		
97.	हिन्दी प्रतिनिधि कहानियाँ (पु०)	मई	1980
98.	हिन्दी प्रतिनिधि एकांकी (पु०)	मई	1980
99.	गणित भाग II (प्र० स०)	जुलाई	1980
100.	भौतिक विज्ञान भाग I (प्र० स०)	जुलाई	1980
101.	केमिस्ट्री पार्ट I (पु०)	मई	1980
102.	रसायन विज्ञान भाग I (प्र० स०)	अगस्त	1980
103.	बायोलॉजी पार्ट I (पु०)	सितम्बर	1980
104.	XI-XII के लिए फ़िज़िक्स (प्र० स०)	जुलाई	1980
105.	फ़ाऊंडेशन्स ऑफ पोलिटिकल साइंस (पु०)	जून	1980
106.	पोलिटिकल सिस्टम (पु०)	जुलाई	1980
107.	राजनीतिक व्यवस्था (पु०)	जून	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
108.	फ़िज़िकल बेसिस ऑफ ज्योग्राफ़ी (पु०)	अप्रैल	1980
109.	भौतिक भूगोल के आधार (पु०)	जून	1980
110.	ज्योग्राफ़ी वर्कबुक (पु०)	मई	1980
111.	जनरल ज्योग्राफ़ी ऑफ इंडिया पार्ट I (पु०)	मई	1980
	कक्षा XI-XII		
	पाठ्यपुस्तकें		
112.	चयनिका (पु०)	अप्रैल	1980
113.	जीव विज्ञान (प्र० स०)	फरवरी	1981
114.	हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास (पु०)	अप्रैल	1980
115.	साहित्य शास्त्र परिचय	मई	1980
116.	अ कोर्स इन रिटेन इंग्लिश (पु०)	अप्रैल	1980
117.	इंग्लिश सप्लीमेंटरी रीडर पार्ट II (कोर) (पु०)	अप्रैल	1980
118.	डियर ट् ऑल दी म्यूसिस (पु०)	अप्रैल	1980
119.	मैथेमेटिक्स बुक III (पु०)	जुलाई	1980
120.	गणित भाग III (पु०)	अप्रैल	1980
121.	भौतिक विज्ञान भाग II खण्ड I (पु०)	जुलाई	1980
122.	कैमिस्ट्री पार्ट II (पु०)	मई	1980
123.	बायोलॉजी पार्ट II वॉलूम I (पु०)	अप्रैल	1980
124.	बायोलॉजी पार्ट II वॉलूम II (पु०)	जून	1980
125.	जीव विज्ञान भाग II खण्ड I (पु०)	जून	1980
126.	मेडिवल इंडिया पार्ट II (पु०)	मई	1980
127.	मॉडर्न इंडिया (पु०)	अगस्त	1980
128.	इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐंड दी गवर्नमेंट (पु०)	जून	1980
129.	भारत संविधान और शासन (पु०)	जुलाई	1980
130.	इंडियन डेमोक्रैसी ऐट वर्क (पु०)	जुलाई	1980
131.	भारत में लोकतन्त्र (पु०)	जुलाई	1980
132.	नेशनल ऐकाउंटिंग (पु०)	जुलाई	1980
133.	इन्ट्रोडक्शन टू इकोनोमिक थियोरी (पु०)	जुलाई	1980
134.	आर्थिक सिद्धांत का परिचय (पु०)	अप्रैल	1980
135.	ह्यूमन ऐंड इकोनोमिक ज्योग्राफ़ी (पु०)	जुलाई	1980
136.	ज्योग्राफ़ी ऑफ इंडिया पार्ट II (पु०)	जुलाई	1980
137.	मैथेमेटिक्स बुक V (प्र० स०)	दिसम्बर	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
138.	गणित भाग V (प्र० स०)	जनवरी	1981
	(ख) उर्दू की पाठ्यपुस्तकें		
	कक्षा III		
139.	हम और हमारा देश (पु०)	अक्तूबर	1980
140.	हम और हमारा देश (पु०)	फरवरी	1981
	कक्षा IV		
141.	माहौल के जरिए तालीम पार्ट I (प्र० स०)	मई	1980
	कक्षा VI		
142.	हिसाब (पु०)	जुलाई	1980
143.	साइंस सीखना (पु०)	अगस्त	1980
144.	तारीख और इल्मेशहरियत (पु०)	जुलाई	1980
	कक्षा VII		
145.	हिसाब बुक II पार्ट I (पु०)	मई	1980
146.	हिसाब बुक II पार्ट I (पु०)	जनवरी	1981
147.	साइंस सीखना (पु०)	मई	1980
148.	मुमालिक और उनके बाशिंदे (प्र० स०)	सितम्बर	1980
	कक्षा VIII		
149.	हिसाब बुक III पार्ट I (प्र० स०)	जून	1980
	कक्षा IX-X		
150.	तहज़ीब की कहानी वॉलूम II (प्र० स०)	सितम्बर	1980
151.	हम और हमारी हुकूमत (पु०)	अगस्त	1980
	कक्षा XI-XII		
152	हिन्दुस्तान का आम जुगराफ़िया (पु०)	अगस्त	1980
153.	हयातियात पार्ट II वॉलूम I (पु०)	फरवरी	1981
154.	हिसाब बुक IV (प्र० स०)	जून	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
	(ग) दूसरी सरकारों या एजेंसियों के लिए पाठ्यपुस्तकें		
	जम्मू व कश्मीर बोर्ड		
155.	हिसाब बुक I (कक्षा VI के लिए) (उर्दू)	नवम्बर	1980
156.	हिसाब बुक II पार्ट II (कक्षा VII के लिए) (उर्दू)	नवम्बर	1980
157.	साइंस सीखना पार्ट I (कक्षा VI के लिए) (उर्दू)	दिसम्बर	1980
158.	साइंस सीखना पार्ट II (कक्षा VII के लिए) (उर्दू)	दिसम्बर	1980
159.	माहौल के ज़रिए तालीम पार्ट I (कक्षा III के लिए) (उर्दू)	फरवरी	1981
160.	माहौल के ज़रिए तालीम पार्ट II (कक्षा IV के लिए) (उर्दू)	फरवरी	1981
161.	हिसाब बुक III पार्ट I (कक्षा VIII के लिए) (उर्दू)	फरवरी	1981
	अरुणाचल प्रदेश सरकार		
162.	अरुण भारती	नवम्बर	1980
163.	अरुण भारती भाग I की अभ्यास-पुस्तिका (कक्षा I के लिए)	दिसम्बर	1980
	फीजी सरकार		
164.	सोपान I	जून	1980
165.	मेरी दूसरी पुस्तक	सितम्बर	1980
	मध्य प्रदेश सरकार		
166.	नया जीवन	सितम्बर	1980
	पश्चिम बंगाल		
167.	काव्य-भारती	सितम्बर	1980
168.	गद्य-भारती	सितम्बर	1980
	(घ) अनौपचारिक शिक्षा की पुस्तकें		
169.	नई रोशनी प्राइमर गाइड (उर्दू)	जून	1980
170.	अमर उमा (हिन्दी)	अप्रैल	1980

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
	(ङ) रेडियो मार्गदर्शी परियोजना की पुस्तकें		
171.	पहली किरण (पु०)	जून	1980
172.	सुचित्रा (पु०)	जुलाई	1980
173.	तीसरी किरण	अगस्त	1980
174.	सुवर्णा (पु०)	जनवरी	1981
175.	चौथी किरण	जनवरी	1981
176.	दूसरी किरण (पु०)	फरवरी	1981
	(च) अनुसंधान ग्रन्थ और अन्य प्रकाशन		
177.	एन० आई० ई० गेस्ट हाउस : इनफ़ारमेशन फॉर गेस्ट्स	अप्रैल	1980
178.	फ़िज़िकल एजुकेशन-—अ ड्राफ्ट करीक्यूलम फॉर क्लासेज़ I-X	मई	1980
179.	यूजिग दि एनवाइनरमेंट ऐज़ अ बेसिस फॉर मीनिंगफुल लर्निंग इन प्राइमरी एजुकेशन	मई	1980
180.	नेशनल सर्वे फॉर पॉपुलेशन एजुकेशन इन इण्डिया	जुलाई	1980
181.	डिफरेनशियल इफेक्टिवनेस ऑफ़ माइक्रो-टीचिंग कम्पोनेंट्स	अगस्त	1980
182.	आकाश दर्शन एटलस	अक्तूबर	1980
183.	स्टडी विज़िट्स टु इनोवेशन एजुकेशन प्रोजेक्ट्स	अक्तूबर	1980
184.	नेशनल साइंस एक्ज़ीबिशन फॉर चिल्ड्रेन—1980	नवम्बर	1980
185.	स्ट्रक्चर ऐंड वर्किंग ऑफ साइंस मॉडल्स—1980	नवम्बर	1980
186.	ए डिकेड ऑफ नेशनल साइंस एक्ज़ीबिशन फॉर चिल्ड्रेन—1970-1980	नवम्बर	1980
187.	दि युनाइटेड नेशंस—ह्वाट इट डज़ ?	नवम्बर	1980
188.	फ़ोर्थ ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे	दिसम्बर	1980
189.	पॉपुलेशन एजुकेशन फॉर टीचर्स	दिसम्बर	1980
190.	एन ऐप्रोच टु एवेल्युएशन इन एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ ऐट प्राइमरी स्टेज	जनवरी	1981
191.	डाइरेक्टरी ऑफ एजुकेशनल इनोवेशंस	जनवरी	1981
192.	रेगुलेशंस ऑफ एन सी ई आर टी	जनवरी	1981
193.	केटालॉग ऑफ फिल्म्स वालूम II	जनवरी	1981

क्रम संख्या	पुस्तक	प्रकाशन का महीना,	वर्ष
194.	मैमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन ऐंड रूल्स	जनवरी	1981
195.	टीचर्स गाइड फॉर एनवाइरनमेंटल स्टडीज़ पार्ट II फॉर क्लास IV	जनवरी	1981
196.	वार्षिक रिपोर्ट 1979-1980	जनवरी	1981
197.	ऐनुअल रिपोर्ट 1979-1980	जनवरी	1981
198.	टीचर्स गाइड फॉर इंग्लिश रीडर V	फरवरी	1981
199.	थर्ड ऑल इंडिया एजुकेशनल सर्वे (लाइब्रेरी, लेबोरेटरी ऐंड साइंस इक्विपमेंट फ़ैसिलिटीज़ इन स्कूल्स)	फरवरी	1981
200.	थर्ड आल इंडिया एजुकेशनल सर्वे (संस्कृत पाठशाला ऐंड मदरसा)	मार्च	1981
201.	स्टडी ऑन नेशनल टैलेंट सर्च	मार्च	1981

17

हिन्दी प्रयोग की दिशा में

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की शब्दावली पर आधारित प्रशासकीय शब्दों की एक अंग्रेज़ी-हिन्दी शब्द-सूची को प्रकाशित कर परिषद् ने वितरित करवाया है। यह सूची 298 पृष्ठों की है और इसमें उन अंग्रेज़ी शब्दों व मुहावरों के हिन्दी समानार्थी दिए गए हैं, जिनका प्रयोग प्रशासन के सिलसिले में बहुधा किया जाता है। आशा की जाती है कि इस संकलन के आ जाने से रा० शै० अ० और प्र० प० में हिन्दी का अधिक से अधिक व्यवहार हो सकेगा।

वर्ष के दौरान हिन्दी का अधिकतम व्यवहार करने वाले विभाग को एक रनिंग शील्ड द्वारा पुरस्कृत किए जाने के लिए परिषद् ने एक पुरस्कार की व्यवस्था की है। यह शील्ड ढाई सौ रुपयों की है। रिपोर्ट-वर्ष में इसे परिषद् के शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने प्राप्त किया क्योंकि परिषद् के सभी विभागों में इस विभाग ने हिन्दी का अधिकतम प्रयोग किया।

परिषद् की 'सरकारी भाषा कार्यान्वयन समिति' की एक बैठक में गृहमंत्रालय के सरकारी भाषा विभाग के उप निदेशक आए। रा० शै० अ० और प्र० प० में हिन्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

परिषद् के "वर्ष 1979-80 के आय और भुगतान के समेकित विवरण" को हिन्दी में तैयार किया गया है। परिषद् के सभी सामान्य आदेशों को, विशेष कर चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से सम्बन्धित आदेशों को हिन्दी में जारी किया गया।

वर्ष 1980-81 के दौरान सरकारी और शैक्षणिक कामों में रा० शै० अ० और प्र० प० ने हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया है। हिन्दी-प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए वर्ष के दौरान कई काम किए गए। उनमें मुख्य हैं :

—जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है, पत्राचार हिंदी में किया जाता है। हिन्दी-भाषी प्रदेशों से पत्राचार करते समय हिन्दी में ही पत्रोत्तर दिया जाता है।

—इस वर्ष के दौरान, प्रशासकीय कार्यों के दैनंदिन मामलों में हिन्दी का प्रयोग और भी बढ़ाया गया है।

—छुट्टी के लिए या दूसरे प्रकार के आवेदन हिन्दी में करने के लिए सभी कर्मचारी स्वतंत्र हैं; इस निमित्त प्रपत्र हिन्दी में भी तैयार किए गए हैं।

—हिन्दी में लिखे पत्र स्वीकार किए जाते हैं और जहाँ तक सम्भव हो, उनका उत्तर भी हिन्दी में ही दिया जाता है।

—हिन्दी पत्रों और फाइलों से सम्बद्ध टिप्पणियाँ हिन्दी में लिखी जाती हैं।

—हिन्दी-प्रयोग की बुनियादी सुविधाओं, विशेष कर हिन्दी टंकण यंत्रों और हिन्दी आशुलिपिकों की कमी को दूर करने की कोशिश की जा रही है। रोजाना के काम हिन्दी में करने में कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं होती। अपनी विविध गतिविधियों में हिन्दी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए परिषद् बड़ी मेहनत से लगी हुई है।

—क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में नियमित कोर्सों और ग्रीष्म कोर्सों में हिन्दी माध्यम से भी पढ़ाने की व्यवस्था की गई है।

—जहाँ और जब भी आवश्यक होता है, सभाओं और कार्यगोष्ठियों में संचालन की भाषा हिन्दी ही रहती है।

—बहुत सी रिपोर्टों और पुस्तिकाओं का हिन्दी संस्करण इस वर्ष के दौरान तैयार किया गया है।

—अधिकारियों की नाम-पट्टिकाएँ हिन्दी में भी तैयार की गई हैं। कुछ रबर मोहरें भी हिन्दी में बनी हैं।

पन्द्रहवीं अखिल भारतीय हिन्दी-प्रयोग-प्रतियोगिता और अखिलभारतीय हिन्दी टंकण एवं आशुलिपि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रा० शै० अ० और प्र० प० ने अपने कर्मचारियों को कहा। शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा विभाग और केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सरकारी भाषा विभाग ने बीच बीच में हिन्दी-प्रयोग से सम्बन्धित जो भी जानकारी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से चाही, उसे संकलित कर उन लोगों को भिजवाया गया।

शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सरकारी भाषा विभाग ने जो भी परिपत्र और आदेश भेजे वे परिषद् द्वारा हिन्दी में ही जारी किए गए। परिषद् में इस्तेमाल के लिए श्योरिटी बॉण्ड्स का हिन्दी संस्करण भी तैयार किया गया।

18

आय और भुगतान

परिषद् ने 1980-81 वर्ष में भारत सरकार से अनुदान के रूप में रु० 6,18,23,654/- प्राप्त किए। इसी के साथ ही, अपने प्रकाशनों की बिक्री से परिषद् को रु० 1,34,59,855/- की, और विविध आय के रूप में रु० 61,18,011/- की प्राप्ति भी हुई जिसमें आवासीय क्वाटरों का किराया भी शामिल है। इसके अलावा सरकार द्वारा 1979-80 में दिए गए अनुदानों में बच रही रु० 40,00,346/- की रकम भी भारत सरकार की अनुमति से खर्च करने को मिल गई।

ऊपर बताई गई निधियों में से, परिषद् ने रु० 6,93,98,272/- 'गैर योजना' के अंतर्गत और रु० 1,07,56,146/- 'योजना' के अंतर्गत खर्च किए।

आय	रकम	भुगतान	रकम
अथ शेष	रु० 53,72,143/-	गैर-योजना व्यय	
शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त अनुदान		वेतन, भत्ते, कार्यक्रम तथा	रु० 6,93,98,272/-
(क) गैर योजना	रु० 4,78,23,654/-	आकस्मिक और अन्य खर्चे	
(ख) योजना	रु० 1,40,00,000/-	योजना-व्यय	
विशिष्ट योजनाओं के लिए विभिन्न		वेतन, भत्ते, कार्यक्रम तथा	रु० 1,07,56,146/-
निकायो/मंत्रालयों से प्राप्त अनुदान	रु० 55,43,230/-	अन्य खर्चे	
प्रकाशनों की बिक्री से आय	रु० 1,34,59,855/-	अन्य निकायों या मंत्रालयों द्वारा	
आवासीय क्वाटरों के भाड़े जैसी		प्रवर्तित योजनाओं पर व्यय	रु० 45,55,182/-
विविध आय	रु० 61,18,011/-	सा० भ० नि/अं० भ० नि०/	
		अ० ज० यो० के भुगतान	रु० 79,97 285/-
सा० भ० नि०/अं० भ० नि०/अ०			
ज० यो० की आय	रु० 85,36,696/-	ऋण प्रेषित, जमा, उचंत और अग्रिम	रु० 3,14,18,767/-
ऋण प्रेषित, जमा, उचंत,			
अग्रिम धन	रु० 3,17,99,655/-	अन्त शेष	रु० 85,27,592/-
कुल आय	रु० 13,26,53,244/-	कुल भुगतान	रु० 13,26,53,244/-

परिशिष्ट

परिशिष्ट-क

व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सहायता देने की योजना

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने शिक्षा और शैक्षिक नव परिवर्तनों के क्षेत्र में स्वयंसेवी प्रयासों की महत्ता को सदैव मान्यता दी है। शैक्षिक संस्थानों एवं अध्यापक-शिक्षकों के साथ राष्ट्रीय परिषद् जैसी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं का सम्पर्क देश में शैक्षिक कायाकल्प लाने में अच्छे उत्प्रेरक का सा काम करेगा। इस तथ्य को ध्यान में रखकर, रा० शै० अ० और प्र० प० व्यायसायिक शैक्षिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना चलाती आई है। योजना के उद्देश्यों और सहायता पाने की पात्रता की शर्तों को नीचे दिया जा रहा है।

उद्देश्य

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं :

—स्कूल-शिक्षा के सुधार के लिए स्वयंसेवी प्रयासों को बनाए रखना और बढ़ावा देना।

—व्यावसायिक प्रकृति की अच्छे स्तर वाली ऐसी पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देना जो शैक्षिक नव परिवर्तनों के बारे में ज्ञान-विज्ञान को प्रचारित-प्रसारित करने में सहायक हों।

—स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शिक्षा में विस्तार के कार्यों को बढ़ावा देना।

पात्रता की शर्तें

वित्तीय सहायता पाने की पात्रता की शर्तें हैं :

संगठन

(i) कोई व्यावसायिक शैक्षिक संगठन (व्या० शै० सं०) इस योजना के अंतर्गत परिषद् का अनुदान पाने का पात्र है, यदि वह—

(क) संस्था पंजीकरण धारा (1860 की धारा XXI) के अंतर्गत एक पंजीकृत संस्था है।

(ख) आज के मान्यता प्राप्त कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक न्यास है।

(ग) शैक्षिक गतिविधियों को चलाने और बढ़ावा देने के काम में लगा हुआ प्रतिष्ठित संस्थान है। किसी राज्य सरकार, या स्थानीय निकाय द्वारा बनाया गया या राज्य विधान की किसी धारा अथवा राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव के अंतर्गत स्थापित किया गया संस्थान इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता पाने का हक़दार नहीं है।

(ii) उस संगठन को स्कूल शिक्षा के सुधार के लिए सामान्यतः राष्ट्रीय या आंचलिक स्तर पर काम करना चाहिए। केवल अपवाद स्वरूप ही, यदि निधियाँ उपलब्ध हैं तो ऐसे व्या० शै० सं० के आवेदन पर विचार किया जाएगा जो राज्य स्तर पर काम कर रहे हैं।

(iii) यह योजना बिना किसी क्षेत्र, नस्ल, जाति, बिरादरी या भाषा के भेदभाव के, भारत के हर नागरिक के लिए, खुली है।

(iv) राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने के लिए जहाँ मान्यता की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ उस संगठन को मान्यता-प्राप्त होना चाहिए।

(v) उस संगठन का समुचित गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए जिसके अधिकार, कर्तव्य, उत्तरदायित्व आदि स्पष्ट रूप से परिभाषित किए गए हों और लिखित संविधान के रूप में रखे गए हों।

(vi) योजना के अंतर्गत सहायता-अनुदान के लिए आवेदन करने के पूर्व उसे कम से कम एक वर्ष तक सामान्यतः काम करता हुआ होना चाहिए।

(vii) आवेदन के दिन उसके सदस्यों की संख्या कम से कम पचास होनी चाहिए।

(viii) उसे किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लिए लाभ अर्जित करने वाला नहीं होना चाहिए।

कार्यकलाप

(i) इस योजना के अंतर्गत सामान्यतः निम्नलिखित कार्यकलाप को राष्ट्रीय परिषद् पोषित करती है :

—वार्षिक सभाएँ बशर्ते कि उनकी एक निश्चित विषय वस्तु हो जो किसी ऐसी राष्ट्रीय शैक्षिक समस्या से सम्बद्ध हो जिसके बारे में राष्ट्रीय परिषद् को चिंता हो और/या वह उसके कार्य को पोषित करे और रा० शै० अ० और प्र० प० के उद्देश्यों की पूर्ति में उपयोगी हो।

—शैक्षिक साहित्य का उत्पादन जिसमें व्यावसायिक पत्रिकाएँ शामिल हैं किंतु पाठ्य सामग्री नहीं शामिल हैं।

—ऐसी शैक्षिक प्रदर्शनियाँ जो शैक्षिक नव परिवर्तनों या अन्य प्रकार के शैक्षिक विकासों से सम्बद्ध हों।

(ii) सामान्यतः नीचे लिखी बातों पर अनुदान नहीं दिए जाते :

—ऐसी परिचर्चाएँ या कार्यगोष्ठियाँ जैसी रा० शै० अ० और प्र० प० प्रायः आयोजित कर सकती है या करती रहती है।

अनुदान की मात्रा

अनुदान पाने वाले संगठन पूरी तरह से रा० शै० अ० और प्र० प० पर ही निर्भर न हो जाएँ, इस विचार से इस योजना के अंतर्गत जो सहायता दी जाती है वह आंशिक ही होती है जैसा कि नीचे स्पष्ट किया गया है :

—किसी वर्ष में किसी कार्यकलाप पर जो खर्च आता है उसके 60% से अधिक का सहायता-अनुदान परिषद् सामान्यतः नहीं देती।

—बाकी बच रहे खर्च का 40% संगठन को दूसरे स्रोतों से जुटाना होता है जैसे कि किसी अन्य संगठन से अनुदान प्राप्त कर या पत्रिकाओं के मामले में बिक्री, वार्षिक चंदा या विज्ञापन शुल्क से जुटाकर। हाँ, यदि दूसरे स्रोतों से खर्च के 40% से अधिक की आय हो जाए, तो परिषद् अपने हिस्से का अनुदान उसी हिसाब से कम कर देगी।

—यदि किसी भी तरह, एक वर्ष में वास्तविक खर्च के 60% से अधिक का भुगतान परिषद् की ओर से हो जाए, तो अगले वर्ष के अनुदान से बढ़ी हुई रकम काट ली जाएगी या समंजित कर ली जाएगी।

आवेदन करने का तरीका

(i) आवेदन करने के लिए व्या० शै० सं० के वास्ते छपे हुए फार्म हैं जिन्हें पूरी तरह से भर कर दो प्रतियाँ भेजनी होती हैं।

(ii) हर कार्यक्रम या गतिविधि के लिए अलग-अलग आवेदन करना होता है।

(iii) हर आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ आने चाहिए :

—संस्थान/संगठन का विवरण पत्र या उसके उद्देश्यों और कार्यकलाप का संक्षिप्त विवरण ।

—संगठन का संविधान ।

—अंतिम वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति ।

—यदि आवेदन किसी पत्रिका/सामग्री के प्रकाशन अनुदान के लिए है, तो पहले के छपे प्रकाशन ।

—संगठन के पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन और उसके साथ संगठन के अध्यक्ष/सचिव और लेखा परीक्षक (चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि) द्वारा हस्ताक्षरित एक उपयोग प्रमाण पत्र ।

सामान्य

यदि अनुदान पत्रिका के प्रकाशन के लिए माँगा जाए तो ब्या० शै० सं० के लिए परिषद् का एक निःशुल्क विज्ञापन छापना अनिवार्य होगा ।

वार्षिक सभा-सम्मेलन के लिए अनुदान के मामले में, संगठन को राष्ट्रीय परिषद् के कुछ प्रतिनिधियों को सम्मेलन से सम्बद्ध करना होगा ।

संस्थान/संगठन को अनुदान से प्राप्त पूर्ण या आंशिक परिसम्पत्तियों का एक लेखा-जोखा रखना होगा, इस तरह की परिसंपत्ति को रा० शै० अ० और प्र० प० की पूर्व अनुमति के बगैर बेचा नहीं जा सकता, न ही उसे जिस उद्देश्य से अनुदान दिया गया था, उस के अलावा किसी और तरह से खर्च किया जा सकता है । यदि किसी समय ऐसा संस्थान/संगठन काम करना बंद कर दे, तो उसकी परिसंपत्तियाँ राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के पास चली जाएँगी ।

भारत के कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल के जाँच परीक्षण के लिए संस्थान के लेखा पत्रों और अन्य दस्तावेजों को तैयार रखना होगा ।

यदि रा० शै० अ० और प्र० प० को कभी ऐसा लगे कि अनुमोदित राशि को उन कार्यों के लिए नहीं खर्च किया जा रहा है जिनके लिए उसे लिया गया था, तो परिषद् को अधिकार होगा कि वह अनुदान देना बंद कर दे और दी गई राशि को वापिस ले ले ।

रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों में संगठन को पूरी मितव्ययिता से चलना होगा ।

अनुदान के लिए आवेदन रा० शै० अ० और प्र० प० के सचिव के पास भेजना चाहिए ।

सन् 1980-81 के दौरान रा० शै० अ० और प्र० प० ने अनेक संगठनों को अनुदान दिए । आगे का संलग्नक बताता है कि किन संगठनों को किन उद्देश्यों से अनुदान दिए गए ।

संलग्नक

विभिन्न व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सन् 1980-81 के दौरान रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा पत्रिका-प्रकाशन के लिए दिए गए अनुदान

क्रम संख्या	संगठन का नाम-पता	पत्रिका का नाम	अनुदान राशि
1.	अखिल भारतीय विज्ञान शिक्षक संघ सरदार पटेल विद्यालय नई दिल्ली	'विज्ञान शिक्षक'	5,000/- रु०
2.	एसोसिएशन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ मैथेमेटिक्स टीचिंग 25, फर्न रोड कलकत्ता	'इंडियन जर्नल ऑफ़ मैथेमेटिक्स टीचिंग'	3,500/- रु०
3.	नेशनल पैरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया एस-47, पंचशील पार्क नई दिल्ली	'पी० टी० ए० क्वाटर्ली जर्नल'	1,750/ रु०
4.	एस० आई० टी० यू० काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च 169, रामकृष्ण मठ रोड मद्रास	'एक्सपेरीमेंट्स इन एजुकेशन'	3,000/- रु०
5.	इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया 169, रामकृष्ण मठ रोड मद्रास	'इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग'	5,000/- रु०

क्रम संख्या	संगठन का साम-पता	पत्रिका का नाम	अनुदान राशि
6.	चाइल्ड गाइडेंस स्कूल सोसायटी बी-66, मोतीनगर नई दिल्ली	'ग्रोइंग माइंड्स'	5,000/- रु०
7.	इंडियन फ़िजिक्स एसोसिएशन c/o टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च होमी भाभा रोड बम्बई	'फ़िजिक्स न्यूज़'	5,000/- रु०
8.	एसोसिएशन फॉर दि प्रमोशन ऑफ़ साइंस एजुकेशन 169, रामकृष्ण मठ रोड मद्रास	'जूनियर साइंटिस्ट'	4,600/- रु०
9.	आल इंडिया फेडेरेशन ऑफ़ एजुकेशन एसोसिएशन 16-ए/10, वेस्टर्न एक्सटेंशन एरिया नई दिल्ली	'इंडियन एजुकेशन'	5,000/- रु०
10.	बंगीय विज्ञान परिषद् कलकत्ता	'ज्ञान-ओ-विज्ञान'	3,500/- रु०
11.	इलाहाबाद भूगोल समाज 7, बेली एवेन्यू प्रसाद मुद्रणालय इलाहाबाद	'नेशनल ज्योग्राफर'	2,000/- रु०

विभिन्न व्यावसायिक शैक्षिक संगठनों को सन् 1980-81 के दौरान रा० शै० अ० और प्र० प० द्वारा सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए दिए गए अनुदान

क्रम संख्या	संगठन का नाम-पता	उद्देश्य	अनुदान राशि
1.	नेशनल पैरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया एस-47, पंचशील पार्क नई दिल्ली	वार्षिक सम्मेलन	3,000/-
2.	इंडियन एकेडेमी ऑफ़ सोशल साइंसेज़ c/o ईश्वरशरण डिग्री कालेज इलाहाबाद	पाँचवीं आइ० एस० सी० कांग्रेस/कांफ्रेंस	5,000/-
3.	इंडियन एसोसिएशन फॉर प्रि-स्कूल एजुकेशन 64, पुनमुरंगम रोड कोयम्बतूर	वार्षिक सम्मेलन	4,000/-
4.	इंडियन एसोसिएशन ऑफ़ टीचर एजुकेटर्स 8-बी, बंध रोड, एलेनगंज इलाहाबाद	बाईसवीं वार्षिक सभा	5,000/-
5.	नेशनल एसोसिएशन फॉर दि ब्लाइंड जहांगीर वाडिया बिल्डिंग 51, एम० जी० रोड बम्बई	आर्गेनाइजिंग प्रोग्राम ऑन दि यूज़ ऑफ़ एवेकस (फॉर दि ट्रेनिंग कम्पोनेंट)	15,000/-

परिशिष्ट-ख

राज्यों में परिषद् के क्षेत्र-सलाहकारों के पते

पते	राज्य/संघ क्षेत्र
1. क्षेत्र सलाहकार (रा० क्षै० अ० और प्र० प०) जू रोड, गौहाटी-781024	असम अरुणाचल प्रदेश
2. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) गीतांजलि टी० सी० नं० 15/1019 जगथी, त्रिवेन्द्रम-14	केरल लक्षद्वीप मिनिकोय अमीनदीवी द्वीपसमूह
3. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) 3-6/147-2, हिमायत नगर हैदराबाद-500029	आंध्र प्रदेश
4. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) बी-47, प्रभु मार्ग, तिलक नगर जयपुर-302004	राजस्थान
5. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) एम० आइ० जी० 161, ब्लाक नं० 6 सरस्वती नगर, जवाहर चौक भोपाल-462017	मध्य प्रदेश

6. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) 555/ई, ममफोर्डगंज इलाहाबाद-211002	उत्तर प्रदेश
7. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) होमी भाभा होस्टेल क्षे० शि० म० कैम्पस भुवनेश्वर-751007	उड़ीसा
8. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) 714, नाइंथ क्रॉस वेस्ट ऑफ कौर्ड रोड राजाजी नगर बंगलौर-560010	कर्नाटक
9. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) 1-बी, चन्द्रा कालोनी अहमदाबाद-380006	गुजरात दादरा व नगर हवेली
10. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) नं० 32, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट त्यागराज नगर, मद्रास-600017	तमिलनाडु पांडिचेरी
11. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) 128/2, कोथरुड, कर्वे रोड (मारुति मंदिर बस स्टाप के पास) पुणे-411029	महाराष्ट्र गोआ
12. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) रोड नं० 2, राजेन्द्र नगर पटना-800016	बिहार

13. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) पी-23, सी० आई० टी० रोड (एल० बी० स्कीम) कलकत्ता-700014	पश्चिमी बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिक्किम
14. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) मकान नं० 23, सैक्टर-8 (ए) चंडीगढ़-160018	पंजाब हिमाचल प्रवेश चंडीगढ़
15. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) निज़ाम मंज़िल शेरे कश्मीर कालोनी सैक्टर-2 रामपुरा छतबल डाक० करन नगर श्रीनगर-190010	जम्मू और कश्मीर
16. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) डानबोस्को शिलॉङ कालेज रोड, डाक० लैतुमख्रा शिलॉङ-793003	त्रिपुरा मिज़ोरम मेघालय

परिशिष्ट-ग

समितियों की संरचना

परिषद्

सामान्य निकाय

(1-4-80 से 31-3-81 तक)

(i) मंत्री, शिक्षा मंत्रालय अध्यक्ष—(पदेन)	1. श्री बी० शंकरानंद केन्द्रीय मंत्री शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली (1-4-80 से 18-10-80 तक) श्री एस० बी० चव्हाण केन्द्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली (19-10-80 से 31-3-81 तक)
(ii) अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग— (पदेन)	2. प्रो० सतीशचन्द्र अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली (1-4-80 से 14-1-81 तक) श्रीमती माधुरी आर० शाह अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली (12-2-81 से 31-3-81 तक)

(iii) सचिव, शिक्षा मंत्रालय —(पदेन)	3. श्री पी० सभानायगम सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली 1-4-80 से 31-8-80 तक) श्री० टी० एन० चतुर्वेदी सचिव, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली (31-1-81 से 31-3-81 तक)
(iv) भारत सरकार द्वारा दो वर्षों के लिए नामजद चार विश्वविद्यालयों के उपकुलपति, प्रत्येक क्षेत्र से एक	4. डा० आर० के० पोद्दार उपकुलपति कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता (1-4-80 से 30-9-80 तक) प्रो० एस० हमीद उपकुलपति अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ (21-2-81 से 31-3-81 तक) 5. श्री एस० एस० वोडेयर उपकुलपति कर्नाटक विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक) (1-4-80 से 30-9-80 तक) श्री आर० के० कनबरकर उपकुलपति शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर (21-2-81 से 31-3-81 तक) 6. श्री ईश्वर भाई जे० पटेल उपकुलपति गुजरात कृषि विश्व विद्यालय, सरदार कृषि नगर, दांतीवाड़ा (1-4-80 से 30-9-80 तक)

प्रो० बी० एस० रामकृष्ण
उपकुलपति
हैदराबाद विश्वविद्यालय
हैदराबाद
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

7. प्रो० ए० एम० खुसरो
उपकुलपति
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़
(1-4-80 से 30-9-80 तक)

डा० वी० के० सुकुमारन नायर
उपकुलपति
केरल विश्वविद्यालय
त्रिवेंद्रम
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

(v) राज्य/विधानांगों वाले संघ-राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि जो वहाँ के शिक्षामंत्री (या उसके प्रतिनिधि) होंगे और दिल्ली के मामले में मुख्य कार्यकारी पार्षद (अथवा उसके प्रतिनिधि) होंगे।

8. शिक्षामंत्री
आंध्रप्रदेश
हैदराबाद

9. शिक्षामंत्री
असम
शिलॉङ

10. शिक्षामंत्री
बिहार
पटना

11. शिक्षामंत्री
गुजरात
अहमदाबाद

12. शिक्षामंत्री
हरियाणा
चण्डीगढ़

13. शिक्षामंत्री
हिमाचल प्रदेश
शिमला

14. शिक्षामंत्री
जम्मू तथा कश्मीर
श्रीनगर

15. शिक्षामंत्री
केरल
त्रिवेन्द्रम

16. शिक्षामंत्री
मध्य प्रदेश
भोपाल

17. शिक्षामंत्री
महाराष्ट्र
बम्बई

18. शिक्षामंत्री
मणिपुर
इम्फाल

19. शिक्षामंत्री
मेघालय
शिलॉङ

20. शिक्षामंत्री
कर्नाटक
बंगलोर

21. शिक्षामंत्री
नागालैंड
कोहिमा

22. शिक्षामंत्री
उड़ीसा
भुवनेश्वर

23. शिक्षामंत्री
राजस्थान
जयपुर

24. शिक्षामंत्री
पंजाब, चंडीगढ़

25. शिक्षामंत्री
तमिलनाडु
मद्रास

26. शिक्षामंत्री
त्रिपुरा सरकार
अगरतला

27. शिक्षामंत्री
सिक्किम
गंगटोक

28. शिक्षामंत्री
उत्तर प्रदेश
लखनऊ

29. शिक्षामंत्री
पश्चिमी बंगाल
कलकत्ता

30. मुख्य कार्यकारी पार्षद
दिल्ली प्रशासन
दिल्ली

31. शिक्षामंत्री
गोआ, दमन और दीव की सरकार
पणजी (गोआ)

32. शिक्षामंत्री
मिज़ोरम
ऐजल

33. शिक्षामंत्री
पांडीचेरी सरकार
पांडीचेरी

(vi) कार्यकारी समिति के सभी सदस्य जो ऊपर शामिल नहीं हैं ।

34. श्रीमती शीला कौल
राज्य मंत्री
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन
नई दिल्ली
(19-10-80 से 30-3-81 तक)

35. ---

36. डा० शिवकुमार मित्र
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली

37. प्रो० पी० के० बोस
सेंटीनरी प्रोफ़ेसर और अध्यक्ष,
सांख्यिकी विभाग
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस
35, बालीगंज सर्कुलर रोड
कलकत्ता-700019

38. प्रो० वी जी० कुलकर्णी
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल
रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस
एजुकेशन, होमी भाभा रोड
बम्बई—400005

39. श्रीमती अबला गोहैन
प्रिंसिपल, बाल्या भवन
जोरहट (असम)

40. श्रीमती के० वी० पोन्नम्मा
हैडमिस्ट्रेस
सेंट जोज़ेफ़ अपर प्राइमरी स्कूल
कीजूमड
एरूमथाला
अल्वेइ (केरल)
(1-4-80 से 19-8-80 तक)
श्री एच० डी० गावकर
के० एम० एस० डा० शिरोडकर
हाई स्कूल
142/49, डा० बॉयजेस रोड
परेल
बम्बई-400012
(25-2-81 से 31-3-81 तक)

41. डा० टी० एन० धर
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

42. श्री एस० एच० खान
रीडर, पी० सी० डी० सी०
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

43. डा० जी० बी० कानूनगो
प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर-751007

44. डा० ए० के० शर्मा
प्रोफ़ेसर इन साइंस (रसायन विज्ञान)
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
मैसूर-570006

45. श्री अनिल बोर्डिया
संयुक्त सचिव
शिक्षा मंत्रालय,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(1-4-80 से 7-5-80 तक)
श्री० एस० सत्यम
संयुक्त सचिव
शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(8-5-80 से 31-3-81 तक)

46. श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन
वित्तीय सलाहकार
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, और शिक्षा
मन्त्रालय, कमरा नंबर 109, सी
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(vii) (क) अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली (पदेन)

(ख) आयुक्त, के० वि० सं० नई दिल्ली (पदेन)

(ग) निदेशक, के० स्वा० शि० ब्यूरो नई दिल्ली (पदेन)

(घ) उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) भा० कृ० अ० प०, नई दिल्ली (पदेन)

(ङ) प्रशिक्षण निदेशक प्र० रो० म०, श्रम मंत्रालय नई दिल्ली (पदेन)

(च) प्रतिनिधि, शिक्षा विभाग योजना आयोग, नई दिल्ली (पदेन)

(viii) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार समय-समय पर नामजद करे। इनकी संख्या 6 से अधिक नहीं होगी और इनमें से कम-से-कम 4 स्कूल अध्यापक होंगे।

47. अध्यक्ष
सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन, 17 बी, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली

48. आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नेहरू हाउस 4, बहादुरशाह जफ़र मार्ग नई दिल्ली

49. निदेशक
केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय) निर्माण भवन, नई दिल्ली

50. उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा)
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
कृषि भवन
नई दिल्ली

51. प्रशिक्षण निदेशक, प्रशिक्षण और रोजगार महानिदेशालय
श्रम मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-1

52. प्रमुख (शिक्षा)
योजना आयोग, योजना भवन, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली-1

53. श्री गोपालकृष्ण सैनी
हेडमास्टर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुखलियाना होशियारपुर (पंजाब)
(1-4-80 से 30-9-80 तक)
श्री एस० रामास्वामी
हेडमास्टर, टी० वी०एस०
आयंगार हायर सेकंडरी स्कूल
मदुरै
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

54. श्रीमती कमला दुबे
हेडमिस्ट्रेस, बालिका प्राथमिक विद्यालय
मोहननगर, सागर (म० प्र०)
(1-4-80 से 30-9-80 तक)
श्री केदारनाथ सिंह, विज्ञान शिक्षक
के० के० विद्या मंदिर, धारवाढ़
वैशाली
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

55. श्री नैनीमाधव बरुआ
प्रिंसिपल, राजकीय हायर सेकंडरी
स्कूल, तेजपुर
दारङ (असम)
(1-4-80 से 30-9-80 तक)
श्रीमती सलमा फिरदौस
प्रिंसिपल, हायर सेकंडरी स्कूल
कोताबी बाग़
श्रीनगर
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

56. सिस्टर राशेल
हेडमिस्ट्रेस
माउंट कार्मेल गर्ल्स हाई स्कूल)
कंजीकुजी
कोट्टयम (केरल)
(1-4-80 से 30-9-80 तक)
श्री वीरसिंह
सहायक प्रोफ़ेसर
राजकीय शिक्षा महाविद्यालय
देवास (मध्य प्रदेश)
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

57. श्री टी० के० वैद्यनाथन
प्रिंसिपल, टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग
इंस्टीच्यूट, सेक्टर 26
चंडीगढ़-160026
(1-4-80से 30-9-80 तक)

डा० एन० के० उपासनी
अवैतनिक प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग
एस० एन० डी० टी० यूनिवर्सिटी
बम्बई
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

58. डा० ए० के० डे
निदेशक
इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलौजी
पवई
बम्बई-400076
(1-4-80 से 31-3-81 तक)
डा० कुमारी एम० डॉली शेनॉय
1-2-212/6/1, गगन महल रोड
दुमालगुडा, हैदराबाद
(21-2-81 से 31-3-81 तक)

(ix) विशेष आमन्त्रित

59. सेक्रेट्री
कौंसिल ऑफ इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट
इक्ज़ामिनेशन, प्रगति भवन
47, नेहरू प्लेस
नई दिल्ली-110025

60. श्री विनोदकुमार पंडित
सचिव
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली-110016 (सचिव)

कार्यकारी समिति

(1-4-1980 से 31-3-1981 तक)

(i) परिषद् का अध्यक्ष जो कार्यकारी समिति का पदेन अध्यक्ष होगा।	1. श्री बी० शंकरानंद केन्द्रीय शिक्षामंत्री शास्त्री भवन नई दिल्ली (1-4-80 से 18-10-80 तक) श्री एस० बी० चव्हाण केन्द्रीय शिक्षामंत्री शास्त्री भवन नई दिल्ली (19-10-80 से 31-3-81 तक)
(ii) (अ) शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री जो कार्यकारी समिति का पदेन उपाध्यक्ष होगा।	2. श्रीमती शीला कौल राज्यमंत्री शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली (19-10-80 से 31-3-1981 तक)
(आ) शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री—रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत	3. ————————
(इ) परिषद् के निदेशक	4. प्रो० शिवकुमार मित्र निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

(iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष (पदेन सदस्य)

5. प्रो० सतीशचन्द्र
अध्यक्ष
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली
(1-4-80 से 14-1-81 तक)
श्रीमती माधुरी आर० शाह
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग
बहादुर ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली
(12-2-81 से 31-3-81 तक)

(iv) रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षा-विद जो स्कूल शिक्षा में विशेष रुचि रखते हों, तथा जिनमें से दो स्कूल अध्यापक होंगे ।

6. प्रो० पी० के० बोस
सेंटीनरी प्रोफ़ेसर और अध्यक्ष,
सांख्यिकी विभाग
यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ़ साइंस
35, बालीगंज सर्कुलर रोड
कलकत्ता-700019

7. प्रो० वी० जी० कुलकर्णी
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ फंडामेंटल
रिसर्च, होमी भाभा सेंटर फ़ॉर
साइंस एजुकेशन, भाभा रोड
बम्बई-400005

8. श्रीमती अबला गोहैन
प्रिंसिपल, बाल्या भवन
जोरहट (असम)

9. श्रीमती के० वी० पोनम्मा
हैडमिस्ट्रेस
सेंट जोज़ेफ़ अपर प्राइमरी स्कूल
कीजूमड, एरूमथाला, अल्वेइ (केरल)
(1-4-80 से 19-8-80 तक)
श्री एच० डी० गावकर
के० एम० एस० डा० शिरोडकर
हाई स्कूल, 142/49, डा० बनर्जीरोड
परेल, बम्बई
(25-2-81 से 31-3-81 तक)

(v) परिषद् के संयुक्त निदेशक

10. डा० टी० एन० धर
संयुक्त निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

(vi) रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा नामजद परिषद् की संकाय के तीन सदस्य जिनमें से कम से कम दो प्रोफ़ेसर और विभागाध्यक्ष के स्तर के होंगे ।

11. श्री एस० एच० खान
रीडर, पी० सी० डी० सी०
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली

12. डा० जी० बी० कानूनगो
प्रिंसिपल, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर-751007

13. डा० ए० के० शर्मा
प्रोफ़ेसर इन साइंस (रसायन शास्त्र)
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
मैसूर-570006

(vii) शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि

14. श्री अनिल बोर्डिया
संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(1-4-80 से 7-5-80 तक)
श्री एस० सत्यम
संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(8-5-80 से 31-3-81 तक)

(viii) वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि जो परिषद् का वित्त सलाहकार होगा ।

15. श्री जे० ए० कल्याण कृष्णन
बित्त सलाहकार
रा० शै० अ० और प्र० प०
तथा शिक्षा मंत्रालय
कमरा नं० 109 'सी', शास्त्री भवन
नई दिल्ली

16. श्री बिनोदकुमार पंडित
सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली-16
(सचिव)

संस्थापन समिति

(1-4-80 से 31-3-81 तक)

(i) निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प० (अध्यक्ष)	1. डा० शिवकुमार मित्र निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली (अध्यक्ष)
(ii) संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०	2. डा० टी० एन० धर संयुक्त निदेशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् नई दिल्ली
(iii) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद शिक्षा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	3. श्री अनिल बोर्डिया संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन नई दिल्ली (1-4-80 से 7-5-80 तक) श्री एस० सत्यम संयुक्त सचिव शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन नई दिल्ली (8-5-80 से 31-3-81 तक)

(iv) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद चार शिक्षाविद, जिनमें से कम से कम एक वैज्ञानिक होगा

4. प्रो० एम० एस० सोढा
भौतिकी विभाग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
हौज खास
(1-4-80 से 9-6-80 तक)

प्रो० एम० एल० सभादत्ती
भौतिकी विभाग
कर्नाटक विश्वविद्यालय
धारवाड़-580003
(27-2-81 से 31-3-81 तक)

5. प्रो० (कु०) मालती बोलर
निदेशक
इंस्टीच्यूट ऑफ एप्लाइड मैन पावर रिसर्च, इंद्रप्रस्थ इस्टेट, रिंग रोड
नई दिल्ली-110002
(1-4-80 से 9-6-80 तक)

प्रो० पी० एल० मल्होत्रा
डीन ऑफ़ कालेजेज़
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली
(27-2-81 से 31-3-81 तक)

6. डा० अमरीक सिंह
उपकुलपति
पंजाबी विश्वविद्यालय
पटियाला (पंजाब)
(1-4-80 से 9-6-80 तक)

डा० फ्रांसिस एक्का
प्रोफ़ेसर और उप निदेशक
केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान
मानस गंगोत्री
मैसूर-570006
(27-2-81 से 31-3-81 तक)

7. प्रो० एस० मन्जूर आलम
भूगोल विभाग
उस्मानिया विश्वविद्यालय
हैदराबाद-500007 (आं० प्र०)
(1-4-80 के 9-6-80 तक)
प्रो० कुमारी ए० एस० दस्तूर
अध्यक्ष, नागरिक शास्त्र और
राजनीति शास्त्र विभाग
बम्बई विश्वविद्यालय, बम्बई
(27-2-81 से 31-3-81 तक)

(v) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय का एक प्रतिनिधि

8. प्रो० जे० एस० राजपूत
प्रधानाचार्य
क्षे० शि० म०, भोपाल
(1-4-80 से 9-6-80 तक)
श्री० पी० सी० जोज़ेफ
स्टोर कीपर
क्षे० शि० म०
मैसूर
(27-2-81 ये 31-3-81 तक)

(vi) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा नामजद राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली का एक प्रतिनिधि

9. डा० आर० सी० दास
डीन (शैक्षणिक) तथा अध्यक्ष
अध्यापक-शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
(1-4-80 से 9-6-80 तक)
कुमारी एस० के० राम
रीडर, सा० वि० मा० शि० विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली
(27-2-81 से 31-3-81 तक)

(vii) परिषद् के नियमित शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक कर्मचारी वर्ग में से एक-एक (कुल दो) प्रतिनिधि

10. श्री बालगोपाल वर्मा
लेक्चरर
क्षे० शि० म०, मैसूर

11. श्री प्रबाध कुमार
उच्च श्रेणी लिपिक
सा० वि० मा० शि० वि०
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

(viii) वित्त सलाहकार, रा० शै० अ० और प्र० प०

12. श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन
वित्त सलाहकार
रा० शै० अ० और प्र० प० तथा
शिक्षा मंत्रालय
कमरा नं० 109 'सी', शास्त्री भवन
नई दिल्ली

(ix) सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प०
(सदस्य-संयोजक)

13. श्री विनोद कुमार पंडित
सचिव
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली (सदस्य-संयोजक)

वित्त समिति

(5-4-80 से 31-3-81 तक)

1. प्रो० शिवकुमार मित्र
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद्
   नई दिल्ली (पदेन अध्यक्ष)

2. श्री एस० सत्यम
   संयुक्त सचिव
   शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन
   नई दिल्ली

3. प्रो० बी० रामचन्द्र राव
   उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय
   अनुदान आयोग
   बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग
   नई दिल्ली
   (27-9-80 से 31-3-81 तक)

4. प्रो० रशीदुद्दीन खान
   अध्यक्ष, राजनीतिक अध्ययन केन्द्र
   जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय
   नई दिल्ली
   (27-9-80 से 25-10-80 तक)

   प्रो० वी० जी० कुलकर्णी
   परियोजना निदेशक
   टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ फंडामेंटल
   रिसर्च
   होमी भाभा सेंटर फॉर
   साइंस एजुकेशन
   होमी भाभा रोड
   बम्बई-400005
   (27-10-80 से 31-3-81 तक)

5. श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन
   वित्त सलाहकार,
   रा० शै० अ० और प्र० प०
   तथा शिक्षा मंत्रालय
   कमरा नं० 109 'सी'
   शास्त्री भवन
   नई दिल्ली
   (पदेन सदस्य)

6. श्री विनोदकुमार पंडित
   सचिव
   रा० शै० अ० और प्र० प०
   नई दिल्ली
   (संयोजक)

भवन तथा निर्माण समिति

(9-12-80 से 31-3-81 तक)

(i) निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प० (पदेन अध्यक्ष)	1. प्रो० शिवकुमार मित्र निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प० नई दिल्ली
(ii) संयुक्त निदेशक रा० शै० अ० और प्र० प० (पदेन उपाध्यक्ष)	2. डा० टी० एन० धर संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली
(iii) मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लो० नि० विभाग अथवा उसके द्वारा मनोनीत व्यक्ति	3. श्री एम० एल० कालरा सुपरिंटेंडिंग सर्वेयर ऑफ वर्क्स (फूड), सी० पी० डब्ल्यू० डी० इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली
(iv) वित्त मंत्रालय (वर्क्स) का एक प्रतिनिधि	4. श्री ए० के० सक्सेना सहायक वित्त सलाहकार वित्त मंत्रालय (वर्क्स) निर्माण भवन, (III मंजिल) नई दिल्ली
(v) परिषद् का परामर्शी वास्तुक	5. श्री के० एम० सक्सेना ज्येष्ठ वास्तुक एच० पी० टी०-2 के० लो० नि० विभाग, निर्माण भवन नई दिल्ली

(vi) परिषद् का वित्त सलाहकार अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति	6. श्री जे० ए० कल्याणकृष्णन वित्त सलाहकार, रा० शै० अ० और प्र० प०, कमरा नं० 109 'सी' शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(vii) शिक्षा मंत्रालय द्वारा मनोनीत व्यक्ति	7. श्री एस० सत्यम संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय शास्त्री भवन, नई दिल्ली
(viii) कोई प्रतिष्ठित सिविल इंजीनियर (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	8. श्री आर० ए० खेमानी मुख्य इंजीनियर दिल्ली विकास प्राधिकरण विकास भवन एनेक्सी इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली
(ix) कोई प्रतिष्ठित बिजली इंजीनियर (अध्यक्ष द्वारा मनोनीत)	9. श्री टी० कृष्णमूर्ति सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर दिल्ली सेंट्रल इलेक्ट्रिक सर्किल-1 केंद्रीय लोक निर्माण विभाग इंद्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट नई दिल्ली
(x) समिति द्वारा मनोनीत कार्यकारी समिति का सदस्य	10. श्री एस० एच० खान रीडर, पी० सी० डी० सी० रा० शै० अ० और प्र० प० नई दिल्ली (23-12-80 से 31-3-81 तक)
(xi) सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प० (सदस्य सचिव)	11. श्री विनोदकुमार पंडित सचिव, रा० शै० अ० और प्र० प० नई दिल्ली

कार्यक्रम सलाहकार समिति

1. प्रो० शिवकुमार मित्र
   निदेशक, रा० शै० अ०
   और प्र० प०
   नई दिल्ली (अध्यक्ष)
2. डा० टी० एन० धर
   सह निदेशक, रा० शै० अ०
   और प्र० प०
   नई दिल्ली (उपाध्यक्ष)
3. प्रो० श्रीनिवास भट्टाचार्य
   शिक्षा के प्रोफ़ेसर
   विद्या भारती
   शान्तिनिकेतन
4. प्रो० बी० के० पासी
   अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
   इंदौर विश्वविद्यालय
   इंदौर
5. प्रो० के० कुमार स्वामी पिल्लै
   शिक्षा के प्रोफ़ेसर
   अन्नामलाइ विश्वविद्यालय
   अन्नामलाइ नगर
   (तमिलनाडु)
6. प्रो० के० पद्म उमापति
   गृह विज्ञान के प्रोफ़ेसर
   मैसूर विश्वविद्यालय
   मैसूर
7. प्रो० बी० आर० कामले
   अध्यक्ष, इतिहास विभाग
   शिवाजी विश्वविद्यालय
   कोल्हापुर
   (महाराष्ट्र)
8. निदेशक
   राज्य शिक्षा संस्थान
   सेक्टर 20-डी
   चंडीगढ़
9. प्रिंसिपल
   राज्य शिक्षा संस्थान
   त्रिवेंद्रम (केरल)
10. प्रिंसिपल
    राज्य शिक्षा संस्थान
    जोरहट-785001 (असम)
11. निदेशक
    राज्य शिक्षा संस्थान
    सदाशिव पेठ, कुमठेकर रोड, पुणे
12. निदेशक
    राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
    प्रशिक्षण विभाग
    श्री बी० पी० बाडिया रोड
    बासवंडगुडी
    बंगलोर

13. अध्यक्ष
मापन और मूल्यांकन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

14. अध्यक्ष
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

15. अध्यक्ष
अध्यापक-शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

16. अध्यक्ष
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी
शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

17. अध्यक्ष
शिक्षण साधन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

18. अध्यक्ष
प्रकाशन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

19. अध्यक्ष
वर्कशॉप विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

20. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
अजमेर

21. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर

22. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भोपाल

23. प्रिंसिपल
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
मैसूर

24. प्रिंसिपल
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

25. डा० प्रीतमसिंह
रीडर
मापन और मूल्यांकन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

26. डा० बृजेशदत्त आत्रेय
रीडर
विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

27. डा० सी० एस० सुब्बा राव
प्रोफ़ेसर
अध्यापक-शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

28. कुमारी एस० के० राम
रीडर
सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी
शिक्षा विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

29. श्री तिलकराज
रीडर
शिक्षण साधन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

30. श्री सी० एन० राव
मुख्य उत्पादन अधिकारी
प्रकाशन विभाग
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

31. डा० एम० वी० रामजी
रीडर
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भुवनेश्वर

32. डा० जे० एस० ग्रेवाल
रीडर
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
भोपाल

33. डा० श्रीमती अमृतकौर
रीडर
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
अजमेर

34. डा० एम० एस० मुरारी राव
रीडर
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय
मैसूर

35. डा० जगदीश सिंह
रीडर
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
रा० शै० अ० और प्र० प०
नई दिल्ली

स्कूल-पाठ्यक्रम की सलाहकार-समिति

1. डा० शिवकुमार मित्र — अध्यक्ष
   निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद्
   श्री अरविंद मार्ग
   नई दिल्ली

2. डा० टी० एन० धर — सदस्य
   संयुक्त निदेशक
   राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
   प्रशिक्षण परिषद्
   श्री अरविंद मार्ग
   नई दिल्ली

3. प्रो० वी० रामचन्द्र राव — सदस्य
   उपाध्यक्ष
   विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
   बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग,
   नई दिल्ली

4. प्रो० आर० सी० पाल — सदस्य
   उपकुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय
   चंडीगढ़

5. प्रो० जी० आर० दामोदरन — सदस्य
   उपकुलपति, मद्रास विश्वविद्यालय
   मद्रास

6. प्रो० रशीदुद्दीन खान — सदस्य
अध्यक्ष, राजनीतिक अध्ययन केन्द्र
स्कूल ऑफ़ सोशल साइंसेज़
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

7. डा० सुमा चिटणीस — सदस्य
प्रोफ़ेसर, टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ सोशल साइंसेज़
सायन-ट्राम्बे रोड, देवनार
बम्बई

8. डा० अमरीक सिंह — सदस्य
सचिव, एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन
यूनिवर्सिटीज़
दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली

9. डा० राजम्मल पी० देवदास — सदस्य
प्रिंसिपल, श्री अविनाशलिंगम
होम साइंस कॉलेज फ़ॉर वीमेन
कोयम्बतूर

10. प्रो० एस० एम० चटर्जी — सदस्य
98/39, गोपाललाल टैगोर रोड
कलकत्ता

11. डा० गोपाल सिंह — सदस्य
अध्यक्ष, वर्ल्ड सिख यूनिवर्सिटी प्रेस
7, पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार
नई दिल्ली

12. श्री० वी० जी० कुलकर्णी — सदस्य
प्रोजेक्ट लीडर
टाटा इंस्टीच्यूट ऑफ़ फंडामेंटल रिसर्च
होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस
एजुकेशन,
होमी भाभा रोड
बम्बई-400005

13. डा० मुहम्मद अहमद — सदस्य
रीडर इन मेडिसिन
जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
अलीगढ़

14. श्री एम० एन० कपूर — सदस्य
निदेशक, गुरु शिखर स्कूल
माउंट आबू
राजस्थान

15. डा० एस० एन० मेहरोत्रा — सदस्य
उपकुलपति, आगरा विश्वविद्यालय
आगरा

16. प्रो० बी० के० रॉय बर्मन — सदस्य
डिपार्टमेंट ऑफ रूरल स्टडीज़
विश्वभारती
जिला वीरभूमि
श्री निकेतन-731236
(पश्चिमी बंगाल)

17. श्रीमती अशिमा चौधरी — सदस्य
प्रिंसिपल, साउथ देलही पॉलिटेकनीक फॉर वीमेन
एन 9, रिंग रोड
साउथ एक्सटेंशन पार्ट I
नई दिल्ली-110049

18. डा० प्रेम कृपाल — सदस्य
63 एफ, सुजानसिंह पार्क
नई दिल्ली-110003

19. डा० पी० एल० मलहोत्रा — सदस्य
प्रिंसिपल, कालेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

20. प्रो० एल० पी० अग्रवाल — सदस्य
निदेशक, ऑल इंडिया इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़
अन्सारी नगर
नई दिल्ली-110016

21. डा० नगेन्द्र — सदस्य
प्रोफ़ेसर, हिन्दी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
16, कैवेलरी लाइंस
दिल्ली-110007

22. डा० (श्रीमती) उषा के० लूथरा — सदस्य
सीनियर डिपुटी डायरेक्टर जनरल
इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च
अन्सारी नगर
नई दिल्ली-110016

23. श्री ए० के० धान — सदस्य
उपकुलपति
नार्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी
शिलॉङ

24. डा० एच० एस० एस० लारेंस — सदस्य
5, अरुलगम, बैंगडंवल रोड
नुंगंबक्कम
मद्रास

25. प्रो० जे० जे० नानावती — सदस्य
सेंट्रल बॉम्बे सर्विस-1 (आर)
11, नैपियर रोड
पुणे-411001

26. प्रो० एल० के० महापात्र — सदस्य
अध्यक्ष, नृशास्त्र विभाग
उत्कल विश्वविद्यालय
वाणी विहार
भुवनेश्वर (उड़ीसा)

27. डा० के० आर० श्रीनिवास आयंगार — सदस्य
152, कचहरी रोड
मइलापुर मद्रास-600004

28. प्रिंसिपल — पदेन सदस्य
नेतरहाट विद्यालय
नेतरहाट (बरास्ता राँची)
बिहार

29. आयुक्त — पदेन सदस्य
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
नेहरू हाउस
बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली

30. सहायक महानिदेशक (शिक्षा) — पदेन सदस्य
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्
कृषि भवन, डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड
नई दिल्ली

31. प्राथमिक शिक्षा निदेशक — पदेन सदस्य
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय
पश्चिमी बंगाल सरकार
नूतन सचिवालय भवन
कलकत्ता

32. अध्यक्ष — पदेन सदस्य
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन
17 बी, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली

33. अध्यक्ष — पदेन सदस्य
कौंसिल ऑफ बोर्ड्स ऑफ सेकंडरी एजुकेशन इन इंडिया
17 बी, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

34. निदेशक — पदेन सदस्य
राज्य शिक्षा संस्थान, महाराष्ट्र
कुमठेकर मार्ग
पुण (महाराष्ट्र)

35. सेक्रेट्री — पदेन सदस्य
कौंसिल फॉर दि इंडियन स्कूल सर्टिफ़िकेट इक्ज़ामिनेशंस
प्रगति हाउस, 47-48, नेहरू प्लेस
नई दिल्ली

36. सदस्य सचिव — पदेन सदस्य
भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्
इन्द्रप्रस्थ इस्टेट
नई दिल्ली-110002

37. निदेशक — पदेन सदस्य
नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कूद संस्थान
मोतीबाग
पटियाला-147001

38. शिक्षा निदेशक — पदेन सदस्य
केरल सरकार
त्रिवेन्द्रम

39. राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान के सभी विभागों/एककों आदि के अध्यक्ष एवं प्रोफेसर — स्थायी आमंत्रित

40. प्रिंसिपल एवं प्रोफेसर — स्थायी आमंत्रित
शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र

41. रीडर (कार्यक्रम) — स्थायी आमंत्रित

42. प्रो० बाक़र मेंहदी — संयोजक
अध्यक्ष,
पाठ्यक्रम दल
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्
नई दिल्ली-110016

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की सलाहकार-समिति

1.	निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	संयुक्त सचिव (स्कूल), भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (शिक्षा विभाग), शास्त्री भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (पोषण और शिशु विकास), भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
4.	संयुक्त सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग भारत सरकार, योजना भवन, पार्ल्यामेंट स्टीट नई दिल्ली	पदेन सदस्य
5.	संयुक्त निदेशक, रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
6.	शिक्षा आयुक्त, बिहार सरकार नया सचिवालय, पटना-800015	पदेन सदस्य
7.	शिक्षा सचिव, मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल—462004	पदेन सदस्य
8.	आयुक्त, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार सचिवालय, जयपुर	पदेन सदस्य
9.	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार हैदराबाद —500022	पदेन सदस्य
10.	शिक्षा आयुक्त, जम्मू एवं कश्मीर सरकार श्रीनगर	पदेन सदस्य
11.	शिक्षा सचिव, शिक्षा विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, राइटर बिल्डिंग कलकत्ता—700001	पदेन सदस्य

12.	सचिव, शिक्षा एवं युवा सेवाएँ विभाग उड़ीसा सरकार, भुवनेश्वर	पदेन सदस्य
13.	निदेशक, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा निदेशालय 0-4, न्यू मेंटल हास्पिटल बिल्डिंग अहमदाबाद-380016	पदेन सदस्य
14.	शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश सरकार ग्लेन हेगन, शिमला-171001	पदेन सदस्य
15.	शिक्षा निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) न्यू पब्लिक आफ़िसेज़, बँगलोर-560001	पदेन सदस्य
16.	शिक्षा निदेशक (प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा) महाराष्ट्र सरकार, पुणे	पदेन सदस्य
17.	शिक्षा सचिव, असम सरकार सचिवालय दिशपुर, गौहाटी	पदेन सदस्य
18.	शिक्षा निदेशक (स्कूल), पंजाब सेक्टर 17-ई, एस० सी० ओ०, 95-97 चंडीगढ़-160017	पदेन सदस्य
19.	स्कूल शिक्षा निदेशक, तमिलनाडु सरकार कालेज रोड, डी० पी० आई० कम्पाउंड मद्रास-600006	पदेन सदस्य
20.	प्रिंसिपल, राज्य शिक्षा संस्थान रूपनगर, दिल्ली-110007	पदेन सदस्य
21.	निदेशक, राज्य शिक्षा संस्थान पूंजपुरा, त्रिवेंद्रम-12	पदेन सदस्य
22.	अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शिवाजी नगर, 401010	पदेन सदस्य
23.	अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान जयपुर रोड, अजमेर-305001	पदेन सदस्य
24.	अध्यक्ष/प्रशासक, पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 77/2, पार्क स्टीट, कलकत्ता-700016	पदेन सदस्य
25.	अध्यक्ष, कर्नाटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा बोर्ड मल्लेश्वरम, बँगलोर-560003	पदेन सदस्य

26.	अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ़ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजुकेशन इक्ज़ामिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद	पदेन सदस्य
27.	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा (5) प्रभाग लखनऊ	पदेन सदस्य
28.	अध्यक्ष, सेंटल बोर्ड ऑफ़ सेकंडरी एजुकेशन 17-B, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य
29.	आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन नेहरू हाउस, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002	पदेन सदस्य
30.	निदेशक, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 34, समुदाय केन्द्र, बसंत लोक, बसंत विहार, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
31.	निदेशक, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की	पदेन सदस्य
32.	डा० एस० बी० अदावाल, अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद-211002	सदस्य
33.	प्रो० एच० बी० मजुमदार विनय भवन, विश्व भारती, शान्तिनिकेतन-731235	सदस्य
34.	डा० सलामत उल्लाह 123-ज़ाकिर नगर, नई दिल्ली-110020	सदस्य
35.	डा० श्रीमती चित्रा नायक निदेशक, स्टेट रिसोर्स सेंटर फॉर नॉन फार्मल एजुकेशन, भारतीय शिक्षा संस्थान 128/2, कर्वे रोड, कोथरूड पुणे-411029	सदस्य
36.	श्री मनुभाई पांचोली निदेशक, लोक भारती, सांसोड़ा, भावनगर-364230	सदस्य
37.	श्री वजुभाई पटेल सचिव, नई तालीम समिति, गांधी शिक्षण भवन, जुहू, बम्बई-400049	सदस्य
38.	श्री० के० एल० बोडिया अध्यक्ष, विद्या भवन सोसायटी, उदयपुर	सदस्य

39. श्री सी० वी० सीतारामैया — सदस्य
हेडमास्टर, पी० एच० स्कूल (बी)
टोनूकू, पश्चिम गोदावरी (आंध्र प्रदेश)

40. श्रीमती विद्या स्टोक्स — पदेन सदस्य
उपाध्यक्षा, भारत कृषक समाज एकांतवन
डा० ढल्ली, शिमला

41. डा० एच० एस० एस० लारेंस — सदस्य
5, अरुरोगम, ब्रैगदम्बा रोड
नुंगंबक्कम, मद्रास-600034

42. डा० सी० प्रसाद
सहायक महानिदेशक (समन्वय) — सदस्य
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, कृषि भवन, नई दिल्ली

43. डा० बी० सी० घोषाल — सदस्य
निदेशक, केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार
कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन
नई दिल्ली

44. प्रिंसिपल — पदेन सदस्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, मैसूर

45. प्रिंसिपल — पदेन सदस्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भुवनेश्वर

46. प्रिंसिपल — पदेन सदस्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

47. प्रिंसिपल — पदेन सदस्य
क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर

48. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प) — पदेन सदस्य
जू रोड, गौहाटी-781024

49. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) — पदेन सदस्य
32, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट
त्यागराज नगर, मद्रास-600017

50. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) — पदेन सदस्य
555 ई, ममफोर्डगंज, इलाहाबाद-211002

51. क्षेत्र सलाहकार (रा० शै० अ० और प्र० प०) 128-2, कोथरुड, कर्वे रोड, (मारुति मंदिर बस स्टाप के पास), पुणे-411029	पदेन सदस्य
52. अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
53. अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
54. अध्यक्ष, अनौपचारिक शिक्षा रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
55. अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
56. अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	पदेन सदस्य
57. अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
58. अध्यक्ष, विस्तार एकक रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
59. प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
60. अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समूह रा० शै० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
61. अध्यक्ष, जनजातीय शिक्षा एकक रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
62. अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
63. रीडर (प्रोग्राम) रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	सदस्य
64. डीन (शैक्षणिक) रा० शै० अ० और प्र० प०, नई दिल्ली	संयोजक

समन्वय-समितियाँ

1. पाठ्यक्रम-विकास के लिए समन्वय-समिति

(क) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग

(ख) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग

(ग) अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक

(घ) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग

(ङ) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम समूह

(च) अध्यक्ष, जनजातीय शिक्षा एकक

(छ) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम बिकास प्रकोष्ठ

(ज) अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक

(झ) प्रो० अनिल विद्यालंकार

(ञ) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि

(ट) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समूह (संयोजक)

2. शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए समन्वय-समिति

(क) अध्यक्ष, शिक्षण-साधन विभाग

(ख) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग

(ग) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग

(घ) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग

(ङ) अध्यक्ष, बिस्तार एकक; राज्यों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी की प्रगति से संबद्ध क्षेत्र सलाहकार

(च) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि

(छ) प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (संयोजक)

3. अनौपचारिक शिक्षा के लिए समन्वय-समिति

(क) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम समूह
(ख) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
(ग) अध्यक्ष, जनजातीय शिक्षा एकक
(घ) अध्यक्ष, स्त्री-शिक्षा एकक
(ङ) अध्यक्ष, विस्तार एकक
(च) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समूह
(छ) अध्यक्ष, मापन और मूल्यांकन विभाग
(ज) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि
(झ) श्री ए० ए० सी० लाल
(ञ) प्रो० कृष्णगोपाल रस्तोगी (संयोजक)

4. मापन और मूल्यांकन के लिए समन्वय-समिति

(क) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
(ख) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग
(ग) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग
(घ) अध्यक्ष, शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक
(ङ) अध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान एकक
(च) अध्यक्ष, पाठ्यक्रम समूह
(छ) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ
(ज) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम समूह
(झ) अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक
(ञ) प्रो० श्रीमती स्नेहलता शुक्ला, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र
(ट) योजना, समन्वय और मूल्यांकन एकक का प्रतिनिधि
(ठ) अध्यक्ष, मापन और मूल्यांकन विभाग (संयोजक)

5. अध्यापक-शिक्षा और अन्य कार्यक्रमों के लिए समन्वय-समिति

(क) अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी शिक्षा विभाग
(ख) अध्यक्ष, शिक्षण-साधन विभाग
(ग) अध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षा : व्यापक उपागम समूह

(घ) अध्यक्ष, शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन एकक

(ङ) अध्यक्ष, शिशु अध्ययन एकक

(च) प्रिंसिपल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र

(छ) अध्यक्ष, मापन और मूल्यांकन विभाग

(ज) अध्यक्ष, शैक्षिक मनोविज्ञान एकक

(झ) अध्यक्ष, योजना, समन्वय और मूल्यांकन-एकक

(ञ) अध्यक्ष, शिक्षा व्यावसायीकरण एकक

(ट) रीडर (प्रोग्राम)

(ठ) अध्यक्ष, विज्ञान और गणित शिक्षा विभाग

(ड) अध्यक्ष, प्राथमिक पाठ्यक्रम विकास प्रकोष्ठ

(ढ) अध्यक्ष, अध्यापक-शिक्षा विभाग (संयोजक)

परिशिष्ट-घ

सन् 1980-81 के दौरान समितियों द्वारा किए गए मुख्य निर्णय

वित्त समिति

(27 सितम्बर 1980/10 अक्तूबर 1980 और 10 मार्च 1981/24 मार्च 1981)

वित्त समिति ने सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि और पेंशन के नियमों को अपनी स्वीकृति इस स्पष्ट शर्त पर दे दी कि इस विषय में भारत सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनसे इन नियमों की विसंगति नहीं होनी चाहिए।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र के निरंतर चलते रहने वाले कार्यकलाप के रूप में एक आडियो-टेप लाइब्रेरी के विकसित किए जाने को स्वीकृति दी गई।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में जनसंख्या-शिक्षा कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा प्रणाली) के अंतर्गत 28 फरवरी 1983 तक की अवधि के लिए लिपिक वर्गीय पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई।

स्कूल के शिक्षकों और प्राथमिक अध्यापक-शिक्षकों के लिए अनुवर्ती शिक्षा केन्द्रों से संबद्ध कार्यों के लिए सृजित लिपिक वर्गीय पदों के राज्यों में नियमित आधार पर 31 मार्च 1985 तक चलते रहने को स्वीकृति दी गई।

चतुर्थ अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के लिए सृजित लिपिक वर्गीय पदों के चलते रहने को स्वीकृति दी गई।

आंतरिक अध्ययन एकक के लिए 28 फरवरी 1982 तक नीचे लिखे पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई—

(क) रु० 650/- से 1200/- के वेतमान में दो कनिष्ठ विश्लेषक।

(ख) रु० 550/- से 900/- के वेतनमान में दो सहायक विश्लेषक।

(ग) एक निम्न श्रेणी लिपिक ।

24 जुलाई 1980 से छह महीनों के लिए सहायक भंडार अधिकारी के पद के चलते रहने को स्वीकृति दी गई ।

प्रकाशन विभाग की आवश्यक ज़रूरतों के लिए 31 अगस्त 1980 तक भरी गई सात जगहों के सृजन को निदेशक के अधिकारों के अंतर्गत स्वीकृत किया गया ।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी केन्द्र ने राजस्थान के तिलोनिया स्थित सामाजिक कार्य एवं अनुसंधान केन्द्र को रु० 2,686·58 कीमत की जो परिसंपत्ति दी थी, उसे उनके द्वारा रखे जाने को स्वीकृति दी गई ।

एरिक परियोजना "खुली कक्षा में एक प्रयोग" (मुक्त अधिगम परिवेश) के सम्बंध में उदयपुर के विद्या भवन को दान किए गए उपकरणों/सामग्री को स्वीकृति दी गई ।

आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद को "विज्ञान प्रदर्शनी की विधियाँ" के प्रदर्शों को दे दिए जाने को स्वीकृत किया गया ।

प्राथमिक विज्ञान किट का मूल्य 230/- रुपए रखे जाने को स्वीकृत किया गया । पहली अप्रैल 1980 से राज्यों को जो किट दिए जाएँगे उन पर यही मूल्य लागू होगा । 31 मार्च 1984 तक बनाकर भेजे जाने वाले किटों का यही मूल्य रहेगा ।

छात्रवृत्तियों की निम्नलिखित दरों को संस्तुत किया गया—

(i) शैक्षिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन में डिप्लोमा	250/- रु० प्रति माह
(ii) एक-वर्षीय बी० एड० कोर्स	125/- रु० प्रति माह
(iii) एम० एड०	250/- रु० प्रति माह
(iv) एम० एससी० एड०	250/- रु० प्रति माह
(v) चार-वर्षीय बी० एस-सी० एड० के	
पहले दो साल	75/- रु० प्रति माह
तीसरे साल	100/- रु० प्रति माह
चौथे साल	125/- रु० प्रति माह

परिषद् के कार्यक्रमों/सम्मेलनों/सभाओं आदि में आने वाले नॉन-अफ़िश्यल प्रतिभागियों/विशेषज्ञों/संसाधन व्यक्तियों को देय टी० ए०/डी० ए०/आनरेरियम के नियमों को संशोधित कियागया । आगे लिखे को संस्तुत किया गया—

	शहर की श्रेणी	
(1) कार्यगोष्ठी/विचार गोष्ठी प्रशिक्षण कोर्स आदि के प्रतिभागियों को डी० ए०	ए	30 रुपए
	बी	25 रुपए
	सी	20 रुपए
(2) उच्च स्तरीय समितियों के सदस्यों को डी० ए०	ए	50 रुपए
	बी	40 रुपए
	सी	35 रुपए
(3) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के ग्रीष्म-स्कूल-सह-पत्राचार कार्यक्रमों के लिए अतिथि प्रशिक्षकों को डी० ए०	नॉन-आफ़िश्यल को ऊपर क्रम संख्या (1) में दिखाई गई दरों पर	
(4) परिषद् के कार्यक्रमों आदि में चाय, कॉफ़ी, ठण्डे पेय के फुटकर खर्चों के लिए	(i) दो सत्रों के लिए 2/- रुपए प्रति दिन प्रति व्यक्ति की दर से	
	(ii) एक सत्र के लिए 1/- रुपया प्रति दिन प्रति व्यक्ति की दर से	
	(iii) विदेशी अतिथियों के स्वागत में 2/- रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से	
(5) राष्ट्रीय एकीकरण शिविर (छात्र शिविर)		
(i) रहने खाने का खर्च	पन्द्रह दिनों के लिए 10/- प्रति दिन प्रति छात्र की दर से	
(ii) क्षेत्र भ्रमण	2000/- रुपए तक (वास्तविक खर्चों की सीमा में)	
(iii) स्टेशनरी, तीसरे वर्ग की सहायता, चिकित्सा, रिपोर्टों के मुद्रण, फ़ोटो आदि के लिए फुटकर खर्च	2500/- रुपए	

सांख्यिकी में प्रोफ़ेसर के तीन पदों और लेक्चरर के एक पद को स्थायी रूप में जारी रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई ।

बांग्ला और भूगोल में, रु० 550/- से 900/- के वेतन मान में स्नातकोत्तर शिक्षकों की दो जगहों के सृजित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ये जगहें योजना के अंतर्गत रहेंगी।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् में यूनिसेफ़-पोषित अस्थायी पदों के जारी रखने/सृजन को स्वीकृति दी गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किए गए मार्ग दर्शन के आधार पर फेलोशिप की वृद्धि को, 1 अक्तूबर 1980 से लागू किए जाने की सिफारिश वित्त समिति ने की। वृद्धि इस प्रकार है—

कनिष्ठ फ़ेलोशिप	पहले दो सालों के लिए 600/- रुपए प्रति माह और फुटकर खर्चों के लिए 3000/- रुपए प्रति वर्ष का अनुदान।
वरिष्ठ फेलोशिप जिसे अब पोस्ट डाक्टोरल फ़ेलो कहा जाएगा	जिन लोगों ने पी-एच० डी० की थीसिस जमा कर दी है, उनके लिए थीसिस जमा करने की तारीख से 800/- रुपए प्रति माह और फुटकर खर्चों के लिए 3000/- रुपए प्रति वर्ष

परिषद् के शैक्षणिक कर्मचारियों के अलावा दूसरे कार्मिकों को पी-एच० डी० करने के लिए फुटकर खर्चों के अनुदान के भुगतान के बास्ते वित्त समिति सहमत हो गई।

डिमांस्ट्रेशन स्कूलों के पढ़ाने वाले या न पढ़ाने वाले कार्मिकों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के कार्मिकों में जिनका मूल वेतन 600/- रुपए प्रति माह से अधिक नहीं है, उनके बच्चे यदि क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों से जुड़े डिमांस्ट्रेशन स्कूलों में भर्ती किए जाते हैं तो उनकी स्कूल फीस माफ़ कर दिए जाने के प्रस्ताव को वित्त समिति ने स्वीकृति दी। निर्णय 1981-82 के शैक्षणिक सत्र से लागू माना जाएगा।

कार्यकारी समिति

(27 जुलाई 1980 और 23 दिसम्बर 1980)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अंतर्गत वर्तमान 500 छात्रवृत्तियों से अलग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए 50 अतिरिक्त छात्रवृत्तियों के प्रावधान को स्वीकृति दी गई।

सन् 1980-81 के लिए विक्रम ए० साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दी जाने वाली निधियों को स्वीकृति दी गई। यह अनुदान कार्यक्रमों के खर्च के 70% के आधार पर होगा बशर्ते कि राष्ट्रीय समिति द्वारा संस्तुत अधिकतम सीमा पार न हो जाए।

विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों जैसे मान्यता प्राप्त दूसरे संगठनों के विशेष कार्यों के प्रस्तावों को हाथ में लेने या परिचर्चाओं, सम्मेलनों आदि में भाग ले पाने के निमित्त रा० शै० अ० और प्र० प० के शैक्षणिक कर्मचारियों को वर्ष में एक महीने की शैक्षणिक छुट्टी पूरे वेतन और भत्तों के साथ दिए जाने के लिए सिद्धान्ततः समिति सहमत हो गई बशर्ते कि इस तरह की प्रतिभागिता से परिषद् को लाभ हो।

भारत सरकार से सहायता-अनुदान के रूप में मिली निधियों को परिषद् द्वारा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया में अल्पकालिक जमा योजना में लगाने का अधिकार एक समिति को दे दिया गया जिसमें सचिव, उप सचिव, मुख्य लेखा अधिकारी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी होंगे।

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों में शिक्षक-जैकारी के चार-वर्षीय एकीकृत कोर्सों को पुनः शुरू करने के लिए सहमति दी गई।

छठी पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

परिषद् की भवन और निर्माण समिति के लिए कार्यकारी समिति के सदस्य श्री एस० एच० खान की नामजदगी पर सहमति दी गई।

रा० शै० अ० और प्र० प० के अध्यक्ष द्वारा वित्त समिति की सदस्यता के लिए प्रो० वी० जी० कुलकर्णी की नामजदगी को अनुमोदित किया गया।